

भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन



जनवरी 2021

खंड 75 अंक 1

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
एस. गंगाधरन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25 शक्तिकान्त दास	1
------------------------------------------------------------------	---

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	5
भारतीय रुपये के प्रभावी विनिमय दर सूचकांक	35
लघु वित्त बैंक: वित्तीय समावेशन और व्यवहार्यता को संतुलित करना	49
भारत में ग्रीन फाइनेंस : प्रगति और चुनौतियां	61

वर्तमान सांख्यिकी	73
--------------------------	-----------

हाल के प्रकाशन	119
-----------------------	------------

अनुपूरक

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 2019-20
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट: जनवरी 2021

भाषण

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25
शक्तिकान्त दास

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-25*

शक्तिकान्त दास

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति पर इस वेबिनार में आधार व्याख्यान देने हेतु आमंत्रण के लिए एनसीईआर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वेबिनार के लिए यह विषय चुनने की एनसीईआर की विचारशील पहल की मैं सराहना करता हूँ। ऐसे समय में जब हम जीवन और आजीविका की एक अभूतपूर्व क्षति वाले वर्ष की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उचित होगा कि वित्तीय समावेशन और साक्षरता पर विचार किया जाए जिसके वित्तीय स्थिरता के लिए व्यापक समष्टि स्तर के निहितार्थों के साथ-साथ व्यक्ति के वित्तीय कल्याण की दृष्टि से व्यक्तिगत संकेतार्थ भी हैं।

भूमिका

कामकाजी आयु में आबादी के एक बड़े हिस्से वाला भारत दुनिया में पहले से ही क्रय शक्ति समानता के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो यूएसडी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। सरकार व्यापक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से श्रृंखलाबद्ध रूप से स्तर पर नपे-तुले कदम उठाते आ रही है। हमें एक बड़ी युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करके जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर के रूप में एक सक्षम वातावरण और बुनियादी ढांचा बनाने की। मानव संसाधन की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था का और अधिक औपचारिकीकरण, उच्च ऋण जीडीपी अनुपात और अधिक वित्तीय समावेशन जनसांख्यिकीय लाभांश और त्वरित विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारक हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था को वांछित स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

* * 16 दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईआर) द्वारा 'भारत में निवेशक शिक्षा में निवेश : कार्यवाई हेतु प्राथमिकताएं' पर आयोजित वेबिनार में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का आधार व्याख्यान।

ऋण जीडीपी अनुपात में सुधार के लिए, ऋण की उपलब्धता और ऋण की लागत को संपार्श्विक सुरक्षा पर कम निर्भरता और अधिक नकदी-प्रवाह-आधारित उधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रेडिट ब्यूरो और प्रस्तावित पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) ढाँचे से क्रेडिट प्रवाह के साथ-साथ क्रेडिट संस्कृति में सुधार की उम्मीद है। वित्तीय समावेशन के संबंध में सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। परिणामस्वरूप आबादी के बड़े और अब तक शामिल नहीं हुए वर्गों को औपचारिक वित्तीय दायरे में लाया गया है। इस संदर्भ में, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना और गहरा करना हमारी सामूहिक क्षमता को साकार करने के हमारे प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

वित्तीय समावेशन पहल-अब तक

भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयास पहल 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के बाद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के साथ शुरू हुए, जिसे आगे चलकर प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद शाखा नेटवर्क के विस्तार, लीड बैंक योजना का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूह का प्रचार (एसएचजी) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) बैंकिंग कॉर्रेस्पॉन्डेंट (बीसी) मॉडल का कार्यान्वयन, बैंकिंग आउटलेट के विस्तार, भुगतान बैंकों के निर्माण, छोटे वित्त बैंकों द्वारा आगे बढ़ाया गया। हाल के वर्षों में सबसे बड़ा प्रभाव जनधन खातों के खुलने और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई के कार्यान्वयन से पड़ा।

2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत से औपचारिक बैंकिंग सेवा' प्रायः हर घर तक पहुंच गई जिसके साथ सस्ते ऋण, बीमा और पेंशन योजनाओं के लाभ भी उपलब्ध थे। इसको बीसी मॉडल जैसे अभिनव बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अच्छा सहयोग मिला जिसके द्वारा बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। प्रौद्योगिकी की वजह से डिजिटल वित्तीय सेवाओं में बड़ी उन्नति हुई है। जनधन

¹ 2 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार 41.38 करोड़ लाभार्थी बैंक से जुड़े, लाभार्थियों के खातों में, ₹130,932.33 करोड़ शेष - <https://www.pmjdy.gov.in>

खाता, आधार और मोबाइल (जेएएम) के परितंत्र (इकोसिस्टम) ने वित्तीय समावेश की दुनिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

इसके अलावा जमीनी स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने और एक सुविधाजनक सुरक्षित और सस्ते तरीके से डिजिटल भुगतानों को सार्वभौमिक बनाने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें महत्वपूर्ण है, रिजर्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिले को 100% डिजिटल रूप से सक्षम बनाना है। आठ आकांक्षात्मक जिलों के साथ 42 जिले इस पहल का हिस्सा हैं। आवश्यक डिजिटल परितंत्र के अलावा, हित धारकों द्वारा लक्षित समूहों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित ध्यान पायलट परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा योगदान देगा और अन्य जिलों में ऐसे प्रयासों को आगे ले जाने का एक खाका प्रदान करेगा।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ एस डी सी) ने वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एन एस एफ आई) दस्तावेज़ को मंजूरी दे दी, जिसे इस वर्ष आरबीआई ने 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया था। समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए एनएसएफआई में बहु हित धारक (मल्टी स्टेक होल्डर) दृष्टिकोण से सभी नागरिकों को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध, सुलभ और सस्ती बनाने की परिकल्पना है।

भारत में वित्तीय शिक्षा

सरकार और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति एजेंडा

वित्तीय समावेश में वृद्धि के साथ ग्राहक संरक्षण और वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करते रहें। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अधिक जागरूकता और विनियमित इकाइयों द्वारा उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और

सेवाओं तक पहुँच का रास्ता बनाकर बनाकर वित्तीय शिक्षा मांग पक्ष का प्रतिसाद तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्तीय शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों और उनके परिवारों की वित्तीय समुत्थानशीलता को भी मजबूत किया जा सकता है। इन विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे दो प्रयासों की मैं चर्चा करता हूँ-

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एन सी एफ ई) की स्थापना

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफआई) के अनुसार जनसंख्या के सभी वर्गों को भारत भर में वित्तीय शिक्षा देने और बढ़ावा देने के लिए एनसीएफई को चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। एनसीएफई सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा अभियान चलाती है ताकि लोग धन का प्रबंधन सही ढंग से कर सकें और इस प्रकार उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो।

वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना- सामुदायिक पद्धति से वित्तीय शिक्षा देने का एक अभिनव तरीका

वित्तीय साक्षरता के लिए ब्लॉक स्तर पर चुनिंदा बैंकों और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करते हुए रिजर्व बैंक ने 2017 में सीएफएल परियोजना की अवधारणा एक अभिनव व सहभागी पद्धति के रूप में प्रस्तुत की। 100 ब्लॉकों में पायलट आधार पर शुरू की गई यह परियोजना अब चरणबद्ध तरीके से मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू होने जा रही है। यह 4 दिसंबर 2020 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के वक्तव्य के अंतर्गत की गई घोषणाओं में से एक थी। आगे चलकर आपूर्ति पक्ष पर संस्थागत प्रयासों में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाने के लिए मांग पक्ष पर समुदाय की अधिक भागीदारी और ग्रहणशीलता सुनिश्चित करते हुए परियोजना में वित्तीय समावेशन के साथ-साथ शिक्षण के प्रतिमान को बदलने की परिकल्पना की गई है।

³ एनएसएफई 20 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/NSFIREPORT100119FF91DAA6B73B497A923CC11E0811776D.PDF>

² <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/NSFIREPORT100119.pdf>.

कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय शिक्षा के प्रसार से मिली सीख

कोविड-19 संबंधी राष्ट्रव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) और विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बड़े पैमाने पर एकत्र होने पर प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप पारंपरिक वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन में व्यवधान आया है। इस अवधि के दौरान देशभर में सोशल मीडिया, मास मीडिया (स्थानीय टीवी चैनलों रेडियो सहित) के प्रयोग, स्थानीय स्कूल शिक्षा बोर्ड से संपर्क, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रशिक्षण मिशनों आदि विभिन्न तरीकों से वित्तीय शिक्षा का प्रसार जारी रखा गया।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई 2020-2025)

दृष्टि (विज्ञान), रणनीतिक उद्देश्य और 5सी पद्धति

वित्तीय शिक्षा रणनीतिक स्तंभों में से एक है, जो वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (2020-2025) के लिए व्यापक संदर्भ निर्धारित करता है। एनएसएफई (2020- 2025) ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने की महत्वकांक्षी विज्ञान तय किया है। यह वित्तीय संस्थानों (बैंक व गैर बैंक दोनों), शिक्षा संस्थानों, हित धारकों और औद्योगिक इकाइयों की भूमिका को बढ़ाकर बैंकिंग, बीमा, पेंशन और निवेश के सभी क्षेत्रों में वित्तीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। स्कूली बच्चों, शिक्षक, युवा, महिलाओं, नए कर्मचारी, एमएसएमई के नए उद्यमियों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग जनों और अशिक्षितों जैसे विभिन्न लक्ष्य समूहों तक पहुँच के लिए लक्षित मॉड्यूलों सहित नवोन्मेषी तकनीकों और वितरण के डिजिटल तरीकों की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित उपयोग और शिकायत निवारण उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय शिक्षा में प्रगति के मूल्यांकन के तरीकों को भी रणनीतिक उद्देश्यों में रखा गया है।

रणनीति में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए प्रासंगिक **सामग्री/कंटेंट** (स्कूलों और कॉलेजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के पाठ्यक्रम सहित) के विकास; वित्तीय सेवाओं और शिक्षा प्रदान करने वाले मध्यस्थों की **क्षमता (कैपेसिटी)**; उपयुक्त संप्रेषण रणनीति के माध्यम से वित्तीय साक्षरता के **समुदाय (कम्यूनिटी)** चालित मॉडल के सकारात्मक प्रभाव के अधिकाधिक उपयोग; और विभिन्न हित धारकों के बीच **सहयोग (कॉलेबोरेशन)** में वृद्धि की '5सी' पद्धति ('5सी' एप्रोच) शामिल है।

आगे का रास्ता और निष्कर्ष

डिजिटल ज्ञान से लैस नई पीढ़ी के कर्मक्षेत्र में आने, शहरी-ग्रामीण विभाजन को मिटाने वाले सोशल मीडिया और नीतिगत हस्तक्षेप को आकार देने वाली प्रौद्योगिकी से देश में वित्तीय समावेश में बड़ी तेजी आनी तय है। आगे, देश भर में बैंक खातों की सार्वभौमिक पहुँच का दोहन करते हुए, अधिक ग्राहक सुरक्षा के साथ मांग से जुड़ी बाधाओं को दूर करके टिकाऊ ऋण, निवेश बीमा और पेंशन उत्पादों के और गहरे पैठ पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

वित्तीय शिक्षा में हस्तक्षेप को विभिन्न लक्षित दर्शकों/श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए ढालना (स्थानीय भाषा और स्थानीय सेटिंग) होगा। वित्तीय साक्षरता की हमारी यात्रा में ब्लॉक स्तर पर देश भर में सीएफएल प्रोजेक्ट का विस्तार समुदाय चालित सहभागी दृष्टिकोण की आधारशिला होगी।

तकनीक सक्षम बनाने का एक महान साधन है, पर इससे समाज के कुछ वर्ग छूट भी सकते हैं। जो अब तक बाहर छूटे हैं, आबादी के उन तबकों के बीच, औपचारिक वित्तीय सेवाओं में विश्वास पैदा कराना जरूरी है। उचित वित्तीय शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, अपविक्रय (मिस सेलिंग), ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण के मुद्दों पर कार्रवाई के लिए जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये बातें वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं पर बड़ी जिम्मेदारी डालते हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लोगों में आकांक्षाएं हैं, वित्तीय शिक्षा केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की जिम्मेदारी नहीं बन सकती। इस पहलू को एनएसएफई दस्तावेज में रेखांकित किया गया है, जिसमें सभी की वित्तीय भलाई के लिए एक बहु हितधारक दृष्टिकोण को आगे रखने की सिफारिश की गई है। आगे, अधिकाधिक शिक्षा संस्थानों, उद्योग निकायों, तथा थिंक टैंकों, अनुसंधान

संस्थाओं जैसे हितधारकों को उचित जागरूकता अभियानों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए सामने आना चाहिए। मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति और संस्था को आमंत्रित करता हूँ, कि वे आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमारे राष्ट्र के निर्माण के मिशन से जुड़ें।

धन्यवाद।

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारतीय रुपये के प्रभावी विनिमय दर सूचकांक

लघु वित्त बैंक: वित्तीय समावेशन और व्यवहार्यता को संतुलित करना

भारत में ग्रीन फाइनेंस : प्रगति और चुनौतियां

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

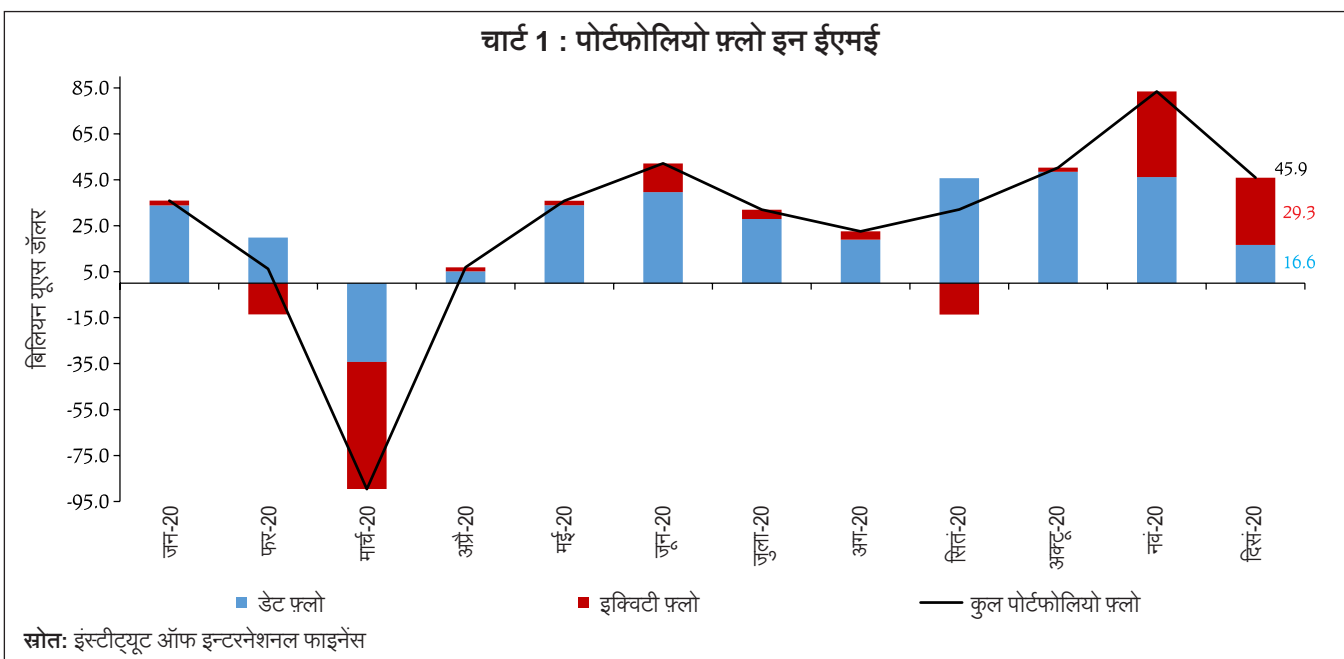
2020 एक ऐसा साल बन गया जिसमें सब कुछ बदल गया। वर्ष 2021 ने दुनिया भर के देशों के साथ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। जीडीपी के सकारात्मक स्थिति को प्राप्त करने में विलंब और मुद्रास्फीति के लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ भारत में, मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य में हालिया बदलाव ने दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है। ईएमई द्वारा मजबूत पोर्टफोलियो इनफ्लो प्राप्त करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की रिकॉर्ड वार्षिक इनफ्लो प्राप्त करने के लिए भारत तैयार है को देखते हुए वित्तीय बाजार उत्साहित हैं।

वर्ष 2020 का समय भी क्या निकला! इसकी शुरुआत किसी अन्य वर्ष की ही तरह ही हुई बस वर्ष 2019 की तुलना में एक दिन अधिक था, चीन के वुहान में एक गीले बाजार से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को निमोनिया जैसी दिखने वाली बीमारी रिपोर्ट की गई। वर्ष के अंत तक, कोविड -19 ने आधिकारिक तौर पर 81 मिलियन लोगों को संक्रमित कर दिया था, और संभवतः 500 मिलियन और अधिक लोगों को डाइग्नोज ही नहीं किया गया (द इकोनॉमिस्ट 19 दिसंबर 2020)। इसके कारण 1.8

मिलियन लोगों की मौत हुई, लेकिन कई हजारों लोगों की मौत तो दर्ज ही नहीं हो पाई। दो विश्व युद्धों और स्पैनिश फ्लू के चलते कहीं अधिक मौतें हुईं, लेकिन कोविड -19 ने लोगों के दैनिक जीवन को इस तरीके से बदल दिया है जो इन घटनाओं में भी नहीं हुआ था। बचे हुए लाखों लोग अभी भी वायरस द्वारा छोड़े गए निशान और थकावट से जूझ रहे हैं, और दुनिया में पीड़ा, गरीबी (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 200 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी में होंगे), असमानता और खतरे का माहौल है। बच्चों ने शिक्षा, ग्रेजुएट प्लेसमेंट, श्रमिकों को जबरन पलायन को झेला और सभी उम्र के लोगों को अकेलेपन का सामना करना पड़ा है।

बेरोजगारी बढ़ गई है और शेयर बाजारों पर भी ऐसा ही असर पड़ा है। विदेशी निवेशक उभरते बाजारों की दिशा में चले गए हैं - जबकि केवल मार्च में ही यूएस में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), पोर्टफोलियो प्रवाह में तब से वापसी हुई है, जो कि नवंबर के महीने में 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और दिसंबर में यूएस \$ 16.6 बिलियन कर्ज में और यूएस \$ 29.3 बिलियन इक्विटी (IIF, 2021) (चार्ट 1) में। ईएमई में, चीन और भारत ने विकास की संभावनाओं के कारण प्रवाह को खींचा।

चार्ट 1 : पोर्टफोलियो फ्लो इन ईएमई



* इस लेख को देबा प्रसाद रथ, प्रज्ञा दास, आशीष थॉमस जॉर्ज, संगीता मैथ्यूज, अभिलाषा, कृष्ण मोहन कुशवाहा, मधुरेश कुमार, कुणाल प्रियदर्शी, अभिनंदन बोराड, जितेंद्र सोकल, मनु शर्मा, शोभित गोयल, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, ऋषभ कुमार, श्रीरूप सेनगुप्ता, राजस सरॉय, शशिधर एम.लोकरे और माइकल देवव्रत पात्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

अनुमानों के प्रति आशंकाओं के रूप में, COVID-19 (द इकोनॉमिस्ट, 9 जनवरी, 2021) के बिना विश्व उत्पादन कम से कम 7 प्रतिशत कम हो सकता है - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मंदी आई है, वर्ल्ड मर्चेन्डाइज़ ट्रेड 9.2% से (डबल्यूटीओ, 2020) और सेवाओं में विश्व व्यापार 15 प्रतिशत से (यूएनसीटीएडी, 2020)। इतिहास से पता चलता है कि सामाजिक अशांति एक महामारी के 14 महीने बाद बढ़ती है और 24 महीने (आईएमएफ, 2020) में चरम पर पहुंचती है। लॉकडाउन के दौरान स्पष्ट नीले आसमान ने खुलासा किया कि तेजी से बढ़ते COVID-19 संकट के भीतर एक धीमी गति से चलने वाला जलवायु संकट है, जो लोकलुभावन इनकार के लिए अभेद्य है, इसकी विघटनकारी क्षमता वैश्विक है और कहीं अधिक महंगी है।

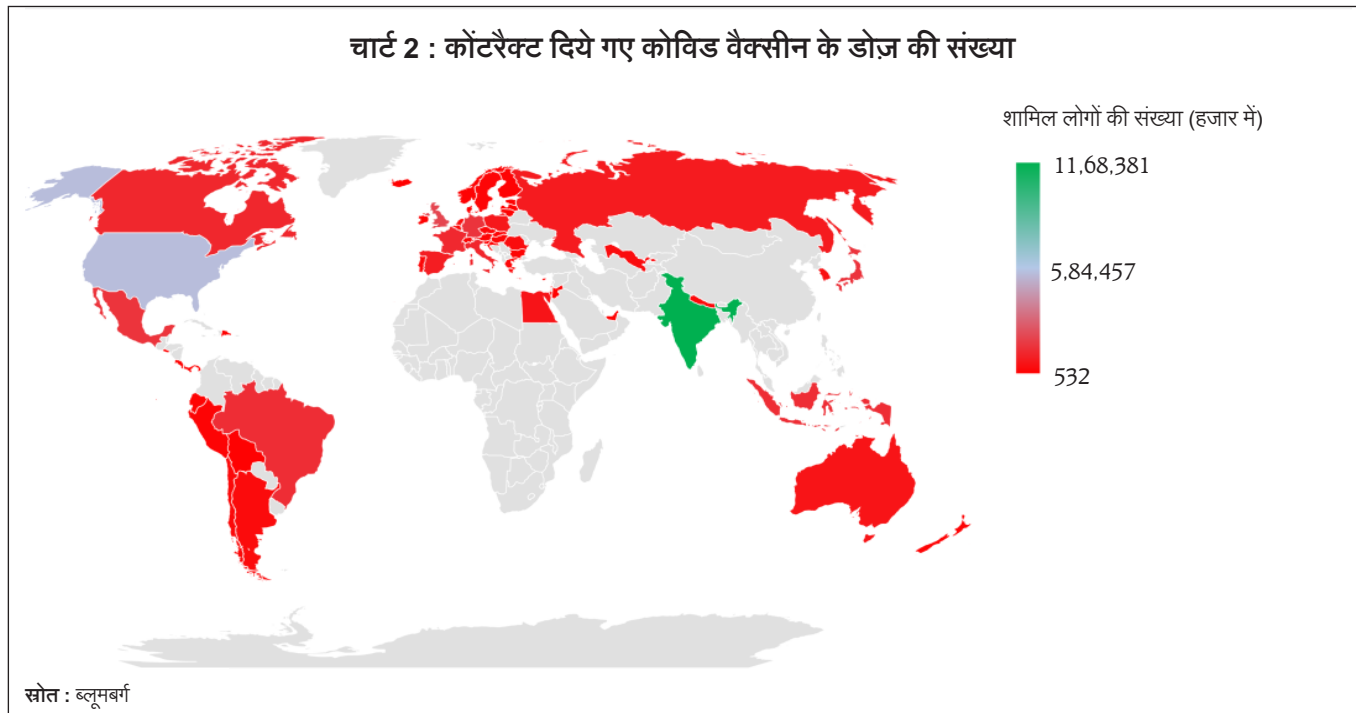
फिर भी, असंभव रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया इस शताब्दी में एक बार आने वाले वर्ष में दुनिया में शीघ्र ही कुछ घटित होने वाला है जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही वर्ष 2021 आया दुनिया में 12 मिलियन से अधिक लोगों को वैक्सीन (चार्ट 2) की पहली खुराक दी जा चुकी थी। समाचार पत्रों ने बताया है कि अग्रिम अनुबंधों के माध्यम से विभिन्न देशों द्वारा वैक्सीन की 8.25 बिलियन खुराकें सुरक्षित की गई हैं (COVID-19 टीके दो-खुराक में दिये जाते हैं)।

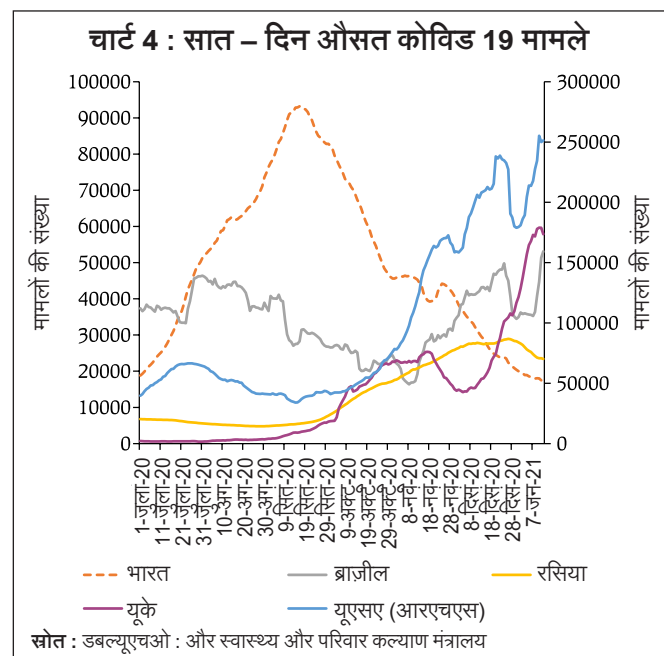
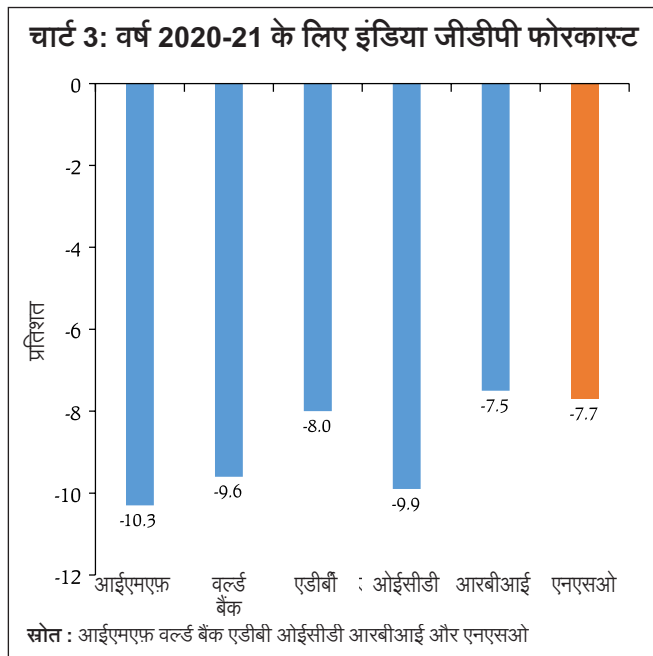
3 जनवरी, 2021 को भारत ने औपचारिक रूप से दो टीकों के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी और 16 जनवरी को,

इसने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण ड्राइव शुरू की, जिसमें इस वर्ष लगभग 300 मिलियन लोगों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने की योजना थी। यह बताया गया है कि भारत ने 1.2 बिलियन अग्रिम खुराक प्राप्त की है, जो 85 प्रतिशत आबादी (ब्लूमबर्ग, 2020) को कवर करती है।

चार अन्य विशेषताएं हैं जिन्होंने भारत को दुनिया से अलग किया है जिससे यह संभावना बढ़ी है कि हमारी रिकवरी अधिकांश अनुमानों से आगे निकल सकती है, जैसा की इस लेख में लगातार बताया गया है। 27-संकेतक आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) (कुमार, 2020) ने तीसरी तिमाही : 2020-21 के लिए अपना नावकास्ट अपडेट किया है और दिसंबर 2020 के अंक में तिमाही की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 0.1 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा 7 जनवरी को जारी 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों में भी परिलक्षित होता है, जिसमें 2020-21 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान (-) 7.7 प्रतिशत के विरुद्ध (- अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 10.3 प्रतिशत और दिसंबर 2020 (चार्ट 3) में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा (-) 7.5 प्रतिशत है।

पहला, भारत अब तक COVID-19 की दूसरी लहर से बचने में सफल रहा है। इसके अलावा, सितंबर के मध्य से, भारत

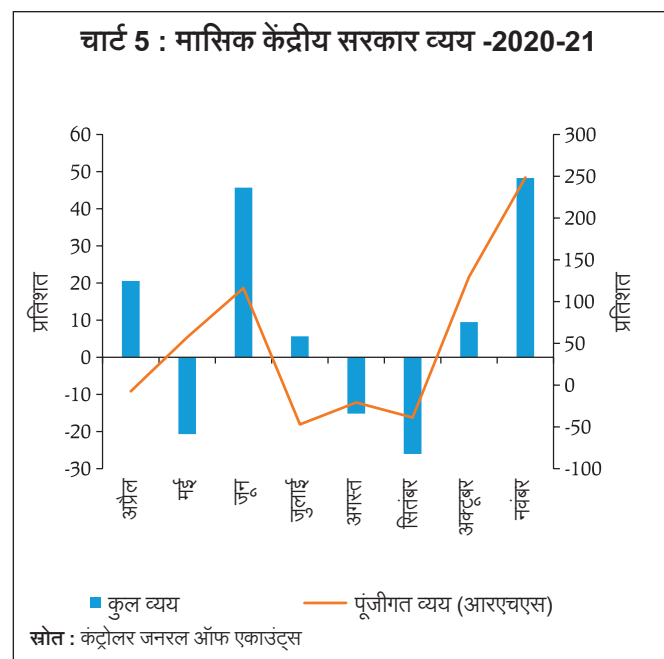


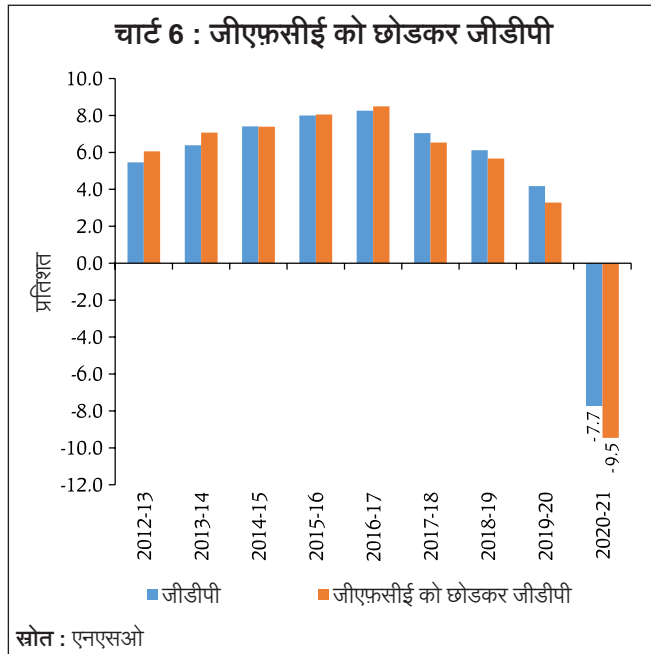


ने 'बेकहम की तरह इसे झुका दिया' - 2020 के अंत तक, सक्रिय मामलों की संख्या 17 सितंबर को 10,17,754 के शिखर से 2,54,254 तक गिर गई थी। भारत में रिकवरी दर सुधरकर 96.1 प्रतिशत हो गई है जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दर है। मृत्यु दर 1.4 प्रतिशत है, जो विश्व मृत्यु दर (2.2 प्रतिशत) से कम है, और एक लाख से अधिक संक्रमण वाले देशों (चार्ट 4) के मध्य दूसरा सबसे कम है।

दूसरा, चार महीने के अंतराल के बाद, जिसके दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च संकुचन में चला गया या मौन रहा, इसने नवंबर 2020 में रिकवरी को फिर से शुरू किया, जो साल-दर-साल के आधार पर 48.3 प्रतिशत बढ़ गया। इस व्यय बढ़ोत्तरी के भीतर, विकास को पोषित करने वाला पूंजीगत व्यय एक तीन महीने के संकुचन में चला गया और यह 248.5 प्रतिशत बढ़ गया जो कि आत्मा निर्भर 2.0 घोषणाओं के अनुसरण में कैपेक्स के लिए राज्यों को किए जाने वाले अंतरण में वृद्धि के चलते इसके आधे के करीब पहुँच गया था (चार्ट 5)। उप-राष्ट्रीय स्तर पर, 20 राज्यों के लिए जानकारी बताती है कि 8 महीने तक लगातार अनुबंध करने के बाद अक्टूबर 2020 के दौरान पूंजीगत व्यय में वृद्धि सकारात्मक रही। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, क्योंकि सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीडी) ने चौथी तिमाही : 2016-17 से

जीडीपी को लगातार मूल्यवान प्रति-चक्रिय समर्थन प्रदान किया है। इस समर्थन के बिना, 2017-18 में 7.0 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि केवल 6.5 प्रतिशत रही होती, जबकि यह 2018-19 में 6.1 प्रतिशत के बजाय 5.7 प्रतिशत रही होती और 4.2 प्रतिशत के बजाय 3.3 प्रतिशत होती, पहली तिमाही : 2019-20 (चार्ट 6)। पहली तिमाही: 2020-21 में जब COVID -19 के

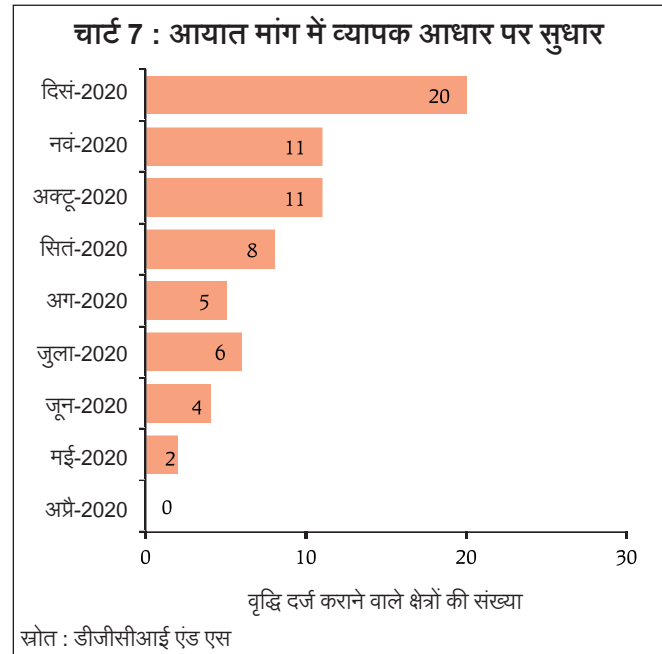




कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में एक अभूतपूर्व 23.9 फीसदी की गिरावट आई थी, जीएफसीई ने 29.3 प्रतिशत की और भी तेज़ गिरावट को रोका था।

तीसरा, माल आयात अंत में लगातार 9 महीनों में संकुचन से बाहर आया और दिसंबर 2020 (चार्ट 7) में 7.6 प्रतिशत (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि हुई। आयात में पलटाव व्यापक था, जिसमें 30 में से 20 प्रमुख वस्तुओं ने विस्तार दर्ज किया। इनमें से कई वस्तुएं आपूर्ति श्रृंखलाओं में मध्यवर्ती वस्तुओं की प्रकृति की हैं, जो घरेलू औद्योगिक गतिविधि और आयात-गहन निर्यात के लिए अच्छी तरह से विकसित होती हैं। इससे पता चलता है कि घरेलू मांग की वजह से अर्थव्यवस्था की मृतप्राय क्षमता वापस आ रही है। पूंजी प्रवाह में वृद्धि, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में देख रही है, यहां से हो सकता है कि यह निवेश और विकास का समर्थन करें और आरक्षित संचय के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली घरेलू बचत के बजाय घरेलू बचत बढ़ा सकती है। भारत के भुगतान शेष के टेल वैगिंग दि डॉग¹ के दिन अंततः समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

¹ भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, यह व्यापारिक व्यापार खाता है जो अपने शेष भुगतान पर हावी है, और पूंजी खाता आमतौर पर एक छोटी वित्तपोषण भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में, हालांकि, विशेष रूप से 2019 के बाद से, भारत में शुद्ध पूंजी प्रवाह एक स्तर तक बढ़ गया है, जिसमें वे शेष राशि के भुगतान में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 'टेल वैगिंग दि डॉग' की घटना होती है। आगे पढ़ने के लिए, कृपया <https://www.bostonfed.org/-/media/Documents/conference/28/conf28h.pdf?la=en> का संदर्भ लें।



चौथा, बैंक क्रेडिट मांग 6 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ी है, जिसने उप-6 प्रतिशत वृद्धि के 5 महीने के समय को उलट दिया है। कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और परिवहन, व्यापार और पर्यटन के नेतृत्व में सेवा क्षेत्र में मजबूत ऋण प्रवाह के शीर्ष पर क्रेडिट चक्र को गतिशीलता प्रदान की है।







इस पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में इस लेख के शेष भाग को पांच खंडों में सृजित किया गया है। खंड II संक्षेप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकास को दर्शाता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित आवेग खंड III में निहित हैं। खंड IV वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करता है, जबकि अंतिम खंड कुछ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

II. ग्लोबल सेटिंग

यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए लॉकडाउन क्रिसमस था, क्योंकि वायरस के एक नए और अधिक वायरल स्ट्रेन ने और दूसरी / तीसरी लहर के तेजी से फैलने ने न केवल इस समय हर्षोल्लास को बल्कि वैक्सीन द्वारा उत्पन्न आशावाद को भी हतोत्साहित किया। कुछ ईएमई में महामारी से होने वाले व्यवधान पहले से प्रत्याशित रूप से अधिक गंभीर हो गए हैं, जिसका खामियाजा कमोडिटी निर्यातकों को भुगताना पड़ रहा है। कुल मिलाकर, 2020 के मध्य से शुरुआती रिबाउंड के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी धीमी हो गई है। विनिर्माण

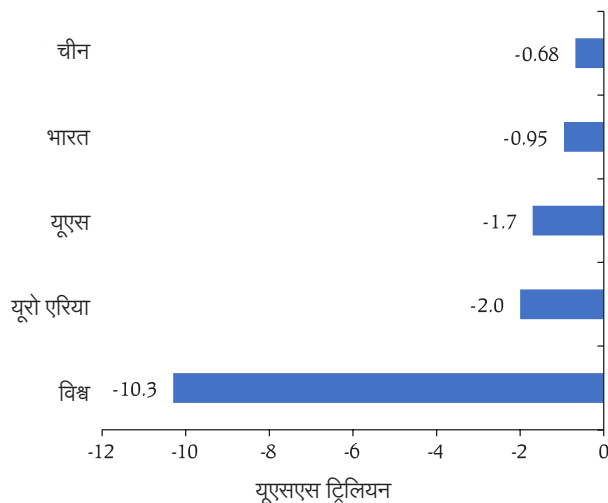
गतिविधि और व्यापार में सुधार को अवसादग्रस्त सेवा क्षेत्रों द्वारा हतोत्साहित कर दिया गया है। वैश्विक निवेश में गिरावट की घोषणा कर दी गई है। जबकि, वित्तीय स्थितियां बेहद आसान हैं, वित्तीय कमजोरियां बढ़ रही हैं, जिससे यह डर बढ़ रहा है कि कोविड -19 संकट अंततः वित्तीय संकट में बदल जाएगा (रेनहार्ट, 2020)। जनवरी के आते ही, लक्ष्यों के अद्यतनीकरण का समय आ गया है, और विश्व बैंक इसका नेतृत्व कर रहा है। 5 जनवरी, 2021 को जारी अपनी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावनाओं (जीडीपी) में, अनुमान है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का 2020 में 4.3 प्रतिशत घट गई है - ईई 5.4 प्रतिशत; ईएमई एक्स -चीन 5.0 प्रतिशत से (तालिका 1)। 2021 में, यह अनुमान है कि वैश्विक उत्पादन में 4 प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन पूर्व-महामारी अनुमानों से 5.3 प्रतिशत नीचे या यूएस \$ 4.7 ट्रिलियन डॉलर से कम रहेगी। ईई और ईएमई और एक्स -चीन मोटे तौर पर विकास प्रोफाइल में एक जैसे दिखेंगे, 3.3-3.4 प्रतिशत के मामूली विस्तार के साथ। भारत के संबंध में 5.4 प्रतिशत विस्तार की उम्मीद है, जो उसके ऐतिहासिक रिकॉर्ड से परिलक्षित होता है। ऐसा अनुमान है कि COVID-19 से 2020 और 2021 (चार्ट 8) में विश्व जीडीपी में 10.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच, भारत को यूएस \$ 950 बिलियन का सबसे बड़ा नुकसान होगा (द इकोनॉमिस्ट, 9 जनवरी, 2021)। महामारी एक तरफ ऋण के संचय के आसपास के जोखिमों को बढ़ा सकती है और दूसरी

तालिका 1 : जीडीपी वृद्धि अनुमान – चुनिन्दा ईई और ईएमई

देश	2020		2021	
	जून 2020	जन 2021	जून 2020	जन 2021
 विश्व	-5.2	-4.3	4.2	4.0
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ				
 यूएस	-6.1	-3.6	4.0	3.5
 यूरो एरिया	-9.1	-7.4	4.5	3.6
 जापान	-6.1	-5.3	2.5	2.5
उदीयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ				
 ब्राज़ील	-8.0	-4.5	2.2	3.0
 रूस	-6.0	-4.0	2.7	2.6
 भारत	-3.2	-9.6	3.1	5.4
 चीन	1.0	2.0	6.9	7.9
 साउथ अफ्रीका	-7.1	-7.8	2.9	3.3

स्रोत : विश्व बैंक

चार्ट 8 : महामारी के पूर्व किए गए अनुमानों की तुलना में 2020 -21 में जीडीपी में कमी



स्रोत : दी इकोनॉमिस्ट, 09 जनवरी 2021









ओर संभावित उत्पादन में लंबे समय तक मंदी का कारण बन सकती है। नतीजतन, अनुमानों के लिए नकारात्मक जोखिम की भविष्यवाणी करते हैं।

मूल्य की स्थिति पर, अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, निम्नलिखित में से ईई और उपरोक्त में से कई ईएमई (तालिका 2)। खाद्य पदार्थों की कीमतों में विशेष रूप से ईएमई में वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि संयुग्मन में काम कर रहे कारकों के संगम के कारण है यथा सरकारों ने अपने खाद्य भंडार बढ़ाने शुरू कर दिये हैं, लॉजिस्टिकल समस्याएँ और ला नीना लैटिन अमेरिका² में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन का खाद्य मूल्य सूचकांक 2020 में 3.1 प्रतिशत बढ़ गया जिसके साथ मासिक सूचकांक दिसंबर में छह साल के उच्च स्तर पर था।

² <https://www.ft.com/content/20a5e763-4d2f-4872-a1f9-7852a5be6d68>

**तालिका 2 : मुद्रारूपीति अनुमान 2020 – दिसंबर में चुनिन्दा
ई और ईएमई अनुमान**

(प्रतिशत)

देश	अनुमान	लक्ष्य / नियंत्रण सीमा का मध्य बिन्दु अथवा वर्ष 2020 के लिए टोलरेंस बैंड
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ		
 यूएस	1.2	2.0
 यूरो एरिया	0.2	2.0
 कनाडा	0.6	2.0
उदीयमान मार्केट अर्थव्यवस्थाएँ		
 ब्राजील	4.3	4.0
 रूस	4.6 to 4.9	4.0
 भारत	6.6*	4.0
 थाईलैंड	-0.9	2.0
 इंडोनेसिया	1 प्रतिशत से कम	3.0

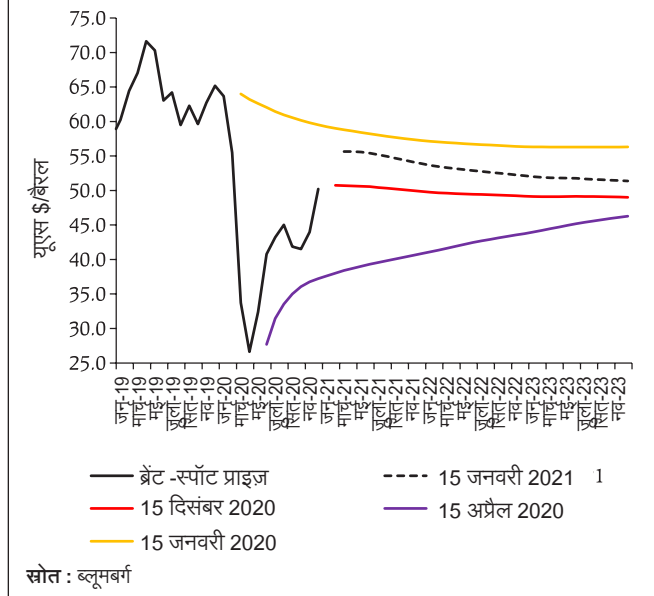
*:एक्चुअल्स (जून-सितंबर 2020) के आधार पर वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित औसत और 4 दिसंबर 2020 के एमपीसी विवरण में ति. 3 और ति. 4 : 2020-21 के लिए अनुमान

स्रोत : केंद्रीय बैंक वेबसाइट

इस बीच, पेट्रोलियम निर्यातक देशों (ओपेक) प्लस के संगठन द्वारा वैक्सीन के मोर्चे पर सकारात्मक विकास और उत्पादन में कटौती के विस्तार की वजह से दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि जारी रही। दिसंबर में यूएस \$ 49.9 प्रति बैरल के औसत पर, ब्रेंट दिसंबर में 15.5 प्रतिशत महंगा था (चार्ट 9)। हालांकि, 2020 में औसत ब्रेंट की कीमत 2019 की तुलना में लगभग 34 प्रतिशत कम थी। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2020 में तेल की मांग में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है।

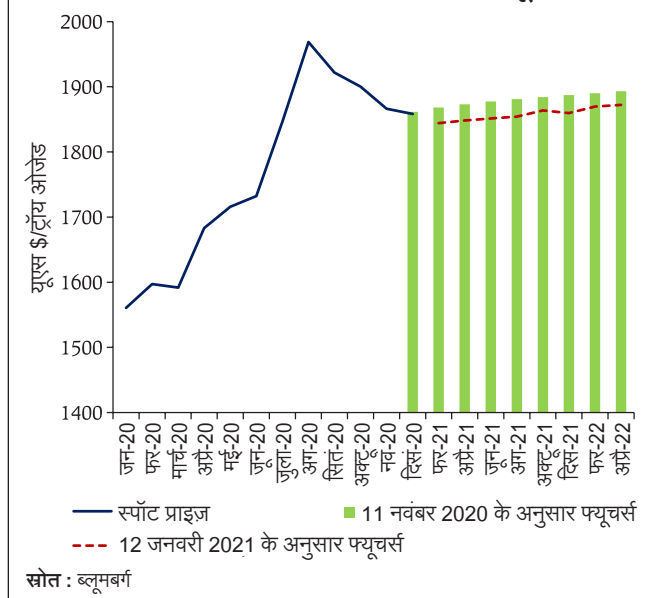
सोने ने एक अभूतपूर्व साल की शुरुआत की, जिसमें अगस्त में बुलियन कीमतों में 25.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ, पिछले वर्ष

चार्ट 9 : ब्रेन्ट फ्यूचर्स



में 18.3 प्रतिशत चढ़ने के बाद सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। सेफ हैवेन डिमांड और अभूतपूर्व मौद्रिक एकोमोडेशन ने बुलियन को 2020 में एक शीर्ष प्रदर्शन वाली परिसंपत्ति बना दिया। 2021 सेफ हैवेन डिमांड कम होने के कारण सेल ऑफ और डॉलर की मजबूती (चार्ट 10) के कारण सोने की कीमतें सही हो गई हैं। सोने की महिमा के आधार पर, चांदी का 2020 में भी

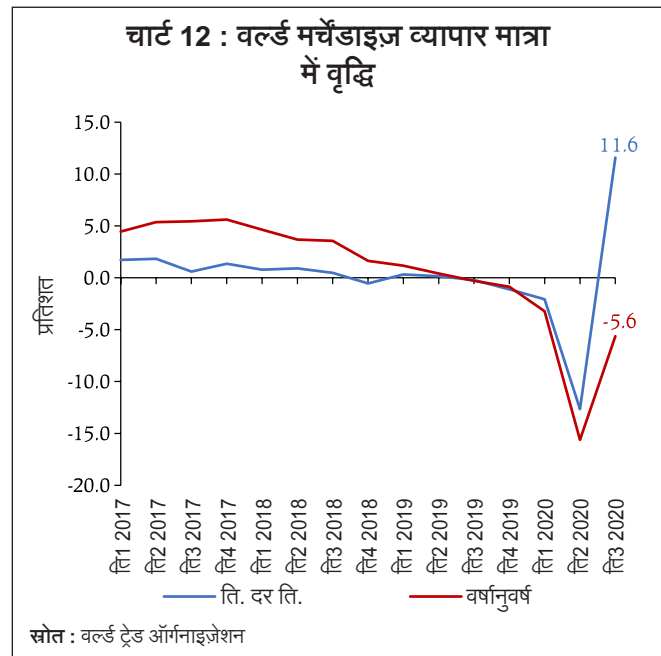
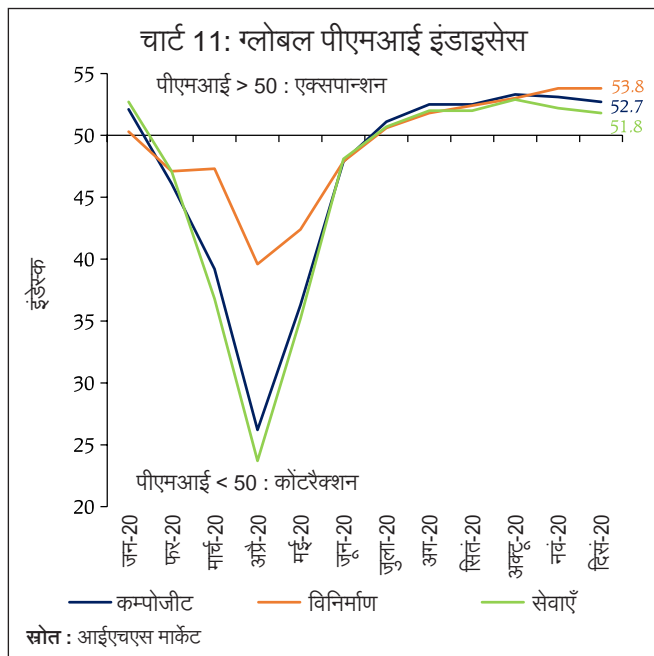
चार्ट 10 : गोल्ड प्राइजेस -स्पॉट एंड फ्यूचर्स



अच्छा साल रहा। बेस मेटल्स, जिन्होंने साल के शुरुआती महीनों में तेज गिरावट देखी थी, एच 2:2020 में मजबूती से उबरने के साथ ही साल का अंत हुआ।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) दिसंबर में 52.7 पर आ गया, जो मुख्य रूप से सेवाओं के पीएमआई के पांच महीने के निचले स्तर तक अर्थात 51.8 पर आने के कारण था। अच्छी खबर यह है कि यह पूरे एच 2: 2020 के लिए विस्तार क्षेत्र में बना हुआ है। दिसंबर में वैश्विक विनिर्माण पीएमआई ने नवंबर के 33 महीने के उच्च स्तर को बनाए रखा। फरवरी और जून (चार्ट 11) के बीच भारी गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पादन एच 2: 2020 में लगातार बढ़ा है। इस बीच, मूल्य गति लगातार बढ़ती जा रही है - मई 2011 के बाद से दिसंबर में इनपुट कीमतें अपनी उच्चतम गति से बढ़ीं।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व व्यापार माल की मात्रा में पिछली तिमाही में 12.7 प्रतिशत के संकुचन के बाद ति.3: 2020 में 11.6 प्रतिशत का क्रमिक सुधार हुआ। हालाँकि, ति. 3 में वर्षानुवर्ष आधार (चार्ट 12) पर 5.6 प्रतिशत का संकुचन था। इसका प्रभावी रूप से मतलब है कि 2020 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान व्यापारिक व्यापार की मात्रा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.2 प्रतिशत कम थी,



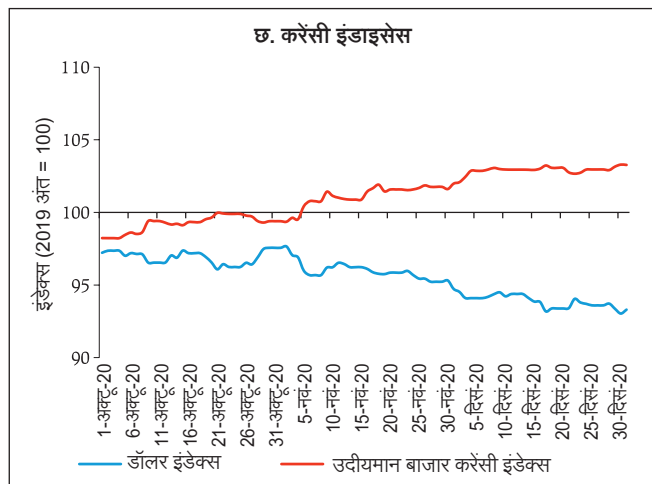
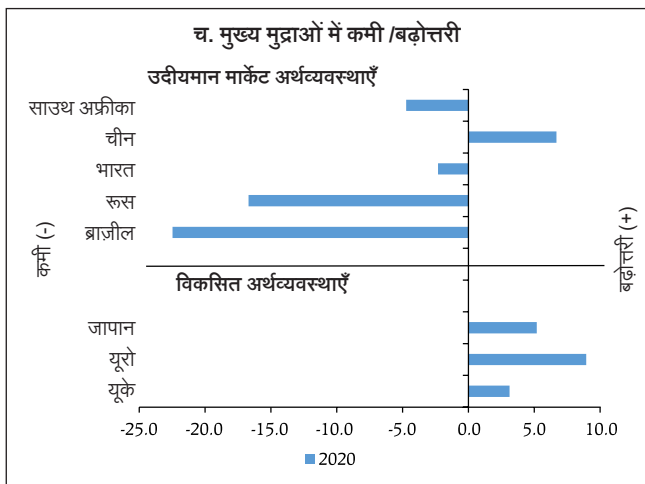
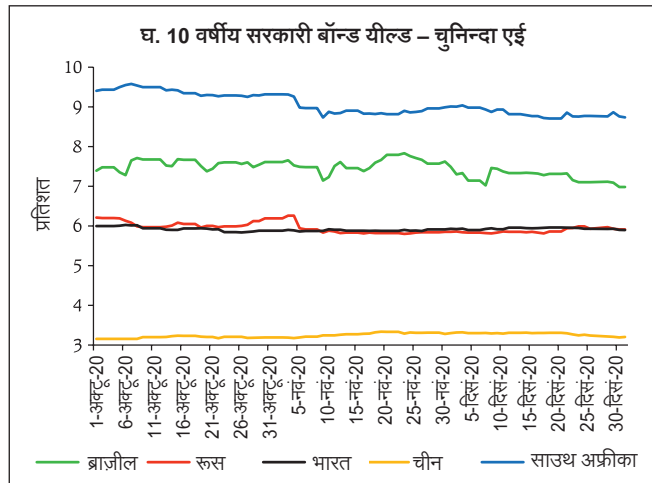
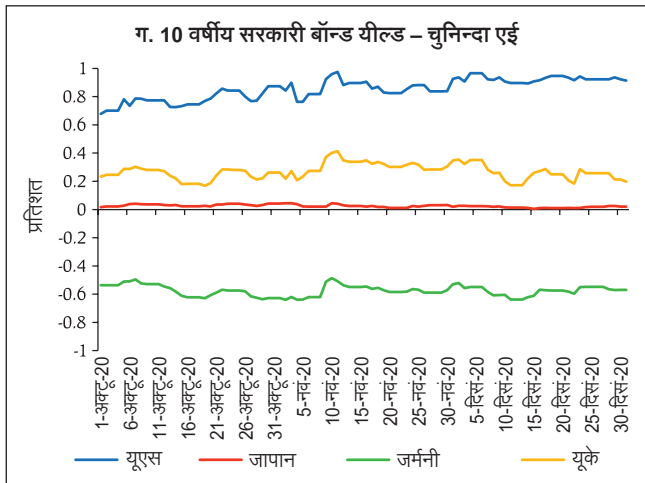
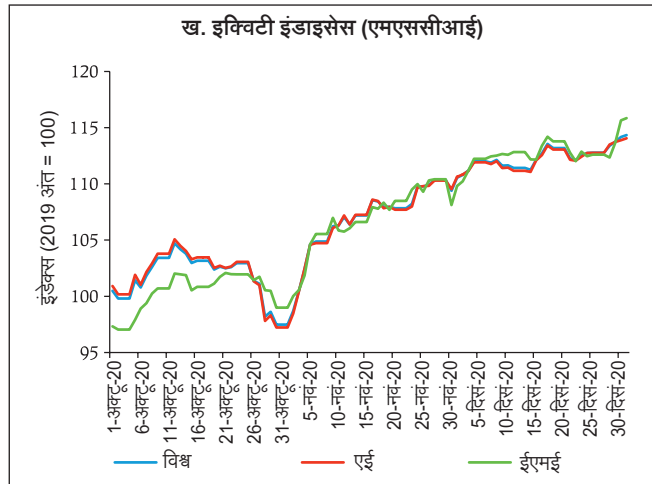
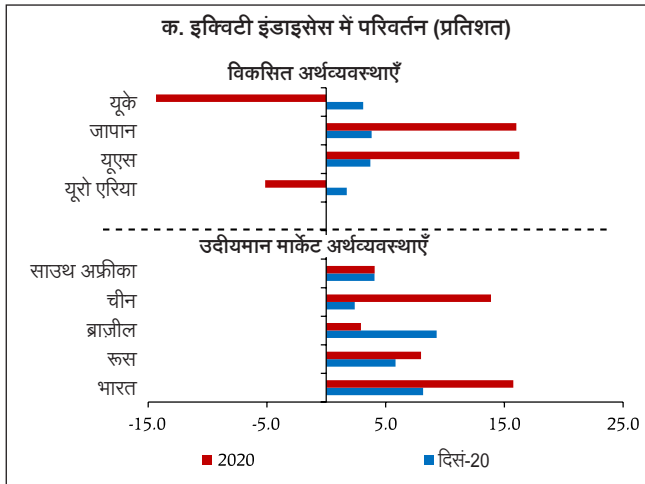
यद्यपि यह अभी भी 2020 में समग्र विश्व व्यापार में विश्व व्यापार संगठन के 9.2 प्रतिशत के संकुचन के अनुमान की तुलना में, अनुकूल है। विश्व बैंक का अनुमान है कि वर्ष 2020 में विश्व व्यापार की मात्रा (माल और गैर-कारक सेवाएँ) में 9.5 प्रतिशत की गिरावट आई है और व्यापार अनिश्चितता का स्तर प्रवृत्ति से अधिक बना हुआ है जो कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जैसी गतिविधियों के बावजूद है।

मैक्रोइकॉनॉमिक दृष्टिकोण में सुधार और तेजी से टीकाकरण के कारण इक्विटी बाजारों में नवंबर 2020 में रिकॉर्ड लाभ हुआ, इस संबंध में ब्रेक्सिट सौदे और दिसंबर के अंत के लिए अमेरिकी प्रोत्साहन का भी लाभ हुआ। मूल्यांकन में वृद्धि के बावजूद, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चिली के शेयर बाजारों ने लाल रंग में साल का अंत किया। दूसरी ओर, ईएमई के शेयर बाजारों में बढ़ते हुए लाभ के कारण मजबूत पोर्टफोलियो प्रवाह हुआ। दिसंबर में ईएमई में कुल पोर्टफोलियो प्रवाह यूएस \$ 45.9 बिलियन था, और पूरे वर्ष के लिए, वे यूएस \$ 313.6 बिलियन (आईआईएफ, 2021) थे। पुनर्मुद्रास्फीति व्यापार और रिस्क ऑन सेंटीमेंट्स ने एई में बांड यील्ड को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर, ईएमई में बांड यील्ड में अनुकूलता बनी रही, जो कि मजबूत

पोर्टफोलियो प्रवाह (चार्ट 13) को परिलक्षित करता है। कोविड-19 वैक्सीन द्वारा प्रदान किए गए अपबीट आउटलुक ने दिसंबर में अमेरिकी डॉलर को नीचे की स्लाइड पर रखा और आई और

ईएमई की मुद्राओं को बहु-वर्षीय ऊँचाइयों तक पहुंचाया। कुल मिलाकर, दिसंबर में डॉलर सूचकांक कमजोर होकर 2.1 प्रतिशत पर आ गया, जो वर्ष 2020 में 6.7 प्रतिशत कम हो गया था। एक

चार्ट 13 : वित्तीय बाजार गतिविधियां

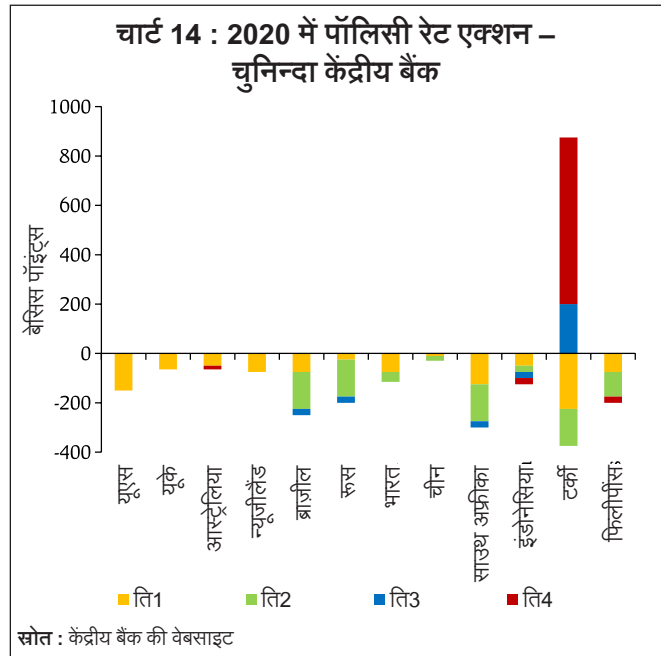


स्रोत : ब्लूमबर्ग और थॉमसन रायटर्स

कोरोलरी के रूप में, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स (MSCI-EM) सूचकांक दिसंबर में 1.6 प्रतिशत और पूरे वर्ष में 3.3 प्रतिशत की बढ़त की। वर्ष 2021 में अब तक, डॉलर मजबूत हुआ है, और यह ज्यादातर यूरो जैसी आई मुद्राओं की तुलना में हुआ है।

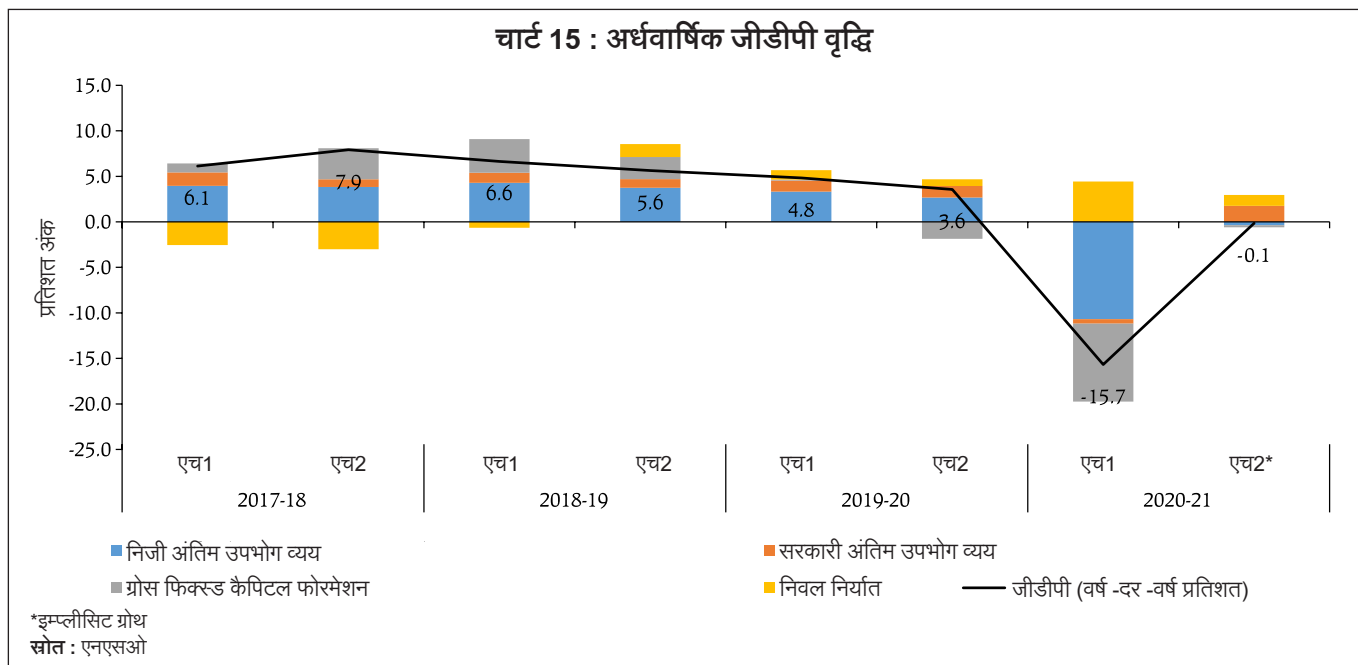
मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, प्रचुर मात्रा में चलनिधि स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों पर रोक की केंद्रीय बैंकों के बीच सामान्य प्रवृत्ति के बीच, दिसंबर में यूरोपीय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान द्वारा मौद्रिक प्रोत्साहन का और विस्तार किया गया था। फेडरल रिजर्व ने निरंतर आस्तियों की खरीद के लिए मार्गदर्शन दिया जब तक कि वह अधिकतम रोजगार और मूल्य स्थिरता लक्ष्यों के संबंध में प्रगति न कर ले। इसके विपरीत, तुर्की के केंद्रीय बैंक ने उच्च और बढ़ती मुद्रास्फीति (चार्ट 14) से जूझते हुए, चार महीनों में तीसरी नीति दर वृद्धि को अंजाम दिया।

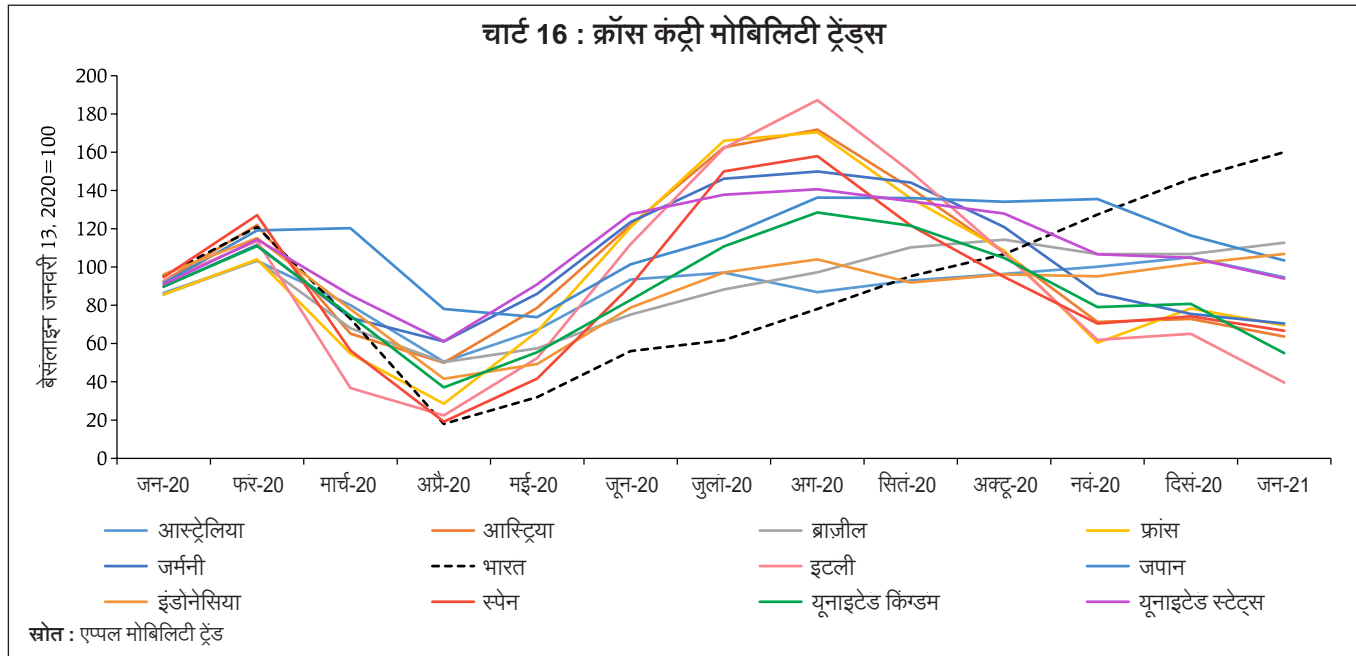
जैसा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था नए साल में कदम रख रही है, निकट भविष्य में काफी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि आई संक्रमण और कड़े लॉकडाउन और वायरल प्रकोप के साथ संघर्ष करेगा और 2017 में देखे गए गरीबी के स्तर पर ईएमई आ सकती है।



III. घरेलू विकास

इस आलेख में जो अनुमान लगाया जा रहा था वह 7 जनवरी की जीडीपी रिलीज में निहित है - एक और लहर के आने की बात को छोड़ते हुए, सबसे खराब समय हमारे पीछे है (चार्ट 15)। हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि बहाली



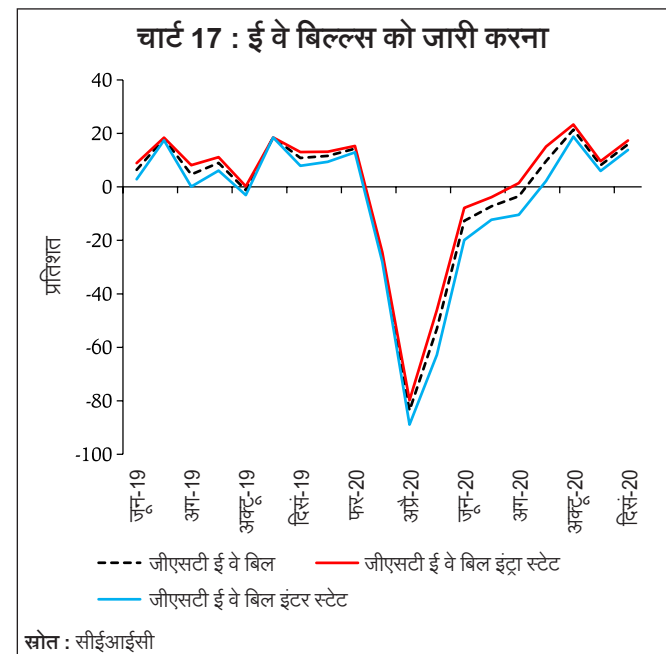


अपने कर्षण में मजबूत हो रही है और जल्द ही हमारे असंतोष की सर्दी को शानदार गर्मी³ बना दिया जाएगा। क्रॉस-कंट्री तुलना इंगित करती है कि भारत अन्य अर्थव्यवस्थाओं (चार्ट 16) से आगे बढ़ रहा है। छह सबसे बड़े राज्य - महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल - ने सार्वजनिक स्थानों पर सामान्य प्रतिशत में 87 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो महामारी (मिंट ट्रैकर) में अब तक का सबसे अच्छा स्तर है। ई-वे बिल जारी करने में परिलक्षित होने वाली घरेलू ट्रेडिंग गतिविधि तेज गति से बढ़ी, यहां तक कि उच्च आधार पर, 15.9 प्रतिशत की वृद्धि वर्षानुवर्ष - आंतर-राज्य में 17.3 प्रतिशत और अंतर-राज्य में 13.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वास्तव में, दिसंबर 2020 के दौरान जारी किए गए ई-वे बिलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, यह सुझाव देते हुए कि अब त्योहार के खर्चों के सामयिक टेलविन्ड्स पर रिकवरी नहीं होती है, बल्कि यह फीनिक्स की तरह एक आंतरिक गति से बढ़ रहा है (चार्ट 17)।

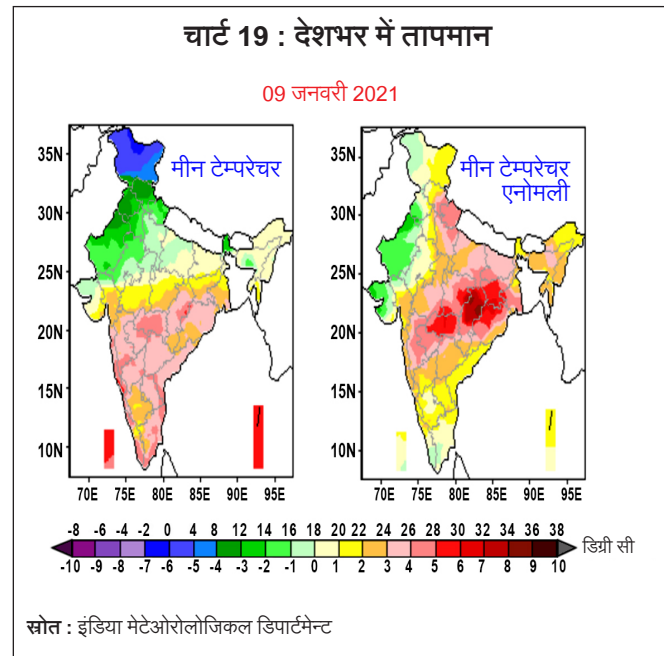
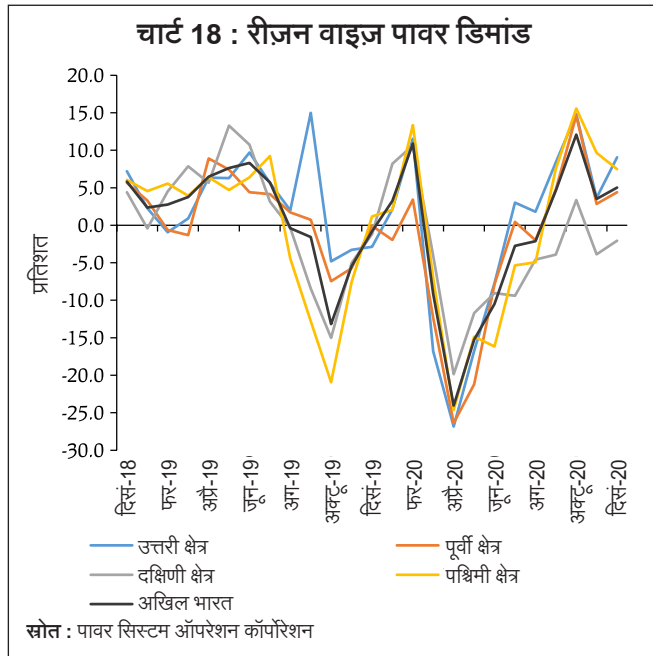
सकल मांग

सकल मांग की स्थितियों ने हाल के लाभ को समेकित किया है या दिसंबर 2020 में गति को मजबूत किया है। बिजली की खपत में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि वर्षानुवर्ष हुई है, जिसने चौथे

क्रमिक महीने (चार्ट 18) में अपनी वृद्धि को बनाए रखा है। दिसंबर में उत्तरी और मध्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश (15 प्रतिशत), राजस्थान (12 प्रतिशत), बिहार (14 प्रतिशत), पंजाब (12 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (10 प्रतिशत) ने हीटिंग लोड बढ़ने के कारण बिजली की मांग में वृद्धि का अनुभव किया। एक असामान्य रूप से तीव्र सर्दियों के रूप में बहु-वर्षीय चढ़ावों के साथ पारा का स्तर गिर गया, जिसमें प्रशांत के पानी को ला नीना ने ठंडा किया



³ रिचर्ड तृतीय में विलियम शेक्सपियर से लिया गया है

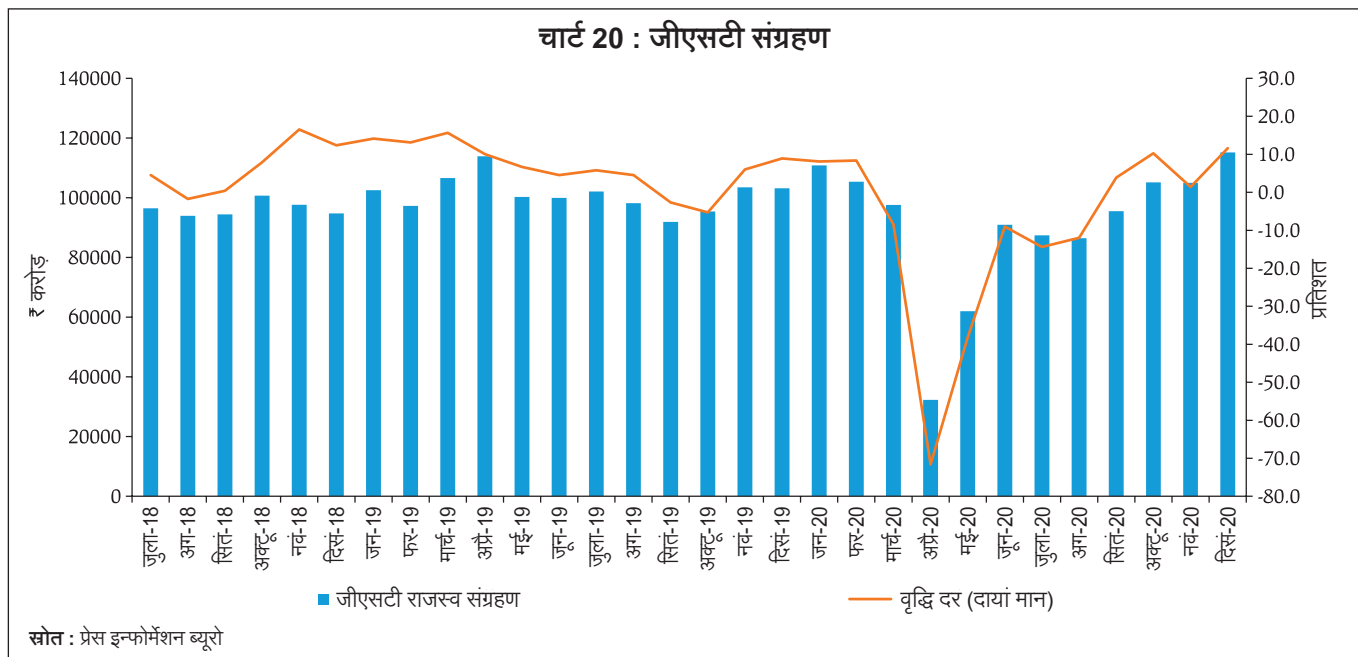


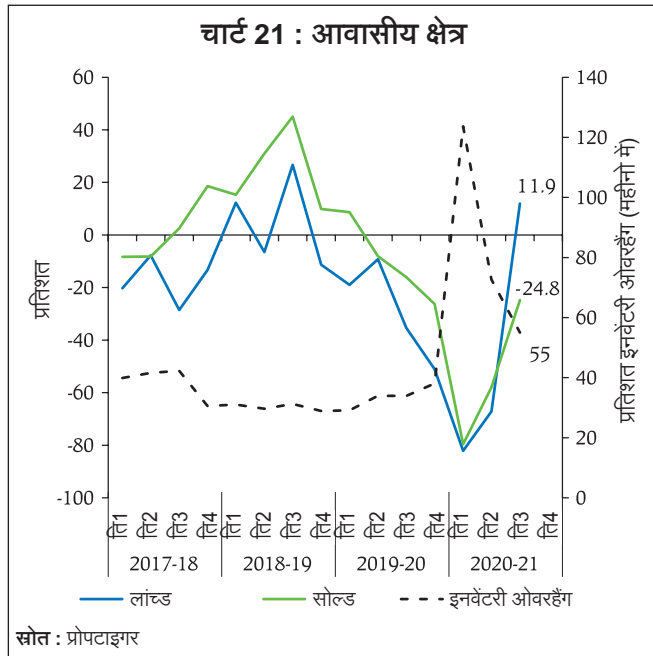
और ऊपरी भारत के अधिकांश हिस्सों में एक शीत लहर ने जोर पकड़ लिया, और इन राज्यों में छिटपुट बेमौसम बारिश भी हुई (चार्ट 19)।

घरेलू खर्च तेजी से सामान्य हो रहा है, और इसी के अनुरूप, माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रह दिसंबर में रुपये 1.15 लाख करोड़ के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसने तीसरे महीने के लिए रुपये 1 लाख करोड़ की

‘बाधा’ को भी लगातार तोड़ दिया, और एक साल पहले (चार्ट 20) से 11.6 प्रतिशत अधिक। व्यावसायिक गतिविधि एक ‘अनलॉक’ मोड में पुनर्जीवित हो रही है, जिसे एक सरलीकृत रिटर्न फाइलिंग सिस्टम द्वारा पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है।

उपभोक्ताओं का विश्वास पुनःस्थापित हो रहा है। रीफिनिटिव -इप्सोस उपभोक्ता कंज्यूमर सेंटीमेंट सूचकांक दिसंबर में 2.1 प्रतिशत अंक ऊपर आया। रोजगार की स्थिति, व्यक्तिगत

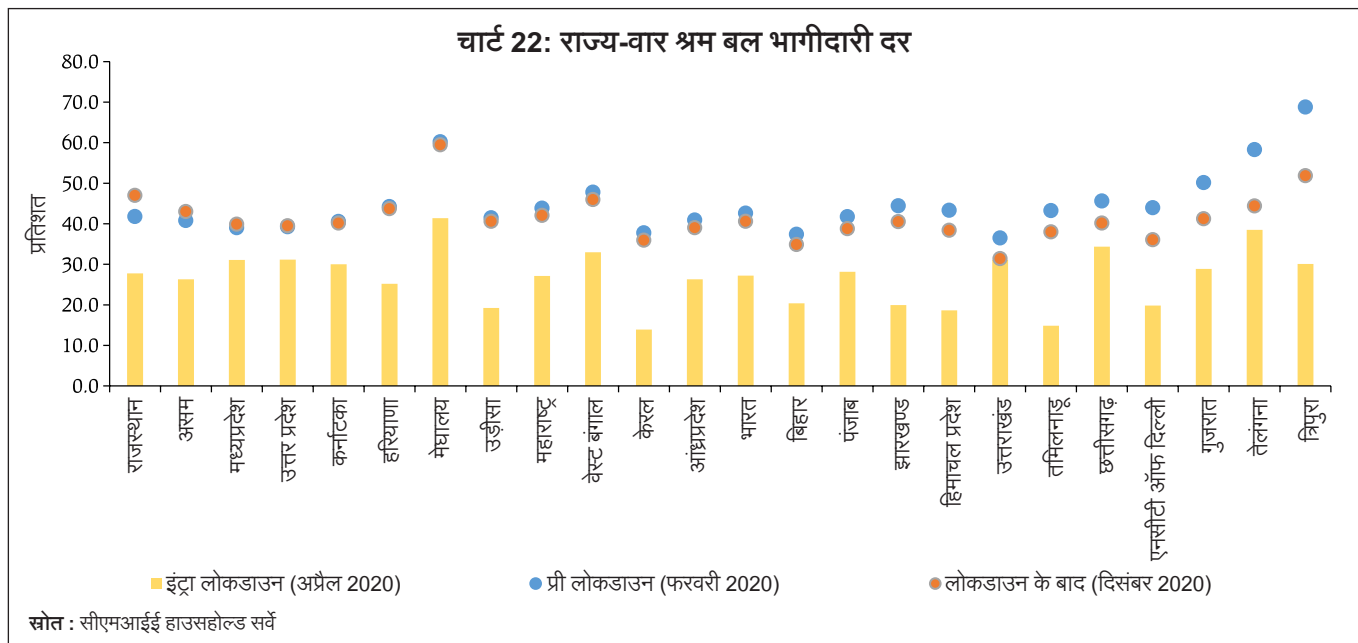




मूल्यवर्धित वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए एक बड़े रुझान के पहले, स्वास्थ्य और कल्याण उत्पादों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रय को वरीयता मिलने की उम्मीद है। बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स से संबन्धित लोगों और किराने की दुकानों के बीच गठजोड़ के विस्तार की उम्मीद है। उपभोक्ताओं का रुझान आवास की ओर भी हुआ है। आवासीय क्षेत्र की बिक्री में ति. 3: 2020-21 में तेज वृद्धि के साथ आवास क्षेत्र के मुड़ने के संकेत हैं - पूर्ववर्ती तिमाही का स्तर लगभग दोगुना - अनुकूल ब्याज दरों से समर्थित, अभी भी आवास की कीमतें अवरूद्ध हैं, डेवलपर्स द्वारा सूची को निपटाने के लिए अधिक छूट और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी (चार्ट 21)। उपभोक्ता खर्च का फिर से आरंभ होना, भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) बाजार में से भी स्पष्ट है, जिसका विस्तार 17.0 प्रतिशत⁴ है।

वित्त, निवेश के माहौल और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में विश्वास के संबंध में सुधार दर्ज किया गया। इस बात की पुष्टि उन और ब्रैडस्ट्रीट की रिपोर्ट द्वारा की गई है कि उपभोक्ता विश्वास जनवरी 2021 से सुधरेगा, जुलाई में चरम पर रहेगा और अगले त्योहारों के समय से पहले सितंबर तक जारी रहेगा। क्रय व्यवहार से डिजिटल और ओमनी- चैनल की बिक्री के माध्यम से

श्रम बाजार की स्थिति भी पैरी पासू सुधार कर रही है, जिसमें स्थान और समय के साथ रोजगार में क्रमिक सुधार हुआ है, जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण द्वारा इंगित किया गया है। अप्रैल 2020 (चार्ट 22) में 35.57 के निम्न स्तर से दिसंबर में श्रम बल की भागीदारी दर बढ़कर 40.06 हो गई। अंतर-राज्य प्रवास

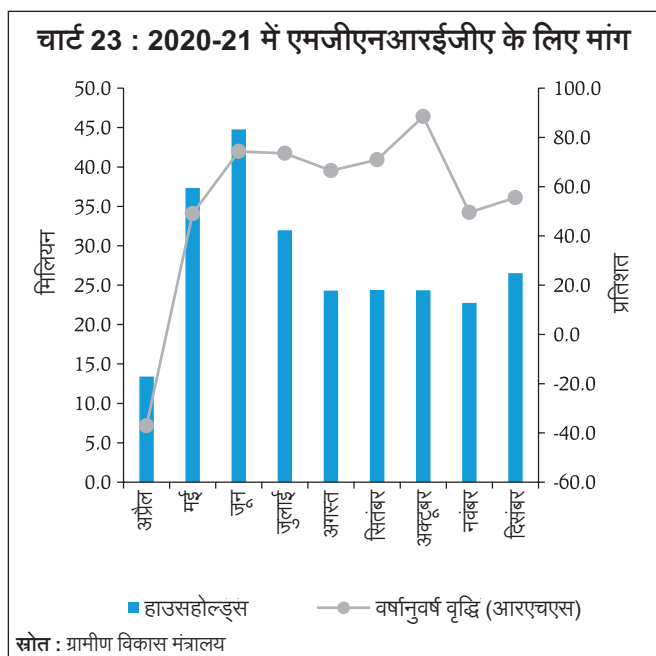


⁴ <https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/fmcg/faster-moving-consumer-goods-sales-up-17-in-q3/articleshow/80124785.cms>

प्रतिबंधों के क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने के साथ, राज्यों में श्रम बल भागीदारी दर दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और त्रिपुरा के को छोड़कर पूर्व-महामारी स्तर तक बढ़ गई है। राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने तेजी से सुधार दर्शाया है जिसमें दिसंबर में दर्ज की गई श्रम बल की भागीदारी पूर्व-लॉकडाउन अवधि (चार्ट 23) में देखी गई भागीदारी की तुलना में अधिक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) के तहत, लगभग 26.5 मिलियन परिवारों ने दिसंबर में रोजगार की मांग की जो पूर्ववर्ती महीने की तुलना में 16.5 प्रतिशत अधिक था और एक साल पहले की तुलना में 55.5 प्रतिशत से अधिक था। दिसंबर के अंत तक, बजट की राशि का 130 प्रतिशत खर्च कर दिया गया था।

यह संभावना है कि आने वाले महीनों में रोजगार की स्थिति और भी अधिक उज्ज्वल होगी। स्टाफिंग समाधान प्रदाता टीमलीज के अनुसार, 2021 में विभिन्न कौशल सेट के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) फर्मों द्वारा लोगों को काम पर रखने के संबंध में 10-12 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक बेहतर विकास जो बहाली की संभावनाओं में सुधार करता है, वह सरकारी खर्चों की अच्छी बहाली है। सरकार के अंतिम उपभोग व्यय की



वृद्धि देने वाली भूमिका ऐसे समय में अमूल्य है जब महामारी के कारण उत्पन्न मेटास्टेसिस के अंतर्गत जीडीपी के अन्य सभी घटकों में अत्यधिक कमी आई हो। निकट-अवधि के दृष्टिकोण के लिए इस गतिविधि की महत्ता को पूरी तरह से समझना कठिन है इस वर्ष दिसंबर 2020 के बुलेटिन में छापे एक आर्टिकल जिसका शीर्षक था 'गवर्नमेंट फाइनेंस 2020-21: एक अर्धवार्षिक समीक्षा '(आरबीआई 2020) जिसमें अंतर्निहित डायनामिक्स पहली बार उजागर हुईं जो संयोगवश, आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) के साथ भारत के अनुपालन को पूरा करती है।

इस लेख के नवंबर 2020 के संस्करण ने विवरण प्रदान किया और केंद्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन में 'प्रणाली' को निर्धारित किया। इससे पहले, स्टेट फ़ाइनेंस (आरबीआई, 2020) पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कैसे राज्यों ने कई असफलताओं के साथ महामारी के खिलाफ रक्षा में मोर्चेबंदी करने वालेयोद्धाओं के रूप में कमान संभाली, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी सफलताएँ भी हासिल कीं जिन्होंने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस लॉग क्रोनिकल के नीचे, वास्तविकता यह है कि महामारी ने सरकारी वित्त पर एक 'कैची का प्रभाव' डाला है। एक ओर, इसने अर्थव्यवस्था को राजकोषीय समर्थन के लिए खर्च को बढ़ाया, जो 2020-21 के लिए बजट तैयार करने के समय पूरी तरह से अप्रत्याशित था। दूसरी ओर, राजस्व में संकुचन था क्योंकि अर्थव्यवस्था में गतिविधि लॉकडाउन और अन्य नियंत्रण उपायों के कारण कैटेटोनिक निकासी में चली गई थी। परिणामस्वरूप, सामान्य सरकारी सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) एच1: 2020-21 में 14.5 प्रतिशत तक बढ़ गया, ति. 1 में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड की गई जिसके परिणामस्वरूप व्यय के युक्तिकरण और प्रत्यावर्तन के रूप में ति.2 इसके में समेकन की आवश्यकता पड़ी (चार्ट 24)। आगे बढ़ते हुए, ये दो सकारात्मक विशेषताएं एच 2 में वित्तीय परिदृश्य को आकार देने जा रही हैं। सबसे पहले, सामान्य सरकारी जीएफडी-जीडीपी अनुपात 10.4 प्रतिशत से कम होने की संभावना है (50 प्रतिशत कोन्फ़ीडेंस बैंड के भीतर 9.7-10.9 प्रतिशत)। यह विकास राजस्व द्वारा संचालित होगी क्योंकि एच 2 द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम आ गए होंगे और प्राप्ति सकारात्मक हो चुकी होगी। दूसरा, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता भी एच 2 में बेहतर होने की संभावना है क्योंकि, आत्मा निर्भर के अंतर्गत दिए जाने वाले

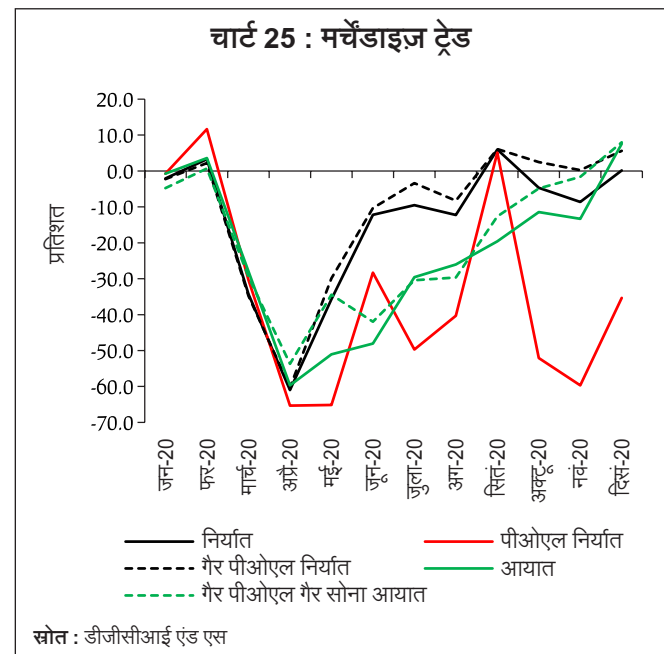
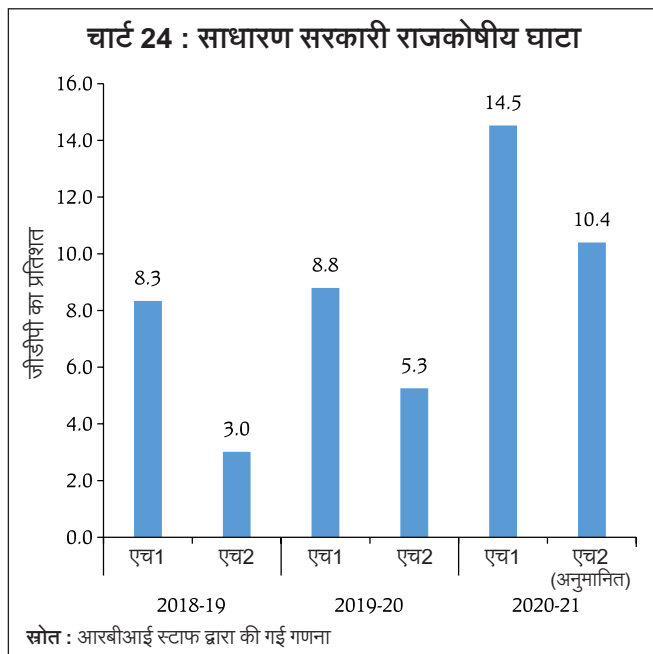
निवेश उन्मुख प्रोत्साहन के एक बड़े हिस्से 2.0 और 3.0 (क्रमशः अक्टूबर और नवंबर 2020 में घोषणा की गई) का इसी अवधि में फलीभूत होने की उम्मीद है। यह नवंबर 2020 में कैपेक्स के मासिक डेटा में पहले से ही स्पष्ट है ; हालाँकि, केंद्र और राज्यों दोनों को राजकोषीय चिंताओं के लिए बड़े पैमाने पर खर्च में कटौती का विरोध करना चाहिए।

बाहरी मांग की ओर रुख करें तो भारत का माल निर्यात कोविड -19 के पूर्व के स्तर तक पहुँच गया है और दिसंबर 2020 में इसमें 0.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। गैर-तेल निर्यात वास्तव में 5.6 प्रतिशत तक बढ़ा है, जो लगातार चौथे महीने में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अधिक उल्लेखनीय माल के आयात में हुआ सुधार था, जो नौ महीने के संकुचन के बाद दिसंबर 2020 में 7.6 प्रतिशत तक पलट गया है। यह सुधार सोने, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वनस्पति तेलों द्वारा किया गया था। मोती और कीमती पत्थरों, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वस्त्रों के बढ़ते आयात घरेलू गतिविधि के सुधार को दर्शाते हैं क्योंकि वे आपूर्ति श्रृंखलाओं में मध्यवर्ती माल की प्रकृति के हैं। यह निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से विकसित करता है। तेल आयात के मामले में भी, संकुचन की दर में गिरावट देखी गई,

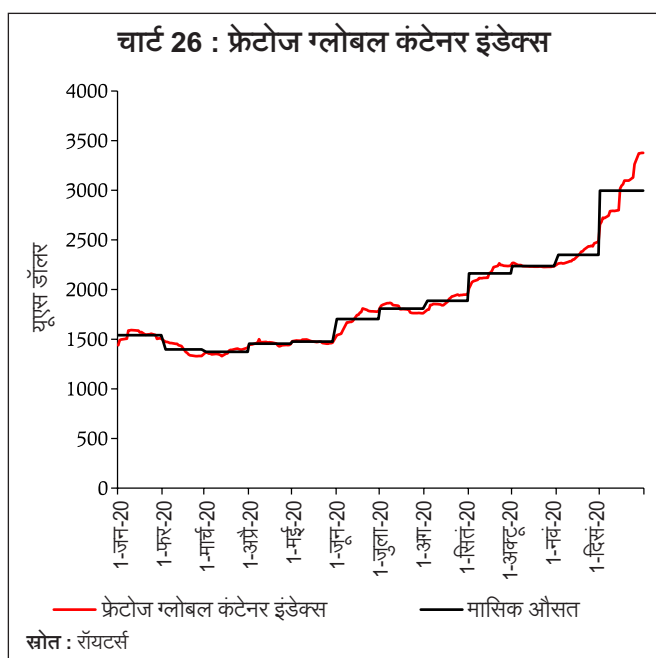
तेल के आयात में दिसंबर में केवल 10.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि यह नवंबर में 43.4 प्रतिशत की तेज गिरावट थी। आयात में बेहतर वृद्धि के साथ, व्यापार घाटा सत्रह महीनों में सबसे अधिक, दिसंबर (चार्ट 25) में यूएस \$ 15.4 बिलियन से अधिक का हो गया।

गैर-तेल निर्यात में तेजी से सुधार के लिए ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि वस्तुओं और लौह अयस्क के शिपमेंट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें से सभी ने महामारी के समय में लचीलापन और विश्व व्यापार में बड़े पैमाने पर संकुचन को प्रदर्शित किया है। जैसे ही दुनिया भर में टीकाकरण की गति बढ़ती है, वैसे ही दुनिया में वैक्सीन निर्माण में सबसे बड़ी क्षमता के मामले में भारतीय फार्मा फर्मों का फायदा होगा - भारत पहले से ही वैश्विक स्तर पर बेचे जाने वाले टीकों का 60 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा, बल्क ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों के लिए शुरू की गई प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और उम्मीद की जा रही है कि इससे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, जबकि कच्चे माल और इंटरमीडिएट के मामले में भारत को कमजोर पड़ने की आशंका कम होगी।



निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्क और कर पर छूट की योजना के तहत लाभ के विस्तार RoDTEP को 1 जनवरी, 2021 से सभी निर्यात माल के लिए प्रभावी करने के चलते भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धा के बढ़ने की उम्मीद है⁵। दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान के कारण कंटेनर आपूर्ति की कमी, शिपिंग लाइनों की घटी हुई क्षमता, लॉकडाउन के दौरान बंदरगाहों पर फंसे खाली कंटेनर, बंदरगाह जनशक्ति में कमी के कारण कार्गो हैंडलिंग की गति में कमी और परिणामस्वरूप बंदरगाहों में अत्यधिक सामान का होना भारत के निर्यात की संभावनाओं के लिए जोखिम का कारण है। विशेष रूप से भारतीय निर्यात के लिए, कोलंबो बंदरगाह पर भारी भीड़ द्वारा स्थिति बिगड़ गई थी, जो भारतीय कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में कार्य करता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कोलंबो से कार्गो यातायात का एक बड़ा हिस्सा कोच्चि बंदरगाह की ओर मोड़ दिया गया है। इसने नवंबर-दिसंबर 2020 (चार्ट 26) के दौरान बढ़ते ग्लोबल कंटेनर फ्रेट इंडेक्स में दर्शाए गए अनुसार माल भाड़े में भी बढ़ोतरी की है।

भारत का चालू खाता जुलाई-सितंबर 2020 (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) में लगातार तीसरी तिमाही के लिए अधिशेष में रहा,



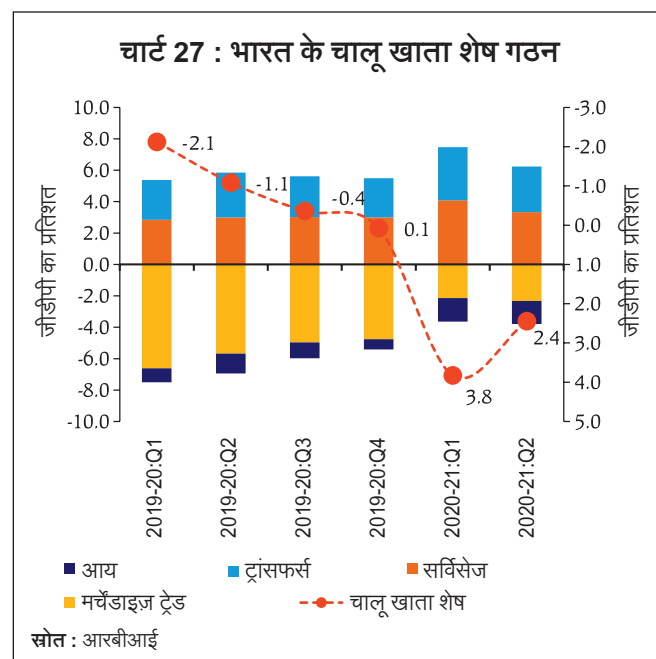
⁵ आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को उनके द्वारा केंद्रीय, राज्य और स्थानीय संदत शुल्कों / करों जिन्हें अब तक रीबेट नहीं दिया गया था /रीफंड नहीं किया गया था।

हालांकि यह घरेलू मांग (चार्ट 27) के फिर से शुरू होने के साथ कम हो गया। जबकि भुगतान संतुलन के चालू और पूंजी खातों में अधिशेषों का सह-अस्तित्व विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रदान किए गए बफर को मजबूत करता है, भारत सुस्त प्रतिरोधक क्षमता के साथ संतुष्ट है। सिल्वर लाइनिंग यह है कि चालू खाते का अधिशेष ति.2 में हटना शुरू हो गया है और एच 2: 2020-21 में इसके और कम होने की संभावना है।

सकल आपूर्ति

कृषि में लचीलापन और विनिर्माण गतिविधि में पुनरुत्थान के आधार पर दिसंबर 2020 तक सकल आपूर्ति की स्थिति मजबूत हुई। सेवा क्षेत्र की गतिविधि भी सुधरती हुई प्रतीत होती है, हालांकि संपर्क-गहन सेवाएं पूर्व-कोविड स्तरों के नीचे बनी हुई हैं।

महामारी से कृषि सुरक्षित है। प्रमुख फसलों की बुवाई सामान्य स्तर से अधिक हो गई है। 15 जनवरी, 2021 तक रबी की बुआई का रकबा 651.9 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक था, और पूरे सीजन के सामान्य रकबे (तालिका 3) को पार कर गया। जलाशय का स्तर 14 जनवरी को पूर्ण क्षमता के 68 प्रतिशत के बराबर था, जो कि औसतन 56 प्रतिशत रहता है; यह रबी



तालिका 3: अखिल भारतीय फसल स्थिति - रबी (2020-21)
15 जनवरी, 2021 को

(लाख हेक्टेयर में क्षेत्रफल)

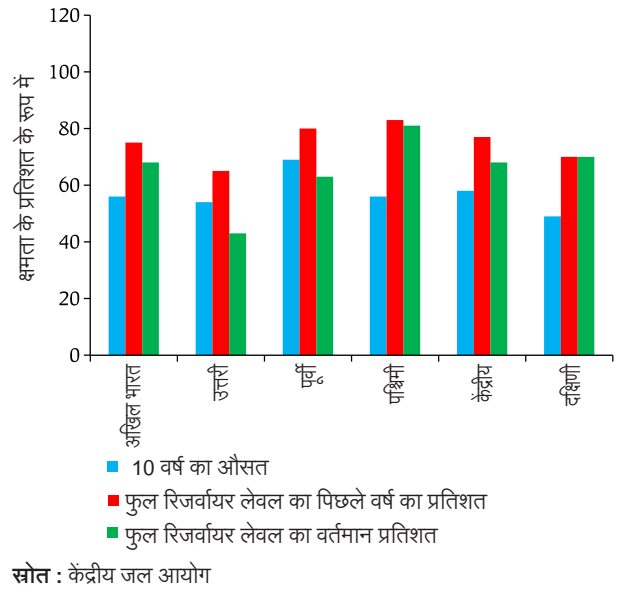
फसल का नाम	प्रतिशत भिन्नता		तिथि के अनुसार बुवाई करें		प्रतिशत भिन्नता	
	पूरा सीजन	आज की तारीख में	इस वर्ष (2021)	पिछले साल (2020)	आज की तारीख में सामान्य से अधिक	पिछले साल से अधिक
1. गेहूँ	303.3	306.8	337.1	330.6	9.9	2.0
2. चावल	41.8	19.7	21.0	20.0	6.8	5.0
3. मोटे अनाज	57.1	52.9	49.1	53.5	-7.2	-8.2
क. ज्वार	33.4	30.3	26.5	29.4	-12.7	-10.0
ख. जौ	6.4	7.4	6.8	7.6	-7.5	-10.5
ग. मक्का	17.4	14.5	14.8	15.1	4.1	-4.9
4. कुल दालें	144.9	152.4	162.1	158.8	6.4	2.1
क. ग्राम	92.8	98.9	109.1	105.5	10.4	3.5
ख. मसूर	14.2	16.3	16.4	16.0	1.1	2.5
ग. मटर	8.8	10.4	10.6	10.9	1.9	-2.3
घ. कुल्थी (हॉर्स ग्राम)	2.2	4.5	3.8	5.1	-15.8	-26.0
ङ. उड़द	8.9	7.6	7.6	7.1	-0.2	6.5
च. मूंग	9.9	5.4	5.2	5.5	-3.5	-4.2
छ. लेंथिरस	4.0	3.5	3.1	3.1	-11.7	0.0
I. कुल खाद्यान्न (1+2+3+4)	547.1	531.8	569.4	562.9	7.1	1.1
5. तिलहन	73.2	79.2	82.6	79.0	4.3	4.6
क. रेपसीड एंड मस्टर्ड	59.4	79.2	73.2	68.6	-7.5	6.7
ख. मूंगफली	7.3	4.6	4.3	4.5	-6.3	-5.1
ग. सूरजमुखी	2.4	1.6	1.0	1.0	-41.4	-1.9
घ. तिल	0.0	0.5	0.4	0.5	-20.2	-22.3
ङ. कुसुम	1.2	0.8	0.6	0.6	-25.5	-6.4
च. अलसी का बीज	2.7	3.5	2.8	3.3	-18.4	-14.3
सभी फसलें (1+2+3+4+5)	620.3	610.9	651.9	641.9	6.7	1.6

नोट: क्षेत्र के आंकड़े राज्य कृषि विभागों के आंखों देखे आकलन के अनुसार हैं। सामान्य क्षेत्र: 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान औसत क्षेत्र दिनांक के अनुसार सामान्य क्षेत्र: 2015-16 से 2019-20 की इसी अवधि के दौरान औसत क्षेत्र।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

मौसम (चार्ट 28) के लिए एक बल को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। गेहूँ - प्राथमिक रबी स्टेपल - ने बुवाई में वृद्धि दर्ज की है (2.0 प्रतिशत), मुख्य रूप से प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक बुवाई के कारण, विशेष रूप से हरियाणा (1.2 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (12.7 प्रतिशत)। दलहन और तिलहन ने भी रकबे में शानदार बदलाव दर्ज किया है। रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन के साथ, 51.3 मिलियन टन खरीफ चावल की खरीद एक साल

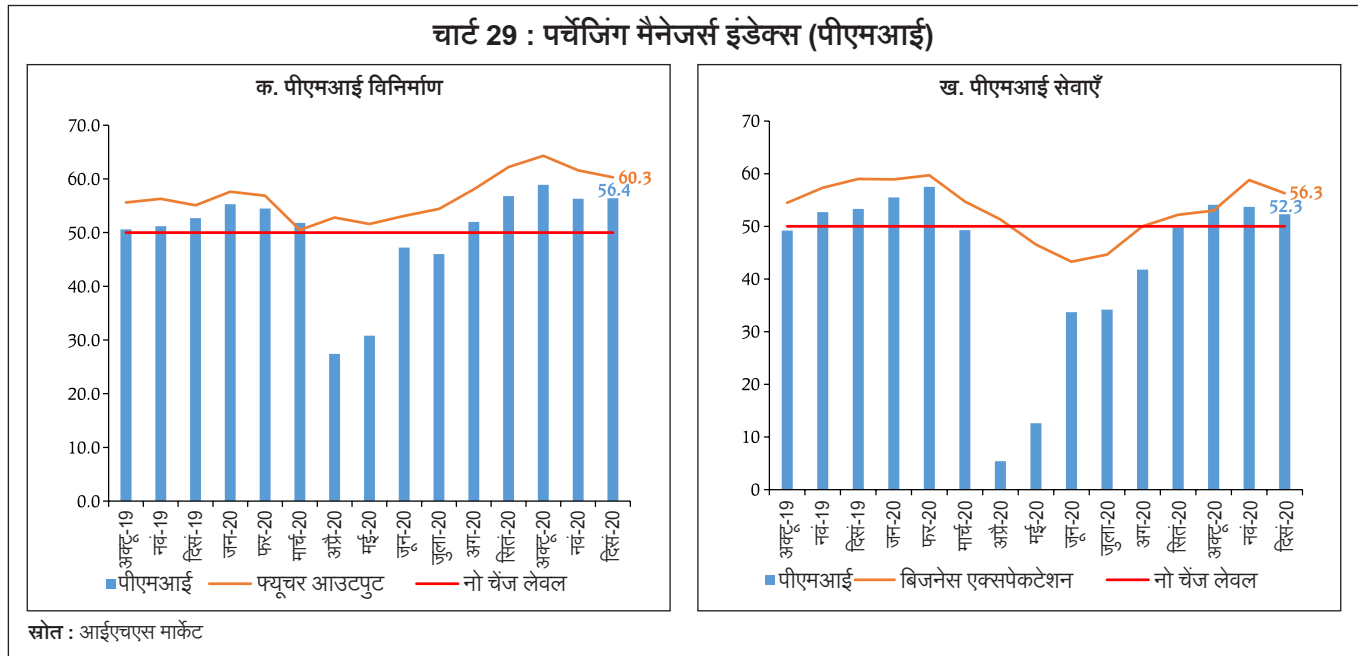
चार्ट 28 : रिजर्वार लेवल



स्रोत: केंद्रीय जल आयोग

पहले की तुलना में 26.2 प्रतिशत अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप 1 जनवरी 2021 तक अनाज (चावल और गेहूँ) बफर स्टॉक 3.7 बढ़ गया।

हालांकि औद्योगिक उत्पादन अस्थिर बना हुआ है, अक्टूबर 2020 में 4.2 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि के बाद नवंबर 2020 में 1.9 प्रतिशत के बाद औद्योगिक गतिविधि आखिरकार बदल रही है। हेडलाइन क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) विनिर्माण दिसंबर 2020 में बढ़कर 56.4 हो गया, जो नवंबर के 56.3 (चार्ट 29) से थोड़ा सा ही अधिक है। नए ऑर्डर आदेश और आउटपुट दोनों दृढ़ता से बढ़ते रहे। भविष्य के उत्पादन सूचकांक में बाजार की स्थितियों में सुधार की उम्मीद पर 60.3 तक विस्तार किया गया, हालांकि मुद्रास्फीति के दबावों पर चिंताओं के कारण आत्मविश्वास में कमी आई। औद्योगिक गतिविधि में क्रमिक सुधार के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड ने ति.3 में कोयला उत्पादन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। यात्री कार वाहनों की बिक्री के संबंध में, मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) में से अधिकांश ने दिसंबर में दोहरे अंक की वृद्धि देखी, जिससे वर्ष की समाप्ति सकारात्मक रही, क्योंकि उन्होंने अपनी इनवेंटरीज को फिर से भर लिया। सड़क और परिवहन मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2020 में पूरे भारत में 1.8 मिलियन से



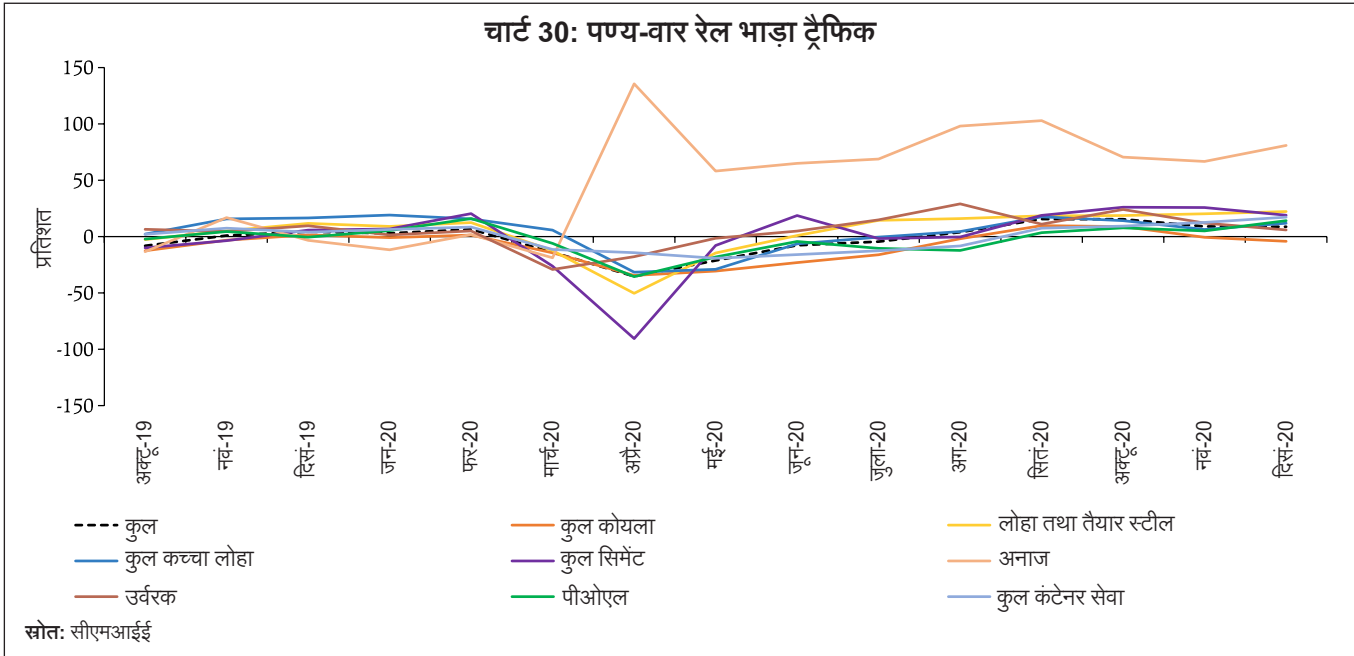
अधिक वाहनों का पंजीकरण किया गया था, जो अप्रैल के बाद से अब तक का सबसे अधिक है – महामारी की अवधि में पहली बार 10.3 प्रतिशत की वृद्धि। इस गतिविधि में तेजी मुख्य रूप से गैर-परिवहन वाहनों के क्षेत्र में थी। मिनी-ट्रकों, पिक-अप वैन और अन्य हल्के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखी जा रही है क्योंकि अधिक भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ग्राहक तक वितरण करने संबंधी लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता बढ़ गई है।

सेवा क्षेत्र में, एक स्थिर सुधार हो रहा है। सेवाओं की पीएमआई लगातार तीसरे महीने में बढ़कर दिसंबर में 52.3 हुई, जो नए घरेलू कार्य बढ़ने के कारण है। इस्पात की खपत - निर्माण गतिविधि के लिए एक अनुमानित संकेतक है - यह भी लगातार तीसरे महीने में बढ़ी और 5.7 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। लोडिंग और आय दोनों के मामले में रेलवे के माध्यम से परिवहन सेवाओं ने प्रभावी गति का प्रदर्शन जारी रखा। दिसंबर में 8.7 प्रतिशत की रफ्तार से माल यातायात बढ़ी, जिसकी शुरुवात अगस्त में हुई थी तथा लगातार पाँच महीने तक इसकी वृद्धि की गति का विस्तार हुआ (चार्ट 30)। कोयले के अपवाद को छोड़कर, सभी पण्य वस्तुओं की श्रेणियों में व्यापक बढ़ोतरी हुई। बंदरगाह

का भी निरंतर विस्तार जारी रहा, जिसने आठ महीने के संकुचन के बाद दिसंबर में लगातार दूसरे महीने में वृद्धि दर्ज की। संपर्क से बचने के लिए व्यक्तिगत यात्रा को प्राथमिकता मिलने के कारण, दिसंबर में लगातार पांचवें महीने के लिए यात्री वाहन बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज हुई।

मुद्रास्फीति

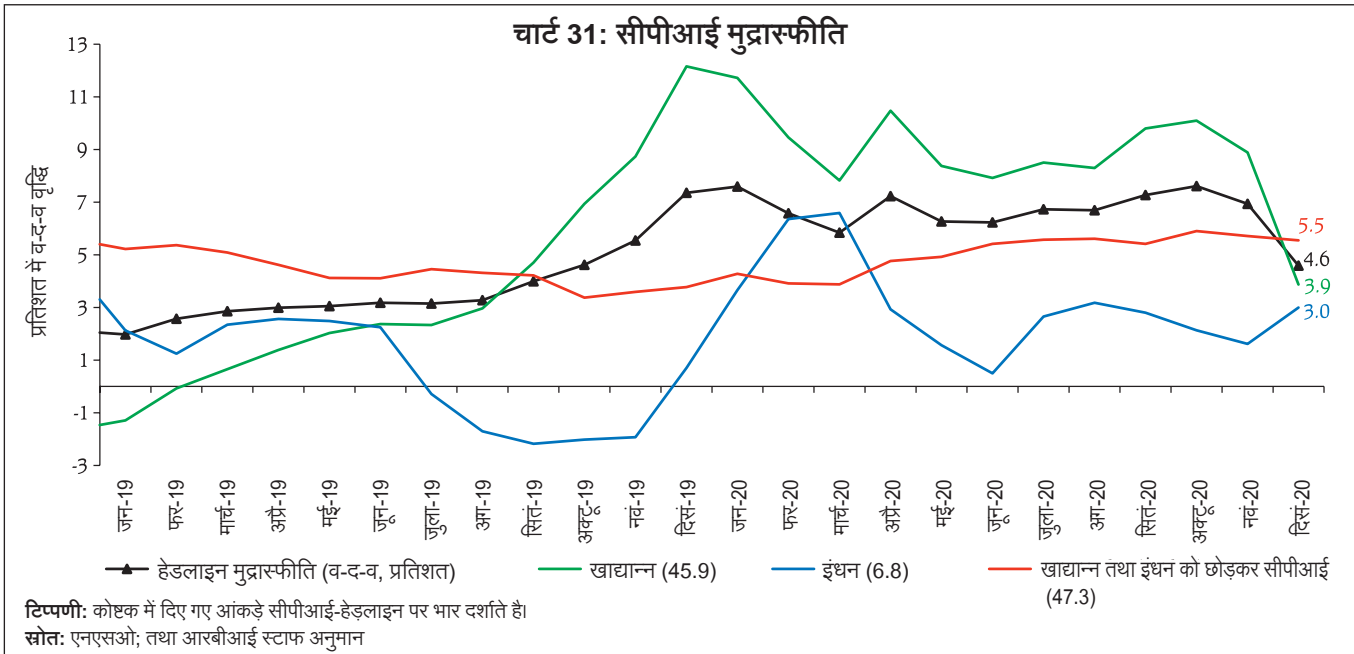
दिसंबर 2020 में सीपीआई मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.9 प्रतिशत से तेजी से कम होकर 4.6 प्रतिशत हो गई। यह मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति नवंबर के 8.9 प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम होकर - दिसंबर में 3.9 प्रतिशत होने के कारण था (चार्ट 31)। सब्जियों और अनाज के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट आयी। प्याज और आलू की कीमतों में हाल के महीनों में काफी वृद्धि हुई थी, जिसमें दिसंबर में तेजी से गिरावट आई। अन्य सब्जियों की कीमतों में भी मौसमी गिरावट देखी गई। एक अनुकूल प्रभाव के कारण, दिसंबर में सब्जी की कीमतों में दोहरे अंक की कमी आई। उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलें विभाग) से उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा के आधार पर, जनवरी (1-13 जनवरी, 2021) के लिए प्रमुख खाद्य कीमतों के पूर्व संकेतक सब्जियों की कीमतों में और



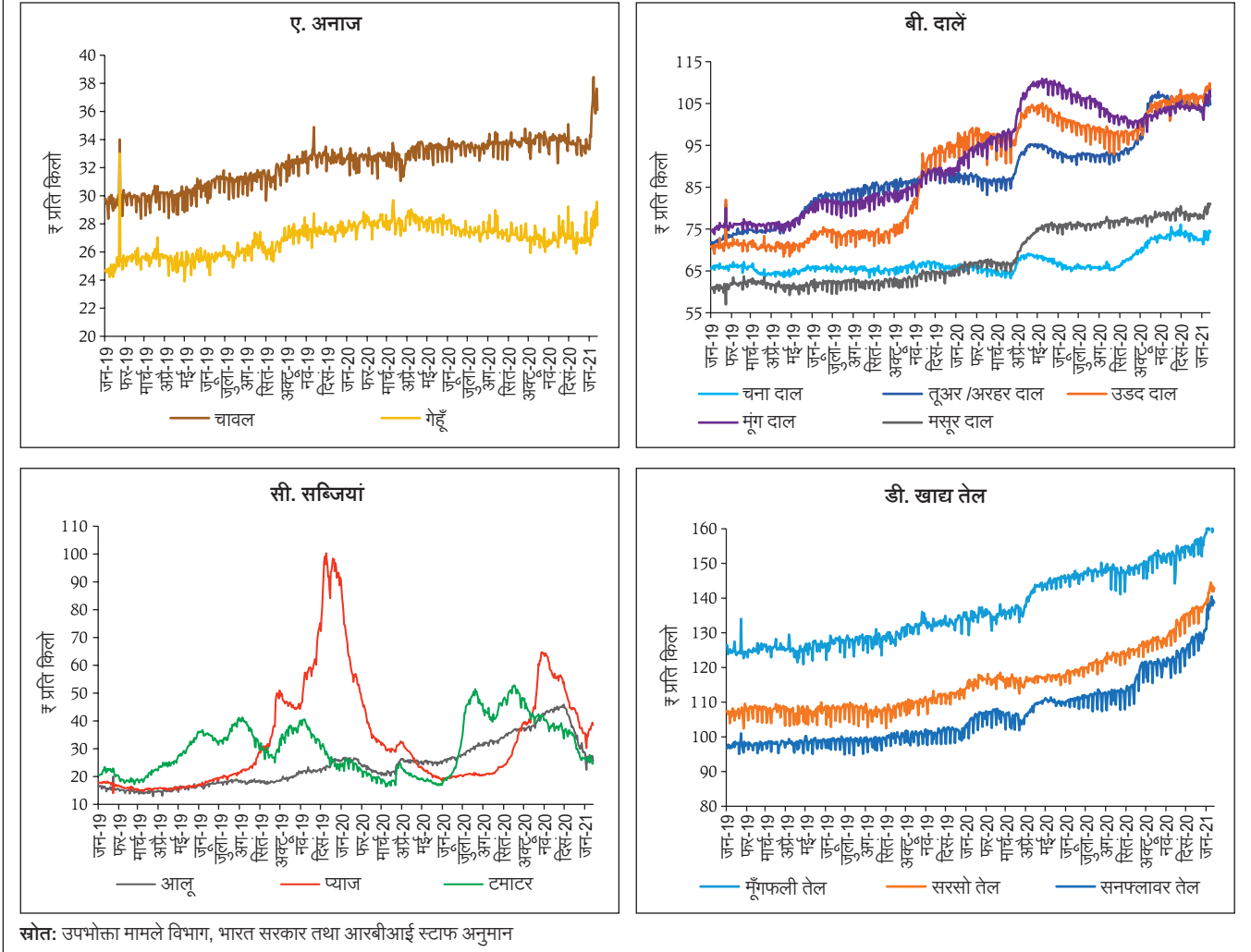
अधिक कमी दर्शाते हैं। हालांकि, खाद्य तेलों में कीमतों का दबाव जनवरी में अब तक जारी रहा है (चार्ट 32)।

भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमतें जनवरी में अब तक 53 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल (1-13 जनवरी 2021) हो गयी हैं

जो दिसंबर में 50 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी। इसके परिणामस्वरूप जनवरी में अब तक घरेलू पंप कीमतों में और वृद्धि हुई है। इसके साथ, घरेलू उत्पाद शुल्क और राज्य करों में हुई अत्यधिक वृद्धि अप्रत्यावर्तित होने के कारण पंप



चार्ट 32: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर तक बढ़ रही हैं। जनवरी में घरेलू केरोसीन की कीमतें भी और बढ़ीं। एलपीजी की

कीमतों में दिसंबर में लगभग ₹100 प्रति सिलेंडर की तेज वृद्धि के बाद, जनवरी 2021 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ (सारणी4)।

सारणी 4: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों का औसत)

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीने-दर-महीने	
		जन 20	दिसं 20	जन 21	दिसं 20	जन 21
पेट्रोल	₹/लीटर	77.79	86.27	86.73 ^	2.5	0.5
डीजल	₹/लीटर	70.52	77.59	78.08 ^	3.8	0.6
केरोसीन	₹/लीटर	28.80	23.21	25.83	4.7	11.3
एलपीजी	₹/सिलेंडर	699.88	704.63*	704.63	16.5	0.0

*: 15 दिसंबर 2020 से लागू

^: 1-13 जनवरी 2021 की अवधि के लिए

टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लिए जाने वाले कीमतों का औसत।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

मुख्य रूप से टेलीफोन शुल्क, शिक्षा खर्च और सोने की कीमतों में कुछ नरमी के कारण खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई नवंबर के 5.7 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर में 5.5 प्रतिशत पर रहा। दिसंबर में व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु और पान, तंबाकू तथा नशीले पदार्थों में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति जारी रही। कुछ नरमी के बावजूद, मोटर वाहनों की कीमतों, पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और परिवहन किराए के कारण दिसंबर में परिवहन और संचार मुद्रास्फीति बढ़ गई।

सब्जियों की कीमते कम होने के कारण मुख्य रूप से सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में काफी नरमी देखी जा रही है। निकट महीनों में, जनवरी में बर्ड फ्लू के संक्रमण की घटनाओं के कारण पोल्ट्री उत्पादों की मांग में कमी आने से अंडे और पोल्ट्री, मांस और मछली की कीमतें भी कम हो सकती हैं। दूसरी ओर, सीपीआई प्रमुख घटकों पर मूल्य दबाव बने रहने की संभावना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का पीएमआई दिसंबर में निविष्टी लागत का दबाव उग्र होने की ओर इशारा करते हैं। यह ईंधन की लागत, औद्योगिक धातु की कीमतों, खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि और लॉकडाउन स्थिति के बाद में व्यापार की बढ़ती लागत के कारण है। ऐसी स्थिति में जहां मांग सामान्य हो रही है और कंपनियों को कीमते निर्धारित करने की शक्ति मिल रही है, बढ़ती निविष्टी लागत के कारण उत्पादन कीमतें बढ़ने का खतरा है।

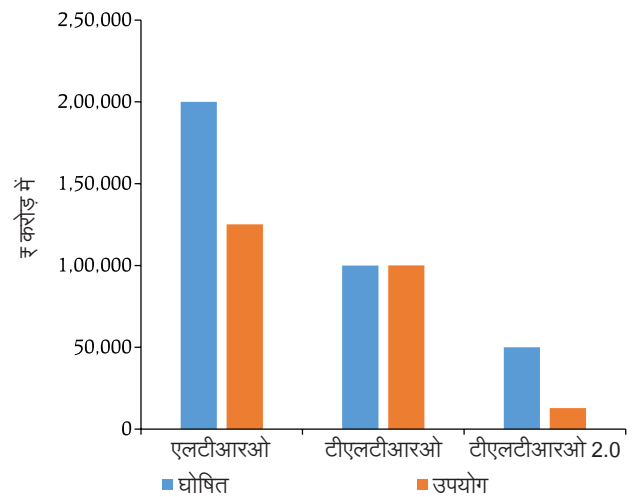
IV. वित्तीय स्थितियां

रिजर्व बैंक अपने बाजार परिचालनों के माध्यम से आसान मौद्रिक और ऋण स्थितियों के रूप में बहाली के लिए पोषक अनुरूप वित्तीय स्थितियां विकसित करना सुनिश्चित कर रहा है। महीने के उत्तरार्ध में बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर प्रवाह के बावजूद दिसंबर 2020 तक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषित राशि बढ़कर ₹5,90,822 करोड़ हो गयी। एलएएफ के तहत ओवरनाईट रिवर्स रेपो के माध्यम से अतिरिक्त चलनिधि को हटाया गया, जो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़कर ₹7,37,314 करोड़ हो गया। ऑन टैप टारगेटेड लॉग टर्म रेपो परिचालन

(टीएलटीआरओ) योजना ⁶ के तहत केंद्रीय बैंक का चलनिधि और केंद्र सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2.0 (ईसीएलजीएस 2.0) का बैंकों द्वारा लाभ उठाया जा सके इसलिए, रिजर्व बैंक ने 21 दिसंबर 2020 को योजना के तहत घोषित पाँच क्षेत्रों के अलावा कामत समिति द्वारा दिए गए सभी दबावग्रस्त क्षेत्रों को 4 दिसंबर 2020 को ऑन टैप टीएलटीआरओ के दायरे का विस्तार किया गया। बैंक रिजर्व बैंक से ऑन टैप टीएलटीआरओ पर धन प्राप्त कर सकते हैं और दबावग्रस्त क्षेत्रों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए सीएलजीएस 2.0 के तहत गारंटी मांग सकते हैं (चार्ट 33)।

माह के दौरान 23 दिसंबर 2020 को राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में खुले बाजार का परिचालन (ओएमओ) आयोजित किया गया था, जिसकी राशि ₹10,000 करोड़ थी, जिससे 22 अक्टूबर 2020 से एसडीएल में ओएमओ की कुल संख्या तीन हुई। टर्म प्रीमिया पर नियंत्रण के लिए 17 और 30 दिसंबर को दो विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) भी किए गए थे।

चार्ट 33: एलटीआरओ और टीएलटीआरओ का उपयोग

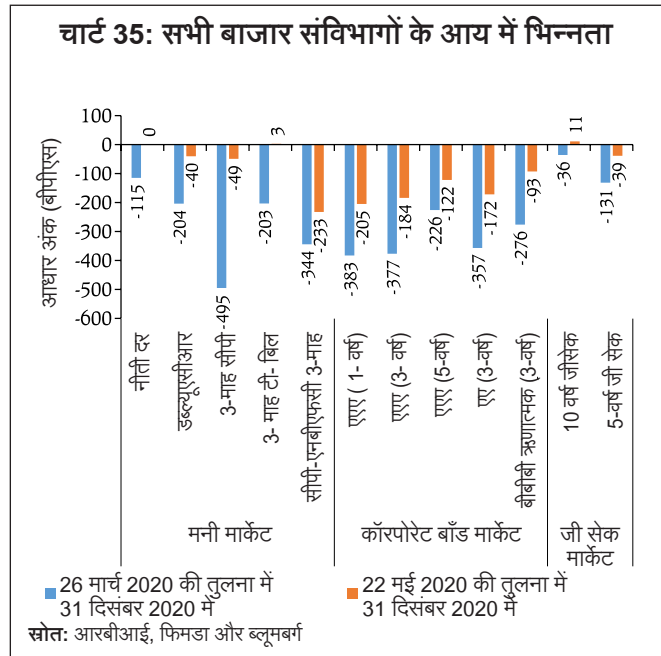
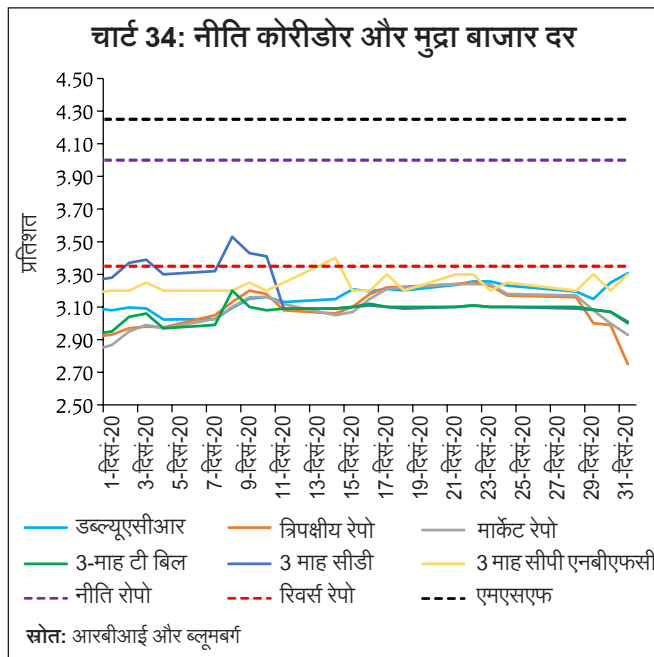


टिप्पणी: बैंकों ने एलटीआरओ टीएलटीआरओ तथा टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत प्राप्त राशि का क्रमशः 98.8 प्रतिशत, 32.4 प्रतिशत तथा 38.1 प्रतिशत राशि चुकायी है।
स्रोत: आरबीआई।

⁶ इस योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त चलनिधि, कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, और विशिष्ट क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 30 सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार उनके निवेश के बकाया स्तर से अधिक निवेश किया जाना चाहिए। योजना के तहत प्राप्त राशि का उपयोग इन क्षेत्रों को बैंक ऋणों और अग्रिम देने के लिए भी किया जा सकता है।

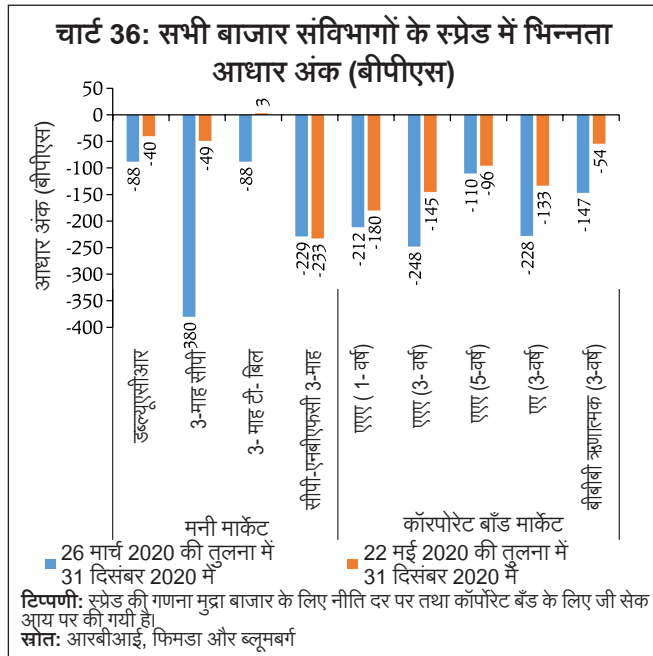
अक्टूबर 2020 के मध्य से पूरे स्पेक्ट्रम की विशेषता वाले उप-एलएफ स्तरों से रिवर्स रेपो दर के करीब बढ़ते हुए, अग्रिम कर बहिर्गमन के कारण मुद्रा बाजार की दरें थोड़ीसी बढ़ी। संपार्श्विक त्रिपक्षीय रेपो दर और बाजार रेपो दर के स्प्रेड की तुलना में भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) नवंबर में (-) 32 आधार अंक (बीपीएस) और (-) 29 बीपीएस से कम होकर दिसंबर 2020 में (-) 7 बीपीएस हो गया। यहां तक कि जमा प्रमाण पत्र (सीडी), 91-दिन के ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) की दरें ओवरनाईट दरों के करीब चली गईं, जबकि वे रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार करते रहे (चार्ट 34)।

वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में, काफी हद तक स्प्रेड संकुचित हो गया, जो चलनिधि उपायों, विनियामक छूट और भावी मार्गदर्शन के प्रभाव को दर्शाता है। 22 मई और 31 दिसंबर 2020 से 1 वर्ष, 3-वर्ष और 5-वर्षीय एए-रेटेड स्पेक्ट्रम के कॉर्पोरेट बॉन्ड के आय में क्रमशः 205 बीपीएस, 184 बीपीएस और 122 बीपीएस की गिरावट हुई है (चार्ट 35)। यहां तक कि 3-वर्षीय बीबीबी- (बीबीबी माइनस)-रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड - सबसे कम रेटेड निवेश ग्रेड बॉन्ड की आय में - 93 बीपीएस की गिरावट आई है, जो यह दर्शाती है कि बिना रेटिंग असर के चलनिधि दबाव एक समान रूप में कम हुआ है। परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान क्रमशः 1 वर्ष, 3-वर्ष, 5-वर्ष एए और 3-वर्षीय बीबीबी-



रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड में 180 बीपीएस, 145 बीपीएस, 96 बीपीएस और 54 बीपीएस की गिरावट आई (चार्ट 36)। पुराने 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.77 जीएस 2030) की आय फिसलकर 31 दिसंबर 2020 को 5.90 प्रतिशत पर बंद हुई, जबकि नए 10-वर्षीय जी-सेक बेंचमार्क (5.85 जीएस 2030) की आय 31 दिसंबर 2020 को लगभग 5.87 प्रतिशत पर बंद हुई। धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था के खुलने से और गतिविधि सामान्य होने के साथ, मांग की स्थिति में सुधार, सस्ती दरें और पर्याप्त चलनिधि के कारण वित्तीय से स्थावर क्षेत्र तक संसाधनों का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।

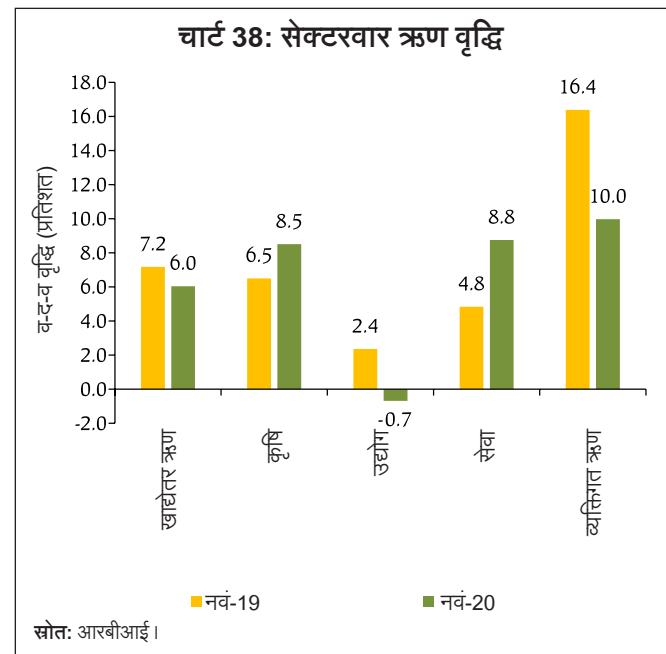
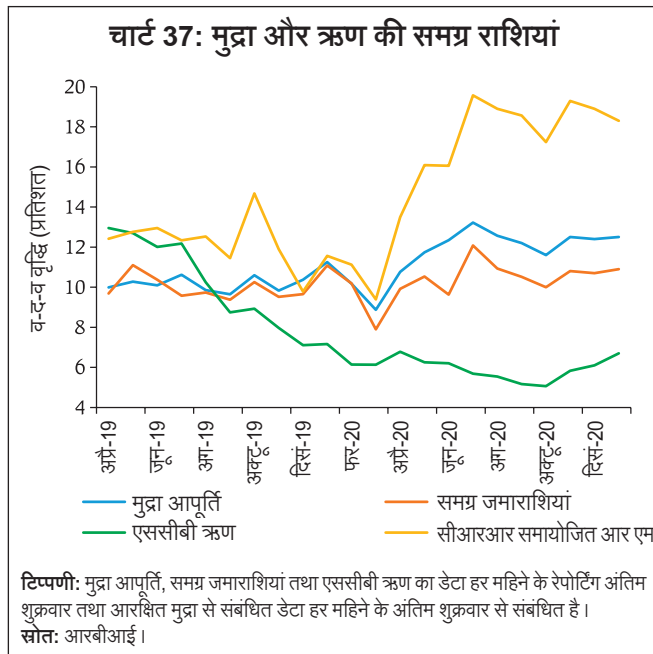
चलनिधि संबंधी व्यापक उपाय सहज मौद्रिक स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 8 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष 18.3 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.3 प्रतिशत) हुई, संसाधनों को संचालनगत मुद्रा (सीआईसी) में चल रही वृद्धि से और स्रोत को निवल विदेशी आस्ति (एनएफए) से बल मिला (चार्ट 37)। 1 जनवरी 2021 की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि (एक वर्ष पहले 10.1 प्रतिशत) हुई, जिसे 10.9 प्रतिशत से बढ़ती समग्र



शेयरों में निवेश पिछले साल की ₹10,524 करोड़ की गिरावट की तुलना में वृद्धिशील आधार पर वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक (1 जनवरी तक) ₹434 करोड़ था। अप्रैल से 1 जनवरी 2021 तक बैंकों ने वाणिज्यिक क्षेत्र को संचयी आधार पर ₹2,93,007 करोड़ का ऋण दिया है- पिछले वर्ष की तुलना में 31.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान निधि के समग्र प्रवाह में बैंक ऋण 29.8 प्रतिशत से बढ़कर 34.1 प्रतिशत हो गया। नवंबर 2020 में कृषि और सेवा क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि हुई, जबकि उद्योग क्षेत्र को ऋण संकुचित हुआ (चार्ट 38)। व्यक्तिगत वाहन ऋण को छोड़कर सभी क्षेत्रों में व्यक्तिगत ऋण में मंदी आई। सेवा क्षेत्र में परिवहन, व्यापार और पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण तेजी से बढ़े। जबकि उद्योग के लिए समग्र ऋण वृद्धि में गिरावट आई थी, मध्यम उद्योग को ऋण में वृद्धि हुई और इन क्षेत्रों के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों के चलते सूक्ष्म और लघु उद्यम संकुचन से बाहर आए।

जमाराशि (एक वर्ष पहले 9.8 प्रतिशत) से बल मिला। पांच महीने के अंतराल के बाद, बहाली के सकारात्मक संकेतों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण 6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 1 जनवरी 2021 को 6.7 प्रतिशत हो गया (एक वर्ष पहले 7.5 प्रतिशत)। एससीबी का वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड, डिबेंचर और कॉर्पोरेट निकायों के

ऋण बाजार में अतिरिक्त चलनिधि स्थिति से ब्याज दरें कम हो गयीं। मार्च से दिसंबर 2020 तक की अवधि में माध्यम अवधि जमा दर (एमटीडीआर) में 146 बीपीएस की गिरावट आई है, एक वर्ष की परिपक्वता के छोटे अवधि की जमाराशियों में गिरावट



सारणी 5: बैंकों की जमा और उधार दरों में रेपो रेट का ट्रांसमिशन

(आधार अंक)

अवधि	रेपो रेट	मीयादी जमा दरें		उधार दरें		
		मीडियन टर्म डिपॉजिट रेट	डब्ल्यूएडीटीडीआर	1-वर्ष मीडियन एमसीएलआर	डब्ल्यूएलआर बकाया रूपया ऋण	डब्ल्यूएलआर नए रूपया ऋण
फरवरी 19 - सितंबर 19	-110	-9	-7	-30	2	-40
19 अक्टूबर - दिसंबर 20*	-140	-177	-120	-115	-85	-125
20 मार्च- दिसंबर 20*	-115	-146	-81	-95	-67	-94
19 फरवरी - दिसंबर 20*		-210	-127	-145	-83	-165

*: डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा नवंबर 2020 से संबंधित है।

डब्ल्यूएलआर: वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट

डब्ल्यूएडीटीडीआर: वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट

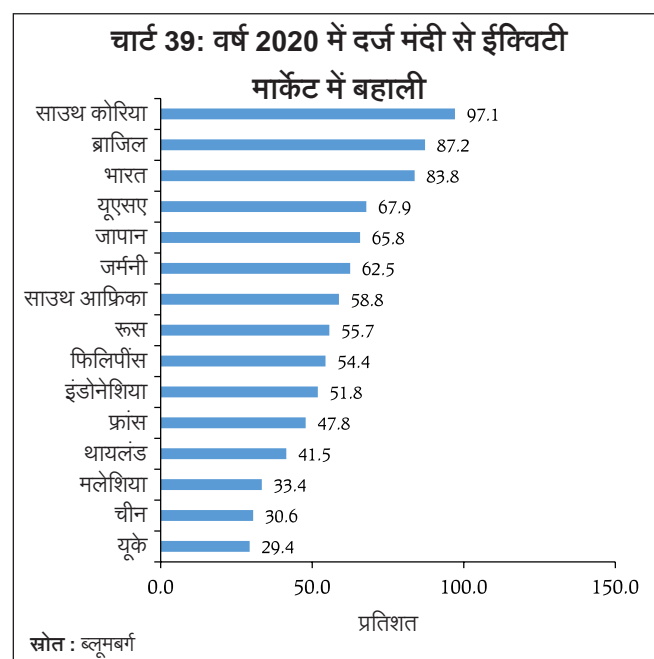
एमसीएलआर: मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट

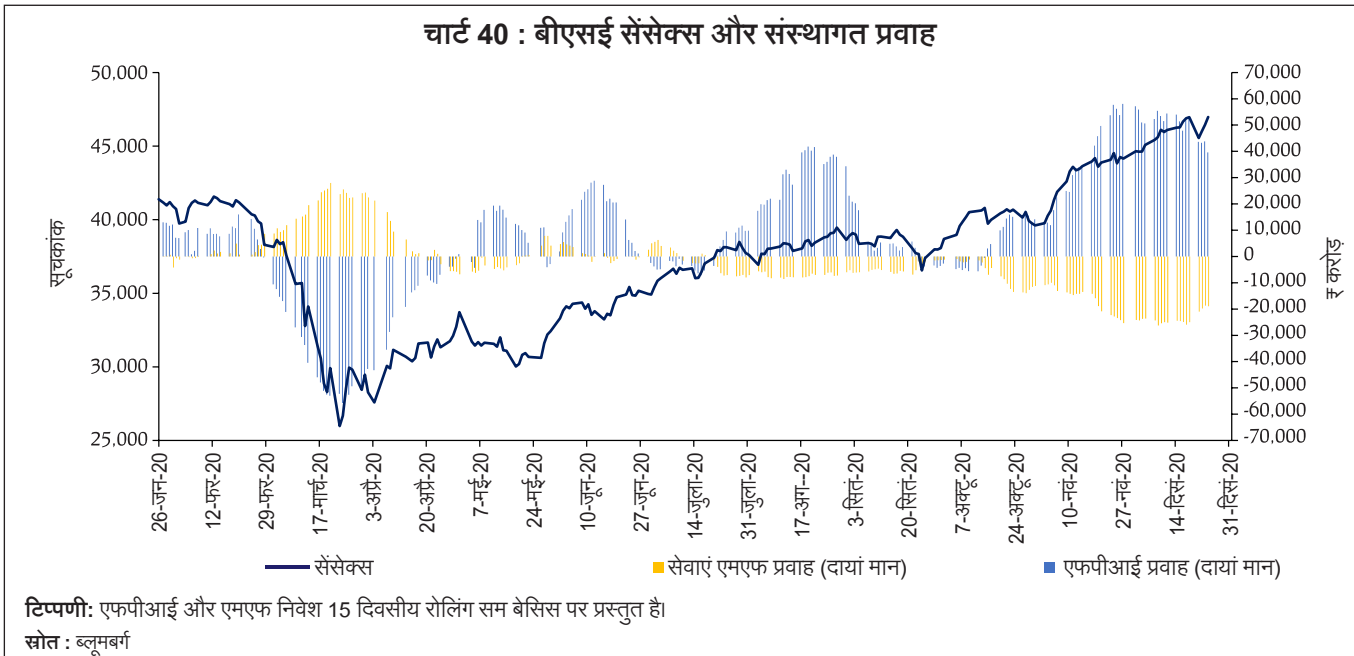
स्रोत : आरबीआई

देखी गयी है (163 बीपीएस)। जमा दरों में प्रारंभिक समायोजन, जो अन्यथा पिछड़ गया है, उधार दरों का संचरण आगे बढ़ने के संकेत देता है। इसी अवधि के दौरान, 1-वर्ष का माध्य एमसीएलआर क्रमिक रूप से कुल 95 बीपीएस से कम हुआ (सारणी 5)। जमा और उधार दरों के बीच की संचरण विषमता को संरचनात्मक अपरिवर्तनीयता के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि थोक या बाजार आधारित वित्त पोषण के स्थान पर बैंकों की खुदरा जमा पर निर्भरता बढ़ रही है।

प्रतिबंधों को कम करते हुए और सामान्य गतिविधियों की बहाली के द्वारा लॉकडाउन के क्रमिक रूप से रोल-बैक के साथ, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित बाजारों के कारोबारी घंटे, जो पहले 7 अप्रैल 2020 से कम किए गए थे, 9 नवंबर 2020 के बाद से चरणबद्ध तरीके से बहाल किए गए। बाद में, 8 जनवरी 2021 को घोषणा की गई कि सामान्य चलनिधि प्रबंधन संचालन चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा, जिसकी शुरुआत संशोधित चलनिधि प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत 15 जनवरी 2021 को आयोजित परिवर्ती दर रिवर्स रेपो नीलामी से होगी। इसके साथ ही, 15 जनवरी से इस लेख को प्रकाशित करने के दौरान ₹4.4 लाख करोड़ रुपये ऑर्डर के औसत दैनिक अवशोषित चलनिधि के साथ स्थिर दर रिवर्स रेपो पूरी तरह से चालू रहा। सामान्य परिचालन की क्रमिक बहाली को कैलिब्रेट करते हुए, रिजर्व बैंक ने अनुकूल वित्तीय स्थितियों का समर्थन करने और बहाली के प्रोत्साहन के प्रयोजन से प्रणाली में पर्याप्त तरलता उपलब्ध करना सुनिश्चित किया है।

बहाली जोर पकड़ रही है यह स्पष्ट होने के कारण और अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज तथा ब्रेक्सिट व्यापार समझौते के पारित होने से सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण इक्विटी बाजार दिसंबर में अपनी तेजी में नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बाजार में अतिउत्साह के कारण अधिकतर वैश्विक साधियों की तुलना में भारतीय इक्विटी में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई, 31 दिसंबर 2020 को बीएसई सेंसेक्स 47,751 को छूने के साथ, 23 मार्च 2020 (25,981) के निचले स्तर से 83.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 39 और 40)।

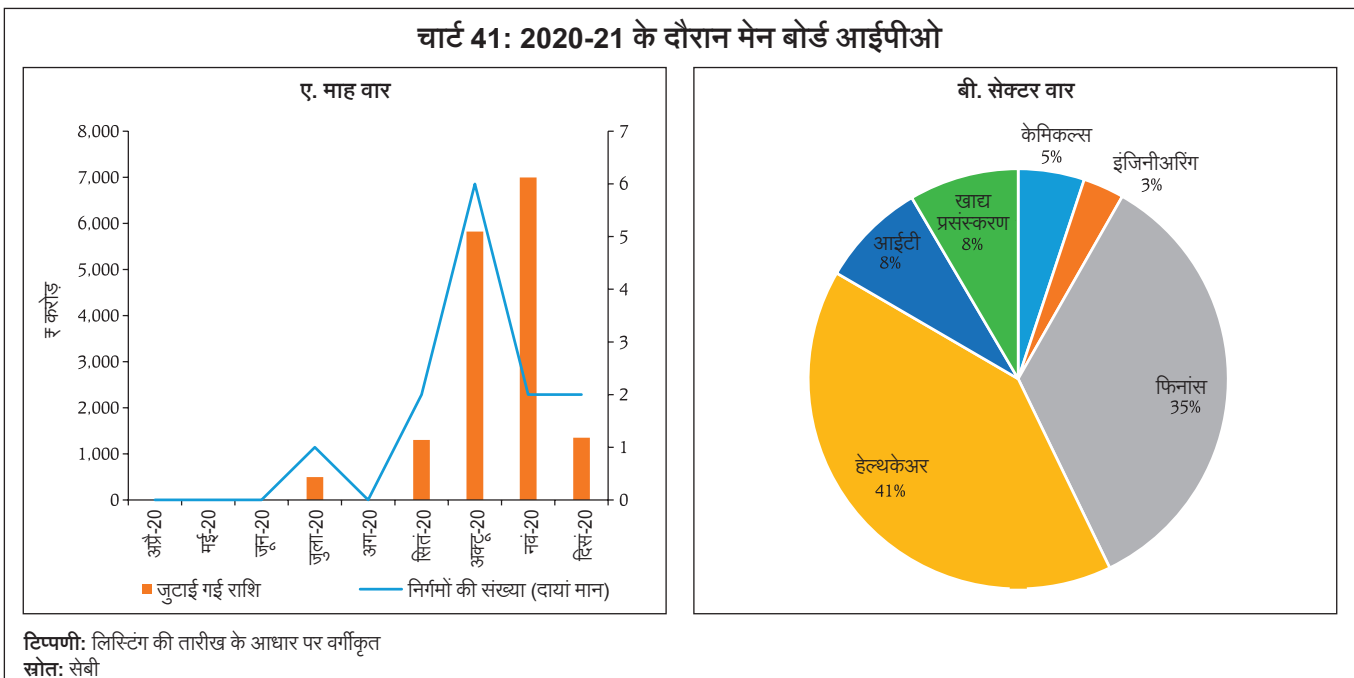


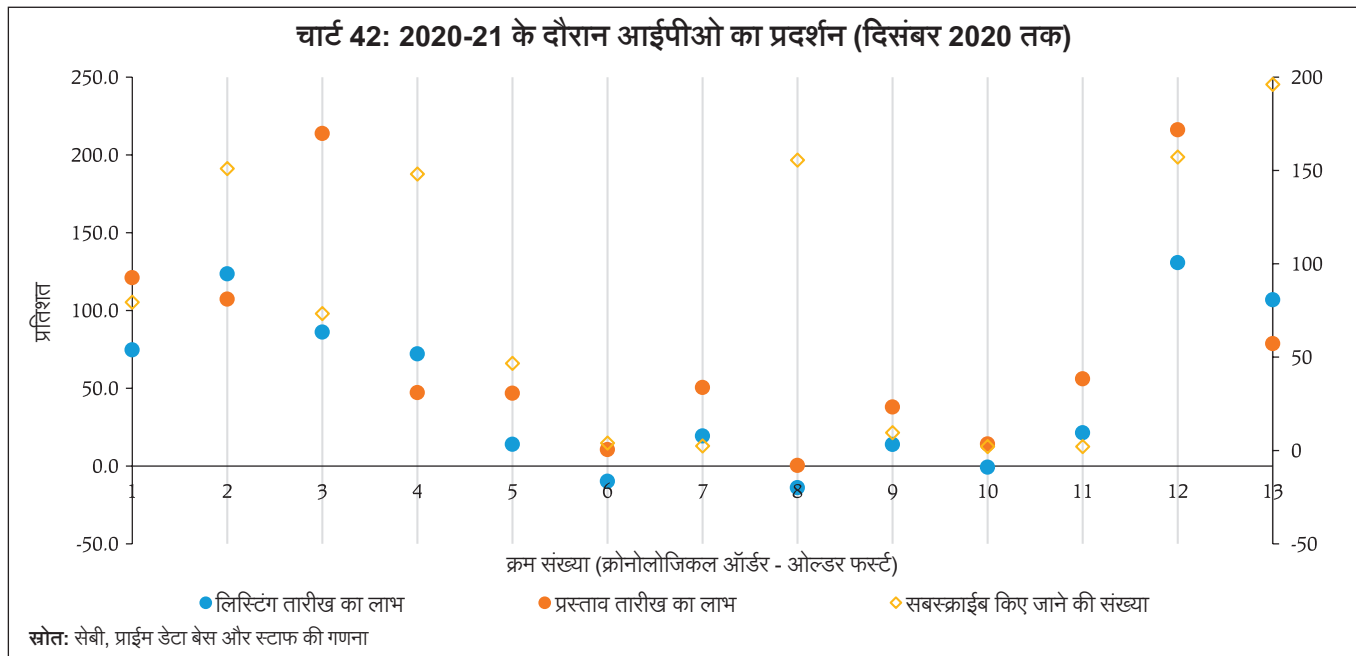


दिसंबर 2020 के दौरान ₹1,351 करोड़ रुपये के कुल दो प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) की लिस्टिंग ने मुख्य बोर्ड आईपीओ के माध्यम से 2020-21 (दिसंबर 2020 तक) में कुल ₹15,971 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹10,487 करोड़ रुपये से तेज उछाल दर्शाता है

(चार्ट 41)। जुलाई 2020 में जारी किए गए पहले आईपीओ ने, स्वास्थ्य सेवा और वित्त क्षेत्र की कंपनियों ने सभी प्रारंभिक प्रस्तावों में अधिकतम राशि जुटायी है।

खुदरा भागीदारी और उच्च प्रणाली-व्यापी चलनिधि में वृद्धि से निवेशकों को शानदार रिटर्न देने में आईपीओ को मदद मिली,





13 में से 10 आईपीओ को लिस्टिंग दिवस पर सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ है और सभी आईपीओ को लिस्टिंग दिवस पर तारीख आधार प्रस्ताव पर सकारात्मक आय प्राप्त हुई है (चार्ट 42)। इसके अलावा, अधिकतर आईपीओ लिस्टिंग दिन के बाद में भी तेजी आई।

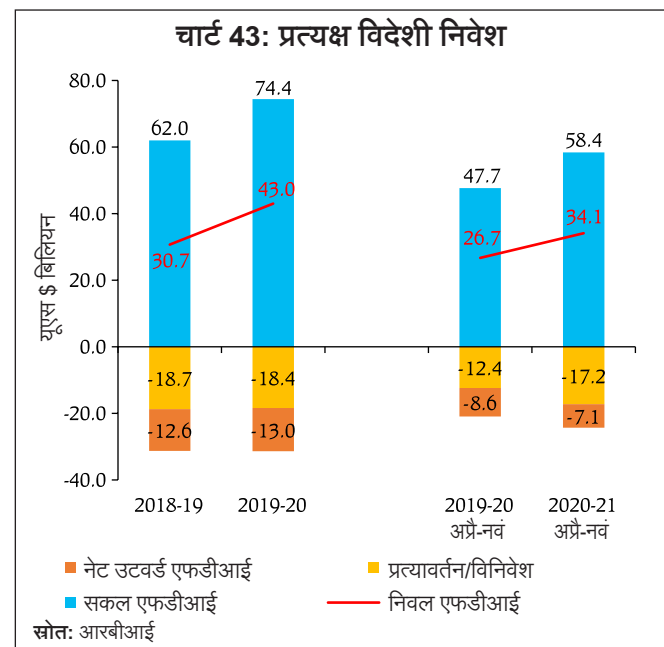
निवेशकों के लिए आईपीओ के लिस्टिंग दिन की आय (-) 14.0 प्रतिशत और 130.7 प्रतिशत के बीच रही। क्षेत्रों में, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और रसायन क्षेत्र में निवेशकों को उच्चतम कमाई हुई (सारणी 6)।

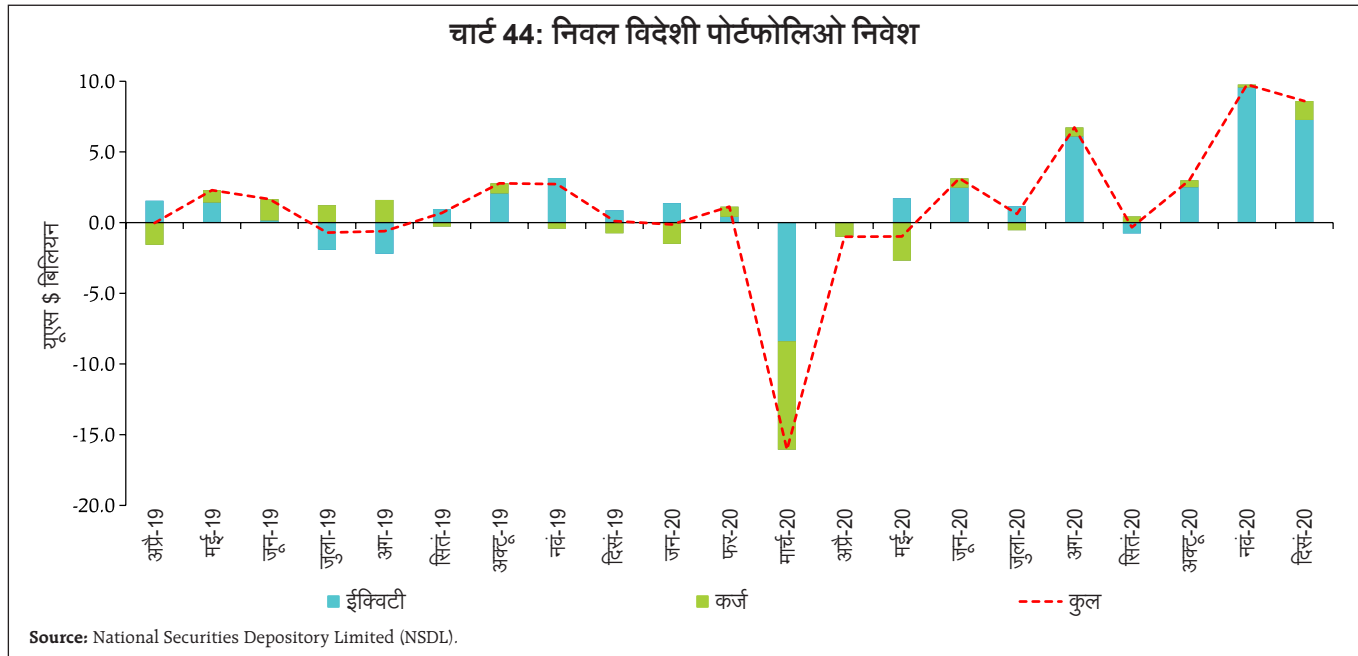
नये इक्विटी निवेश के कारण अगस्त-नवंबर 2020 में निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) बढ़ा है। फलस्वरूप, अप्रैल-नवंबर 2020 में निवल एफडीआई पिछले वर्ष के अमेरिकी डॉलर 26.7 से बढ़कर अमेरिकी डॉलर 34.1 बिलियन तक बढ़ गया (चार्ट 43)।

सारणी 6: आईपीओ सूचीबद्ध होने के दिन की आय (क्षेत्र-वार)

क्रम सं.	क्षेत्र	न्यूनतम	अधिकतम	माध्य
1	केमिकल्स	72.0	74.7	73.3
2	इंजीनियरिंग	13.8	19.3	16.6
3	फिनांस	-14.0	14.0	-2.7
4	हेल्थकेअर	21.4	21.4	21.4
5	आईटी	86.0	123.5	104.8
6	फुड प्रोसेसिंग	106.8	130.7	118.7

नवंबर 2020 में ऑल टाइम इंट्रा-महीने के उच्च स्तर के बाद दिसंबर 2020 में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह मजबूत रहा। इसका कारण सतत वैश्विक मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन, अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना और भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की प्रवृत्ति में बहाली हो सकता है। दिसंबर 2020 में, 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई आगमन काफी हद तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर की

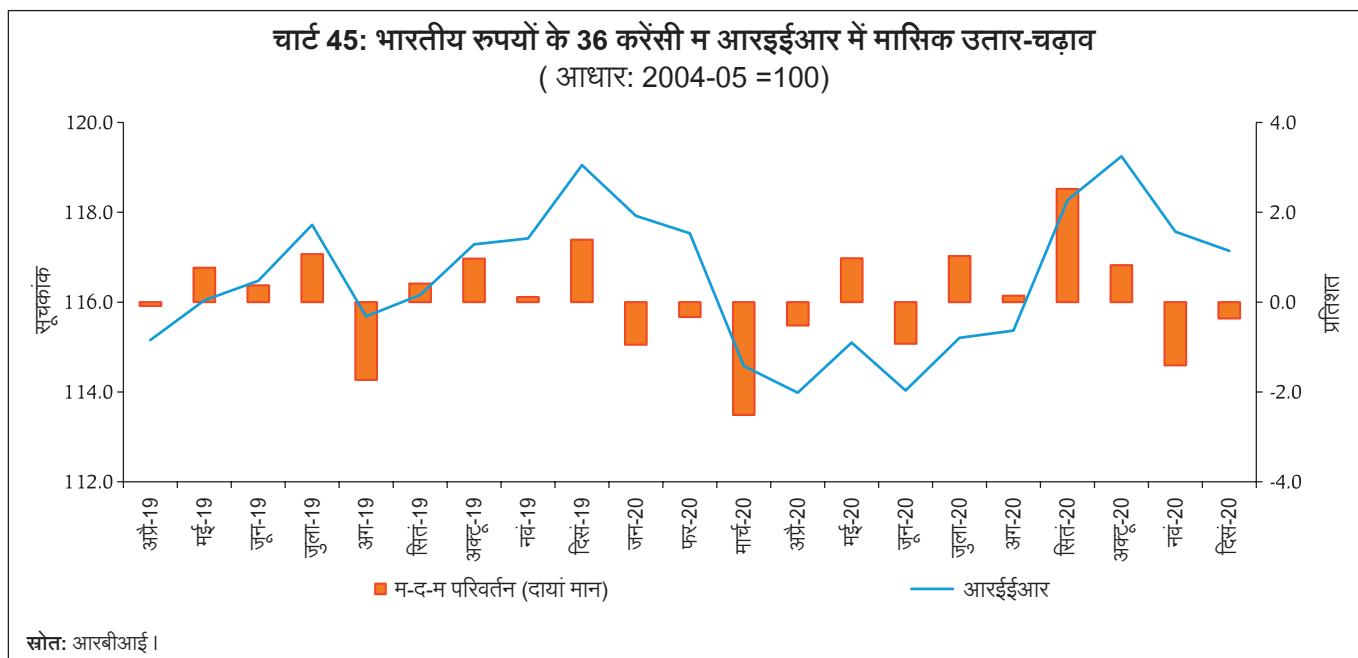




ईक्विटी खरीद से प्रेरित था। डेट सेगमेंट में, 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफपीआई आगमन, चालू वित्त वर्ष में अब तक की उच्चतम मासिक अभिवृद्धि है (चार्ट 44)। स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवल निवेश 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था।

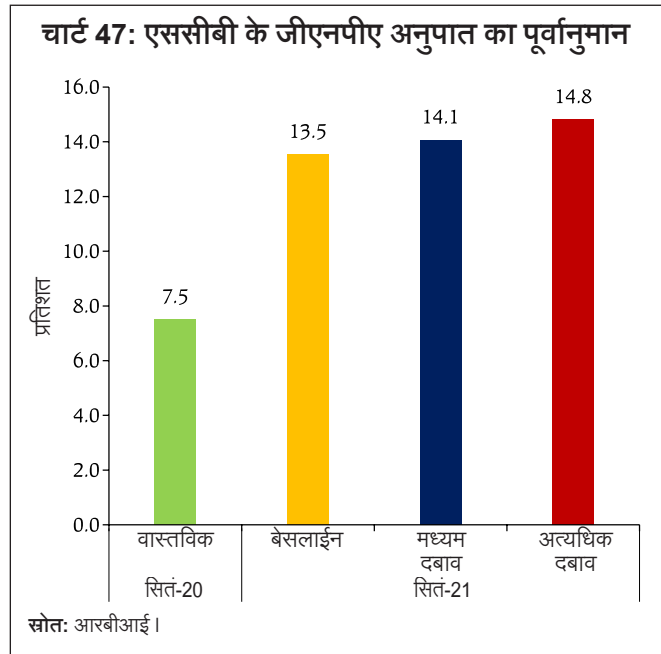
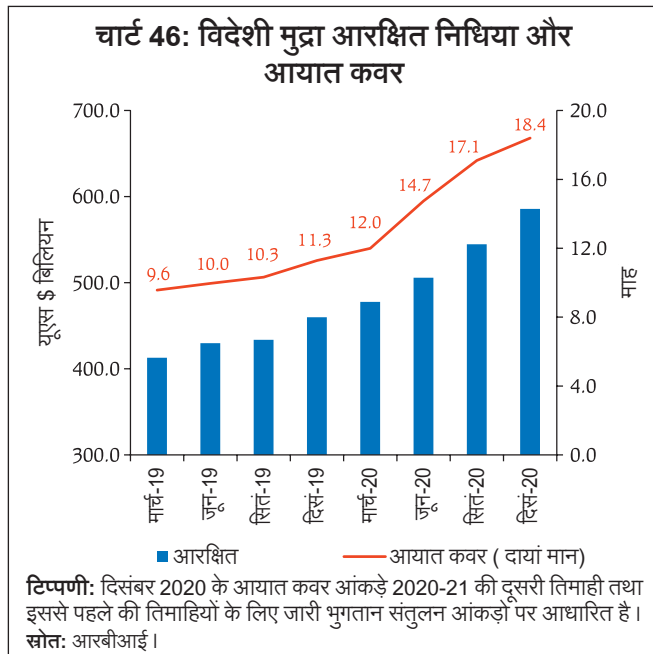
वैक्सीन समाचारों से विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपया (रुपये) ने मजबूत पूंजी प्रवाह से प्रभावित होकर, दिसंबर 2020

में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले महीने की तुलना में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मार्च 2020 के अंत की स्थिति की के अपने स्तर से दिसंबर 2020 के अंत तक रुपये में 3.2 प्रतिशत वृद्धि हुई और अमेरिकी डॉलर की तुलना में ₹73.05 पर बंद हुआ, यह स्थिति आखिरी बार सितंबर 2020 की शुरुआत में देखी गयी थी (चार्ट 45)।



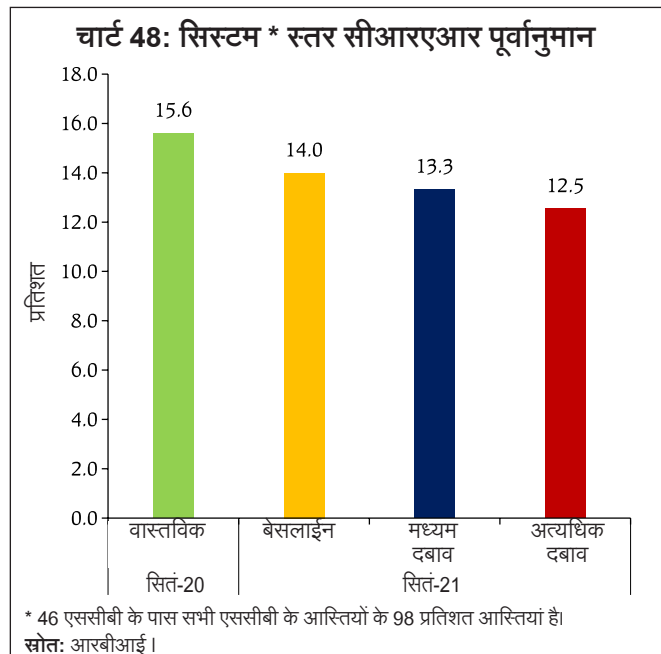
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 के अंत तक के भारत के विदेशी कर्ज के आंकड़े 31 दिसंबर 2020 को जारी किए गए थे। भारत का विदेशी कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बाहरी वाणिज्यिक उधार, पोर्टफोलियो कर्ज निवेश और अल्पकालिक व्यापार ऋण के कारण बाहरी कर्ज संतुलित रहा। दिसंबर 2020 के अंत तक, आरक्षित निधियों ने 585.8 बिलियन डॉलर का उच्च स्तर छू लिया, जो 18.4 महीनों के आयात के बराबर है या सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार बकाया बाहरी कर्ज का 105.3 प्रतिशत है (चार्ट 46)।

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विनियामक उपायों में ऋण आपूर्ति और प्रणालीगत लचीलापन बनाए रखते हुए आर्स्ति वर्गों में आघात सहनशीलता आवश्यक है। सभी एससीबी का सकल गैर-निष्पादित आर्स्तियों (जीएनपीए) का अनुपात में दिसंबर 2019 के 9.2 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत हो गया है, इसे विनियामक व्यवस्थाओं से काफी सहायता मिली। जनवरी 2021 की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में किए गए मैक्रो स्ट्रेस परीक्षणों से पता चलता है कि बेसलाइन परिदृश्य के तहत सितंबर 2021 तक एससीबी का जीएनपीए अनुपात बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो सकता है, जो गंभीर



दबाव परिदृश्य के तहत बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो सकता है (चार्ट 47)।

कुल स्तर पर, एससीबी के पास गंभीर दबाव परिदृश्य में भी पर्याप्त पूंजी कुशन ⁷ है (चार्ट 48)। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर, कुछ



⁷ एससीबी द्वारा जोखिम भारित आर्स्तियों के अनुपात (सीआरएआर) में 9 प्रतिशत न्यूनतम पूंजी बनाए रखना अपेक्षित है।

बैंकों के पूंजी बफर विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से नीचे हो सकते हैं। इसलिए, आगे बढ़ते हुए, चरणवार पूंजी वृद्धि या अन्य कार्यनीतिक कार्रवाइयों जैसे कार्यों को कम करना इन बैंकों के लिए सूक्ष्म विवेकपूर्ण नजरिए से प्रासंगिक हो जाएगा।

नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर में सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान मामूली वृद्धि हुई; दूसरी ओर, अंतर-बैंक बाजार सिकुड़ने और बैंकों के पूंजीकरण के कारण बैंकिंग प्रणाली में मार्च 2020 की स्थिति की तुलना में संक्रमण का खतरा कम कर दिया।

भुगतान प्रणाली

भुगतान प्रणाली में, दिसंबर 2020 में डिजिटल लेनदेन में वृद्धि जारी है, दोनों खुदरा और थोक लेनदेन में आर्थिक सुधार के व्यापक बेस के अनुरूप विस्तार हुआ। चूंकि थोक सेगमेंट में तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) को 14 दिसंबर 2020 से चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया गया था, इसकी मात्रा वृद्धि (वाई-ओ-वाई) तेजी से बदल गई और दिसंबर 2020 में 20.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक महीने पहले 2.9 प्रतिशत थी। आरटीजीएस के माध्यम से लेनदेन का मूल्य, अक्टूबर 2019 के बाद से घटना शुरू हुआ था और महामारी में तेजी से घट गया था, दिसंबर 2020 में इसमें 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

रिटेल सेगमेंट में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेनदेन की मात्रा में दिसंबर 2020 में 31.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जबकि एक महीने पहले यह 24.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। मूल्य के संदर्भ में, एनईएफटी लेनदेन क्रमशः 31.7 और 27.9 प्रतिशत बढ़ा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन मात्रा पिछले महीने के ऐतिहासिक 2.2 बिलियन से ऊपर बना हुआ है, जबकि लेनदेन मूल्य दिसंबर 2019 की तुलना में 105.5 प्रतिशत बढ़ गया है (सारणी 7)। तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से लेनदेन में वृद्धि हुई है, जिससे मात्रा और मूल्य वृद्धि दोनों में दोहरे अंकों का स्तर बढ़ गया है। नकदी आहरण भी बहाली की स्थिति में अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करता है।

सारणी 7: 2020-21 में भुगतान लेनदेन

(₹ करोड़ में)

	आरटीजीएस	एनईएफटी	यूपीआई	आईएमपीएस
अप्रैल-20	64,43,653	13,06,406	1,51,141	1,21,141
मई-20	70,41,869	14,81,750	2,18,392	1,69,402
जून-20	86,51,978	19,06,586	2,61,835	2,06,951
जुलाई-20	83,35,279	19,63,113	2,90,538	2,25,775
अगस्त-20	72,92,380	19,30,552	2,98,308	2,35,137
सितंबर-20	94,89,066	21,65,515	3,29,032	2,48,662
अक्टूबर-20	84,96,046	22,35,389	3,86,107	2,74,645
नवंबर-20	79,87,655	22,18,252	3,90,999	2,76,459
दिसंबर-20	1,06,59,120	25,58,304	4,16,176	2,92,325

स्रोत: आरबीआई

बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स, पेमेंट स्पेस में बिगटेक के बढ़ते पदचिह्न और बैंकों पर अपने भुगतान इको-सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए प्रतिस्पर्धी दबाव के साथ इस वर्ष डिजिटल पेमेंट की ओर प्राथमिकता बढ़ने का एक अलग पैटर्न स्पष्ट हो रहा है। कैशबैक, ई-कॉमर्स पोर्टल्स पर छूट, आसान ईएमआई और अब खरीदे बाद में भुगतान करे जैसे प्रोत्साहन योजनाओं ने एक व्यापक ग्राहक बेस बनाया है। उन्होंने डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग को भी बढ़ावा दिया है और खुदरा भुगतान प्रणालियों में लेनदेन की मात्रा को विशेष रूप से यूपीआई पर कर रहे हैं। चूंकि भुगतान उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, नए प्रतिभागी लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं, भारत महामारी से पहले से कहीं अधिक डिजिटल उभर कर आ सकता है। यह उपभोक्ता खर्च को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था के औपचारिकता की डिग्री को बढ़ा सकता है।

रिजर्व बैंक ने अब अपने विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) के तहत 'क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स' इस विषय के दूसरे कोहार्ट की घोषणा की है। भारत दुनिया भर में इनबाउंड प्रेषण का सबसे बड़ा लाभार्थी है, जो वैश्विक प्रवाह का 15 प्रतिशत का हिस्सेदार है। वर्ष 2019 में भारत को 83 अरब अमेरिकी डॉलर मिले थे और 2020 की पहली छमाही में 27.4 अरब अमेरिकी डॉलर मिले हैं। इस कोहार्ट से कम लागत, सुरक्षित, सुविधाजनक और पारदर्शी प्रेषण प्रणाली की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ

उठाकर सीमा पार भुगतान परिदृश्य को फिर से ढालने में सक्षम नवाचारों को प्रेरित करने की उम्मीद है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाने के लिए प्रतिभागी संस्थाओं के लिए नेटवर्थ आवश्यकताओं को ₹ 25 लाख रुपये से घटाकर ₹10 लाख रुपये कर दिया गया है, साझेदारी फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को अब रुपये में भाग लेने की अनुमति है।

V. निष्कर्ष

वर्ष 2021 कैसे होगा? बहाली का आकार वी आकार होगा और ' वी ' का मतलब वैकसीन है। 16 जनवरी को, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी वैकसीन विनिर्माण क्षमता होने के अपने तुलनात्मक लाभ और पोलियो और खसरा के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीका अभियानों का एक समृद्ध अनुभव है। यदि सफल होता है, तो यह जोखिमों के संतुलन को ऊपर की ओर झुका देगा। ई-कॉमर्स और डिजिटल प्रौद्योगिकियां विश्व के मुकाबले भारत की बहाली में उज्ज्वल स्थान होंगे, जिसमें निश्चित रूप से रिबाउंड होगा, लेकिन उत्पादन और रोजगार का महामारी पूर्व स्तर पाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। जापानिफिकेशन अधिकतम उन्नत दुनिया पर साफ झलकता है, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, संभावित उत्पादन बहुत कम होगा।

मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य में हालिया बदलावों ने दृष्टिकोण को उज्ज्वल किया है, जीडीपी के साथ सकारात्मक क्षेत्र प्राप्त करने की दूरी और मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। यदि ये गतिविधि बनाए रखते हैं, तो बहाली का समर्थन करने के लिए नीतिगत स्थान खुल सकता है। घरेलू मांग की धीमी गति बहाली और निर्यात के अनलॉक होने के साथ, मर्केडाइज़ व्यापार जनवरी की शुरुआत में रिबाउंड हुआ। चालू खाता अधिशेष घरेलू गतिविधि के रूप में तेज़ हो रहे हैं। विदेशी निवेश प्रवाह पहले से ही आसन्न संकट को भांप रहा है। इक्विटी बाजारों द्वारा हाल ही में दर्ज नई उचाइयां, तीसरी तिमाही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस, इंफोसिस और विप्रो जैसे आईटी कंपनियों में वृद्धि के कारण कॉर्पोरेट आय के परिणामों से प्रेरित हैं।

वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, जीडीपी वृद्धि सांख्यिकीय समर्थन से लाभान्वित होगी और ज्यादातर खपत-चालित होने की संभावना है। रबी की बुआई सीजन के अंत से पहले सामान्य क्षेत्रफल पार करने से, 2021 में बम्पर कृषि उत्पादन की उम्मीद है। भारत वैकसीन विनिर्माण के लिए वैश्विक पूंजी राजधानी होने के नाते, फार्मास्यूटिकल्स निर्यात को विश्व स्तर पर टीकाकरण अभियानों की शुरुआत के साथ एक बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। कृषि निर्यात लचीला बना हुआ है और हाल ही में उत्पादन लिंकड (पीएलआई) योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कम मूल्य वाले अर्ध-प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों में बदलाव करके सहक्रियाओं का उपयोग करने से न केवल उत्पादकता में सुधार होगा बल्कि भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिलेगा।

वर्ष 2020 में विकास ने खपत की मांग को मजबूत करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बढ़ते व्यापार लेनदेन के पीछे एक नए डिजिटल परिवर्तन का सूत्रपात किया है। विश्व आर्थिक मंच की 7 जनवरी 2021 को जारी रपोर्ट इंडियन सिटीज इन द पोस्ट पेनडेमिक के अनुसार - महामारी बेहतर नया शहरी प्रतिमान बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है - जो भारतीय शहरों को स्वस्थ, अधिक समावेशी और अधिक लचीला बनाने में सक्षम बनाता है। शहरी सुधार एजेंडा सात विषय यथा योजना; आवास; परिवहन; वातावरण; सार्वजनिक स्वास्थ्य; लिंग; और कमजोर आबादी के अनुरूप स्थापित किया जा सकता है।

स्थायी विकास तथा एक स्थिर बदलाव के लिए तत्काल किकस्टार्ट निवेश की आवश्यकता है। भारत को ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए, जिसमें कॉरपोरेशन और बैंकों की बैलेंस शीट में नकद रूप से बैठे और रिज़र्व बैंक के साथ रिवर्स रेपो बैलेंस, उत्पादक क्षेत्रों के लिए क्रेडिट में और निवेश गतिविधि पर वास्तविक खर्च करने से पहले वास्तविक गतिविधि में लगातार अपक्षय भार वहन करने के तरीके का पता लगाएं। भारत को ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए, जिसमें कॉरपोरेशन और बैंकों की बैलेंस शीट की निष्क्रिय नकद और रिज़र्व बैंक के रिवर्स रेपो बैलेंस, यह वास्तविक गतिविधि पर लगातार अपस्फीति भार

लगाने से पहले, उत्पादक क्षेत्रों के लिए कर्ज देने में और निवेश गतिविधि पर वास्तविक खर्च के लिए काम आए। वित्तीय क्षेत्रों की बैलेंस शीट में तनाव, अधिस्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव तथा कमजोर पुनर्गठन के रूप में तेज हो सकता है, लेकिन बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट की तुलना में मजबूत पूंजी बफर्स के साथ स्वास्थ्य संकट में प्रवेश किया है। स्लिपेज अनुपात कम हो रहा है और ऋण वसूली में सुधार हो रहा है तथा प्रावधान कवरेज अनुपात में भी 70 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। पूंजी लगाना और ऋण अपचार से निपटने के अभिनव तरीकों पर नीति का ध्यान केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसांख्यिकीय लाभांश फिसलने के पहले वित्त के माध्यम से वृद्धि को टिकाऊ आधार पर निर्बाध बनाया जा सके। अर्थव्यवस्था को ठीक होने में कई साल लगेंगे, लेकिन अभिनव दृष्टिकोण महामारी को अवसरों में बदल सकते हैं। क्या केंद्रीय बजट 2021-22 गेम-चेंजर होगा?

संदर्भ:

Agarwal, R., Padhi, I., Goyal, S., Behera, S.R. and Misra, S. 'Government Finances 2020-21: A Half-Yearly Review', *RBI Monthly Bulletin*, December 2020.

Covid-10 trn. (January 9-15, 2021). *The Economist*.

Financial Stability Report. (Issue No. 22, 2021). *RBI*.

Global Economic Prospects. (January 2021). *World Bank*.

IIF Capital Flows Tracker – December 2020. (January 2021). *Back from the Brink*.

Kumar, P. 'An Economic Activity Index for India', *RBI Monthly Bulletin*, November 2020.

Reinhart, C., 'The coming COVID-19 Credit Crunch', *World Bank Blogs*, December 2020.

Sedik, T.S. and Xu, R., 'A Vicious Cycle: How Pandemics Lead to Despair and Economic Unrest?', *IMF Working Paper*, October 2020.

Shahidi T., Dantewadia P., (2021, January 05), 'State Recovery Tracker: UP, Rajasthan, other large states led economic recovery in December'. *Livemint*.

State Finances: A Study of Budgets of 2020-21. (2020). *RBI*.

भारतीय रुपये के प्रभावी विनिमय दर सूचकांक*

भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और भारत के विदेशी व्यापार के रुझान में बदलावों के कारण भारतीय रुपये की सांकेतिक/ वास्तविक प्रभावी विनिमय दर [एनईईआर (नीर) / आरईईआर(रीर)] के व्यापक (मौजूदा 36-मुद्रा-आधारित) सूचकांकों को अद्यतन करना आवश्यक हो जाता है। यह आलेख दो महत्वपूर्ण नवाचारों के साथ अद्यतन श्रृंखला प्रस्तुत करता है: आधार वर्ष 2004-05 से बदल कर 2015-16 हो गया है; और वर्तमान मुद्रा सूचकांकों की संख्या 36 से बढ़कर 40 हो गयी है, जिसमें आठ नई मुद्राएं शामिल हैं और चार मुद्राएं हटा दी गई हैं। 2004-05 से 2019-20 तक की नमूना अवधि के अधिकांश भाग में नए रीर सूचकांक बेंचमार्क (यानी आधार वर्ष मूल्य= 100) के आसपास बने हुए हैं, जो भारत की बाह्य स्पर्धात्मकता को पुरानी श्रृंखला की तुलना में बेहतर दर्शाते हैं। लक्षित लचीली मुद्रास्फीति (एफआईटी फ्रेमवर्क) ढांचे को अपनाने के बाद से भारत और इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति में अंतर घटे हैं और स्थिर हुए हैं, जो कि भारत की बाहरी प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छा संकेत है।

भूमिका

प्रभावी विनिमय दर (ईईआर) किसी मुद्रा के उचित मूल्य व अर्थव्यवस्था की बाह्य प्रतिस्पर्धा के आकलन में एक मापदंड का और यहां तक कि मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के निर्धारण में दिशा सूचक की तरह काम करती है।¹ ईईआर व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के उतार-चढ़ाव का एक संक्षिप्त संकेतक है। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर), व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के द्विपक्षीय विनिमय दरों के भारित औसत का एक सूचकांक है जहाँ घरेलू मुद्रा के व्यापार समूह में उनके हिस्से के आधार पर भार तय किया जाता है। सापेक्ष कीमत या लागतों द्वारा समायोजित एनईईआर एक

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) होता है, जो आमतौर पर घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर में दिखाई देता है। वैचारिक रूप से प्रभावी विनिमय दर (ईईआर) क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की परिकल्पना पर आधारित है (बलासा, 1964; फ्रूट और रोजोफ, 1994; सर्नो और टेलर, 2002)।

रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के एनईईआर और आरईईआर (व्यापार और निर्यात-भारित दोनों) के सूचकांकों का संकलन और प्रसार करता है तथा इसकी नवीनतम श्रृंखला को 2004-05 को आधार वर्ष रखते हुए बनाया गया है।² आधार वर्ष 2004-05 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और भारत के व्यापारिक भागीदारों के महत्व के सापेक्ष बदलाव के कारण मुद्राओं के वर्तमान समूह और भार-निर्धारण योजना की समीक्षा की आवश्यकता है। एक 'सामान्य' वर्ष में भारत के समष्टि-आर्थिक और बाह्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन के आधार पर, नीर (एनईईआर)/ रीर(आरईईआर) सूचकांकों के लिए 2015-16 को नए आधार वर्ष के रूप में चुना गया है। भारत के विदेशी व्यापार में उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के बढ़ते महत्व और बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता में हो रहे बदलावों को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए, नीर/रीर का कवरेज 36 से बढ़ाकर 40 मुद्राओं तक किया गया है। एनईईआर/ आरईईआर के नए सूचकांक 2004-05 के बाद से पुरानी श्रृंखला को बदल देंगे।

आलेख के शेष भाग का संयोजन निम्नानुसार है: खंड II में 2015-16 को नए आधार वर्ष के रूप में चुनने के औचित्य पर चर्चा की गई है। खंड III में नये मुद्रा समूह में मुद्राओं के चयन के लिए कार्यक्षेत्र और मानदंड बताए गए हैं और नया भार आरेख प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद खंड IV में एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों की संगणना के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई है। खंड V में एनईईआर / आरईआर सूचकांकों की नई श्रृंखला से तैयार किए जा सकने वाले मुख्य निष्कर्षों के विश्लेषण की चर्चा की गई है और इसके बाद समापन टिप्पणियाँ और कुछ नीतिगत परिप्रेक्ष्य दिये गए हैं।

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के जॉन वी गुरिया और जितेंद्र सोकल द्वारा तैयार किया गया है। आनंद शंकर द्वारा योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित है। डॉ. राजीव जैन के बहुमूल्य सुझावों के लिए लेखकों की ओर से धन्यवाद।

¹ सिंगापुर में विनिमय दर आधारित मौद्रिक नीति ढांचा है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) सिंगापुर डॉलर के सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) को परिचालन लक्ष्य के रूप में उपयोग करती है। यह एनईईआर को नीति सीमा (पॉलिसी बैंड) के भीतर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है (देखें, एमएएस, 2013)।

² रिजर्व बैंक अप्रैल 2014 से अपने मासिक बुलेटिन और अन्य प्रकाशनों में 6-और 36-मुद्राओं के समूह के लिए सीपीआई आधारित आरईईआर के सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के अप्रैल 2014 अंक में प्रकाशित 'भारत के लिए मूल्य सूचकांक के रूप में सीपीआई पर आधारित वास्तविक प्रभावी विनिमय दर' शीर्षक आलेख का संदर्भ है।

II. आधार वर्ष का चयन

एनईईआर और आरईईआर के सूचकांकों के निर्माण / रिबेसिंग (पुनर्निर्धारण) के लिए एक उपयुक्त आधार वर्ष तय करने के लिए समष्टि-आर्थिक और बाह्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया ताकि व्यापक तौर पर उसका आंतरिक और बाह्य संतुलन (बैलेंस) के साथ सामंजस्य हो।³ आंतरिक संतुलन (बैलेंस) का तात्पर्य है कि वास्तविक उत्पादन अपने संभावित स्तर पर या उसके करीब है, और मुद्रास्फीति निम्न है और त्वरणशील नहीं है (वोंग, 2002)। बाह्य संतुलन (बैलेंस) एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूंजी के अंतर्वाह से चालू खाता शेष धारणीय बना रहता है, और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ पर्याप्त और अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं (मोर्टीएल, 2002; वोंग, 2002)। इन परिभाषाओं के आधार पर, एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों के आधार के पुनर्निर्धारण के लिए 2015-16 को उपयुक्त वर्ष पाया गया, जिसमें वास्तविक जीडीपी विकास दर 8.0 प्रतिशत, सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत और चालू खाता घाटा (सीएडी) जीडीपी का 1.1 प्रतिशत है।

III. कवरेज और मुद्राओं का चयन

भारत के बदलते विदेशी व्यापार के स्वरूप को दर्शाते हुए, नए आधार वर्ष यानी 2015-16 के लिए एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों का कवरेज 36 से बढ़ाकर 40 मुद्राओं तक किया गया है।

नयी एनईईआर/आरईईआर शृंखला के लिए मुद्राओं का चयन दो प्रमुख मानदंडों पर आधारित है। सबसे पहले, अत्यधिक उच्च और अस्थिर मुद्रास्फीति वाले व्यापारिक भागीदारों को बाहर रखा गया है क्योंकि उनकी मुद्राएं तेजी से नामिक (नॉमिनल) गिरावट दर्ज करती हैं जिससे एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों की स्थिरता कम होती है और बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता के मूल्यांकन में उनकी उपयोगिता को अस्पष्ट कर देती है।⁴ दूसरा, व्यापारिक भागीदारों की मुद्रास्फीति और विनिमय दरों का डेटा नियमित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

³ मैक्रोइकोनॉमिक बैलेंस रीयल एक्सचेंज रेट की अवधारणा और आंतरिक और बाह्य संतुलन के साथ इसके आदान-प्रदान पर विस्तृत चर्चा के लिए वोंग (2002) देखें।

⁴ तदनुसार, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार होने के बावजूद, नए एनईईआर/आरईईआर समूह में शामिल नहीं हैं।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, द्विपक्षीय पण्य वस्तु व्यापार श्रेणियों को 2014-15 से 2016-17 (अर्थात् 2015-16 के आसपास पर केंद्रित) की अवधि के लिए प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार प्रवाहों के तीन-वर्ष के अंकगणितीय औसत के रूप में निकाला गया है। प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के द्विपक्षीय व्यापार श्रेणियों के विकास ने आठ नये देशों यानी अंगोला, चिली, घाना, इराक, नेपाल, ओमान, तंजानिया और यूक्रेन को 40 मुद्राओं के समूह में शामिल किया। पहले की 36 मुद्राओं के समूह में शामिल चार देश अर्थात् अर्जेंटीना, पाकिस्तान, फिलीपींस और स्वीडन प्रतिस्थापित कर दिए गए। भारत के कुल व्यापार में मौजूदा देशों द्वारा 1.4 प्रतिशत हिस्से की तुलना में आठ नये देशों का 5.4 प्रतिशत का व्यापारिक हिस्सा है। भारत के कुल व्यापार में 36 मुद्राओं के समूह के 84 प्रतिशत व्यापार की तुलना में नई एनईईआर/आरईईआर 88 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत के विदेशी व्यापार के गतिशील स्वरूप को प्रतिबिंबित करने के लिए रुपये के एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों की गणना करने के लिए समय परिवर्ती के द्विपक्षीय व्यापार भार का उपयोग किया जाता है।⁵ व्यापार आधारित मुद्रा भार प्राप्त करने के लिए, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान व्यापारिक साझेदारों के साथ भारत के व्यापार (निर्यात और आयात) के ज्यामितीय माध्य की गणना की जाती है और फिर इसे 100 तक सामान्यीकृत (जेनरलाइज्ड) कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 2020-21 के लिए भार पूर्ववर्ती तीन वर्षों 2017-18 से 2019-20 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार प्रवाह के ज्यामितीय माध्य पर आधारित हैं (सारणी 1)। नये व्यापार-भारित समूह पर उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) की मुद्राओं का वर्चस्व है। व्यापार-समूह में जहाँ यूरो क्षेत्र ने अपनी शीर्ष स्थिति को बरकरार रखा है, वहीं 2015-16 में निर्यात-समूह में सबसे अधिक भार अमेरिका का है।

⁵ द्विपक्षीय व्यापार भार योजना के तहत, घरेलू अर्थव्यवस्था के कुल व्यापार प्रवाह में उस व्यापारिक साझेदार के व्यापार प्रवाह के अनुपात के अनुसार प्रत्येक मुद्रा को एक भार सौंपा जाता है।

सारणी 1: एनईईआर/ आरईईआर की नयी 40 मुद्राओं का समूह- सामान्यीकृत भार

(प्रतिशत)

देश/ क्षेत्र	2015-16		2020-21 (अनंतिम)	
	व्यापार आधारित भार	निर्यात आधारित भार	व्यापार आधारित भार	निर्यात आधारित भार
1. यूरो क्षेत्र	11.4	14.0	11.6	14.7
2. चीन	10.0	5.0	12.0	5.6
3. यूई	9.4	12.4	7.8	10.4
4. संयुक्त राष्ट्र	9.1	14.7	11.6	18.4
5. सऊदी अरब	6.4	4.1	4.4	2.1
6. स्विट्जरलैंड	3.7	0.5	2.7	0.4
7. हांगकांग	2.9	4.8	3.9	4.6
8. इंडोनेशिया	2.9	1.8	2.8	1.6
9. सिंगापुर	2.8	4.4	3.2	3.7
10. इराक	2.7	0.4	3.2	0.6
11. कोरिया	2.5	1.6	2.9	1.7
12. कुवैत	2.5	0.4	1.3	0.5
13. जापान	2.5	2.3	2.3	1.7
14. कतर	2.4	0.3	1.5	0.5
15. नाइजीरिया	2.3	1.0	1.8	1.0
16. यूनाइटेड किंगडम	2.2	3.5	2.2	3.3
17. मलेशिया	2.2	1.8	2.2	2.2
18. ईरान	2.1	1.5	1.4	1.1
19. ऑस्ट्रेलिया	2.0	0.9	2.2	1.2
20. दक्षिण अफ्रीका	1.8	1.9	1.5	1.4
21. ब्राजील	1.5	2.2	1.1	1.3
22. थाईलैंड	1.3	1.4	1.6	1.5
23. वियतनाम	1.1	1.9	1.8	2.3
24. बांग्लादेश	0.9	2.2	1.3	3.1
25. ताइवान	0.9	0.9	0.9	0.8
26. अंगोला	0.9	0.2	0.6	0.1
27. रूस	0.9	0.8	1.3	0.9
28. तुर्की	0.9	1.7	1.0	1.9
29. मेक्सिको	0.9	0.8	1.2	1.3
30. इजराइल	0.9	1.3	0.7	1.3
31. श्रीलंका	0.8	1.9	0.7	1.6
32. कनाडा	0.8	0.8	0.9	1.0
33. मिस्र	0.7	1.1	0.6	0.9
34. ओमान	0.7	1.0	0.8	0.8
35. नेपाल	0.6	1.4	1.1	2.6
36. केन्या	0.6	1.5	0.3	0.7
37. तंजानिया	0.5	1.0	0.4	0.6
38. चिली	0.5	0.2	0.3	0.3
39. यूक्रेन	0.4	0.2	0.4	0.1
40. घाना	0.2	0.3	0.5	0.2
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

मेमो मदें:

ईई मुद्राएँ	41.7	49.7	45.0	52.6
ईएमडीई मुद्राएँ	58.3	50.3	55.0	47.4

ईई: उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ। ईएमडीई: उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ।

पी: अनंतिम।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना

IV. कार्यप्रणाली

एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों की गणना करने की पद्धति निम्नानुसार है:

एनईईआर की गणना व्यापारिक साझेदार मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा की द्विपक्षीय विनिमय दरों के ज्यामितीय भारित औसत के रूप में की जाती है। विशेष रूप से, नीर (एनईईआर) की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

$$\text{एनईईआर} = \prod_{i=1}^n \left(\frac{e}{e_i}\right)^{w_i} \quad (1)$$

और आरईईआर, जो विदेशी कीमतों के घरेलू कीमतों के भारित औसत द्वारा समायोजित एनईआर है, की गणना निम्नानुसार की जाती है:

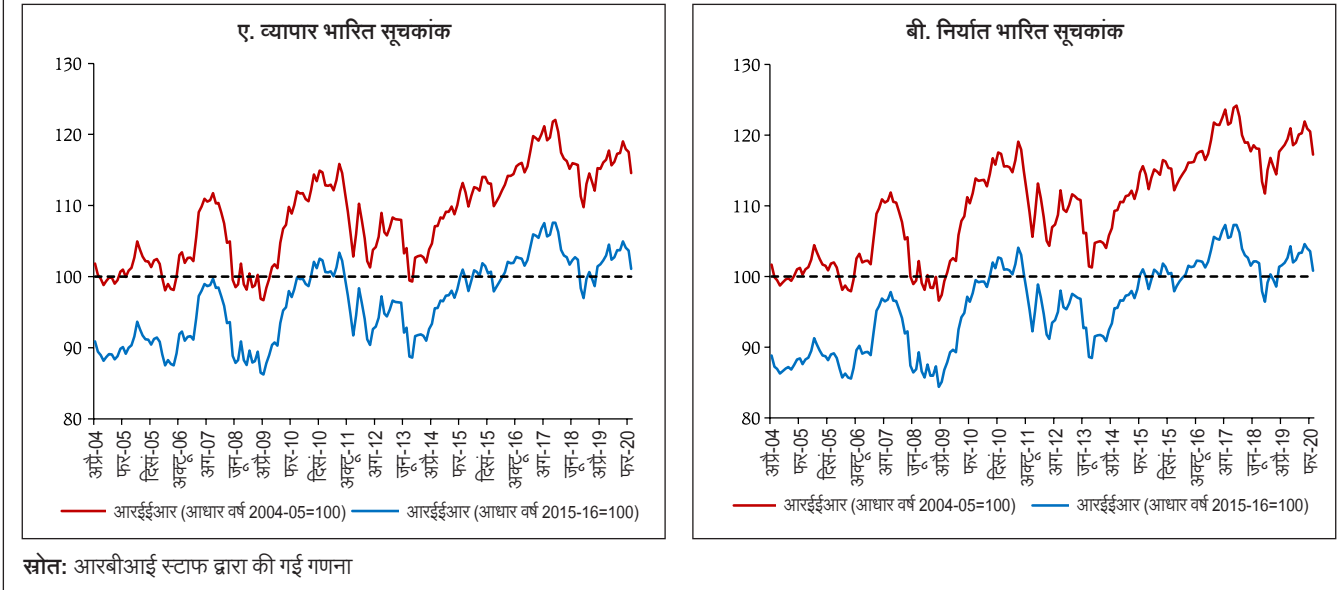
$$\text{आरईईआर} = \prod_{i=1}^n \left[\left(\frac{e}{e_i}\right) \left(\frac{P}{P_i}\right)\right]^{w_i} \quad (2)$$

जहाँ 'e' एक मूल्यमान पर रुपये की विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि, सूचकांक रूप में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) है, और 'e_i' जो सूचकांक रूप में मूल्यमान पर विदेशी मुद्रा 'i' की विनिमय दर है। 'e' या 'e/e_i' में वृद्धि मुद्रा 'i' के सापेक्ष रुपये का अधिमूल्यन दर्शाता है और विलोमतः। 'P' और 'P_i' क्रमशः घरेलू अर्थव्यवस्था और व्यापारिक साझेदारों के मूल्य सूचकांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'w_i' व्यापार/ निर्यात आधारित भार जो विदेशी मुद्रा/ व्यापारिक साझेदारों को सौंपा गया है, जबकि 'n' एनईईआर/ आरईईआर समूह में शामिल मुद्राओं (घरेलू मुद्रा के अलावा) की संख्या है।

V. नए एनईईआर/ आरईईआर सूचकांकों का कार्य-निष्पादन

नयी 40 मुद्राओं वाले एनईईआर/आरईईआर सूचकांक (व्यापार और निर्यात-भारित दोनों) और पुरानी 36-मुद्राओं वाली श्रृंखला, लगभग 1 के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध गुणांक के आसपास ही हैं (परिशिष्ट सारणी 1)। नए आरईईआर सूचकांक (व्यापार और निर्यात-भारित दोनों), जो न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) (जो कि आधार वर्ष मूल्य=100) के आसपास बने हुए हैं, नवंबर 2015 से मई 2019 (चार्ट्स 1ए और 1बी, और परिशिष्ट सारणियाँ 2 और 3) की अवधि के दौरान पुरानी श्रृंखला के सापेक्ष मामूली मूल्यवृद्धि/ उच्चतर मूल्यहास दर्शाते हैं।

चार्ट 1: आरईआईआर सूचकांक- नयी और पुरानी शृंखला

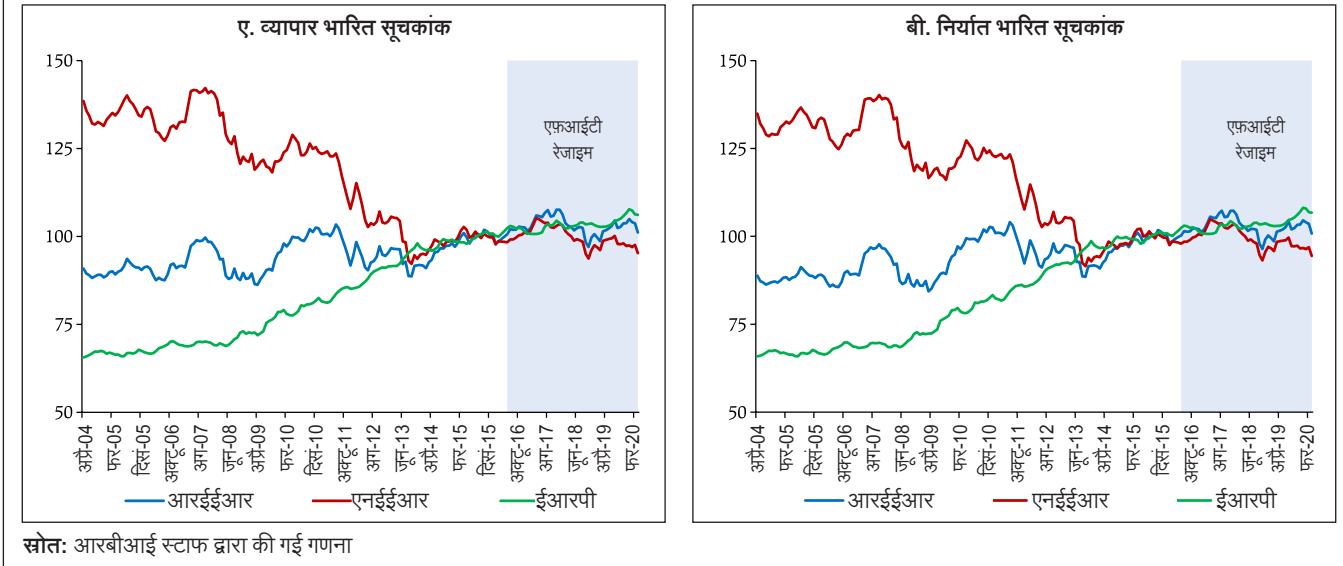


V.1. मुद्रास्फीति अंतर और आरईआईआर

एनईआईआर में आरईआईआर का अपघटन और भारत औसत या प्रभावी सापेक्ष मूल्य (ईआरपी)⁶ यह दर्शाता है कि हालिया वर्षों में मुद्रास्फीति के अंतर मोटे तौर पर स्थिर रहे हैं, वहीं 2008-09

से 2014-15 के दौरान सतत वृद्धि हुई है (चार्ट 2ए और 2बी, और परिशिष्ट सारणी 4)। इसे रिजर्व बैंक द्वारा जून 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को औपचारिक रूप से

चार्ट 2: मुद्रास्फीति के अंतर और आरईआईआर (आधार वर्ष 2015-16=100)



⁶ जोशी (1984) ने वेट के लिए 'प्रभावी सापेक्ष मूल्य (ईआरपी) शब्द का इस्तेमाल तत्संबंधी कीमतों के भारत औसत के लिए किया है।

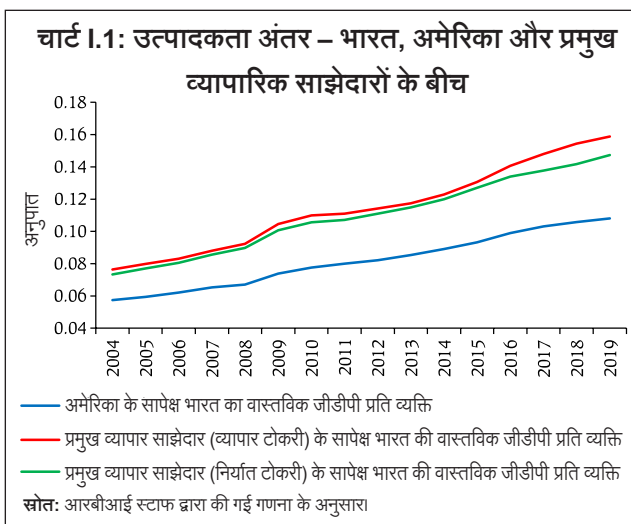
अपनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कीमत को स्थिर बनाए रखने का अधिदेश (सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ +/- 2 प्रतिशत के आसपास की सहन सीमा के साथ परिभाषित), जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति कम हुई है और एफआईटी में मुद्रास्फीति की उम्मीदों को बढ़ाया है (आइकेनग्रीन, गुप्ता और चौधरी, 2020)। औसत सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 2009-10 से 2015-16 के दौरान 8 प्रतिशत से अधिक थी जबकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान घटकर 4 प्रतिशत से भी कम हो गयी घटकर (अर्थात् वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एफआईटी पूर्व की अवधि)।

एनईआईआर नमूना अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के अंतर के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सहसंबंध 0.95 गुणांक का है। यह पीपीपी परिकल्पना के मूल आधार के अनुरूप है, जिसके अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच मुद्रास्फीति के अंतर में वृद्धि से घरेलू मुद्रा का मूल्यहास होता है और विलोमतः (कैगिनाप, 1982;) कार्बो, 2002; सॉयर और स्प्रिंकल, 2015)। नए आरईआईआर सूचकांकों ने 2004-05 के बाद से प्रशंसनीय रुझान दिखाया है, जो भारत की बढ़ती उत्पादकता के समक्ष उसके व्यापारिक साझेदार, यानी बलासा-सैमुअलसन प्रभाव (बॉक्स I) को दर्शाते हैं।

बॉक्स-I: बालस्सा समुएलसन प्रभाव और नया आरईआईआर

बालस्सा समुएलसन परिकल्पना (बालस्सा, 1964; समुएलसन, 1964) का मानक संस्करण मानता है, कि क्रय शक्ति समतुल्यता (पीपीपी) केवल लंबे समय में व्यापारिक माल के लिए है, और साथ ही भविष्यवाणी करता है, कि व्यापार बनाम गैर व्यापार माल की सापेक्ष उत्पादकता में वृद्धि एक (तेजी से बढ़ते हुए) देश और इसके व्यापार साझेदार की घरेलू मुद्रा की वास्तविक विनिमय दर के अभिमूल्यन को प्रेरित करते हैं। (इतो एवं अन्य, 1997; चौधरी और शम्बरी 2009; बोर्डो एवं अन्य, 2014) अनुभवजन्य साहित्य में वास्तविक विनिमय दर और उत्पादकता अंतर के बीच संबंधों की पुष्टि की गयी है। (चौधरी और खान, 2005; रिक्की एवं अन्य, 2008; मेशूलम और सनेफी, 2019)

बालस्सा (1964), रोगोफ़ (1996) और चोंग और अन्य (2010) के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अमरीका तथा प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के समूह (अमरीका सहित) के सापेक्ष उत्पादकता अंतर के लिए एक प्रॉक्सि के रूप में लिया जाता है। 2004 से 2019 के डेटा का उपयोग करते हुए, भारत का वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पीपीपी के संदर्भ में (2017 के स्थिर अंतरराष्ट्रीय डॉलर पर) भारत और इसके व्यापारिक साझेदारों के लिए, (जो पुराने और नए एनईआईआर /आरईआईआर बास्केट दोनों में हैं) ऐसा देखा गया कि अमेरिका तथा इसके मुख्य साझेदारों के सापेक्ष भारत की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आय 2004 से बढ़ी है (चार्ट I.1)। 2004-05 से 2019-20 के अनुभवजन्य विश्लेषण के लिए नए आरईआईआर सूचकांकों (व्यापार और निर्यात भारत) पर जो मासिक डेटा है उसका उपयोग किया जाता है।



आरईआईआर और सापेक्ष वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी के बीच संबंध सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। इकाई रूट परीक्षण परिणाम बताते हैं कि चर अंतर स्थिर है, अर्थात् क्रम 1 से एकीकृत (परिशिष्ट सारणी 5)।

उत्पादकता अंतर से वास्तविक विनिमय दर तक कार्य-कारण की दिशा में साक्ष्य साहित्य में समर्थित है ; हालांकि अनुभवजन्य साहित्य का एक और किनारा उत्पादकता पर वास्तविक विनिमय दर में बदलाव के प्रभाव के समर्थन में सबूत प्रदान करता है। (हैरिस, 2001; गुड्ल्लौमोंट, जेयन्नेने और हुय, 2003; फुंग, 2008)

(जारी...)

¹ पीपीपी के संदर्भ में भारत और इसके प्रमुख व्यापारिक साझेदार की प्रति व्यक्ति जीडीपी (स्थिर अंतरराष्ट्रीय डॉलर 2017) विश्व बैंक की विश्व विकास संकेतक के डेटाबेस से ली गयी है। ताइवान की प्रति व्यक्ति जीडीपी का डेटा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ भारत के 31 प्रमुख साझेदार विश्लेषण में शामिल हैं (आरईआईआर/एनईआईआर के बास्केट के कुल व्यापार भार का 93% प्रतिनिधित्व)।

सारणी 1.1: उत्पादकता अंतर और नयी आरईआर के बीच संबंध
(नमूना अवधि: 2004M04 से 2020M03)

	एलपीडीयूस	एलपीडीएमपीटी	एलपीडीएमपीएक्स
एलआरईआरटी	0.76*	0.76*	-
एलआरईआरएक्स	0.81*	-	0.80*

एलआरईआरटी: लॉग(आरईआर) (व्यापार भारत)

एलआरईआरएक्स: लॉग (आरईआर) (निर्यात भारत)

एलपीडीयूस: लॉग (अमेरिका के सापेक्ष भारत की वास्तविक जीडीपी प्रति व्यक्ति);
एलपीडीएमपीटी: लॉग [भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी के सापेक्ष प्रमुख
व्यापार साझेदार (व्यापार समूह)]

एलपीडीएमपीएक्स: लॉग [भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति जीडीपी के सापेक्ष प्रमुख
व्यापार साझेदार (निर्यात टोकरी)]

*1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण संकेत

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना के अनुसार।

उत्पादकता पर वास्तविक विनिमय दर में परिवर्तन के प्रभाव पर साहित्य का तर्क है कि वास्तविक विनिमय दर की सराहना आयातित पूंजीगत वस्तुओं की लागत को कम करती है। और पूंजी श्रम अनुपात को बढ़ाती है, जिससे तकनीकी प्रगति और उत्पादकता में वृद्धि होती है। वास्तविक विनिमय दर में सराहना भी वास्तविक मजदूरी में वृद्धि को प्रेरित कर सकती है, और इस प्रकार ऐसे देश में श्रम उत्पादकता जहां अकुशल श्रमिकों की मजदूरी आपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा, वास्तविक विनिमय दर में सराहना विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती है, जिससे तकनीकी दक्षता और कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है।

साहित्य में वास्तविक विनिमय दर और उत्पादकता अंतर के बीच द्वि-दिशात्मक कारण के साक्ष्य को देखते हुए, नयी आरईआर और उत्पादकता अंतर के लिए एक वेक्टर ऑटोरेगेशन (वीएआर) ग्रेंजर कारण परीक्षण किया जाता है।

परिणाम बताते हैं कि इन चर सारणी 1.2 (चर सारणी) के बीच द्वि-दिशात्मक ग्रेंजर कारण हैं।

सारणी 1.2: ग्रेंजर कॉजुयलिटी टेस्ट परिणाम @
(नमूना अवधि: 2004M04 से 2020M03)

निर्भर चर	Δएलआरईआरटी	Δएलआरईआरएक्स	Δएलपीडीयूस	Δएलपीडीएमपीटी	Δएलपीडीएमपीएक्स
Δएलआरईआरटी	-	-	27.42**	27.61*	-
Δएलआरईआरएक्स	-	-	28.60**	-	34.89**
Δएलपीडीयूस	22.62*	23.29*	-	-	-
Δएलपीडीएमपीटी	26.68*	-	-	-	-
Δएलपीडीएमपीएक्स	-	25.99*	-	-	-

@: पंजीकृत आंकड़े ची-वर्ग (χ^2) आंकड़े हैं। इष्टतम अंतराल लंबाई आधारित है।
अर्थात् सूचना मानदंड पर (एकाईसी)।

Δ: पहला अंतर ऑपरेटर।

**और * दर्शाता है 1% और 5% के स्तर पर महत्वपूर्ण संकेत।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान

आरईआर के लिए उत्पादकता अंतर से कार्य-कारण की दिशा बालस्सा समुलसन परिकल्पना की पुष्टि करता है, जबकि आरईआर से उत्पादकता अंतर तक कार्य-कारण की दिशा भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक विनिमय दर संचालित उत्पादकता वृद्धि का संकेत देती है।

अनुभवजन्य साहित्य में, आरईआर बाहरी व्यापार संतुलन को ठीक करने में विनिमय दर की प्रभावकारिता को कम करने के लिए मार्शल-लर्नर की स्थिति का आकलन करने में सक्षम एक उपयोगी संस्करण के रूप में कार्य करता है। भारतीय संदर्भ में सिंग (2010) और आरबीआई (2015), ने पाया कि दूसरों के बीच मार्शल लेमर की स्थिति मजबूत है। आरबीआई (2015) ने अनुमान लगाया कि निर्यात की वास्तविक विनिमय दर (कीमत) की मूल्य सापेक्षता 0.7 से 0.9 की सीमा में होगी। जबकि आयात की मूल्य सापेक्षता 0.3 से 0.5 सीमा में पाया जाता है। इसके विपरीत रेस्सी और तुलिन (2015), और चीनोय और जैन (2015) जैसे अध्ययनों ने पाया कि निर्यात की वास्तविक विनिमय दर मूल्य सापेक्षता 0.9 से 2.3 की सीमा में थोड़ी अधिक है।

VI. निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ और नीतिगत परिप्रेक्ष्य

फ्लोटिंग विनिमय दरों को अपनाने के बाद से, ईईआर विदेशी व्यापार-योग्य क्षेत्रों की तुलना में किसी अर्थव्यवस्था के व्यापार योग्य क्षेत्रों की बाह्य प्रतिस्पर्धा का एक प्रमुख त्वरित/संक्षिप्त माप (समरी मेज़र) बन गए हैं। नीति निर्माताओं के लिए आरईआर की गति, घरेलू मुद्रा की विनिमय दर के किसी भी तरह के समग्र असामंजस्य में एक उपयोगी दिशा सूचक की तरह काम करती है। दरअसल, मुद्राओं के अधिक/कम मूल्यांकन का मुद्दा हमेशा से वैश्विक व्यापार विवाद के मूल में रहा है। अंतर्राष्ट्रीय

मुद्रा कोष किसी अर्थव्यवस्था के बाह्य संतुलन (एक्सटर्नल बैलेंस) आकलन के लिए तथा चालू खाते और वास्तविक विनिमय दर मानदंडों व अंतरालों के लिए बहुपक्षीय रूप से सुसंगत अनुमान के लिए आरईआर मॉडल (चालू खाता मॉडल के साथ) का उपयोग करता है।

इस तथ्य को देखते हुए कि वैश्विक व्यापार वातावरण एक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि रुपये के एनईआर /आरईआर समूह की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। भारत के मामले में, व्यापारिक साझेदारों का सापेक्षिक

महत्व 2004-2005 से मुख्यतः ईएमडीई की ओर स्थानांतरित हो गया है। इन कारकों का संज्ञान लेते हुए रुपए के एनईईआर/आरईईआर सूचकांकों का व्यापक समूह 36 से बढ़ाकर 40 किया गया और 2015-16 में रिबेस किया गया। नया आरईईआर औसत आधार पर 2016-17 से 2019-20 के दौरान अपने आधार वर्ष के स्तर से 0.8 प्रतिशत ऊपर था। यह वही अवधि है जब एफ़आईटी ढांचे को अपनाने के बाद मुद्रास्फीति में नरमी देखी गई। इसका तात्पर्य है कि एफ़आईटी व्यवस्था में भारत और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति अंतराल भारत की बाह्य स्पर्धात्मकता के लिए उतनी चिंता का विषय नहीं था। आगे चलकर, बड़े पूँजी प्रवाह जब तक चालू खाता घाटे के माध्यम से पूरी तरह से अवशोषित नहीं किए जाते और/या विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में समेटे नहीं लिए जाते, तब तक रुपये का अधिमूल्यन कर सकते हैं, और संभावित रूप से निर्यात प्रतिस्पर्धा को कम कर सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में एफ़आईटी व्यवस्था के तहत मूल्य स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करना नीतिगत प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए, ताकि नामिक तौर पर रुपये के अधिमूल्यन से बाह्य स्पर्धात्मकता में होने वाले क्षरण की भरपाई की जा सके।

संदर्भ

Balassa, B. (1964), "The purchasing-power parity doctrine: A reappraisal", *Journal of Political Economy*, 72(6), 584-596.

Bordo, M. D., Choudhri, E. U., Fazio, G. and MacDonald, R. (2014), "The real exchange rate in the long run: Balassa-Samuelson effects reconsidered", *NBER Working Paper Series*, No. 20228.

Caginalp, O. A. (1982), "Inflation differentials and exchange rate: Theory and empirical evidence", *Nebraska Journal of Economics and Business*, 21(4), 19-31.

Carbaugh, R. J. (2002), *International economics*, South-Western, Thomson Learning.

Chong, Y., Jordà, Ò. and Taylor, A. M. (2010), "The Harrod-Balassa-Samuelson hypothesis: Real exchange rates and their long-run equilibrium", *NBER Working Paper Series*, No. 15868.

Choudhri, E. U. and Schembri, L. L. (2009), "Productivity, the terms of trade, and the real exchange rate: The Balassa-Samuelson hypothesis revisited", Bank of Canada Working Paper 2009-22.

Choudhri, E. U. and Khan, M. S. (2005), "Real exchange rates in developing countries: Are Balassa-Samuelson effects present", *IMF Staff Papers*, 52(3), 387-409.

Chinoy, S. Z. and Jain, T. (2019), "What drives India's exports and what explains the recent slowdown? New evidence and policy implications", in S. Shah, B. Bosworth and K. Muralidharan (eds), *India Policy Forum 2018*, National Council of Applied Economic Research, 15(1), 217-256.

Eichengreen, B., Gupta, P. and Choudhary, R. (2020), "Inflation targeting in India: An interim assessment", Policy Research Working Paper 9422, World Bank Group.

Froot, K. A. and Rogoff, K. (1994), "Perspectives on PPP and long-run real exchange rates", *NBER Working Paper Series*, No. 4952.

Fung, L. (2008), "Large real exchange rate movements, firm dynamics, and productivity growth", *Canadian Journal of Economics*, 41(2).

Harris, R. G. (2001), "Is there a case for exchange rate induced productivity changes?", Centre for International Economic Studies, Discussion Paper No. 0110, Adelaide University.

Hsing, Yu (2010), "Test of the Marshall-Lerner condition for eight selected Asian countries and policy implications", *Global Economic Review*, 39(1), 91-98.

Ito, T., Isard, P. and Symansky, S. (1997), "Economic growth and real exchange rate: An overview of the Balassa-Samuelson hypothesis in Asia", *NBER Working Paper Series*, No. 5979.

Guillaumont Jeanneney, S. and Hua, P. (2003), "Real exchange rate and productivity in China", Document

de travail de la série, CERDI, *Etudes et Documents*, Ec 2003.28, Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement International.

Joshi, V. (1984), "The nominal and real effective exchange rate of the Indian rupee 1971-83", *Reserve Bank of India Occasional Papers*, 5(1), 27-87.

Meshulam, D. and Sanfey, P. (2019), "The determinants of real exchange rates in transition economies", Working Paper No. 228, European Bank for Reconstruction and Development.

Monetary Authority of Singapore (2013), *Monetary policy operations in Singapore*, Monetary Authority of Singapore.

Montiel, P.J. (2002), "The long-run equilibrium exchange rate: Theory and measurement", in M. S. Khan, S. M. Nsouli and Chorng-Huey Wong (eds), *Macroeconomic Management – Programs and Policies*, IMF Institute, International Monetary Fund.

Raissi, M. and Tulin, V. (2015), "Price and income elasticity of Indian exports – The role of supply-side bottlenecks", IMF Working Paper, No. WP/15/161.

Reserve Bank of India (2015), *Annual Report 2014-15*, Reserve Bank of India.

Ricci, L. A., Milesi-Ferretti, G. M. and Lee, J. (2008), "Real exchange rates and fundamentals: A cross-country perspective", IMF Working Paper, No. WP/08/13.

Rogoff, K. (1996), "The purchasing power parity puzzle", *Journal of Economic Literature*, XXXIV, 647-668.

Samuelson, P. A. (1964), "Theoretical notes on trade problems", *The Review of Economics and Statistics*, 46(2), 145-154.

Sarno, L. and Taylor, M. P. (2002), "Purchasing power parity and the real exchange rate", *IMF Staff Papers*, 49(1).

Sawyer, W. C. and R. L. Sprinkle (2015), *Applied international economics*, Routledge, Taylor & Francis Group: London and New York.

Wong, Chorng-Huey (2002), "Adjustment and internal-external balance", in M. S. Khan, S. M. Nsouli and Chorng-Huey Wong (eds), *Macroeconomic Management – Programs and Policies*, IMF Institute, International Monetary Fund.

परिशिष्ट सारणी 1: एनईआर / आरईआर सूचकांक-नयी और पुरानी शृंखला

ए. एनईआर सूचकांक				
वर्ष	व्यापार भारत		निर्यात भारत	
	आधार वर्ष: 2004-05 = 100	आधार वर्ष: 2015-16 = 100	आधार वर्ष: 2004-05 = 100	आधार वर्ष: 2015-16 = 100
2004-05	100.0	133.8	100.0	130.8
2005-06	102.2	136.8	102.2	133.7
2006-07	97.6	130.6	98.0	128.2
2007-08	104.8	140.1	105.6	138.1
2008-09	93.3	124.9	94.0	123.0
2009-10	90.9	121.6	91.4	119.6
2010-11	93.5	125.1	94.7	123.9
2011-12	87.4	116.9	89.1	116.6
2012-13	78.3	104.8	80.1	104.7
2013-14	72.3	96.7	73.6	96.2
2014-15	74.1	99.1	75.2	98.4
2015-16	74.8	100.0	76.4	100.0
2016-17	74.7	100.1	76.4	99.6
2017-18	76.9	103.2	78.9	103.1
2018-19 (पी)	72.6	97.5	74.2	97.1
2019-20 (पी)	73.3	98.0	74.3	97.4
बी. आरईआर सूचकांक				
वर्ष	व्यापार भारत		निर्यात भारत	
	आधार वर्ष: 2004-05 = 100	आधार वर्ष: 2015-16 = 100	आधार वर्ष: 2004-05 = 100	आधार वर्ष: 2015-16 = 100
2004-05	100.0	89.2	100.0	87.4
2005-06	102.4	91.3	102.0	89.1
2006-07	100.8	89.9	100.5	87.8
2007-08	109.2	97.4	109.2	95.4
2008-09	99.6	88.9	99.7	87.1
2009-10	103.9	92.7	105.0	91.7
2010-11	112.7	100.5	115.0	100.5
2011-12	110.3	98.4	113.2	98.9
2012-13	105.6	94.2	108.7	95.0
2013-14	103.3	92.1	105.5	92.2
2014-15	109.0	97.2	111.2	97.2
2015-16	112.1	100.0	114.4	100.0
2016-17	114.5	101.8	116.4	101.4
2017-18	119.7	105.9	121.9	105.7
2018-19 (पी)	114.0	100.6	116.3	100.3
2019-20 (पी)	116.8	103.2	119.6	102.8

पी: अनंतिम

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना के अनुसार।

परिशिष्ट सारणी 2: एनईईआर सूचकांक (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
ए. व्यापार भारत सूचकांक												
2004-05	138.5	135.8	134.2	132.1	131.8	132.6	132.0	131.4	133.2	134.1	135.1	134.4
2005-06	135.5	137.0	138.8	140.1	138.4	137.6	136.2	134.4	134.1	136.1	136.8	136.3
2006-07	133.3	129.9	129.4	128.1	127.1	128.7	131.0	131.5	130.6	132.4	132.6	132.5
2007-08	137.0	141.3	141.7	141.5	140.8	141.2	142.2	140.7	141.3	140.7	138.9	134.3
2008-09	135.2	129.1	127.1	126.2	128.5	123.8	120.6	122.7	121.6	121.2	123.4	119.0
2009-10	119.9	121.2	121.8	119.8	119.5	118.2	121.3	121.3	121.9	123.9	124.5	126.5
2010-11	128.9	127.8	126.6	123.1	123.1	124.2	126.4	124.9	125.4	124.0	123.5	123.7
2011-12	124.2	122.8	122.7	123.6	121.1	117.2	114.0	110.7	107.8	111.0	115.2	112.4
2012-13	108.8	104.7	102.7	103.8	103.3	104.2	107.1	103.9	103.7	104.3	105.6	105.3
2013-14	105.2	104.4	98.6	98.4	93.1	92.2	94.7	93.6	94.8	95.1	94.7	96.2
2014-15	97.4	99.1	98.6	98.2	97.3	98.4	98.6	98.9	98.5	99.7	101.7	102.7
2015-16	101.9	99.6	100.1	101.4	100.3	99.5	100.8	100.1	99.7	99.8	97.7	98.7
2016-17	98.5	98.5	98.3	99.2	99.1	99.7	100.3	100.5	101.2	100.7	101.6	103.4
2017-18	105.2	104.9	104.3	103.8	103.9	102.6	102.4	103.0	103.6	103.1	101.5	100.7
2018-19 (पी)	100.0	98.8	99.2	98.9	98.5	95.1	93.7	96.1	97.5	96.9	96.1	98.7
2019-20 (पी)	99.0	99.3	99.4	100.1	97.9	97.8	98.1	97.3	97.4	96.9	97.6	95.3
बी. निर्यात भारत सूचकांक												
2004-05	134.9	132.1	130.8	128.9	128.4	129.2	129.0	129.0	131.1	131.8	132.6	132.1
2005-06	132.9	134.3	135.7	136.7	135.4	134.5	132.8	131.0	130.8	133.1	133.7	133.3
2006-07	130.6	127.7	126.9	125.6	124.8	126.1	128.3	129.2	128.5	130.0	130.3	130.3
2007-08	134.6	138.9	139.2	139.3	138.4	139.0	140.2	139.0	139.3	139.1	137.5	133.3
2008-09	133.8	127.6	125.7	125.0	126.9	122.1	118.6	120.4	119.4	118.7	120.9	116.6
2009-10	117.6	119.0	119.5	117.5	117.2	116.1	119.3	119.3	119.9	122.0	122.7	124.9
2010-11	127.3	126.1	125.0	122.3	121.6	122.9	125.2	123.7	124.5	123.1	122.6	123.0
2011-12	123.4	122.1	122.2	123.3	121.0	117.0	113.8	110.5	107.6	110.8	114.8	112.3
2012-13	108.8	104.6	102.6	103.7	103.3	104.1	107.0	103.9	103.7	104.2	105.5	105.1
2013-14	105.3	104.4	98.7	97.7	92.4	91.5	93.9	92.9	94.1	94.3	94.0	95.5
2014-15	96.7	98.5	97.9	97.5	96.6	97.8	97.9	98.1	97.6	98.9	101.1	102.1
2015-16	102.1	99.9	100.4	101.5	100.3	99.4	100.8	100.1	99.6	99.6	97.5	98.6
2016-17	98.4	98.2	97.9	98.5	98.5	99.0	99.7	99.9	100.7	100.3	101.2	103.0
2017-18	104.9	104.5	104.0	103.5	103.7	102.5	102.2	102.8	103.4	103.1	101.6	100.7
2018-19 (पी)	100.0	98.7	99.2	98.4	98.0	94.7	93.1	95.6	97.0	96.6	95.8	98.4
2019-20 (पी)	98.6	98.7	98.9	99.7	97.2	97.1	97.3	96.6	96.7	96.4	96.9	94.4

पी: अनंतिम

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना के अनुसार

परिशिष्ट सारणी 3: आरईआईआर सूचकांक (आधार वर्ष: 2015-16 = 100)

	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च
ए. व्यापार भारत सूचकांक												
2004-05	90.9	89.4	88.9	88.2	88.7	89.1	89.1	88.4	88.8	89.9	90.1	89.2
2005-06	90.0	90.3	91.6	93.7	92.6	91.8	91.2	91.1	90.4	91.2	91.4	90.8
2006-07	89.0	87.5	88.3	87.7	87.5	89.2	91.9	92.3	91.0	91.5	91.6	91.1
2007-08	94.2	97.3	98.0	99.0	98.7	98.8	99.7	98.4	98.5	97.3	95.9	93.5
2008-09	93.6	88.8	87.9	88.2	90.9	88.3	87.6	89.6	87.9	88.1	89.5	86.5
2009-10	86.2	87.8	88.9	90.4	90.8	90.3	93.5	95.3	95.7	98.0	97.1	98.2
2010-11	99.9	99.7	99.7	99.0	98.7	100.1	102.1	101.2	102.5	102.3	100.7	100.6
2011-12	100.8	100.0	101.3	103.4	102.2	99.8	97.3	94.8	91.7	94.6	98.4	96.3
2012-13	94.0	91.2	90.4	92.6	93.0	94.2	97.2	94.8	94.4	95.4	96.7	96.4
2013-14	96.4	96.3	92.1	92.8	88.7	88.6	91.6	91.8	91.9	91.7	91.0	92.6
2014-15	93.4	95.5	95.6	96.7	96.5	97.3	97.4	98.0	97.0	98.2	100.0	101.0
2015-16	99.8	98.0	99.4	100.9	100.6	100.1	101.9	101.5	100.4	100.7	97.9	98.6
2016-17	99.2	99.9	100.6	102.1	101.9	101.9	102.8	102.6	102.5	101.6	102.3	104.1
2017-18	106.0	105.7	105.5	106.7	107.5	105.6	105.9	107.6	107.6	106.3	103.8	103.0
2018-19 (पी)	102.8	101.7	102.3	102.7	102.4	98.4	97.0	99.6	100.6	99.7	98.6	101.4
2019-20 (पी)	101.7	102.3	103.0	104.5	102.4	102.7	103.7	103.7	105.0	104.1	103.7	101.0
बी. निर्यात भारत सूचकांक												
2004-05	88.8	87.2	86.9	86.3	86.6	87.0	87.2	86.8	87.5	88.2	88.4	87.6
2005-06	88.2	88.5	89.4	91.3	90.4	89.5	88.8	88.7	88.1	89.0	89.1	88.5
2006-07	86.9	85.7	86.2	85.7	85.5	87.0	89.6	90.2	89.1	89.3	89.3	88.9
2007-08	92.0	95.1	95.8	96.9	96.5	96.7	97.8	96.6	96.5	95.3	94.1	91.9
2008-09	92.2	87.4	86.4	86.9	89.3	86.6	85.7	87.6	86.0	85.9	87.3	84.4
2009-10	85.1	86.8	87.9	89.3	89.6	89.3	92.5	94.2	94.8	97.1	96.4	97.6
2010-11	99.5	99.2	99.3	99.3	98.5	100.0	102.0	101.2	102.7	102.5	100.9	101.0
2011-12	100.9	100.3	101.7	104.0	103.0	100.4	97.9	95.3	92.2	95.1	98.8	97.0
2012-13	94.7	91.8	91.1	93.5	93.8	95.0	98.0	95.6	95.3	96.2	97.5	97.3
2013-14	97.0	96.8	92.7	92.7	88.6	88.5	91.5	91.6	91.7	91.5	90.9	92.4
2014-15	93.3	95.5	95.6	96.6	96.6	97.3	97.4	98.0	96.9	98.2	100.2	101.0
2015-16	100.0	98.2	99.5	101.0	100.6	100.0	101.8	101.4	100.3	100.5	97.9	98.7
2016-17	99.3	99.8	100.2	101.5	101.3	101.4	102.2	102.2	102.1	101.2	102.0	103.7
2017-18	105.6	105.3	105.2	106.5	107.3	105.5	105.6	107.3	107.3	106.2	103.9	103.0
2018-19 (पी)	102.6	101.5	102.1	102.1	101.8	97.9	96.4	99.1	100.3	99.5	98.6	101.3
2019-20 (पी)	101.6	101.9	102.6	104.3	102.0	102.3	103.3	103.3	104.6	104.0	103.6	100.7

पी: अंतिम

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना के अनुसार

परिशिष्ट सारणी 4: मुद्रास्फीति अंतर और आरईईआर
(आधार वर्ष : 2015-16 = 100)

वर्ष	व्यापार भारत सूचकांक			निर्यात भारत सूचकांक		
	आरईईआर	एनईईआर	ईआरपी	आरईईआर	एनईईआर	ईआरपी
2004-05	89.2	133.8	66.7	87.4	130.7	66.8
2005-06	91.3	136.8	66.8	89.1	133.7	66.7
2006-07	89.9	130.6	68.8	87.8	128.2	68.5
2007-08	97.4	140.1	69.5	95.4	138.1	69.1
2008-09	88.9	124.9	71.2	87.1	123.0	70.9
2009-10	92.7	121.6	76.2	91.7	119.6	76.7
2010-11	100.5	125.1	80.4	100.5	123.9	81.1
2011-12	98.4	116.9	84.2	98.9	116.6	84.9
2012-13	94.2	104.8	89.9	95.0	104.7	90.7
2013-14	92.1	96.7	95.3	92.2	96.2	95.9
2014-15	97.2	99.1	98.1	97.2	98.4	98.8
2015-16	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2016-17	101.8	100.1	101.7	101.4	99.6	101.8
2017-18	105.9	103.2	102.6	105.7	103.1	102.6
2018-19 (पी)	100.5	97.4	103.2	100.3	97.1	103.2
2019-20 (पी)	103.2	98.0	105.3	102.8	97.4	105.6

पी: अन्तिम

स्रोत: आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना के अनुसार।

परिशिष्ट सारणी 5: यूनिट रूट टेस्ट परिणाम

चर	स्तर					
	निरंतर			निरंतर, प्रवृत्ति		
	एडीएफ़	पीपी	केपीएसएस	एडीएफ़	पीपी	केपीएसएस
एलआरईईआरटी	-1.94	-2.05	1.20	-3.31	-2.88	0.05**
एलआरईईआरएक्स	-1.78	-1.89	1.31	-3.22	-2.74	0.05**
एलपीडीयूएस	-1.62	-1.09	1.69	-1.64	-3.51*	0.23
एलपीडीएमपीटी	-1.29	-0.89	1.67	-2.52	-3.27	0.16**
एलपीडीएमपीएक्स	-1.68	-1.44	1.68	-1.57	-2.68	0.33
चर	प्रारंभिक अंतर					
	निरंतर			निरंतर, प्रवृत्ति		
	एडीएफ़	पीपी	केपीएसएस	एडीएफ़	पीपी	केपीएसएस
एलआरईईआरटी	-12.05**	-11.96**	0.03**	-12.02**	-11.93**	0.03**
एलआरईईआरएक्स	-11.81**	-11.72**	0.04**	-11.78**	-11.69**	0.03**
एलपीडीयूएस	-2.20	-16.96**	0.15**	-2.55	-17.27**	0.07**
एलपीडीएमपीटी	-2.23	-17.03**	0.11**	-2.36	-17.15**	0.06**
एलपीडीएमपीएक्स	-2.31	-16.97**	0.20**	-2.70	-17.16**	0.05**

** और * क्रमशः 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं।

एडीएफ़; संवर्धित डिकी-फुलर

पीपी-फिलिप्स पेरोन

केपीएसएस-क्वियताकोव्स्क- फिलिप्स शिमिट-शिना

स्रोत; आरबीआई स्टाफ द्वारा की गयी गणना अनुसार।

लघु वित्त बैंक: वित्तीय समावेशन और व्यवहार्यता को संतुलित करना*

लघु वित्त बैंक वित्तीय समावेशन पर एक अलग फोकस के साथ भारतीय बैंकिंग प्रणाली में नए हैं। उन्होंने स्वस्थ संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखने और परिसंपत्तियों पर उच्च प्रतिफल पैदा करते हुए अपने शाखा नेटवर्क और परिसंपत्ति आधार में तेजी से वृद्धि देखी है। ये बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे अल्प-सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुँचने में यथोचित रूप से सफल रहे हैं, और इनकी ऋण की छोटी जरूरतों वाले उधारकर्ताओं तक प्रभावशाली कवरेज है।

परिचय

2005 से, भारत ने वित्तीय समावेशन की नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है। इस नीति के भाग के रूप में, रिजर्व बैंक ने कई उपाय किए हैं, जिसमें बैंक क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ खोलना, व्यवसाय संवाददाताओं और सुविधाकर्ताओं में बैंकिंग की अंतिम कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और छोटे व्यवसाय खाते खोलना शामिल हैं। वित्तीय साक्षरता के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड 2010 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाओं की शुरुआत ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों को एक निश्चित दिशा और संरचना दी है। 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के हिस्से के रूप में उन लोगों के साथ वित्तीय समावेशन योजना के उद्देश्यों ने इन प्रयासों को एक मिशन मोड प्रदान किया है।

नए उत्पादों और प्लेटफार्मों को पेश करने के प्रयासों के साथ-साथ, रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थागत संस्करण पेश किए हैं। ऐसा ही एक संस्थान लघु वित्त बैंक (एसएफबी) रहा है। एसएफबी को सौंपा गया विशिष्ट मैनडेट वित्तीय समावेशन को निम्नलिखित द्वारा बढ़ाने के लिए है (i) सेविंग वेहिकल्स उपलब्ध कराना, और (ii) लघु और

सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों सहित लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की आपूर्ति; और अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयाँ, और विभिन्न निम्न आय समूह और उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत वाले अभियानों के माध्यम से प्रवासी कार्य बल।¹ लघु वित्त जरूरतों के साथ आबादी की सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, इन्हें विभेदित वित्तीय संस्थानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, और इस प्रकार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से भिन्न हैं – इन बैंकिंग संस्थानों को मुख्य रूप से सरकारी अंशधारिता के साथ अंडर-सर्विस् सेक्शन को शामिल करने के उद्देश्य से बनाया गया है।²

2014 में लाइसेंसिंग दिशानिर्देश जारी करने के बाद, अब तक 10 एसएफबी ने परिचालन शुरू किया है। पहले दो, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2016 में परिचालन शुरू किया, इसके बाद 2017 में सात और 2018 में एक और ने परिचालन शुरू किया। अधिकांश एसएफबी पहले माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) थे, जिनमें कुछ उल्लेखनीय अपवाद थे, जैसे कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो एक स्थानीय क्षेत्र का बैंक था। एमएफआई के रूप में, इनमें से अधिकांश संस्थानों में पहले से ही ग्राहकों का एक विकसित नेटवर्क था, जो ज्यादातर मध्यम और निम्न-आय वर्ग के थे। इन एमएफआई ने अपनी पहुंच को और अधिक विस्तारित करने के लिए स्वयं को एसएफबी में परिवर्तित कर दिया, जबकि अपनी पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए धन की कम लागत से लाभान्वित हुए ताकि वे एसएफबी के रूप में आनंद ले सकें।

यह आलेख वित्तीय समावेशन के अपने उद्देश्य और अपने व्यवसाय मॉडल की व्यवहार्यता के विशिष्ट संदर्भ के साथ एसएफबी के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। इसके अलावा, विभिन्न नियामक दिशा-निर्देशों का अनुपालन, जहाँ भी सीधे औसत दर्जे का है, की भी जांच की जाती है। हालांकि उनकी स्थापना के बाद से अपेक्षाकृत कम समय की कमी के कारण,

* भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग से ऋचा सराफ और पल्लवी चव्हाण द्वारा तैयार किया गया। व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और उनके विचार उस संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जिससे वे संबद्ध हैं।

¹ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति, "निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश", 27 नवंबर 2014।

² आरआरबी का मूल अधिदेश विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों सहित ग्रामीण गरीबों की क्रेडिट जरूरतों को पूरा करना था, माहेश्वरी (1995) देखें।

विश्लेषण इन संस्थानों के संचालन को आकार देने के तरीके पर प्रकाश डाल सकता है।

इस लेख के लिए उपयोग किए गए डेटा को विभिन्न पर्यवेक्षी रिटर्न, मूल सांख्यिकीय रिटर्न ऑफ क्रेडिट और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) (बीएसआर -1 और बीएसआर -2) के जमा के साथ ही शाखा बैंकिंग सांख्यिकी से लिया जाता है। अध्ययन की अवधि जून 2016 से शुरू होती है, जब पहले एसएफबी ने अपना संचालन शुरू किया था। हालांकि एसएफबी के नमूने का आकार अध्ययन अवधि में भिन्न होता है, लेकिन 2018 से इस अवधि को तुलनीय माना जा सकता है क्योंकि अधिकांश एसएफबी ने 2017-18 के दौरान अपना संचालन शुरू किया था।

लेख के बाकी हिस्सों को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के रूप में एसएफबी को नियंत्रित करने वाले नियामक दिशानिर्देशों का अवलोकन प्रदान करता है। खंड III अपने बैंक और गैर-बैंक समकक्षों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में एसएफबी के संचालन के आकार और पैमाने के बारे में कुछ संकेतक प्रदान करता है। खंड IV एसएफबी पर पर्यवेक्षी और बैंकिंग डेटा के विश्लेषण से महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और खंड V समापन करता है।

II. एसएफबी के लिए विनियामक दिशानिर्देशों का संक्षिप्त अवलोकन

एसएफबी, जो एससीबी के रूप में काम करते हैं, अन्य एससीबी के समान विवेकपूर्ण विनियामक मानदंडों के अधीन हैं। हालांकि, उनके व्यवसाय की प्रकृति में अंतर होने के कारण कुछ अंतर हैं। एसएफबी के लिए ये इन विभेदित दिशानिर्देशों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- (i) एक विभेदित या निश बैंक होने के नाते, एसएफबी के लिए न्यूनतम नेट वर्थ अन्य एससीबी की तुलना में निचले स्तर पर तय किया गया है। अन्य एससीबी के लिए 5 बिलियन की तुलना में एसएफबी को न्यूनतम नेट वर्थ 2 बिलियन (इन बैंकों के लिए ऑन-टैप

लाइसेंसिंग के लिए दिशानिर्देश जारी करने के बाद 1 बिलियन से बढ़ा दिया गया) की आवश्यकता है; ³

- (ii) वित्तीय समावेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, एसएफबी को अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एनबीसी) का कम से कम 75 प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रदान करना है, जबकि अन्य एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के मामले में यह 40 प्रतिशत है।
- (iii) छोटे आकार के ऋण पर उनके ध्यान को देखते हुए, उनके ऋण पोर्टफोलियो के कम से कम 50 प्रतिशत में 25 लाख तक के ऋण शामिल होने चाहिए ;
- (iv) निहित व्यावसायिक जोखिमों के मद्देनजर, एसएफबी के लिए पूंजी की तुलना में जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को न्यूनतम 15 प्रतिशत तय किया गया है।

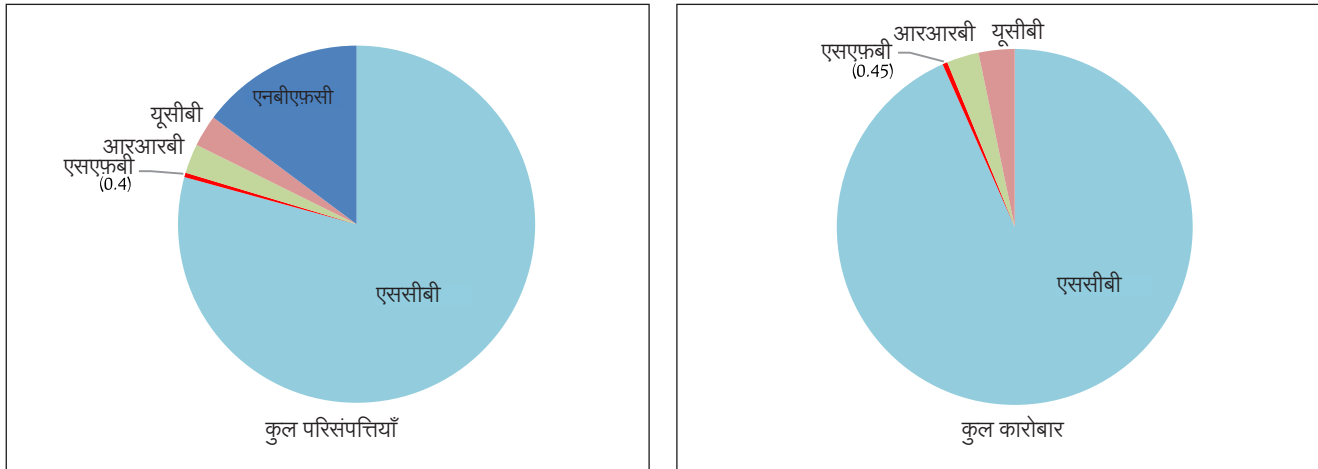
III. बैंकिंग और गैर-बैंकिंग सेगमेंट की तुलना में एसएफबी

वर्तमान में, एसएफबी वित्तीय क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा (एससीबी (आरआरबी और यूसीबी सहित) और एनबीएफसी खंड शामिल है) (चार्ट 1) का गठन करते हैं। मार्च 2019 में वित्तीय क्षेत्र की कुल संपत्ति में एसएफबी की हिस्सेदारी 0.4 प्रतिशत थी। 2018-19 में, एसएफबी के बैंकिंग कारोबार का अनुपात आरआरबी जो एक अन्य बैंकिंग संस्थान है, के संबंध में 15 प्रतिशत था, जिसका लक्ष्य अलग ही था।

कम आधार से शुरू होकर, एसएफबी ने अपनी शाखा उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है, जो मार्च 2020 तक 4,307 शाखाओं तक पहुंच गया। एससीबी शाखाओं (आरआरबी को छोड़कर) में एसएफबी शाखाओं का अनुपात मार्च 2020 में 1

³ इस विनियामक आवश्यकता का अपवाद ऐसे शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) हैं जो स्वेच्छा से स्वयं को एसएफबी में परिवर्तित करना चाहते हैं; ऐसे यूसीबी के लिए न्यूनतम निवल मूल्य की आवश्यकता रु. 1 बिलियन है।

चार्ट 1 : कुल परिसंपत्तियों और बैंकिंग कारोबार में एसएफबी की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)



टिप्पणियाँ: 1) कुल कारोबार = कुल जमा + कुल क्रेडिट
 2) एससीबी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक
 3) मार्च 2019 के आंकड़ों के आधार पर।
स्रोत : पर्यवेक्षी विवरणियाँ

प्रतिशत की तुलना में मार्च 2020 में 3.5 प्रतिशत था। (चार्ट 2)।
 मार्च 2020 में आरआरबी शाखाओं के लिए एसएफबी शाखाओं का अनुपात लगभग 20 प्रतिशत था।

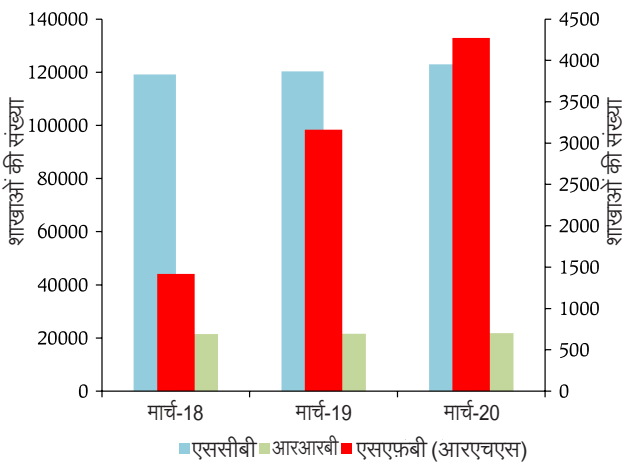
IV. एसएफबी के परिचालन की प्रमुख विशेषताएं संरचनात्मक विशेषताएं

एसएफबी के भीतर कंसंट्रेशन की उच्च डिग्री

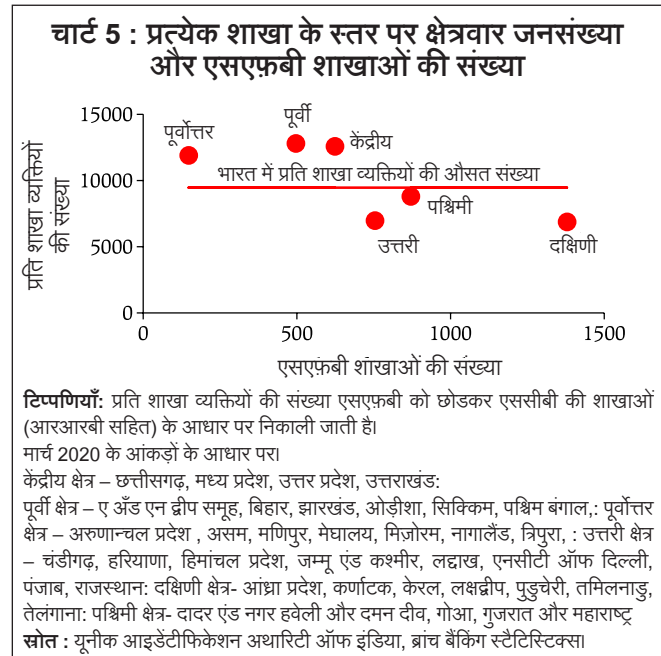
एसएफबी ने अपनी स्थापना के बाद से उच्च परिसंपत्ति वृद्धि दिखाई है। 2017 और 2020 के बीच, एसएफबी की परिसंपत्ति की औसत वृद्धि कम आधार के कारण प्रति वर्ष लगभग 150 प्रतिशत थी, क्योंकि अधिकांश एसएफबी ने 2017-18 में अपना परिचालन शुरू किया था। औसत वृद्धि 2018 और 2020 के बीच कम होकर लगभग 61 प्रतिशत रही।

वर्तमान में, एसएफबी समूह के भीतर परिसंपत्ति की काफी मात्रा है। मार्च 2020 में सभी एसएफबी की कुल संपत्ति का 46% हिस्सा टॉप-दो एसएफबी के पास था और 60% शेयर (चार्ट 3) टॉप-तीन एसएफबी की पास था। तथापि, अपेक्षाकृत बड़े आकार के एसएफबी ने हाल के वर्षों (चार्ट 4) में परिसंपत्ति की कम वृद्धि को प्रदर्शित किया है। अतः एसएफबी समूह के भीतर परिसंपत्तियों की मात्रा समय के साथ कम हो सकती है।

चार्ट 2 : अन्य एससीबी के साथ एसएफबी की बैंक शाखाओं की तुलना



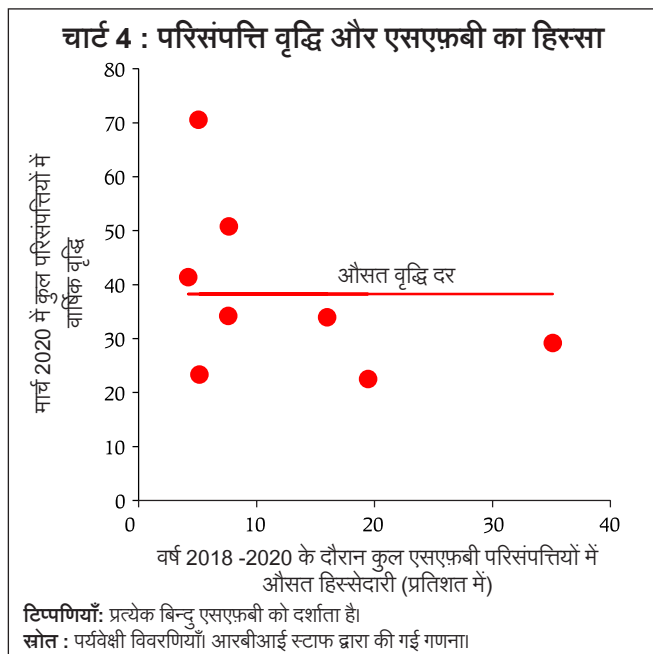
टिप्पणियाँ: एससीबी में केवल पीएसबी, पीवीबी और एफबी शामिल है।
स्रोत : ब्रांच बैंकिंग सांख्यिकी



क्षेत्रीय और खंडीय विशेषताएँ

अपेक्षाकृत बैंकों की बेहतर सुविधा से युक्त राज्यों में शाखा नेटवर्क की अधिक संख्या

अपनी स्थापना के बाद से एसएफबी के शाखा नेटवर्क में तेजी से वृद्धि हुई है, यह विकास मुख्य रूप से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से केंद्रित किया गया है,

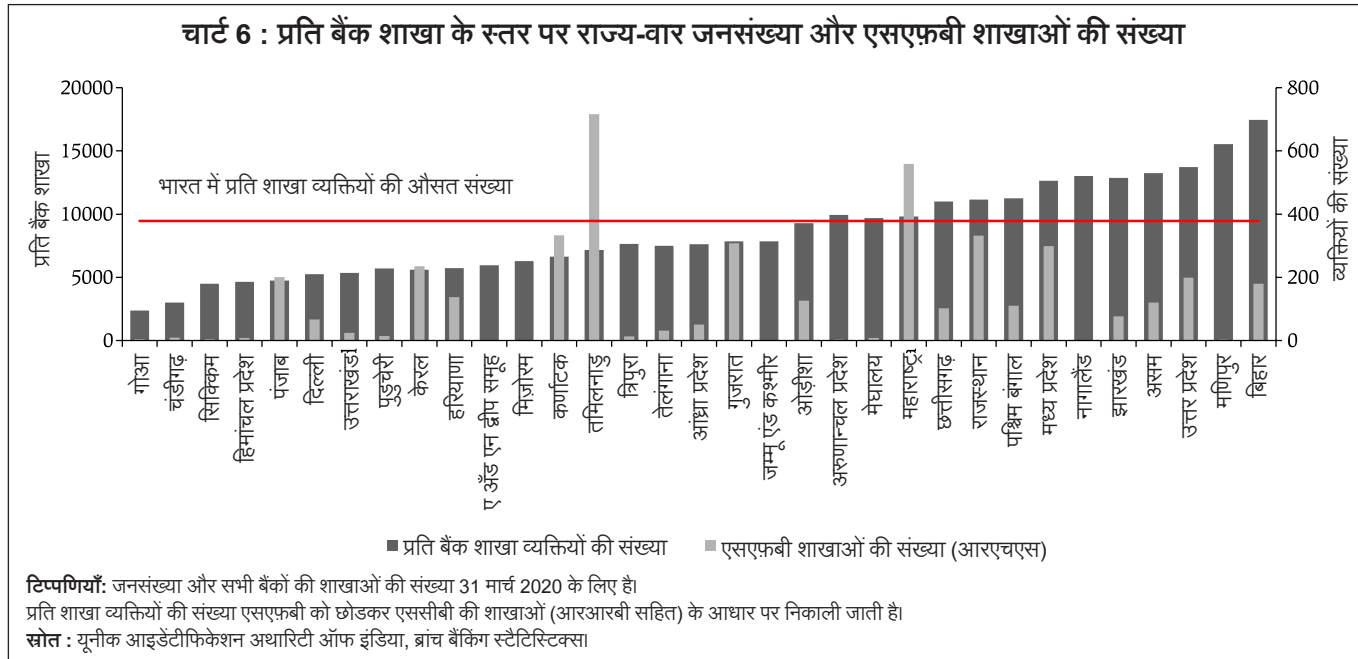


जिनमें देश में अपेक्षाकृत बैंकों की बेहतर सुविधा से युक्त वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है (चार्ट 5)। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इनकी पैठ है, जिसे बैंकों की कम सुविधा से युक्त वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

राज्य स्तर पर, जबकि एसएफबी मध्यप्रदेश और राजस्थान के कुछ कम सेवा वाले राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पंजाब में केंद्रित हैं – ऐसे राज्य जो प्रति बैंक शाखा सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं (चार्ट 6)। इनमें से, दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में एमएफआई की मात्रा 1990 के दशक की शुरुआत से ही अधिक थी (गोलाइत और कुमार, 2009) जब भारत में सूक्ष्म वित्त की उत्पत्ति हुई। एसएफबी भी, जिनमें से कई एमएफआई बैंकों में बदल गए हैं, ने बड़े पैमाने पर शाखा विस्तार के इस पैटर्न का पालन किया है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों और एसएफबी की शाखाओं के विस्तार में कुछ समानता दिखाई देती है, दोनों ही अपेक्षाकृत बैंकों की बेहतर सुविधा से युक्त क्षेत्रों/ राज्यों (परिशिष्ट तालिका 1) में अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं।

अर्ध-शहरी केंद्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना

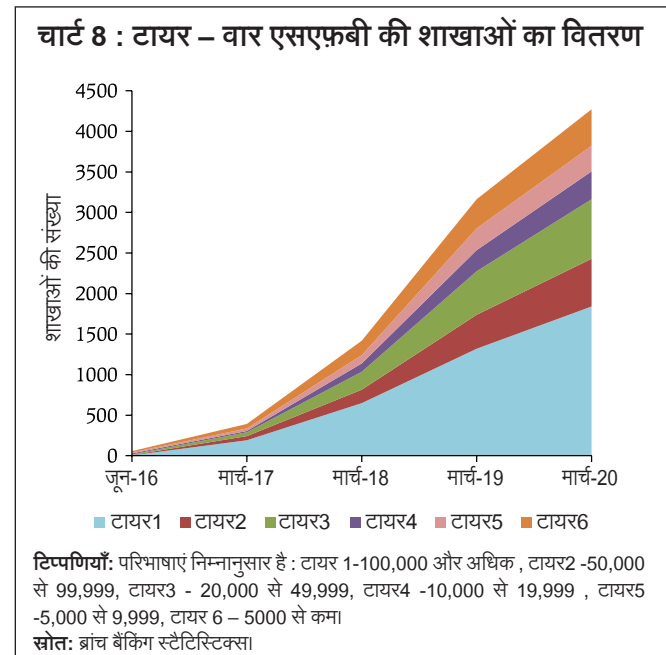
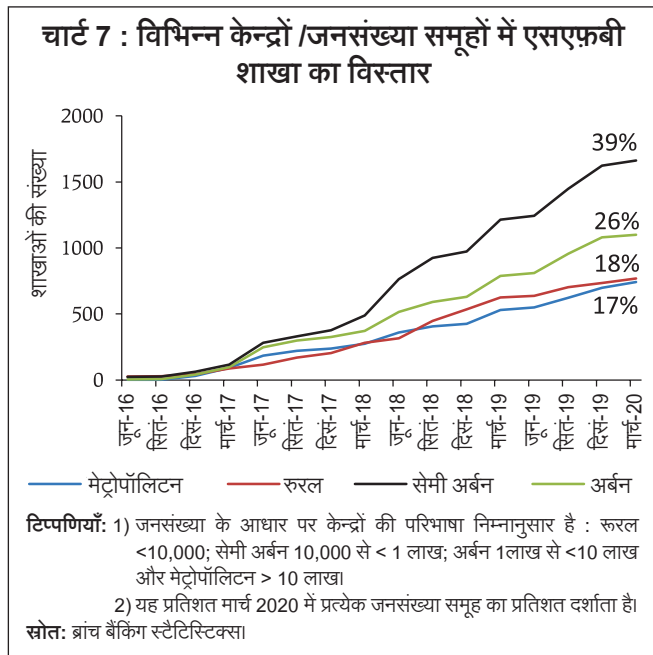
एसएफबी शाखाओं की तेजी से वृद्धि अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में हुई है; मार्च 2020 में, कुल एसएफबी शाखाओं का लगभग



39 प्रतिशत हिस्सा अर्ध-शहरी प्रकृति का था और शहरी केंद्रों (चार्ट 7) में यह 26 प्रतिशत था।

जैसा कि अर्ध-शहरी श्रेणी में 10,000 से 1 लाख की आबादी वाले केंद्र शामिल हैं, काफी व्यापक रूप से केंद्रों को शामिल करते हुए, एसएफबी के लिए शाखाओं के एक स्तरीय वितरण का प्रयास किया गया है। यह बताता है कि एसएफबी की लगभग 31 प्रतिशत

शाखाएं टायर 2 और 3 केंद्रों में स्थित हैं (जिनकी जनसंख्या 20,000 और 1 लाख के बीच है), और लगभग 8 प्रतिशत शाखाएं टायर 4 केंद्रों में स्थित हैं (जनसंख्या 10,000 और 19,999 के बीच), टायर 5 और 6 केंद्र (ग्रामीण) (10,000 से कम जनसंख्या) में एसएफबी शाखाओं (चार्ट 8) की केवल 18 प्रतिशत उपस्थिति है। केवल तीन एसएफबी के मामले में, ग्रामीण शाखाओं की कुल हिस्सेदारी मार्च 2020 तक 25 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि

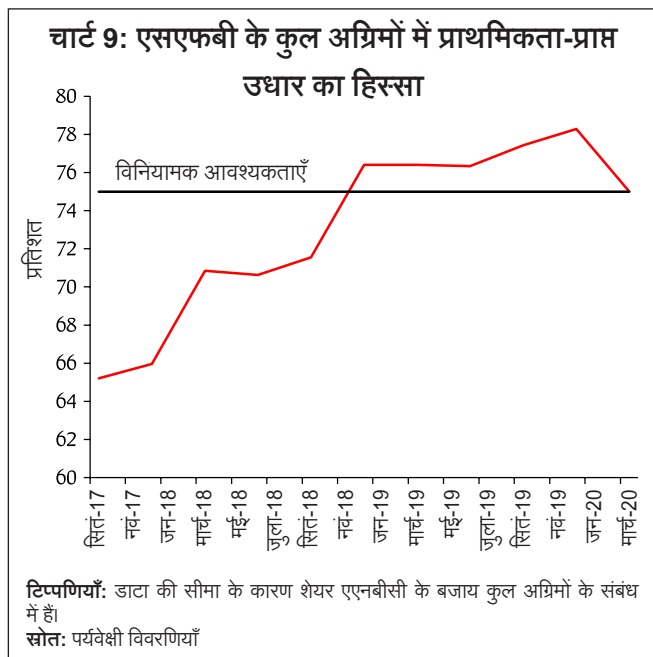


अन्य के संबंध में यह हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के बीच थी। उनके लघु वित्त पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार करते हुए, ग्रामीण केंद्रों और यहां तक कि छोटे अर्ध-शहरी केंद्रों पर एसएफबी के सीमित प्रसार के संबंध में बहुत कुछ विचार किया जा सकता है।

दिलचस्प रूप से फिर से, एसएफबी निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के समान शाखा वितरण पैटर्न दर्शाते हैं; मार्च 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ पीवीबी की कुल शाखाओं में अर्ध-शहरी केंद्रों की हिस्सेदारी लगभग 32 प्रतिशत थी।

उधार पोर्टफोलियो में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की प्रमुख उपस्थिति

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र-उधार के विभिन्न लक्ष्यों को देखते हुए और यह तथ्य भी कि उनमें से अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं (एमएफआई) के रूप में जनसंख्या के कम सेवा-प्राप्त आर्थिक क्षेत्रों/वर्गों की सेवा कर रहे थे, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) ने अपने उधार पोर्टफोलियो में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों की प्रमुख उपस्थिति देखी है (चार्ट-9)। प्रणालीगत स्तर पर, एसएफबी के कुल ऋण का लगभग 75% हिस्सा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जाता है। बैंक के स्तर पर भी अधिकांश एसएफबी में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के 75% से अधिक के अंश के साथ-साथ थोड़ा बदलाव था (तालिका-1)।



तालिका 1: प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार के शेयर के अनुसार एसएफबी का वितरण

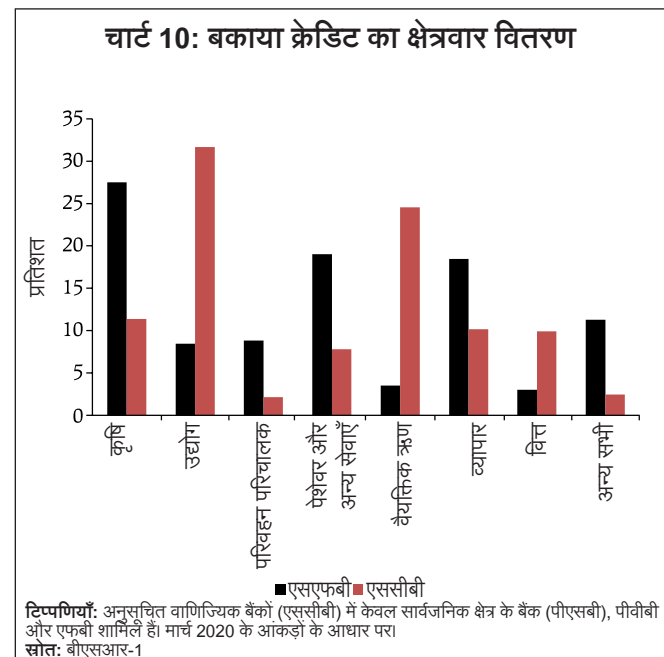
कुल अग्रिमों में पीएसएल का हिस्सा*	लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) का प्रतिशत
> =75%	60
50% = < & <75%	40

* आकार श्रेणियाँ और रिपोर्ट किए गए शेयर मार्च 2020 के डेटा पर आधारित हैं। अधिकांश एसएफबी 75 प्रतिशत के लक्ष्य के ऊपर या उसके बहुत करीब हैं।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा अपेक्षाकृत कम-सेवा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों को लक्षित करने वाले लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) ने कृषि, व्यापार और पेशेवर सेवाओं के क्षेत्र में अधिक मात्रा में ऋण प्रदान किए। मार्च 2020 में लघु वित्त बैंकों के कुल ऋण का लगभग 65% हिस्सा (इन तीन क्षेत्रों) में रहा, जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने इसी अवधि में उनके कुल ऋण का लगभग 66% हिस्सा उद्योग, व्यक्तिगत ऋण और वित्त के लिए उधार दिया (चार्ट 10)। यह देखते हुए कि एसएफबी को उनके डिजाइन के अनुसार छोटे आकार के ऋणों का विस्तार करने की अपेक्षा की गई थी, यह मानना गलत नहीं होगा कि उन्होंने लघु कृषकों, छोटे व्यापारियों और लघु व्यवसायों को वित्त पोषित किया। वास्तव में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की समग्र ऋण पोर्टफोलियो के साथ-साथ औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो में प्रमुख उपस्थिति थी (तालिका 2)।



तालिका 2: कुल ऋण में एमएसएमई हिस्सेदारी

वर्ष	एसएफबी (%)	एससीबी (%)
मार्च 2018	42 (81)	17
मार्च 2019	40 (83)	18
मार्च 2020	41 (82)	17

टिप्पणियाँ: उद्योग और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई के शेयरों में क्रेडिट कोष्ठकों में दिखाये गए हैं।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), पीवीबी और एफबी शामिल हैं।

मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ

ऋण पोर्टफोलियो में छोटे आकार के ऋणों का बड़ा हिस्सा

एसएफबी अपने ऋण पोर्टफोलियो के आकार-वार वितरण से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। मार्च 2020 में उनके कुल ऋण खातों और कुल ऋण राशि के क्रमशः 99.9% और 83% की ऋण सीमा रु. पच्चीस लाख तक थी। इन ऋणों में भी, इन बैंकों द्वारा बहुत छोटे आकार के ऋणों पर स्पष्ट ध्यान था। उनके कुल ऋण खातों और कुल ऋण की राशि की लगभग क्रमशः 96% और 48% ऋण सीमा रु. दो लाख थी,

जो लघु उधार खाते (स्माल बोरोवल अकाउंट) कहलाते हैं (चार्ट 11)।

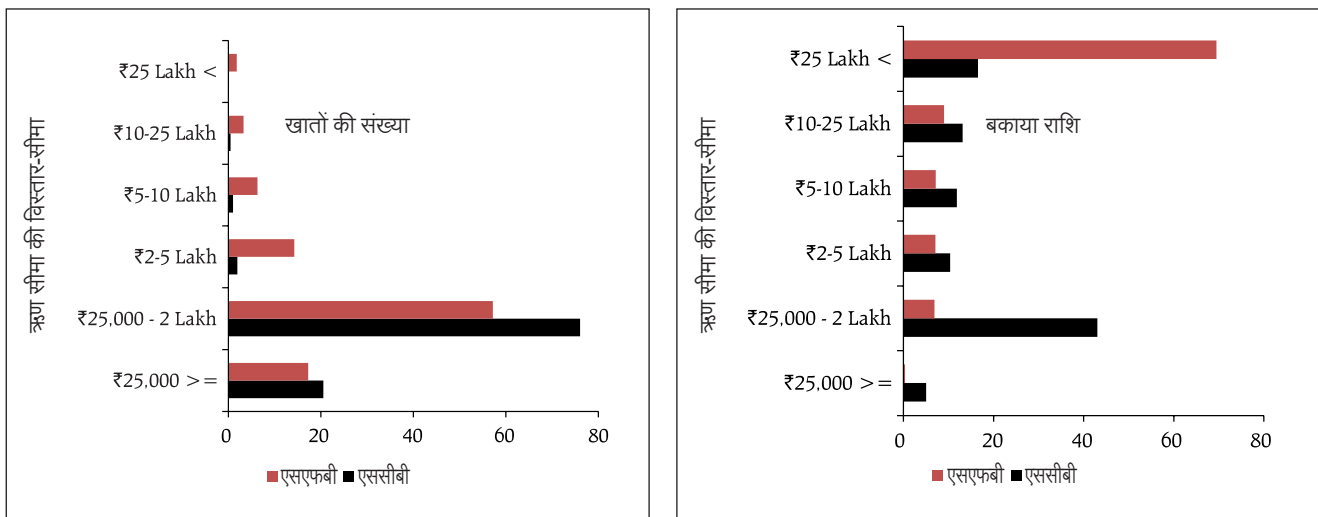
तुलन पत्र संबंधी विशेषताएं

जमा राशि आधार में तीव्र वृद्धि

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश लघु वित्त बैंक मूल रूप से सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं थे और लघु वित्त बैंक में उनके रूपांतरण में सहायक कारकों में से एक - जमा राशि तक उनकी पहुंच थी। प्रत्याशा के अनुसार, उनके अस्तित्व में आने से जमा आस्ति अनुपात (सीडी रेशियो) में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त लघु वित्त बैंकों की जमा राशि की वृद्धि में थोड़ा अंतर है (चार्ट 12)।

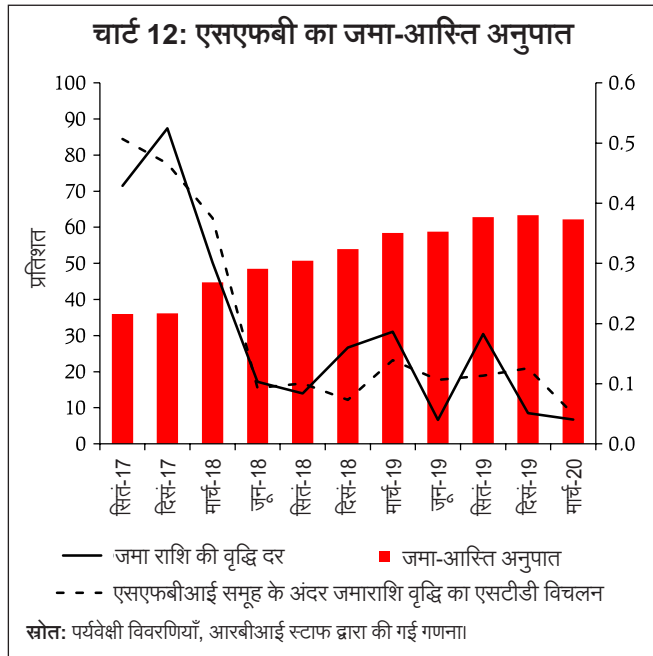
जबकि एसएफबी का जमा आधार बढ़ रहा है, उन्हें अभी भी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में चालू और जमा खातों या कासा जमाराशि (CASA) को जुटाने में एक लंबी दूरी तय करना बाकी है। यद्यपि एसएसबी की कुल जमा राशि में कासा जमाराशि के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, मार्च 2020 में अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 41% कासा की तुलना में यह 15% रहा।

चार्ट 11: ऋण सीमा द्वारा एसएफबी और एससीबी के ऋण का वितरण



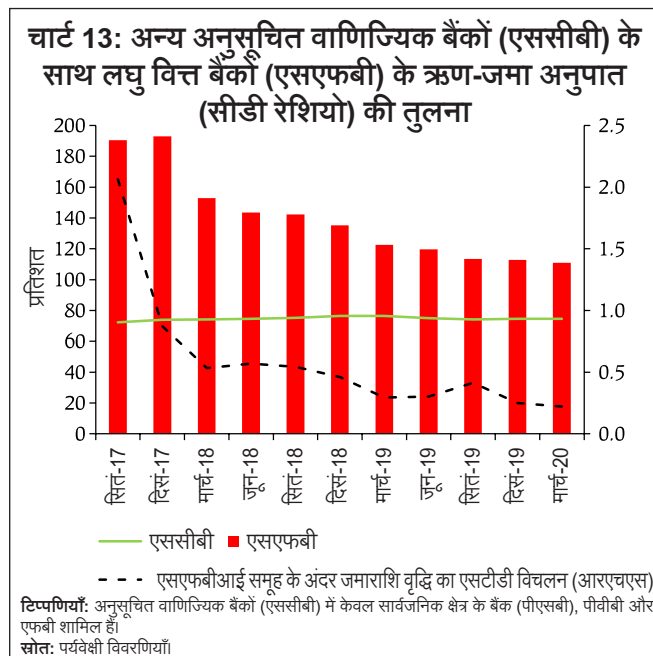
टिप्पणियाँ: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), पीवीबी और एफबी शामिल हैं। मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर।

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ



उच्चतर ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो)

एसएसबी की शुरुआत एक उच्च ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) के साथ हुई, जो कि प्रारंभिक वर्षों में अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ढाई गुना अधिक थी (चार्ट 13)। इसमें समय के साथ जमा राशि में वृद्धि होने पर गिरावट दर्ज हुई, लेकिन तब भी यह मार्च 2020 में 111% की उच्च दर पर था।



2017 में एसएफबी में ऋण-जमा अनुपात व्यापक रूप से भिन्न स्तर पर रहा जिससे उसका फैलाव कम हुआ है।

वित्तीय परिचालन संबंधित विशेषताएँ

अधिक लागत वाली निधियाँ

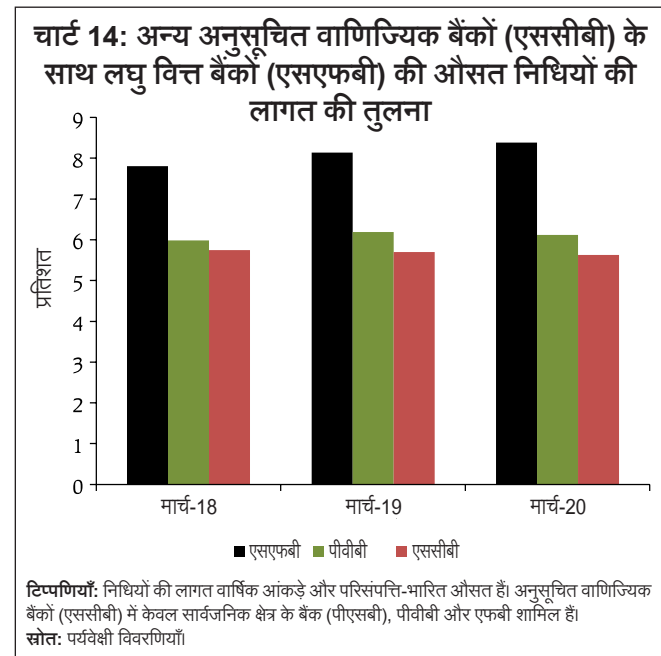
जैसा कि ऊपर की गई चर्चा में पता चलता है कि जमा राशि की बढ़ती हुई पहुंच के बावजूद एसएफबी के लिए निधियों की लागत अधिक रही (चार्ट 14)। अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में एसएसबी के कासा जमा राशि के गिरते हुए प्रतिशत के प्रकाश में निधियों की उच्च लागत पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

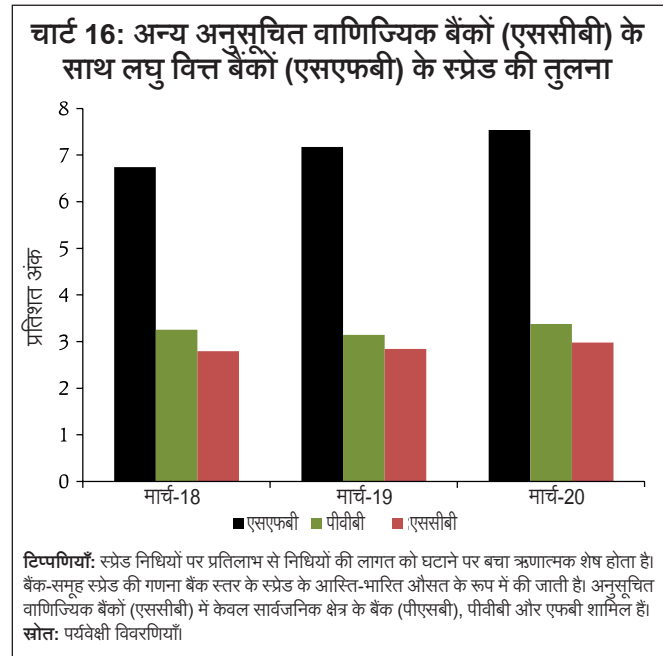
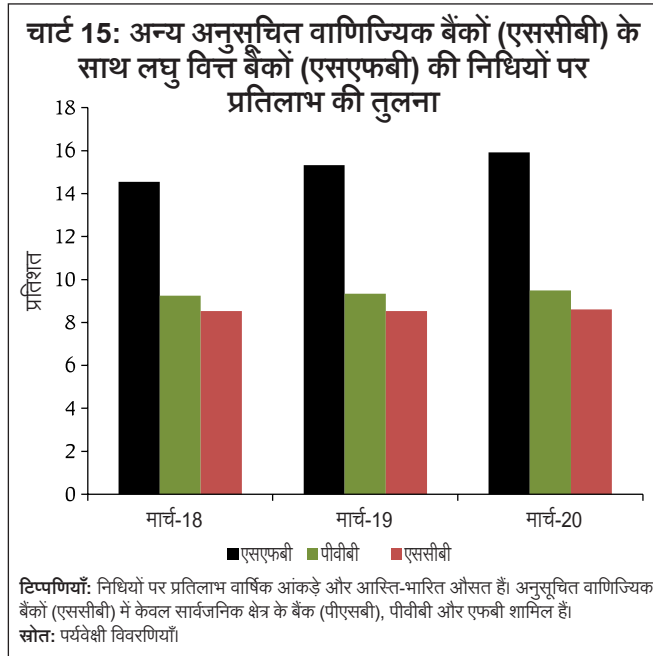
निधियों पर उच्चतर प्रतिलाभ (रिटर्न)

एसएफबी के अधिक फैलाव के कारण निधियों पर अधिक प्रतिलाभ (रिटर्न) मिला है (चार्ट 15-16)। यह दिलचस्प/रोचक तथ्य है कि एसएफबी की निधियों की लागत और प्रति लाभ के संबंध में बहुत अधिक अंतर नहीं था (तालिका 3)।

आस्तियों पर उच्चतर प्रतिलाभ

ऊपर चर्चित निधियों पर उच्चतर प्रतिलाभ प्राप्त करने के बाद अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में एसएससी में औसत रूप से आस्तियों पर उच्चतर प्रतिलाभ (शुद्ध लाभ/औसत





कुल आर्स्टियाँ दर्ज किया गया। हालांकि इस प्रकार की तुलना भ्रामक सिद्ध हो सकती है क्योंकि (ए) ऐसी आर्स्टियों का आकार अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कहीं अधिक कम है; (बी) अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनर्जक आर्स्टियों (एनपीए) की समस्या बनी रहती है जिससे समय के साथ उनकी लाभप्रदता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसीलिए एसएफबी के लिए आर्स्टियों पर प्रतिलाभ (आरओए) की तुलना का एक बेहतर बिंदु गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म ऋण संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) हो सकते हैं। अध्ययन के दौरान एनबीएफसी-एमएफआई ने एसएसबी की तुलना में आर्स्टियों पर अधिक प्रतिलाभ अर्जित किया लेकिन

समय के साथ दोनों संस्थाओं के बीच यह अंतर कम होता जा रहा है (चार्ट 17)

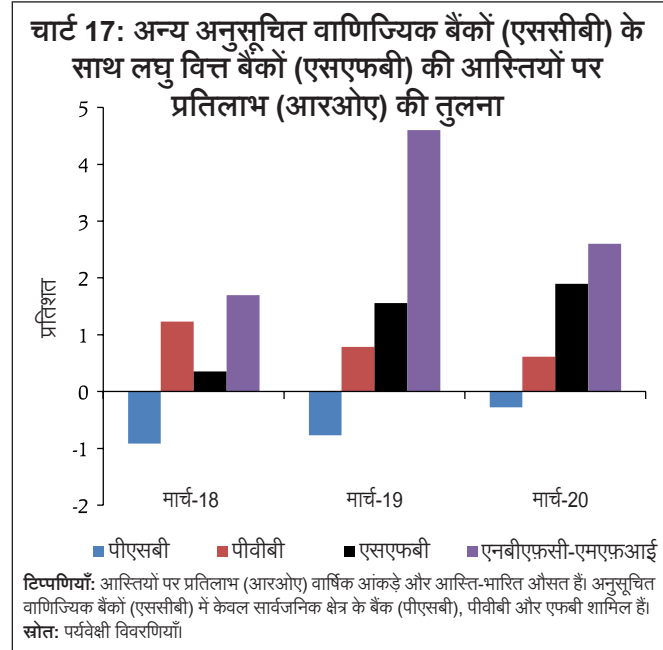
निम्नतर अनर्जक आर्स्टि अनुपात

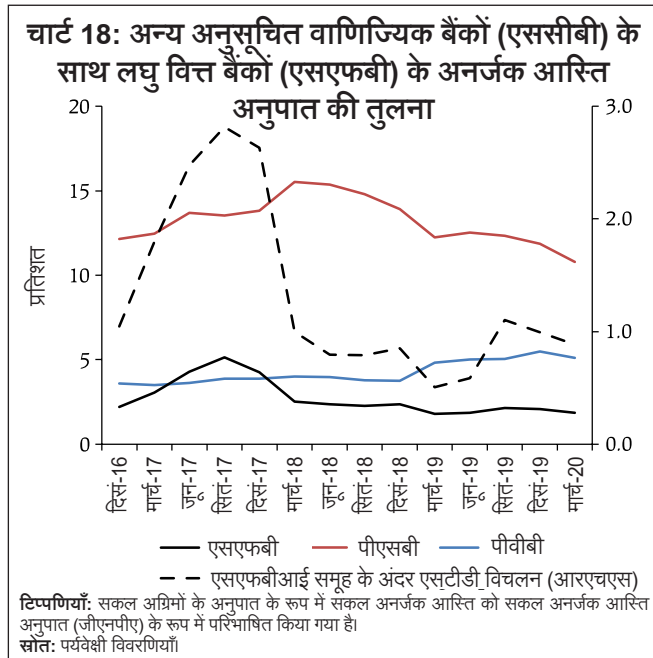
अनर्जक आर्स्टियाँ (एनपीए) लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं, फलतः जिससे किसी भी वित्तीय संस्थान की पूंजी की आंतरिक अभिवृद्धि (accretion) होती है। सूक्ष्म ऋण से जुड़ी विश्वसनीय विशेषताओं में से एक इसकी कम ऋण चूक (defaults) है, जिन्हें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सामाजिक रोजगार

तालिका 3: निधियों पर प्रतिलाभ (आरओए), निधियों की लागत (सीओएफ) और स्प्रेड के अनुसार एसएफबी का संवितरण

आरओए/सीओएफ/स्प्रेड की विस्तार-सीमा (रेंज)	लघु वित्त बैंक (एसएफबी) का प्रतिशत		
	निधियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	निधियों की लागत (सीओएफ)	स्प्रेड
3%-5%	-	-	20
5%-8%	-	20	10
8%-10%	-	80	50
10%-11%	10	-	20
11%-15%	10	-	-
15%-20%	70	-	-
>20%	10	-	-

टिप्पणियाँ: आंकड़ें मार्च 2020 के आंकड़ों से संबंधित हैं।
स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियाँ





समर्थन के माध्यम से ऋण पोर्टफोलियो के बेहतर प्रबंधन और पर्यवेक्षण द्वारा संभव बनाया गया है।

कई लघु वित्त बैंक, जिनमें से कई पूर्व में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म ऋण संस्थान (एनबीएफसी-एमएफआई) थे, में भी अनर्जक आस्ति अनुपात दर्ज किया गया है। इसके अलावा, एसएफबी के बीच अनर्जक आस्ति अनुपात के बिखराव में भी समय के साथ गिरावट दर्ज की गई है (चार्ट 18)।

निकट भविष्य में, एसएफबी में अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों को अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की भांति विभिन्न विनियामक हस्तक्षेपों द्वारा आकार दिया जा सकता है। इन हस्तक्षेपों में ऋणस्थगन (मोराटोरियम) और रेसोल्यूशन फ्रेमवर्क, जो कि कोविड से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए शुरू किए गए थे, सम्मिलित हैं।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के मामले में कोविड संबंधित रेसोल्यूशन फ्रेमवर्क को जनवरी 2019 में पहले से घोषित एमएसएमई पुनर्गठन पैकेज के साथ निर्धारित कर दिया गया है। इसने एमएसएमई के लिए प्रभावी रूप से एक निरंतर विनियामक सहयोग सुनिश्चित किया है जो कि एसएफबी के ऋण पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है।

V. समापन प्रेक्षण/ टिप्पणियां

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में लघु वित्त बैंक एक नया चेहरा हैं जो वित्तीय समावेशन पर मुख्य रूप से केंद्रित हैं। इन संस्थाओं की

शुरुआत के समय से पर्यवेक्षक और मूलभूत सांख्यिकीय विवरण (बीएसआर) के आंकड़ों के आधार पर इन बैंकों का प्रारंभिक मूल्यांकन इस लेख में किया गया है।

एसएफबी ने अपने तुलन-पत्र के आकार और शाखा नेटवर्क के विस्तार के संबंध में तीव्र वृद्धि दर्ज की है। हालांकि वे वित्तीय प्रणाली का एक छोटा-सा हिस्सा हैं। एसएफबी के समूहों के अंदर उच्च स्तर का संकेंद्रण है, शीर्ष दो और शीर्ष तीन बैंकों के पास इस समूह की कुल आस्तियों का लगभग क्रमशः 46% और 60% हिस्सा है। हालिया वर्षों में ऐसे संकेंद्रण को भंग करने वाली ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति है, क्योंकि छोटे आकार के कुछ एसएफबी अपने से बड़े आकार के समकक्षियों की तुलना में उच्चतर आस्ति वृद्धि दर्ज कर रहे हैं।

जहां एसएफबी के शाखा नेटवर्क में तेजी से विस्तार हुआ है, पीवीबी के समान उनकी शाखाएं पर्याप्त बैंकिंग सुविधायुक्त क्षेत्रों/राज्यों में केंद्रित हैं। इनमें दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र शामिल हैं। एसएफबी शाखाओं का उच्च संकेंद्रण विशेष रूप से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में है, जिनकी राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति बैंक शाखा की आबादी बहुत है। एसएफबी शाखाएँ शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में या खासतौर से टियर-1 से टियर-3 के केंद्रों में, जिनकी 20000 व्यक्तियों और उससे अधिक की जनसंख्या है, में भी सघनता दर्शाती हैं। मार्च 2020 में 10000 से कम जनसंख्या वाले टियर 5-6 (ग्रामीण) केंद्रों में एसएफबी शाखाओं का केवल 18% हिस्सा था।

एसएफबी उन आर्थिक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जहां अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत कम सेवा प्रदान की जा रही हैं। इन क्षेत्रों में कृषि (छोटे पैमाने पर), व्यापार और पेशेवर सेवाएँ सम्मिलित हैं। इसके अलावा, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के ऋण की परिधि में ये बैंक एमएसएमई तक पहुंचने में यथोचित सफल रहे हैं। कम बैंकिंग सेवा-प्राप्त क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के अलावा एसएफबी का ऋण पोर्टफोलियो लघु ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं तक भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। मार्च 2020 में समग्र स्तर पर उनके ऋण पोर्टफोलियो के लगभग 83% हिस्से की ऋण सीमा रु. 25 लाख तक थी।

यद्यपि एसएफबी का जमा राशि आधार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उनकी कासा जमाराशियों पर प्रतिशत अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कम है। इन बैंकों के कासा जमाराशि आधार में वृद्धि, भविष्य में निधियों की लागत में कमी ला सकती है।

अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में एसएफबी की निधियों पर अधिक प्रतिलाभ मिला है। इसी तरह स्प्रेड, जो कि निधियों पर प्रतिलाभ का निश्चय करता है, बहुत अधिक रहा है। फलस्वरूप आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) द्वारा मापी गई इन संस्थाओं की लाभप्रदता बैंकिंग क्षेत्र में इनके समकक्षियों की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि यह गैर-बैंकिंग क्षेत्र में उनके समकक्ष एनबीएफसी-एमएफआई से कम है।

अपनी स्थापना के समय से ही लघु वित्त बैंकों का अनर्जक आस्ति अनुपात मामूली रहा है, जो कि एक स्वस्थ आस्ति

गुणवत्ता को रेखांकित करता है। ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह यह बैंक अनर्जक आस्तियों की दीर्घ समस्या से नहीं जूझ रहे हैं। हालांकि छोटे आकार के ग्राहक-वर्ग को सेवा प्रदान करने के बावजूद उनके अनर्जक आस्ति अनुपात का निम्न स्तर ऋण जोखिम के बेहतर प्रबंधन को प्रतिबिंबित करता है।

संदर्भ

कुमार, पी., और गोलैत, आर. (2009), "बैंक व्यापन और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम: ए क्रिटिक", रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओकेसनल पेपर्स, 29, 119-138।

माहेश्वरी, श्रीराम (1995), "रुरल डेवलपमेंट इन इंडिया: ए पब्लिक पॉलिसी अप्रोच", एशिया-पैसिफिक जर्नल ऑफ रुरल डेवलपमेंट. 5 (2), 121-126।

परिशिष्ट
परिशिष्ट तालिका 1: बैंक शाखाओं का राज्यवार वितरण

राज्य	शाखाओं की संख्या			की कुल शाखाओं में राज्य की हिस्सेदारी		
	पीवीबी	पीएसबी	एसएफबी	पीवीबी	पीएसबी	एसएफबी
तमिलनाडु	3701	6486	716	10.6%	7.4%	16.6%
महाराष्ट्र	3920	7809	563	11.3%	8.9%	13.1%
राजस्थान	1490	4219	343	4.3%	4.8%	8.0%
कर्नाटक	2488	5913	332	7.1%	6.7%	7.7%
गुजरात	2166	5222	310	6.2%	5.9%	7.2%
मध्य प्रदेश	1320	4117	302	3.8%	4.7%	7.0%
केरल	2334	3393	235	6.7%	3.9%	5.5%
पंजाब	1650	4271	204	4.7%	4.9%	4.7%
उत्तर प्रदेश	2141	10900	199	6.2%	12.4%	4.6%
बिहार	1037	4000	180	3.0%	4.6%	4.2%
हरियाणा	1409	2861	138	4.0%	3.3%	3.2%
ओडिशा	922	3087	126	2.6%	3.5%	2.9%
असम	758	1458	123	2.2%	1.7%	2.9%
पश्चिम बंगाल	2459	5419	112	7.1%	6.2%	2.6%
छत्तीसगढ़	574	1488	103	1.6%	1.7%	2.4%
झारखंड	438	2120	77	1.3%	2.4%	1.8%
दिल्ली के एन.सी.टी.	1226	2290	72	3.5%	2.6%	1.7%
आंध्र प्रदेश	1199	4627	48	3.4%	5.3%	1.1%
तेलंगाना	1187	3137	31	3.4%	3.6%	0.7%
उत्तराखंड	346	1471	24	1.0%	1.7%	0.6%
पुदुचेरी	59	146	14	0.2%	0.2%	0.3%
त्रिपुरा	162	236	14	0.5%	0.3%	0.3%
चंडीगढ़	127	255	10	0.4%	0.3%	0.2%
हिमाचल प्रदेश	175	1170	8	0.5%	1.3%	0.2%
मेघालय	62	196	8	0.2%	0.2%	0.2%
गोवा	199	473	4	0.6%	0.5%	0.1%
सिक्किम	49	105	4	0.1%	0.1%	0.1%
अरुणाचल प्रदेश	20	108	3	0.1%	0.1%	0.1%
मणिपुर	42	131	3	0.1%	0.1%	0.1%
मिजोरम	35	77	1	0.1%	0.1%	-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13	57	0	0.0%	0.1%	-
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	42	69	0	0.1%	0.1%	-
जम्मू और कश्मीर	958	446	0	2.8%	0.5%	-
लद्दाख	46	20	0	0.1%	0.0%	-
नगालैंड	43	120	0	0.1%	0.1%	-
लक्षद्वीप	1	12	0	0.0%	0.0%	-
भारत	34798	87909	4307	100%	100%	100%

नोट: ' - ' शून्य / नगण्य को दर्शाता है।

मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर।

स्रोत: शाखा बैंकिंग सांख्यिकी

भारत में ग्रीन फाइनेंस : प्रगति और चुनौतियां*

सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता के रूप में ग्रीन फाइनेंस तेजी से उभर रहा है। यह लेख वैश्विक स्तर पर और भारत में ग्रीन फाइनेंस के विकास की समीक्षा करता है। हम ग्रीन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक जागरूकता (गूगल के रुझान) और वित्तपोषण विकल्प (बैंक क्रेडिट और जारी किए गए बॉन्ड) दोनों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों का उपयोग करते हैं। हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत में सार्वजनिक जागरूकता और वित्तपोषण विकल्पों में सुधार हुए हैं, बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से असममित जानकारी में कमी और हितधारकों के बीच समन्वय में वृद्धि एक ग्रीन और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की ओर मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

परिचय

ग्रीन फाइनेंस से तात्पर्य उन वित्तीय व्यवस्थाओं से है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ या ऐसी परियोजनाओं के लिए उपयोग के लिए विशिष्ट हैं जो जलवायु परिवर्तन के पहलुओं को अपनाती हैं। पर्यावरणीय रूप से स्थायी परियोजनाओं में सौर, पवन, बायोगैस, आदि जैसे अक्षय स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन शामिल है; स्वच्छ परिवहन जिसमें कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शामिल है; ग्रीन बिल्डिंग जैसी ऊर्जा कुशल परियोजनाएं; अपशिष्ट प्रबंधन जिसमें पुनर्चक्रण, कुशल निपटान और ऊर्जा में रूपांतरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रीन डेट सिक्क्योरिटीज के लिए प्रकटीकरण आवश्यकता के तहत परियोजना को परिभाषित किया गया है जिसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, स्थायी अपशिष्ट और जल प्रबंधन, टिकाऊ वानिकी और कृषि सहित स्थायी भूमि उपयोग और जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं (सेबी2017)। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नए वित्तीय लिखत जैसे कि ग्रीन बॉन्ड; कार्बन मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स (जैसे कार्बन टैक्स); और नए वित्तीय संस्थान (जैसे

ग्रीन बैंक और ग्रीन फंड) स्थापित किए जा रहे हैं। वे एक साथ ग्रीन फाइनेंस¹ का गठन करते हैं।

ग्रीन फाइनेंस आर्थिक विकास की स्थिरता पर समग्र चर्चा का केंद्र है। तीव्र आर्थिक विकास अक्सर पर्यावरण की कीमत पर प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों का हास, विकृत पर्यावरण और प्रचंड प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और स्थायी आर्थिक विकास के समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत करता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने लिए और इसमें व्यापक सुधार लाने के लिए दुनिया भर के देशों में तेजी से पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तथापि, पर्यावरण के अनुरूप स्थायी परियोजनाओं को स्थापित करने या अपनाने की दिशा में धन के आवंटन में उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना की आवश्यकता होती है। एक बार जब फंड पारंपरिक उद्योगों से मुक्त हो जाते हैं और ग्रीन और पर्यावरण के अनुकूल क्षेत्रों में प्रसारित होते हैं, तो भूमि और श्रम सहित अन्य संसाधन भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप अंततः संसाधनों² के का इष्टतम आवंटन किया जाता है जो लंबे समय के लिए स्थायी विकास का समर्थन करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आर्थिक विकास के सभी हितधारकों, कॉर्पोरेट्स, सरकारों और केंद्रीय बैंकों को शामिल करने वाले प्रमुख देशों में ग्रीन फाइनेंस पर लक्षित नीतियां बनाई गई हैं।

इस लेख में, हम भारत में ग्रीन फाइनेंस की प्रगति का आकलन करते हैं। खंड II में हम संक्षेप में दुनिया भर में ग्रीन वित्त को बढ़ावा देने के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं और भारत में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ पर चर्चा करेंगे। खंड III में, हम भारत में ग्रीन वित्त की प्रगति की रूपरेखा तैयार करेंगे। खंड IV में हम चुनौतियों और आगे के रास्ते पर चर्चा करेंगे और खंड V समापन होगा।

II. ग्रीन फाइनेंस के प्रति सार्वजनिक नीति

(ए) अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएँ

2008 में जी 20 के पहले शिखर सम्मेलन के बाद से जलवायु परिवर्तन इसके एजेंडे में शामिल रहा है यद्यपि, हाल ही में

* यह लेख सौरभ घोष, सिद्धार्थ नाथ और आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) के रणनीतिक अनुसंधान इकाई के अभिषेक रंजन द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। रिसर्च इंटरन द्वारा भी इस संबंध में सहयोग प्रदान किया गया।

¹ <https://development.asia/explainer/green-finance-explained> (एशियाई विकास बैंक)

² चीन की हरित वित्तीय प्रणाली की स्थापना, ग्रीन फाइनेंस टास्क फोर्स की रिपोर्ट, अप्रैल 2015।

हानिकारक उत्सर्जन से निपटने के लिए सर्कुलर कार्बन अर्थव्यवस्था (सीसीई) पर अधिक ध्यान दिया गया है। कई फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में ग्रीन पहलों के वित्तपोषण को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्मों को अपने वित्तपोषण में पर्यावरणीय विचारों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रमुख फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट (PRI), फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इक्वेटर प्रिंसिपल्स (EP), यूनाइटेड नेशन्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, सिग्नेटरीज के बीच ग्रीन फाइनेंस को लागू करने के तरीके सुझाते हैं। भारत से कई संस्थाएं इन कार्यक्रमों के लिए सिग्नेटरीज हैं (तालिका 1)। हालांकि, स्थायी परियोजनाओं में वित्त के एक स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करना केवल तभी संभव है जब संस्थाओं के पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों के समग्र प्रबंधन के बारे में जानकारी का कोई विश्वसनीय स्रोत है, जो अच्छी खासी रिटर्न रेट और पर्यावरणीय लाभ (यूएनईपी)³ लाने वाले अवसरों की पहचान पर संस्थाओं के रिकॉर्ड पर नज़र रखता है। इस संबंध में, सस्टेनेबल

स्टॉक एक्सचेंज एक पहल है जो हस्ताक्षरकर्ता देशों के स्टॉक एक्सचेंजों को स्टॉक मूल्य सूचकांकों के साथ आने की सिफारिश करता है जो इन देशों में काम करने वाली कंपनियों के एक समूह के स्टॉक प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक शासन (ईएसजी) सिद्धांतों⁴ को अपने वित्तपोषण पहलुओं में पहचानने में अग्रणी हैं। इन सूचकांकों का उद्देश्य उन निवेशकों का मार्गदर्शन करना है जो ग्रीन गतिविधियों में निवेश करने में रुचि रखते हैं। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) इस पहल का हिस्सा हैं और अलग-अलग ईएसजी सूचकांकों को प्रकाशित करते हैं।

दुनिया भर में नियामक ढांचे को मोटे तौर पर चार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों द्वारा स्थिरता का खुलासा किया जाता है, जिसके द्वारा कंपनियों को समय-समय पर अपने परिचालन से ईएसजी से संबंधित जोखिमों के बारे में अपने जोखिम की रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। इस तरह के खुलासे जी 20 द्वारा दिए गए बल के बाद जलवायु-संबंधी वित्तीय प्रकटीकरणों (टीसीएफडी) पर टास्क फोर्स की सिफारिशों के कॉरपोरेट्स द्वारा एक स्वैच्छिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करके उठाए गए हैं। जून 2020 तक, दुनिया की 100 सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में से 60 फीसदी ने टीसीएफडी सिफारिश⁵ का समर्थन किया। चीन (2008)⁶, हांगकांग (2012), यूके (2012), भारत (2012), फिलीपींस (2013), वियतनाम (2013), सिंगापुर (2016) देशों के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, वित्तीय बाजार नियामक और कॉर्पोरेट मामलों से निपटने वाले मंत्रालयों ने अपने अधिकार क्षेत्र (Volz, 2018)⁷

तालिका 1: वैश्विक पहल में एशियाई वित्तीय संस्थानों की भागीदारी

पहल का नाम	वैश्विक हस्ताक्षरकर्ता	एशियाई हस्ताक्षरकर्ता	वैश्विक हस्ताक्षरकर्ता	एशियाई हस्ताक्षरकर्ता
	वोलज़, 2018 से		2019 के अंत तक	
जिम्मेदार निवेश के लिए सिद्धांत	1,874	122	2,698	387 *
ईक्वेटर सिद्धांत वित्तीय संस्थान	91	12	101	22 **
सतत विकास (2011) पर वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिबद्धता का यूएनईपी वक्तव्य	214	38		
स्थायी स्टॉक एक्सचेंज	66	14 ***		

स्रोत: वोल्ज़, यू. (2018 मार्च)। कार्यक्रमों, वेबसाइटों से नवीनतम जानकारी एकत्र की गई।

नोट: एशिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।

*: भारत से 3 शामिल हैं: एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इक्विप एशिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और इंडस एनवायरनमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

**: भारत से केवल आईडीएफसी।

***: भारत से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों शामिल हैं।

³ देखें <https://www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing>

⁴ पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांत कंपनी के संचालन के लिए मानकों का एक समूह है जो कुछ सामाजिक, पर्यावरण और शासन मानकों के अनुरूप हैं। यह एक बेंचमार्क है जिसका उपयोग कई निवेशक अपने संभावित निवेश की स्थिरता का आकलन करने के लिए करते हैं। पर्यावरणीय मापदंड इस बात पर विचार करते हैं कि कैसे एक कंपनी पर्यावरणीय लागतों के साथ अपने संचालन को संतुलित करती है। सामाजिक मानदंड अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ कंपनियों के रिश्तों के साथ व्यवहार करते हैं जहां यह संचालित होता है। शासन एक कंपनी के नेतृत्व, कार्यकारी वेतन, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारक अधिकारों से संबंधित है।

⁵ तीसरी टीसीएफडी स्थिति रिपोर्ट ग्रेटर जलवायु-संबंधित प्रकटीकरण और पारदर्शिता के लिए प्रगति और हाइलाइट की आवश्यकता को दर्शाती है

⁶ शंघाई में स्टॉक एक्सचेंज।

⁷ कोष्ठक इन स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्थिरता प्रकटीकरण को अपनाने के वर्षों का संकेत देते हैं।

में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ईएसजी से संबंधित जोखिमों के प्रकटीकरण के लिए रूपरेखा को लागू किया। बांग्लादेश ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों (CSR) की द्वि-वार्षिक रिपोर्टिंग को 2008 में शुरू किया। गैर- बैंकिंग संस्थानों को मानदंड के विस्तार के साथ 2011 में बैंकों द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन के हिस्से के रूप में व्यवस्थित पर्यावरणीय जोखिम विश्लेषण को 2013 में प्रोत्साहित किया और 2017 में सामाजिक जोखिमों के मूल्यांकन को शामिल किया (वोल्ज़, 2018)। बांग्लादेश ने बैंकों के लिए 2013 की शुरुआत में एक समान जोखिम रिपोर्टिंग प्रारूप जारी किया। 2015 में फ्रांस द्वारा पारित ग्रीन ग्रोथ लॉ के लिए ऊर्जा संक्रमण ने संपत्ति के मालिकों और प्रबंधकों के लिए इस बात को रिपोर्ट करने को अनिवार्य कर दिया कि कैसे भौतिक और संक्रमण जोखिम उनकी गतिविधियों और परिसंपत्तियों को प्रभावित करते हैं। इस नीति का उद्देश्य फ्रांस⁸ में ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के व्यापक प्रयासों से डिस्क्लोजर्स को जोड़ना है। दूसरा प्रत्यक्ष और रियायती ऋण है, जिसका अभ्यास कई देशों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, \$ 26 मिलियन का एक 'रिवाल्विंग फंड' बांग्लादेश में 2009 में ग्रीन री-फाइनेंसिंग स्कीम के तहत स्थापित किया गया था ताकि 50 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन उद्योगों को कम ब्याज ऋण दिया जा सके। इसके अलावा 2016 में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर स्विच करने के लिए लेदर-टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए \$ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त फंड स्थापित किया गया था। 2015 से बांग्लादेश ने वाणिज्यिक बैंकों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और अन्य ग्रीन प्रौद्योगिकियों (वोल्ज़ 2018) में अपने ऋण का कम से कम 5 प्रतिशत आवंटित करने के लिए बाध्य किया। तीसरे, वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों के सूक्ष्म और मैक्रो-विवेकपूर्ण नियम हैं। 2006 में, चीन ने अपने पर्यावरणीय अनुपालन के आधार पर कंपनियों को ऋण प्रतिबंध लागू किया। लेबनान ने 2010 में वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतर आरक्षित आवश्यकता की नीति को लागू किया, जिसमें बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो में ग्रीन परियोजनाओं के बड़े हिस्से के साथ कम भंडार (डिकौ और वोल्ज़ 2018) रखने की आवश्यकता होती है। 2011 में, ब्राजील ने पर्यावरण और सामाजिक जोखिम (डिकौ और वोल्ज़ 2018) वाली परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम के बारे में विचार करके बैंकों की आंतरिक पर्याप्तता मूल्यांकन की आंतरिक

प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय विचारों को शामिल किया। आखिरकार, ब्राजील ने बैंकों को 2017 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सामाजिक और पर्यावरणीय नुकसान के जोखिम के तरीकों और जोखिम को रेखांकित करने की सिफारिश की। चौथा ग्रीन वित्तीय संस्थानों की स्थापना है। यूके ग्रीन इन्वेस्टमेंट बैंक पीएलसी, एक जीबीपी 3 बिलियन (यूएसडी 3.9 बिलियन) संस्थान, पूरी तरह से यूके सरकार के स्वामित्व में 2012 (गेड्स एट आल 2018) में स्थापित किया गया था। 2013 के बाद से, नॉर्डिक देशों ने स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का गठन किया जिन्होंने वित्तीय बाजार में बांड जारी किया और अपने उप-राष्ट्रीय सदस्यों को इससे प्राप्त प्रोसीड्स को वितरित किया। कम्प्यूनिवेस्ट (स्वीडन), कम्प्यूनलबैंकेन और केएलपी कम्प्यूनक्रेडिट एएस (नॉर्वे), कम्प्यूनक्रेडिट (डेनमार्क), और म्यूनिफिन (फिनलैंड) (नासिरि, 2018)। एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ग्रीन वित्त के लिए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में भागीदार बैंकों और देशों को आंशिक क्रेडिट और बॉन्ड गारंटी प्रदान करते हैं। इन अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, भारत ने पिछले दशक के दौरान कई नीतिगत टूल भी लागू किए हैं, जैसा कि निम्नलिखित खंडों में विस्तृत है।

(ख) भारत में सार्वजनिक नीति

भारत ने 2007 की शुरुआत में ग्रीन फाइनेंस पर जोर देना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2007 में, रिज़र्व बैंक ने "कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, सतत विकास और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग - बैंकों की भूमिका" पर एक अधिसूचना जारी की और ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के महत्व का उल्लेख किया। 2008 में, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय नीति योजना (एनएपीसीसी) को एक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया था ताकि जलवायु परिवर्तन (जैन, 2020) के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक नीतिगत ढांचे की रूपरेखा तैयार की जा सके। जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफ़्यू) का गठन 2011 में वित्त मंत्रालय के भीतर भारत में ग्रीन फाइनेंस के लिए जिम्मेदार विभिन्न संस्थानों के लिए एक समन्वय एजेंसी के रूप में किया गया था। 2012 के बाद से प्रमुख रणनीतिक कदम में स्थिरता प्रकटीकरण आवश्यकताओं का कार्यान्वयन शामिल था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 2012 के बाद से बीएसई और एनएसई पर बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक व्यावसायिक उत्तरदायित्व

⁸ वित्त का भविष्य, (2019), बैंक ऑफ इंग्लैंड, जून।

रिपोर्ट प्रकाशित करने को अनिवार्य बना दिया और समय-समय पर इसे संशोधित किया। मई 2017 में, सेबी ने प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हुए ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों (सीएसआर) पर प्रगति की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लागू किया।⁹ अक्टूबर 2017 में, कॉर्पोरेट प्रशासन पर समिति की रिपोर्ट ने प्रस्ताव दिया है कि विशेष रूप से रणनीति, बजट, बोर्ड मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, ईएसजी और उत्तराधिकार नियोजन पर चर्चा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक होगी।

भारत में काम के दौरान कई राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन रहे हैं। ये प्रोत्साहन 2005 के समझौते के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता को कम करने के लिए 2015 के पेरिस समझौते के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं, जो 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत कम है, और 2030¹⁰ तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 प्रतिशत, स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए है। भारत सरकार (जीओआई) ज्यादातर राज्यों¹¹ में रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना लागत का 30 प्रतिशत संस्थागत, आवासीय और सामाजिक क्षेत्रों के लिए सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों में¹², सब्सिडी स्थापना लागत का 70 प्रतिशत तक है। इसके अलावा, लाभार्थी एक पीढ़ी-आधारित प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें वे प्रति यूनिट रु. 2/- प्राप्त कर सकते हैं, यदि बिजली उत्पादन 1100किलोव्हाट -1500किलोव्हाट प्रति वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा, सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ पर अतिरिक्त बिजली बेची जा सकती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 2015 में और 2019 में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएएमई) स्कीम के दो चरणों को शुरू किया, ताकि क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाया जा सके, जिससे सभी वाहनों के अप-

फ्रंट खरीद मूल्य को कम किया जा सके और मूलभूत ढांचे को विकसित किया जा सके (जैसे चार्जिंग स्टेशन) जिससे हरित वाहन उत्पादन और बिक्री को प्रोत्साहित किया जा सके (जैन, 2020)। ऐसे वाहनों की उच्च अप-फ्रंट लागत का मुकाबला करने के लिए, भारतीय स्टेट बैंक ने मौजूदा कार ऋणों की तुलना में 20 आधार अंक कम ब्याज दर और लंबी रीपेमेंट विंडो वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 'ग्रीन कार ऋण' योजना शुरू की है (जैन, 2020)। सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उच्च दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक उत्पादन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना भी आरंभ की है।

ग्रीन फाइनेंस पहलों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए रिजर्व बैंक भी सक्रिय नीतिगत उपाय कर रहा है। इसने 2015 में अपनी प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) योजना के तहत छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया है। इस योजना के तहत, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र¹³ में फर्म ₹ 30 करोड़ (4 सितंबर, 2020 से 15 करोड़ से अधिक) तक के ऋण के लिए पात्र हैं। जबकि परिवार अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए 10 लाख तक के ऋण के पात्र हैं। सितंबर 2019 में, भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन के 450 गीगावॉट तक पहुंचने के लक्ष्य की घोषणा की।

रिजर्व बैंक अपनी नियमित रिपोर्टों और अन्य संचारों के माध्यम से सार्वजनिक, निवेशकों और बैंकों को ग्रीन फाइनेंस की आवश्यकता, अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूक कर रहा है। उदाहरण के लिए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट (2015-16) में, रिजर्व बैंक ने ग्रीन बॉन्ड में सीमा पार निवेश की सुविधा प्रदान करने, पर्यावरणीय जोखिमों के बारे में जानकारी साझा करने, और समग्र ग्रीन फाइनेंस गतिविधियों में सुधार करने पर स्थानीय ग्रीन बॉन्ड बाजारों के विकास की आवश्यकता पर जी 20 ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप (जीएफएसजी¹⁴) के निष्कर्षों का उल्लेख किया है। वार्षिक रिपोर्ट में ग्रीन फाइनेंस से संबंधित व्यापक मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जिन पर भविष्य में विचार की आवश्यकता है। इनमें ग्रीन गतिविधियों की परिभाषा,

⁹ https://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/FAQ_CSR.pdf

¹⁰ <https://climateactiontracker.org/countries/india/pledges-and-targets/>

¹¹ <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/productline/power-generation/solar-subsidies-government-subsidies-and-other-incentives-for-installing-rooftop-solar-system-in-india/articleshow/69338706.cms?from=mdr>

¹² उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, मई 2019 तक।

¹³ नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन-आधारित ऊर्जा और माइक्रो-हाइडल ऊर्जा शामिल हैं।

¹⁴ G20 ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप (GFSG) का काम G20 के मजबूत, स्थायी और संतुलित विकास के रणनीतिक लक्ष्य का समर्थन करता है। यह दिसंबर 2015 में सान्या, चीन में जी 20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स मीटिंग के बाद स्थापित किया गया था।

विकास में बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलुओं और विकसित देशों से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और बैंकों द्वारा पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति (2018-19) पर अपनी रिपोर्ट में, रिजर्व बैंक ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर जलवायु परिवर्तन के जोखिम और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के लिए ग्रीन फाइनेंस में तेजी लाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। यह ग्रीन फाइनेंस के विकास में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है, जैसे कि “ग्रीनवाशिंग” या पर्यावरणीय अनुपालन के झूठे दावे, परिभाषाओं की बहुलता, दीर्घकालिक निवेश और निवेशकों के अल्पकालिक हितों के बीच मेच्योरिटी मिसमैच। यह समन्वित प्रयासों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ावा देकर भारत में ग्रीन फाइनेंस ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाले ढांचे की स्थापना के लिए नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देता है।

ग्रीन वित्तीय संस्थानों के संदर्भ में, स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा समर्थित एजेंसी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (आईआरडीडीए) ने मई 2016 में भारत का पहला ग्रीन बैंक बनाने की योजना की घोषणा की। इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने पांच साल (जून, 2020) से अधिक के बॉन्ड टेनर के साथ व्यवहार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ‘क्रेडिट एन्हांसमेंट स्कीम’ के रूप में जानी जाने वाली एक समर्पित योजना भी आरंभ की। इन चरणों को ध्यान में रखते हुए, हम भारत में ग्रीन फाइनेंस की प्रगति का आकलन करेंगे, जिसमें अगले भाग में पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में सामान्य जागरूकता शामिल है।

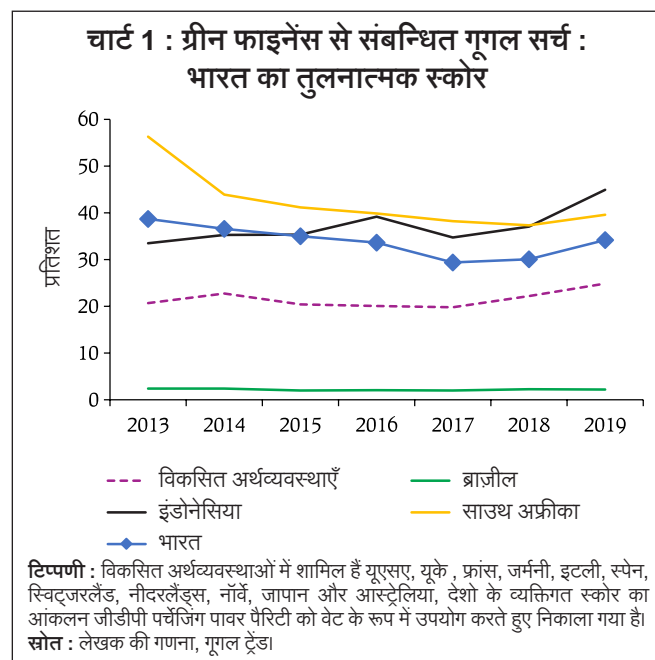
IIII भारत में ग्रीन फाइनेंस की प्रगति और चुनौतियाँ

क) सामान्य जागरूकता में सुधार

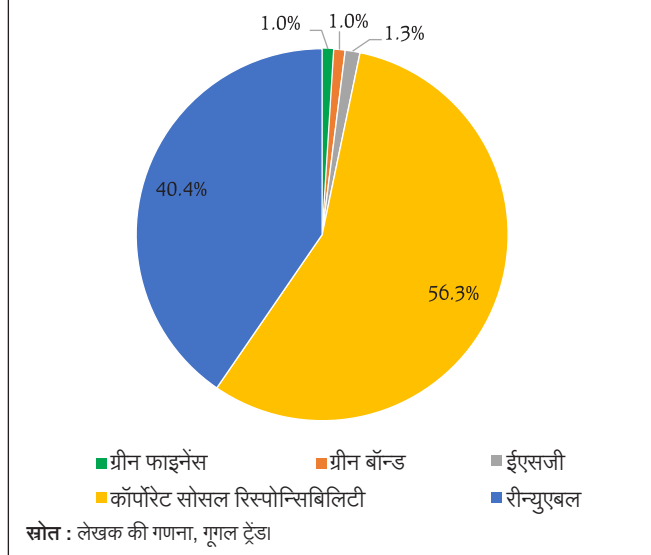
पारंपरिक स्रोतों से ग्रीन फाइनेंस और सतत विकास के बारे में जागरूकता का आकलन करने के लिए डेटा की कमी है। इस संबंध में, गूगल ट्रेंड्स विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग स्थानों पर किए गए गूगल खोजों के पैटर्न को समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह गूगल में की गई खोजों की संख्या के आधार पर, किसी दिए गए विषय पर रुचि को समझने में हमारी मदद कर सकता है। गूगल रुझानों में, किसी भी विषय पर गूगल में

की गई खोजों की संख्या के बारे में जानकारी को सामान्यीकृत किया जाता है क्योंकि निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में सभी विषयों पर की गई खोजों की संख्या का अनुपात। यह सामान्यीकरण गूगल पर संपूर्ण खोज गतिविधियों में परिवर्तन के कारण होने वाले पूर्वाग्रह को निकाल देता है। उदाहरण के लिए, आज दुनिया भर में इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के सामान्य विस्तार के कारण समग्र खोज मात्रा की संख्या 2004 की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए, किसी भी विषय में खोजों की पूर्ण संख्या समय के साथ उस विषय में सामान्य रुचि की तुलनात्मक जानकारी नहीं दे सकती है। गूगल रुझानों पर आधारित साक्ष्य ग्रीन फाइनेंस में जागरूकता बढ़ाने और स्थायी आर्थिक विकास में इसकी भूमिका का सुझाव देते हैं।

हम किसी एक समय में किसी देश में समग्र खोजों के अनुपात के अनुसार खोज की तीव्रता को खोजते हैं जिसमें पाँच कीवर्ड शामिल हैं अर्थात् ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बॉन्ड, ईएसजी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिन्यूएबल। चार्ट 1 से पता चलता है कि भारत में जलवायु परिवर्तन और ग्रीन फाइनेंस से संबंधित गूगल खोजों की तीव्रता उन्नत है और प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कम नहीं है। चार्ट 1 से पता चलता है कि भारत का तुलनात्मक स्कोर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से अधिक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, गूगल रुझान चुने हुए कीवर्ड



**चार्ट 2 : गूगल सर्च ऑफ की वर्ड्स का वितरण
(कुल का प्रतिशत): 2013-2019 औसत**



के लिए सामान्यीकृत खोज तीव्रता की रिपोर्ट करता है। सामान्यीकरण करते समय, खोज तीव्रता का अधिकतम मूल्य वाला देश 100 पर सेट होता है। फिर अन्य देशों के लिए खोज की तीव्रता आनुपातिक रूप से समायोजित की जाती है। चार्ट 1 में देश के स्कोर पाँच कीवर्ड के लिए इन अंकों के भारित औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ वज़न इन पाँच कीवर्ड में कुल खोज में किसी विशेष कीवर्ड पर खोज के प्रतिशत शेयर हैं। चार्ट 2 दर्शाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित विषय भारत में सार्वजनिक हित पर हावी हैं। ग्रीन-फाइनेंस और ग्रीन बॉन्ड जैसे विशिष्ट उपकरणों से संबंधित वेब-खोज, अभी भी सीमित हैं (सभी पाँच कीवर्ड खोजों में से लगभग 2 प्रतिशत)।

(ख) ग्रीन लेंडिंग

स्थायी परियोजना के लिए बैंक ऋण आकर्षण के लिए हम रिजर्व बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस जैसे पारंपरिक स्रोतों की ओर रुख करते हैं, जिनमें नीतिगत दरो, कुल ऋण, क्षेत्रीय ऋण और अनुसूचित वाडीज्यिक से संबन्धित प्रमुख वित्तीय अनुपात दर पर सार्वजनिक रूप से डाटा उपलब्ध है। भारत में बैंक नमूने में व्यक्तिगत एससीबी की संख्या 2005 में 88 से 2019 में 95 तक भिन्न है।

तालिका 2: मार्च, 2020 तक गैर-पारंपरिक ऊर्जा के लिए बैंक क्रेडिट बकाया

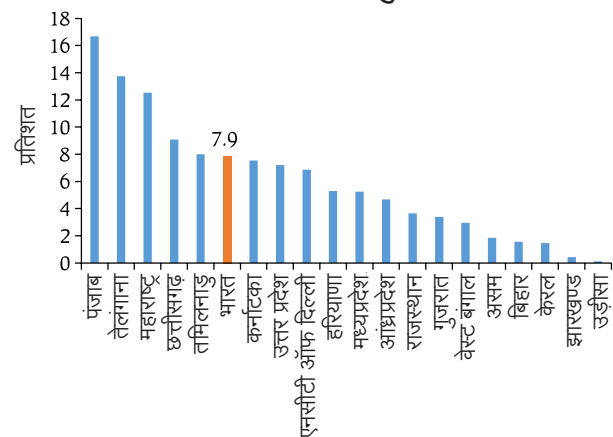
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी बैंक
बकाया राशि (करोड़ रुपये)	21,655	12,302	2,586	36,543
बिजली क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार	6.2	11.9	27.1	7.9
कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में (व्यक्तिगत ऋणों को छोड़कर)	0.5	0.5	0.7	0.5

नोट: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को छोड़कर।

स्रोत: बीएसआर, आरबीआई, लेखकों की गणना

ग्रीन फाइनेंस पहल के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक ने 2015 में अपनी प्राथमिकता क्षेत्र उधार (पीएसएल) योजना के तहत छोटे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को शामिल किया है। मार्च अंत 2020 तक गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए कुल बकाया बैंक क्रेडिट 36, 543 करोड़ था। जो की बिजली उत्पादन के बैंक ऋण का 7.9 प्रतिशत है, जबकि 2015 में यह 5.4 प्रतिशत ही था। बैंक समूहों के बीच गैर पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र के लिए वाडीज्यिक बैंकों का अनावरण और भारत में प्रमुख राज्य (चार्ट 3)

**चार्ट 3 : गैर पारंपरिक ऊर्जा वित्त की हिस्सेदारी :
मार्च 2020 के अनुसार**



नोट : यह चार्ट बिजली उत्पादन की तुलना में बकाया बैंक क्रेडिट में गैर पारंपरिक ऊर्जा के हिस्से (प्रतिशत में) को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों को शामिल नहीं करता है।

स्रोत: बीएसआर, आरबीआई, लेखकों की गणना

(ग) ग्रीन बॉन्ड

ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु इकाई, अंतर सरकारी समूहों या गठबंधनों और कोरपोरेट्स द्वारा जारी किए गए बॉन्ड होते हैं, जिन का उद्देश्य बॉन्ड की आय को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के उपयोग के लिए किया जाता है। हमने भारत और अन्य देशों में कॉर्पोरेट और सरकारों द्वारा जारी किए गए हरे बॉन्ड पर विस्तृत जानकारी के लिए ब्लूमबर्ग का इस्तेमाल किया है। भारत के लिए हमने पहली बार 21 जनवरी 2015 के बाद से कॉर्पोरेट और सरकार द्वारा जारी किए गए अधिकांश बॉन्ड निकाले, भले ही वह हरे रंग के बॉन्ड हो या नहीं। इस संबंध में हमने उन बोनड्स को लिया है, जहां जोखिम वाले देश को भारत के रूप में चिन्हित किया गया है, निगमन के जारी करता देश के बावजूद। हमारे डाटा में अमेरिकी डॉलर में प्रारम्भिक जारी राशि, कूपन दर, कुल संपत्ति अनुपात के लिए ऋण शामिल है। और हमने तब देखा कि जो 2015 से 5000 से अधिक बोनड्स परियोजनाओं के लिए जारी किए गए, उन्हें हरी परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाना था या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए हमने विस्तृत जानकारी निकाले बिना ब्लूमबर्ग टर्मिनल का उपयोग करके सारांश जानकारी निकली है।

भारत ने 2015 में ग्रीन बॉन्ड जारी करना शुरू कर दिया था। 12, फरवरी 2020 तक, भारत में ग्रीन बॉन्ड की बकाया राशि 16.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। भारत ने 1 जनवरी 2018 से लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए, जो कि भारत के वित्तीय बाजार द्वारा जारी किए गए कुल बॉन्ड का 0.7 प्रतिशत है। हलाकी 2018 से जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड, कुल जारी किए गए बॉन्ड का बहुत कम हिस्सा हैं। भारत ने फिर भी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में एक अनुकूल स्थिति बनाए रखी।

2015 के बाद से जारी किए गए अधिकांश ग्रीन बॉन्ड में पाँच साल या उससे अधिक की लेकिन 10 साल से कम की पारिपक्वता थी। हलाकी कुछ जारीकर्ताओं जैसे येस बैंक लिमिटेड (2015), इंडियन रीनेवेबल एनर्जि डेवलपमेंट एजन्सि लिमिटेड (2017, 2019), ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या आरईसी लिमिटेड (2017), पावरफ़ाइनेंस कार्पोरेशन (2017), इंडियन

तालिका 3 : 1 जनवरी 2018 से जारी किए गए बॉन्ड (कॉर्पोरेट और सरकारी –कुल परिपक्वता)

देश	जारी की गयी राशि (\$Mn)	जारी किए गए बॉन्ड की संख्या	सभी जारी किए गए बॉन्ड की राशि प्रतिशत में	कुल जारी किए गए बॉन्ड की संख्या प्रतिशत में
यूरो क्षेत्र ¹	1,96,854	594	1.7	0.4
चीन	63,023	183	0.3	0.2
यू.एस.ए.	35,421	71	0.2	0.2
जापान	11,815	88	0.1	1.1
दक्षिण कोरिया	11,781	44	1.0	0.4
दक्षिण मध्य अमेरिका ²	8,869	53	0.5	1.0
भारत	7,992	22	0.7	0.3
दक्षिण पूर्वी एशिया ³	7,208	86	0.6	1.4
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	5,878	15	1.1	0.8
यू.के.	5,311	17	0.4	0.5
हाँग कॉंग	4,781	19	0.5	1.0
सिंगापुर	496	9	0.05	1.2

स्रोत: लेखक की गणना, ब्लूमबर्ग

नोट: इसमें कॉर्पोरेट और सरकारी दोनों बॉन्ड शामिल हैं।

¹: यूरो क्षेत्र में यूके, रूस और स्विट्जरलैंड को छोड़कर सभी यूरोपीय देश शामिल हैं।

²: दक्षिण-पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

³: मध्य और दक्षिणी अमेरिका में मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली शामिल हैं।

रेल्वे फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड। अदानी नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (2019) ने 10 या अधिक वर्षों की परिपक्वता के साथ हरित बॉन्ड जारी किए हैं। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने 2019 में 5 साल से कम की परिपक्वता अवधि के साथ हरित बॉन्ड जारी किए हैं। 2015 के बाद से भारत में जारी किए गए हर एक बॉन्ड में से लगभग 76% अमेरिकी डॉलर में दिए गए थे। कॉर्पोरेट और सरकार के अलावा विश्व बैंक ने भी समय-समय पर भारत में कई परियोजनाओं के लिए हरित बॉन्ड जारी किए हैं। विश्व बैंक द्वारा ग्रीन इंपैक्ट रिपोर्ट 2019 के आधार पर अनुमान है कि 30 जून 2019, तक भारत में इस तरह की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आवंटित ग्रीन बॉन्ड आय की बकाया राशि यूएस डॉलर 640 मिलियन है।

¹⁵ कोष्ठक जारी करने का वर्ष दर्शाता है।

¹⁶ सक्रिय परियोजनाओं के लिए कुल राशि।

संक्षेप में भारत में हरित वित्त अभी भी नवजात अवस्था में है। 2018 से भारत में जारी किए गए सभी बॉन्ड में से केवल 0.7 प्रतिशत ग्रीन बॉन्ड का गठन किया गया, और मार्च 2020 तक बिजली क्षेत्र में बकाया ऋण का लगभग 7.9 प्रतिशत बैंक गैर पारंपरिक ऊर्जा को दे रहा है। अगले भाग में हम भारत में हरित बॉन्ड बाजार के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे।

4. चुनौतियां और आगे का रास्ता

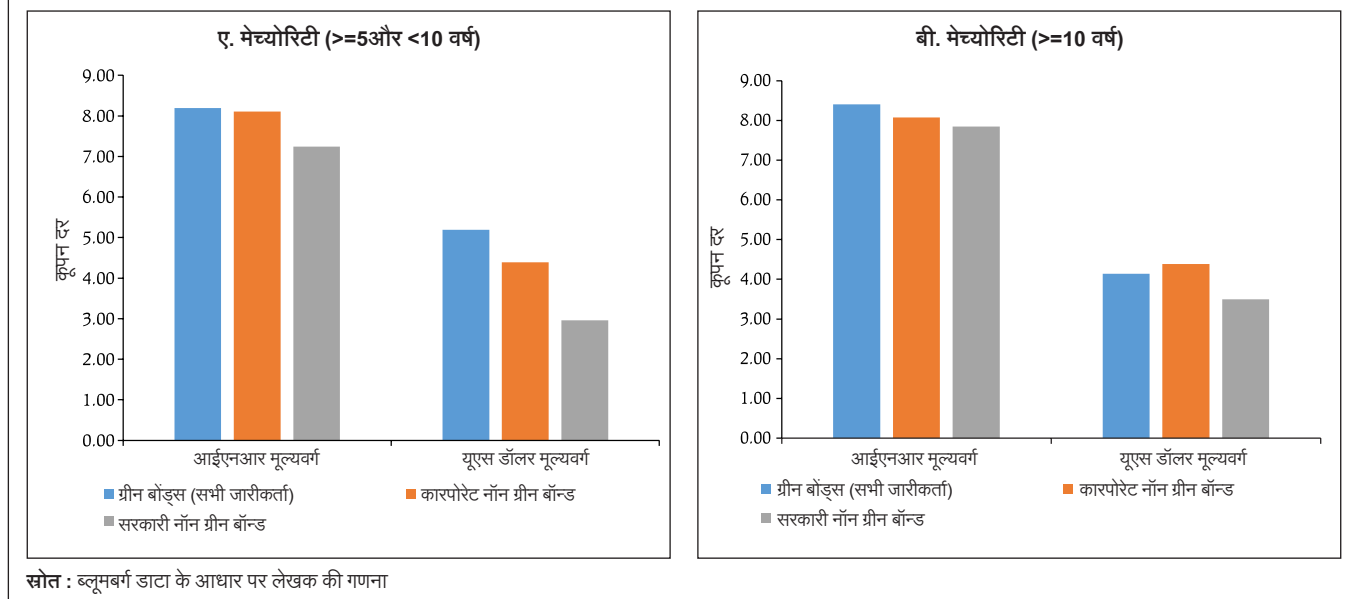
मौजूदा साहित्य और वैश्विक अनुभव बताते हैं, कि ग्रीन फाइनेंस के लिए एकीकृत नीति दृष्टिकोण धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। भारत में जबकि सार्वजनिक जागरूकता और वित्त पोषण विकल्पों में सुधार हुए हैं। प्रमुख चुनौतियां उच्च उधार लागत, पर्यावरण अनुपालन के झूठे दावे, ग्रीन लोन परिभाषाओं की बहुलता, परिपक्वता लंबी अवधि के हरे निवेश और निवेशकों के अपेक्षाकृत अल्पकालीन हितों के बीच मेल ना होना है। हम इन चुनौतियों में से कुछ को विस्तृत करते हैं, और कुछ संभावित नीतिगत उपायों पर चर्चा करते हैं।

उधार लेने की लागत

ग्रीन बांड जारी करने की लागत आमतौर पर भारत में अन्य बांड की तुलना में अधिक रही है। चार्ट 4 में पैनेल दर्शाता है कि 2015 से 5 से 10 वर्षों के बीच परिपक्वता के साथ जारी किए गए हरे बांड के लिए औसत कूपन दर आमतौर पर, इसी तरह के कार्यकाल के साथ कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड की तुलना में अधिक है। चार्ट 4 पैनेल बी INR के हरित बॉन्ड के लिए एक समान पैटर्न दिखाता है अमेरिकी डॉलर के लिए 10 वर्षों से अधिक या इसके बराबर के कार्यकाल के साथ हरित बॉन्ड की कूपन दर हालांकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स से कम थी।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत में ज्यादातर ग्रीन बॉन्ड सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों¹⁷ या कॉर्पोरेट द्वारा बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य के साथ जारी किए जाते हैं या तथ्य से स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र के ग्रीन बांड जारी करने वालों ने औसतन ग्रीन बॉन्ड¹⁸ के टेबल 6 के जारीकर्ताओं की तुलना में कम ऋण से संपत्ति अनुपात की सूचना दी। उनका बेहतर वित्तीय स्वास्थ्य उनके शेयर की कीमतों से भी स्पष्ट है। चार्ट 5 से पता चलता है

चार्ट 4 : जारी किए गए बॉन्ड्स के लिए औसत कूपन दर (प्रतिशत)



¹⁷ उदाहरण के लिए, भारतीय रेल वित्त निगम लि, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या आरईसी लिमिटेड और पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

¹⁸ इन संस्थाओं ने, हालांकि, अन्य बांड जारी किए।

तालिका 6: कॉर्पोरेट्स के लिए कुल संपत्ति के प्रतिशत के रूप में ऋण: जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की श्रेणी के आधार पर (औसत 1 जनवरी, 2015 और 12 फरवरी, 2020 के बीच)

क्षेत्र	जारीकर्ता	गैर जारीकर्ता
सभी	63.8	72.9
ऊर्जा	67.6	77.7
अक्षय / गैर-पारंपरिक ऊर्जा	69.4	96.6

स्रोत: ब्लूमबर्ग डेटा पर आधारित लेखकों की गणना।

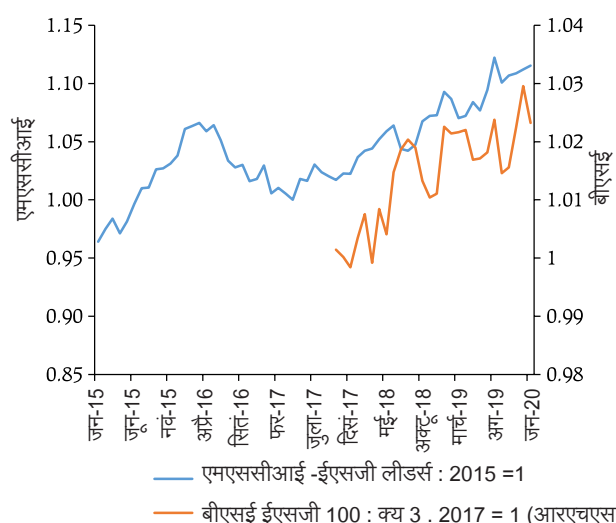
नोट: 10 वर्ष से कम (लेकिन > 5 वर्ष) की परिपक्वता के साथ बांड शामिल हैं। सरकारी बांड शामिल नहीं हैं।

एक इकाई को जारीकर्ता के रूप में टैग किया जाता है यदि उसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक ग्रीन बांड जारी किया हो।

की ईएसजी लीडर के स्टॉक मूल्य सूचकांक, स्टॉक मूल्य सूचकांक के शीर्षक का अनुपात हाल के दिनों में लगातार बढ़ रहा है तात्पर्य यह है कि आमतौर पर, ईएसजी से संबंधित पहलों में जिन संस्थाओं के शेयर की कीमत तय होती है वही होती है जो बाजार में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करती है।¹⁹

अपेक्षाकृत सुरक्षित होने के बावजूद भारत में ग्रीन बॉन्ड की उच्च उधार लागत असममित जानकारी (बाद में चर्चा की गई) के कारण हो सकती है। इस खंड में उच्च जोखिम की धारणा और अन्य शासन संबंधी मुद्दे मौजूदा साहित्य से पता चलता है, कि हरी

चार्ट 5 : जनरल स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में ईएसजी



स्रोत : एमएससीआई की ऑफिसियल वेबसाइट और सीईआईसी के आधार पर लेखक की गणना। बीएसई ईएसजी इंडेक्स अक्टूबर 2017 से उपलब्ध था।

¹⁹ हमने भारत के लिए MSCI समग्र सूचकांक MSCI ESG लीडर्स इंडेक्स के अनुपात को आधार के रूप में 2015 के साथ लिया। इसी प्रकार, हमने आधार के रूप में Q3 2017 के साथ बीएसई 100 सूचकांक के बीएसई ईएसजी 100 इंडेक्स के अनुपात को प्लॉट किया है। सभी वर्ष कैलेंडर वर्ष हैं।

परियोजनाओं में अक्सर उच्च लागत-सामने की लागत होती है, जिसमें कुछ लागत बचत विशेषता केवल लंबी अवधि में लागू होती है। हरित परियोजनाओं में परिपक्वता बेमेलता और उनके वित्तपोषण से उधार की लागत में वृद्धि होती है। (G20 GFSG 2016)²⁰ ग्रीन फाइनेंस और सूचना विषमता की एक सार्वभौमिक परिभाषा की अनुपस्थिति अक्सर "हरी धुलाई" में परिणित होती है। जिसमें निवेशकों को ग्रीन बॉन्ड (बेरेन्समैन और लिंडेनबर्ग 2016) के बारे में गलत संकेत मिल रहे हैं। इसमें से कई मुद्दे भारत में भी मौजूद हैं, जहां विकसित बाजारों की तुलना में वित्तीय बाजार अभी भी उभर रहा है।

उधारी लेने की लागत और जानकारी विषमता

उच्च उधारी लागत में शायद सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रही है। और हमारा विश्लेषण बताता है, कि यह असममित जानकारी के कारण हो सकता है। इसलिए भारत में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने से परिपक्वता बेमेल को कम करने, लागत उधार लेने और इस सेगमेंट में कुशल संसाधन आवंटन करने में मदद मिल सकती है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस तरह के सूचना अंतर को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं से संबंधित डेटाबेस है जबकि भारत पीएटी (प्रदर्शन प्राप्त व्यापार) और आरपीओ (अक्षय खरीद दायित्व सहित) विभिन्न रिपोर्टिंग तंत्रों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी करता है। कई अन्य देशों की तरह इसमें जलवायु वित्त पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय माप रिपोर्टिंग और सत्यापन मंच नहीं है। (जैन 2020)

बाजार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास

घरेलू बाजार के बड़े आकार और अब तक, हरे उपकरणों के बहुत छोटे प्रवेश को देखते हुए, अभी भी बहुत सारे और सर उपयोग में लाए जा सकते हैं। इस संदर्भ, में कुछ अध्ययनों के महत्व पर ध्यान दिया गया। (क) निवेश और पर्यावरण नीतियों के बीच समन्वय में वृद्धि, और (ख) मौजूदा घर्षणों को संबोधित करने में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर के लिए एक कार्यान्वयन योग्य

²⁰ <https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2017/the-banks-response-to-climate-change.pdf?la=en&hash=F676C781E5FAEE994C2A210A6B9EEE44879387>.

नीति ढांचा। इस नस में, कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को गहरा करने, ग्रीन इन्वेस्टमेंट शब्दावली के मानकीकरण, लगातार कॉरपोरेट्स रिपोर्टिंग और निवेशकों और प्राप्तकर्ताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करने जैसे कुछ नीतिगत उपाय ग्रीन फाइनेंस की कुछ कमियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। (बाजार आरबीआई 2019)

अन्य सार्वजनिक नीतियां

अन्य दृष्टिकोण उद्योग निकायों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्होंने हरी इमारतों के विस्तार की दिशा में पहल की है। जो कम पानी और ऊर्जा संसाधनों का उपभोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन बनाए रखते हैं, और रहने के लिए स्वस्थ स्थान प्रदान करते हैं। सरकार सभी स्तरों पर संभवतः अपनी वित्तीय और परिचालन आवश्यकताओं का बेहतर आकलन करने के लिए इन निकायों के साथ जुड़ सकती है। यह ऐसी नीतियां भी बना सकता है, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन और वितरण को लाभदायक बनाती है, खासकर छोटी फर्मों के लिए। आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रास्फीति दबाव और राजकोषीय समेकन पर उनके प्रभाव का संज्ञान लेते हुए भारत में हरित परियोजनाओं के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से कैलिब्रेट नीतियों की गुंजाइश है।

5. निष्कर्ष

सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता के रूप में ग्रीन फाइनेंस तेजी से उभर रहा है। इस अध्ययन में हम भारत में हरित वित्त के विकास की समीक्षा करते हैं, और हमारे निष्कर्ष बताते हैं, कि हाल के वर्षों में भारत में जन जागरूकता और वित्त पोषण विकल्पों में कुछ सुधार हुए हैं। मौजूदा साहित्य से पता चलता है कि बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में असम्मित जानकारी में कमी हुई है। हित धारकों के बीच समन्वय बढ़ने से दीर्घकालिक आर्थिक विकास की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

इस मोड़ पर दुनिया कोविड-19 और वैश्विक आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव से लड़ रही है। निसंदेह तत्काल नीति चुनौती वैश्विक अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करना है। हालांकि, महामारी ने सभी हित धारकों को नीतियों और वित्तीय परिचालन रणनीतियों के बारे में पुनर्विचार करने का अवसर भी प्रदान किया है, जो उन्होंने अब तक अपनाई है। और लंबे समय में एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, जो अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है। ग्रीन फाइनेंस निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साधन है, जो स्थाई आर्थिक विकास की दिशा में इस तरह के बदलाव को सुविधाजनक बना सकता है

संदर्भ

- Berensmann, K., & Lindenberg, N. (2016), "Green finance: actors, challenges and policy recommendations", German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Briefing Paper, 23
- Dikau, S., & Volz, U. (2018, September), "Central Banking, Climate Change and Green Finance", ADBI Working Paper Series (867).
- Geddes A., Schmidt T. S. and Steffen, B. (2018), "The multiple roles of state investment banks in low-carbon energy finance: An analysis of Australia, the UK and Germany", Energy Policy, 115 (2018), 158-170
- Jain, S. (2020), "Financing India's green transition", ORF Issue Brief No. 338, January 2020, Observer Research Foundation.
- Nassiry, D. (2018), "Green Bond Experiences in Nordic Countries", ADBI Working Paper, No. 816, March
- Olga, B., & Smorodinov, O. (2017), "Challenges to green finance in G20 countries", Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, 61 (10), 16-24

RBI (2019), "*Opportunities and Challenges of Green Finance*", Report on Trend and Progress of Banking in India (2018-19), 17-18.

Reddy, A. S. (2018), "*Green Finance- Financial Support for Sustainable Development*", International Journal of Pure and Applied Mathematics, 118(20), 645-650.

Shen, C., Zhao, K., & Ge, J. (2020), "*An Overview of Green Building Performance Database*", Journal of Engineering.

Volz, U. (2018, March), "*Fostering green finance for sustainable development in Asia*", ADBI Working Paper Series(814)

परिशिष्ट तालिका 1: भारत के प्रति विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड प्रतिबद्धता

क्षेत्र	परियोजना का नाम	स्थिति	स्वीकृति तिथि	अंतिम तिथि	कुल परियोजना लागत (मिलियन यूएस डालर)	आवंटित राशि (मिलियन यूएस डालर)
अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता	पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट IV	बंद किया हुआ	18 मार्च, 2008	31 जुलाई 2014	2114	400
अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता	रामपुर जल विद्युत परियोजना	बंद किया हुआ	13 सितंबर, 2007	31 दिसंबर 2014	670	400
अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता	ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम	सक्रिय	13 मई 2016	30 नवंबर, 2021	915	282.2
अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता	सौर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचा	सक्रिय	30 मार्च, 2017	31 जुलाई, 2022	200	8.5
स्वच्छ परिवहन	सतत शहरी परिवहन	बंद किया हुआ	10 दिसंबर, 2009	31 मार्च 2018	328.33	88.8
स्वच्छ परिवहन	पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर - II	सक्रिय	२२ अप्रैल २०१४	31 दिसंबर, 2020	1650	295.7
जल और अपशिष्ट प्रबंधन	आंध्र प्रदेश जल क्षेत्र में सुधार	बंद किया हुआ	3 जून 2010	28 जुलाई 2018	988.97	399.2
कृषि, भूमि उपयोग, वन और पारिस्थितिक संसाधन	जलवायु लचीला कृषि पर महाराष्ट्र परियोजना	सक्रिय	27 फरवरी, 2018	30 जून, 2024	599.55	4.2
कृषि, भूमि उपयोग, वन और पारिस्थितिक संसाधन	मेघालय समुदाय के नेतृत्व वाले परिदृश्य प्रबंधन परियोजना	सक्रिय	13 मार्च 2018	30 जून, 2023	60	0.3
कृषि, भूमि उपयोग, वन और पारिस्थितिक संसाधन	तमिलनाडु सिंचाई कृषि आधुनिकीकरण परियोजना	सक्रिय	1 दिसंबर, 2017	2 जून, 2025	455.8	48.9

स्रोत: विश्व बैंक

आवंटित राशि 30 जून, 2019 तक परियोजनाओं के वित्तपोषण का समर्थन करने के लिए आवंटित ग्रीन बॉन्ड आय की राशि है।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	75
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	76
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	77
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	78
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	79
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	79
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	80
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	81
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	82
9	कुल चलनिधि राशियां	82
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	83
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	83
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	84
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	84
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	85
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	86
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	87
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	88
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	89
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	89
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	89
21	थोक मूल्य सूचकांक	90
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	94
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	94
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	95
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	95
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	96
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	97
28	वाणिज्यिक पत्र	97
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	97
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	98

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	99
32	विदेशी मुद्रा भंडार	99
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	99
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	100
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	100
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	101
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	101
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	102
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	103
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	104
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	105
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	106
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	107
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	109
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	110
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	111
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	112
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	113
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	114

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2019-20		2020-21	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	3.9	4.8	4.3	-22.8	-7.0
1.1.1 कृषि	4.0	3.0	3.5	3.4	3.4
1.1.2 उद्योग	0.8	3.8	-0.2	-33.8	0.1
1.1.3 सेवाएं	5.0	5.5	6.1	-24.3	-11.1
1.1क अंतिम खपत व्यय	6.3	5.6	7.8	-19.2	-13.3
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-2.8	4.6	-3.9	-47.1	-7.3
	2019-20	2019		2020	
		अक्टू.	नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.8	-6.6	2.1	3.6	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	10.3	9.5	11.1	10.5
2.1.2 ऋण	6.1	8.9	7.2	5.6	5.7
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	8.8	7.2	5.6	5.8
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	7.0	8.6	21.5	19.2
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	15.3	12.4	12.8	15.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	10.6	9.8	11.6	12.5
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.50	18.50	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	4.9	4.8	3.8	3.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	75.8	75.5	72.0	72.2
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	17.0	22.5	2.0	9.5
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.6	28.3	28.3	31.0	30.5
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	36.2	73.3	62.4	85.4	74.7
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	5.15	5.15	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	4.90	4.90	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.95/9.40	8.95/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	7.70/8.20	7.65/8.10	6.65/7.10	6.60/7.10
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.25/6.85	6.25/6.60	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.25/3.50	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	5.07	5.03	3.19	3.10
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	5.04	4.99	3.20	2.93
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	5.21	5.12	3.36	3.26
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	5.30	5.14	3.45	3.39
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	6.54	6.65	5.91	5.84
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	70.96	71.73	73.97	73.80
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	78.81	78.98	86.97	88.02
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	8.98	3.38	3.35	3.24	3.36
3-माह (%)	5.93	3.61	3.35	3.46	3.52
6-माह (%)	5.05	3.99	3.76	3.89	4.23
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	4.6	5.5	7.6	6.9
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	7.6	8.6	5.9	5.3
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.69	0.0	0.6	1.5	1.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.77	6.0	7.6	4.7	2.7
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.63	-8.1	-7.3	-10.9	-9.9
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.29	-0.9	-0.8	2.1	3.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-7.66	-15.0	-11.8	-11.5	-13.3
7.2 निर्यात	-5.06	-1.7	-1.2	-5.1	-8.7

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2019	2020				
		दिसं.	नव. 27	दिसं. 4	दिसं. 11	दिसं. 18	दिसं. 25
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2244106	2744155	2746809	2758409	2749859	2751458
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	12	12	13	11	11	12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2244118	2744167	2746822	2758420	2749870	2751470
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	89990	113222	114371	114890	117642	116647
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2153365	2630160	2631676	2642769	2631474	2633880
1.2.3 रुपया सिक्का	846	763	785	775	761	754	942
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	913132	1445616	1468534	1460553	1454026	1460970
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	100	101	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	43	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	541417	461900	476750	445715	488262	457719
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	6593	5547	5613	5262	5437	5507
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	2698	2414	2411	2383	2510	2586
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	31221	27334	25782	26871	25967	27481
2.1.1.8 अन्य	605100	331060	944501	944440	966883	926924	962753
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	-	3778	13395	13296	4783	4782
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1145007	1462954	1469301	1462455	1480676	1476078
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	2058139	2908570	2937835	2923008	2934702	2937049
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	12	12	13	11	11	12
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	903533	1349768	1362970	1336197	1353079	1348295
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	2112	2112	10576	13017	6303	3946
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	30427	77097	77097	77097	77098	77318
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	23596	25833	25833	26133	26133
2.2.3.7 एक्विजिमेंट बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	10064	4479	9216	9242	9242	9241	9241
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	-	9703	10451	18479	15828	15826
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1042951	1005802	1284031	1286500	1286421	1285853	1296115
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	111774	153035	155153	156711	161156	160163
2.2.6.1 सोना	127644	105494	147429	149289	150333	154686	153378

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
नव. 1, 2020	-	148	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-147
नव. 2, 2020	-	679830	-	-	165	-	-	-	20000	-	-	-	-	-659665
नव. 3, 2020	-	692072	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-692072
नव. 4, 2020	-	682680	-	-	159	-	-	-	2830	-	-	-	-	-679691
नव. 5, 2020	-	691021	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-984	-691990
नव. 6, 2020	-	647614	-	-	18	-	-	-	10000	-	-	-	-	-637596
नव. 7, 2020	-	10386	-	-	2958	-	-	-	-	-	-	-	-	-7428
नव. 8, 2020	-	215	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-137
नव. 9, 2020	-	642236	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-642228
नव. 10, 2020	-	670096	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-670095
नव. 11, 2020	-	659861	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-659561
नव. 12, 2020	-	698316	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-491	-698795
नव. 13, 2020	-	666219	-	-	143	-	-	10000	10000	-	-	-	-236	-666312
नव. 14, 2020	-	298	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-261
नव. 15, 2020	-	193	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-180
नव. 16, 2020	-	22358	-	-	632	-	-	-	-	-	-	-	-	-21726
नव. 17, 2020	-	717800	-	-	330	-2525	-	-	-	-	-	-	-493	-720488
नव. 18, 2020	-	715755	-	-	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-715615
नव. 19, 2020	-	730129	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-1025	-731154
नव. 20, 2020	-	668078	-	-	266	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-667812
नव. 21, 2020	-	8016	-	-	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-7298
नव. 22, 2020	-	219	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-209
नव. 23, 2020	-	652825	-	-	34	350	-	-	-	-	-	-	-493	-652934
नव. 24, 2020	-	653535	-	-	44	-	-	-	-	-	-12773	-	-	-666264
नव. 25, 2020	-	646452	-	-	0	-1325	-	-	-	-	-8091	-	-493	-656361
नव. 26, 2020	-	673385	-	-	84	1	-	-	-	-	-6974	-	-	-680274
नव. 27, 2020	-	646182	-	-	0	-	-	10000	10000	-	-9510	-	-	-655692
नव. 28, 2020	-	2290	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-2220
नव. 29, 2020	-	588	-	-	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-446
नव. 30, 2020	-	27353	-	-	4950	-	-	-	-	-	-	-	-	-22403

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल हैं। ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंक द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार

विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के लिए प्राप्त परिपक्वता आय के लिए ऋणात्मक (-) चिन्ह दर्शाता है।
और ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	6928	15640	10261
1.1 क्रय (+)	72205	7458	15640	14289
1.2 विक्रय (-)	27108	530	0	4028
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	49142	114896	76326
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	25381	58127	68388
(करोड़ ₹)	312005	174408	432863	509189
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-6143	13556	28344

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	0	0	0
1.2 विक्रय (-)	7713	0	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	0	0	780

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)**

मद	30 नवंबर 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2637	0	2637
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	5692	0	5692
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	24864	0	24864
4. 1 वर्ष से अधिक	5171	10020	-4849
कुल (1+2+3+4)	38364	10020	28344

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2019	2020					
			दिसं. 20	जुला. 31	अग. 28	सितं. 25	अक्टू. 23	नव. 20
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	3856	80	300	50	6	266	1
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	4782	1615	30	0	0	-	0	0
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	65000	65000	65000	65000	75000	82500
4.2 बकाया	-	-	34376	34166	37691	36488	33234	34760
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	5471	34486	34466	37741	36494	33500	34761

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्विज बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2019	2020		
		नवं. 22	अक्टू. 23	नवं. 6	नवं. 20
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349748	2172488	2619578	2637687	2673534
1.1 संचलन में नोट	2420964	2241262	2688064	2707002	2743952
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25605	25380	25738	25798	25798
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	94897	94967	95856	96958
2 जनता की जमाराशियां	1776200	1480272	1666403	1657494	1674841
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1447960	1625686	1615836	1632938
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	32312	40717	41658	41904
3 एम₁ (1 + 2)	4125948	3652760	4285981	4295180	4348375
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	139402	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4276911	3792162	4436944	4446143	4499338
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	12292989	13517758	13639674	13589563
7 एम₃ (3 + 6)	16799963	15945749	17803739	17934854	17937939
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	401165	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	17233404	16346914	18237180	18368295	18371380

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
			नव. 22	अक्टू. 23	नव. 6
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4890841	5587218	5716069	5691514
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	965438	905454	996346	1023947
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	1001006	1248802	1291718	1293290
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	1000408	1242339	1282681	1282559
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	598	6463	9037	10731
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	55616	35568	343348	295372	269343
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	35526	343305	295330	269301
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	42	43	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3968170	3925403	4681764	4719723	4667567
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10468270	10999620	11079549	11092385
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	7144	14792	14934	12173
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10461126	10984828	11064615	11080212
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	9860303	10338868	10419271	10434880
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	588692	636209	635748	635516
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	12132	9750	9597	9815
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3801036	3425222	4365595	4447921	4493779
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	3207225	4120941	4203267	4249125
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	3207434	4121184	4203510	4249368
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	209	243	243	243
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	210634	217997	244655	244655	244655
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26123	26481	26541	26541
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3026427	2864707	3175175	3335226	3366279
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1137091	1412121	1471603	1464944
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1648085	1727616	1763054	1863623	1901335
एम₃ (1+2+3+4-5)	16799963	15945749	17803739	17934854	17937939

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		1	नव. 22	अक्टू. 23	नव. 6
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125948	3652760	4285981	4295180	4348375
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745776	9103488	10294913	10358590	10389164
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923893	16087659	17894503	18027697	18036372
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2172488	2619578	2637687	2673534
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13560689	14978869	15090079	15056913
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1447960	1625686	1615836	1632938
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	12112729	13353183	13474243	13423975
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5450728	6008932	6063409	6040789
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	158123	180512	74470	66156
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6662001	7344251	7410834	7383186
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	32312	40717	41658	41904
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	322170	255339	258274	264021
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16857025	16251859	17549226	17769707	17737777
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	4890841	5587218	5716069	5691514
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	965438	905454	996346	1023947
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3968170	3925403	4681764	4719723	4667567
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896663	11361017	11962008	12053638	12046263
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	7144	38919	38336	35419
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11883497	11353873	11923089	12015302	12010844
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	883989	926628	940632	919780
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26123	26481	26541	26541
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	3141351	4222595	4298103	4366249
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3207225	4120941	4203267	4249125
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-65874	101655	94836	117124
2.4 पूंजी खाता	2670439	2482957	2862261	2910875	2900745
2.5 अन्य मदें (निवल)	901344	848715	1041538	1155778	1193449

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2019		2020	
		नव.	सित्त.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	16923893	16087659	17826724	17894503	18036372
2 डाकघर जमाराशियां	433441	401165	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	17357334	16488824	18260165	18327944	18469813
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	56839	38481	35342	34778
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	3262	5700	3114	2645
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	49162	29300	28700	28600
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	4415	3481	3528	3533
5 एल₂ (3 + 4)	17414813	16545663	18298646	18363286	18504591
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	..	31905
7 एल₃ (5 + 6)	17446718	..	18330551

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		नव. 22	अक्टू. 23	नव. 6	नव. 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2267385	2714545	2733543	2770493
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	555408	470552	484539	504678
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	517462	437010	450857	471488
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	32312	40717	41658	41904
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029707	2855104	3225814	3259739	3317074
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	758848	490513	501535	506353
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	965438	905454	996346	1023947
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	964882	899034	987351	1013258
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	999581	1241461	1281845	1281765
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	999581	1241461	1281845	1281765
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	827	878	836	794
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	35526	343305	295330	269301
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	556	6420	8995	10689
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	-213734	-453860	-533147	-553013
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	-213734	-429733	-509745	-529767
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	7144	38919	38336	35419
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	1604	-	-	-
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	24127	23402	23246
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26123	26481	26541	26541
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3207225	4120941	4203267	4249125
2.3.1 सोना	230527	192307	271325	278941	267074
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	3014935	3849633	3924343	3982068
2.4 पूंजी खाता	1165066	1012649	1251601	1300949	1288399
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	124442	160520	170654	176545

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2019-20	2019		2020			
		नव. 29	अक्टू. 30	नव. 6	नव. 13	नव. 20	नव. 27
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3029707	2874296	3244482	3259739	3313435	3317074	3313212
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2256875	2715266	2733543	2777389	2770493	2770773
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	581895	488063	484539	494286	504678	497195
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	35526	41154	41658	41761	41904	45244
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	992192	1001249	944911	996346	1022936	1023947	1036501
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-214059	-247355	-467693	-509745	-528027	-529767	-545484
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	13166	6877	14795	14934	14736	12173	11175
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3222285	4150295	4203267	4258517	4249125	4246261
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26178	26541	26541	26541	26541	26618
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1378342	1134938	1424366	1471603	1481267	1464944	1461859

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		नवं. 22	अक्टू. 23	नवं. 6	नवं. 20
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	12778214	14126937	14237881	14204846
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1331740	1505254	1495022	1511516
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	11446474	12621683	12742859	12693330
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	5150913	5679757	5734287	5711999
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	158123	180512	74470	66156
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6295561	6941925	7008573	6981332
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	309439	322170	255339	258274	264021
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14967529	14463919	15708663	15837921	15782139
2.1.1 सरकार को ऋण	3738696	3715868	4438623	4475235	4423853
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228833	10748051	11270040	11362686	11358285
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	9860303	10338868	10419271	10434880
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	9768999	10272209	10335640	10345924
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11997	9021	11896	10318	11115
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	3700	1610	1428	1472
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	875027	917666	931670	910818
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-65874	101655	94836	117124
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	236374	330844	324993	348921
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	180260	164575	165431	165588
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	121989	64614	64726	66208
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	816180	951675	1046118	1087871
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	517462	437010	450857	471488
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	84984	84932	85516	86616
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	-213734	-429733	-509745	-529767
2.4 पूंजी खाता	1481202	1446137	1586490	1585756	1588175
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	716216	667703	793227	896965	930091
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	385783	499287	541929	570401
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	66273	-45368	68612	62107	62737

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020	2019	2020		
	की स्थिति	नवं. 22	अक्टू. 23	नवं. 6	नवं. 20
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3747349	3719568	4440234	4476662	4425325
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	99328	88751	88669	85133
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	11286	11363	11225	11380
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	66368	71675	71981	71283
3.3 अन्य	5734	5515	5430	5095	5416
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	123067	126857	123301	122421
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	239223	306444	306410	304812
4.3 अन्य	191690	199063	146949	146379	144147
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	48279	31082	35432	35074
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	82173	128920	131050	131153

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2019-20	2019	2020		2019-20	2019	2020	
		नव.	अक्टू.	नव.		नव.	अक्टू.	नव.
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	219	219	209	208	142	142	133	132
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	320240	249308	277233	263597	314513	244433	272101	258505
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	187449	210335	208057	234348	182731	205405	203177
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	49892	50821	38428	64001	49866	50821	38428
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	11967	16077	17112	16163	11836	15875	16901
2 अन्य के प्रति देयताएं	14905949	14314792	15733984	15770273	14480607	13953219	15303052	15340848
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	13447567	14835260	14891439	13567492	13098829	14420000	14478103
2.1.1 मांग	1653242	1448683	1606832	1605873	1617003	1416506	1571374	1570449
2.1.2 मीयादी	12322309	11998884	13228427	13285566	11950489	11682323	12848625	12907654
2.2 उधार	313908	335569	266583	273826	309439	331841	262285	269599
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	531656	632141	605007	603676	522549	620767	593146
3 रिजर्व बैंक से उधार	285623	23012	115757	77097	285623	23012	115757	77097
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	285623	23012	115757	77097	285623	23012	115757	77097
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	643038	642086	557017	570196	623446	626159	541682	554866
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	85089	89874	95116	87260	83184	87683	92966
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	553367	556997	467143	475081	536186	542975	453999	461900
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	323680	262359	276923	264846	260238	207281	216919	205766
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	168690	189036	181133	155401	142276	155579	147537
5.1.1 चालू खाते में	17204	14405	21643	14218	14457	12215	19438	12120
5.1.2 अन्य खातों में	164256	154285	167393	166914	140945	130062	136141	135417
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	24263	29193	28166	20273	7015	7747	7305
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	28990	22005	21766	30531	24968	21494	21321
5.4 अन्य आस्तियां	60619	40416	36689	33782	54032	33022	32099	29602
6 निवेश	3865544	3814598	4597987	4552090	3747349	3716854	4468088	4419911
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3850819	3797839	4590080	4544271	3738696	3706537	4466431	4418470
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	16759	7907	7819	8653	10317	1656	1441
7 बैंक ऋण	10705336	10176213	10721829	10791739	10370861	9890071	10387948	10457104
7क खाद्यान्न ऋण	82172	117557	100684	123083	51763	90526	70281	92681
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	9969053	10548573	10620894	10149509	9686695	10217564	10288180
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	24641	24977	23595	25658	23902	23826	23324
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	147209	126309	102181	99515	145683	124288	101193	98610
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	23182	17127	17344	20458	22762	16877	17091
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	33028	28971	30391	29554	32424	28488	29899

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक 2020-21	वर्ष-दर-वर्ष 2020
		नवंबर 22	अक्टू. 23	नवंबर 20		
1	2	3	4	5	6	
1 सकल बैंक ऋण	9263134	8764913	9213059	9286902	0.3	6.0
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	91005	66428	88662	71.9	-2.6
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211544	8673908	9146631	9198240	-0.1	6.0
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157796	1134004	1218717	1230526	6.3	8.5
1.2.2 उद्योग	2905151	2772248	2739841	2753281	-5.2	-0.7
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	381825	362758	361563	364515	-4.5	0.5
1.2.2.2 मझौले	105598	102601	123150	124028	17.5	20.9
1.2.2.3 बड़े	2417728	2306889	2255128	2264738	-6.3	-1.8
1.2.3 सेवाएं	2594945	2362955	2576581	2569834	-1.0	8.8
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	144466	139754	148172	154752	7.1	10.7
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20051	19052	19368	19120	-4.6	0.4
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45977	43468	48594	51309	11.6	18.0
1.2.3.4 नौवहन	6557	6704	5364	5329	-18.7	-20.5
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	177085	170660	178191	128577	-27.4	-24.7
1.2.3.6 व्यापार	552392	501677	575886	575549	4.2	14.7
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	263397	217569	268058	275279	4.5	26.5
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	288995	284108	307828	300270	3.9	5.7
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	220685	227992	233150	1.5	5.6
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	807383	730907	778739	788222	-2.4	7.8
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	611264	530048	594275	613826	0.4	15.8
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553652	2404701	2611492	2644599	3.6	10.0
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9298	5499	6881	6937	-25.4	26.2
1.2.4.2 आवास	1338964	1274747	1373277	1383427	3.3	8.5
1.2.4.3 मीयादी जमा राशि की जमानत पर अग्रिम	79496	62892	61460	64512	-18.8	2.6
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	4982	6296	4655	-12.7	-6.6
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108094	105860	110207	114307	5.7	8.0
1.2.4.6 शिक्षा	65745	66902	65432	65180	-0.9	-2.6
1.2.4.7 वाहन ऋण	220609	207996	224022	228758	3.7	10.0
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	726112	675823	763917	776823	7.0	14.9
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2897461	2694733	2930417	2934836	1.3	8.9
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1146624	1125474	1203789	1214929	6.0	7.9
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1149394	1057378	1125326	1122053	-2.4	6.1
1.2अ.2.1 विनिर्माण	381826	362758	361562	364515	-4.5	0.5
1.2अ.2.2 सेवाएं	767568	694620	763764	757538	-1.3	9.1
1.2अ.3 आवास	449945	454000	462216	462488	2.8	1.9
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	38237	33526	32760	32644	-14.6	-2.6
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	51906	53410	51789	51506	-0.8	-3.6
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	388	387	540	588	51.5	51.9
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	731409	698449	727814	766575	4.8	9.8
1.2अ.8 निर्यात ऋण	16114	13219	13850	12916	-19.8	-2.3

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2020
			नव. 22	अक्टू. 23		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2905151	2772248	2739841	2753281	-5.2	-0.7
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43927	41372	42944	43831	-0.2	5.9
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154146	136930	144158	147775	-4.1	7.9
1.2.1 चीनी	27382	24624	18371	20291	-25.9	-17.6
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19240	17430	17956	18354	-4.6	5.3
1.2.3 चाय	5375	5832	5851	5809	8.1	-0.4
1.2.4 अन्य	102149	89044	101980	103321	1.1	16.0
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16522	14030	14830	14454	-12.5	3.0
1.4 वस्त्र	192424	186324	185856	186774	-2.9	0.2
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	83448	84289	84853	-5.0	1.7
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2181	2318	2429	14.8	11.4
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	25821	26628	27251	4.5	5.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	74874	72621	72241	-3.6	-3.5
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	10813	11368	11404	2.8	5.5
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12233	11968	12786	12795	4.6	6.9
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30965	30230	33159	33986	9.8	12.4
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	75834	52466	61172	60025	-20.8	14.4
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	173231	171479	177799	-12.4	2.6
1.9.1 उर्वरक	49066	34112	36560	37894	-22.8	11.1
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	48501	48477	48875	-8.5	0.8
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	37445	35172	39564	-6.3	5.7
1.9.4 अन्य	58223	53173	51270	51466	-11.6	-3.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	47029	47580	49523	-1.8	5.3
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	8686	8748	8785	0.1	1.1
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	59309	57789	57993	-1.2	-2.2
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	347906	337746	334078	-4.6	-4.0
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	265599	247448	245072	-6.6	-7.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87929	82307	90298	89006	1.2	8.1
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157259	162680	137361	137233	-12.7	-15.6
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30159	32895	27146	27488	-8.9	-16.4
1.14.2 अन्य	127100	129785	110215	109745	-13.7	-15.4
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	81472	88400	86153	4.3	5.7
1.16 रत्न और आभूषण	59515	61310	57374	60910	2.3	-0.7
1.17 निर्माण	104288	100091	104447	101379	-2.8	1.3
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1025154	999104	1007085	-4.4	-1.8
1.18.1 पावर	559774	562711	552553	551731	-1.4	-2.0
1.18.2 दूरसंचार	143760	130961	100969	103550	-28.0	-20.9
1.18.3 सड़क	190676	186528	197379	201550	5.7	8.1
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	159703	144954	148203	150254	-5.9	3.7
1.19 अन्य उद्योग	239266	221247	223540	221299	-7.5	0.0

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2019		2020					
		अक्टू. 25;	अग. 14.	अग. 28;	सितं. 11	सितं. 25	अक्टू. 09	अक्टू. 23	अक्टू. 30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	124101.8	64187.1	125939.1	126547.5	126582.5	126143.1	126795.8	127166.1	127348.2
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	26213.8	18520.0	24074.5	24751.6	24479.0	22274.4	23152.3	20866.1	22714.0
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	5179.8	3821.7	3773.1	3873.1	4189.6	4308.6	3860.0	4028.2
2.1.1.2 अन्य	14,523.6	9889.1	13677.4	14264.3	14492.2	13472.0	13419.2	13039.0	13517.3
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	20.0	135.0	264.9	209.9	229.9	70.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	3431.1	6440.4	6449.2	5903.7	4382.9	5354.5	3967.1	5168.5
2.2 मीयादी देयताएं	167684.5	109889.9	172745.5	171640.9	171314.7	172128.5	172383.8	174055.4	172354.2
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	54683.9	58983.7	57209.2	57723.3	56835.6	57391.0	57259.1	56969.6
2.2.1.2 अन्य	109578.2	54297.9	112261.6	112283.2	112090.2	112671.1	113376.6	114127.1	113830.9
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	0.0	629.9	629.9	629.9	673.0	656.5	749.9	629.9
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	908.1	870.2	1518.6	871.2	1948.9	959.6	1919.2	923.8
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	45401.3	57354.0	53795.3	56629.9	57927.2	58455.2	56285.3	55909.0
4.1 मांग	13764.4	12636.9	14067.2	13174.5	13809.3	14065.7	14318.1	13606.7	13041.1
4.2 मीयादी	39007.8	32764.4	43286.7	40620.8	42820.6	43861.5	44137.2	42678.5	42867.9
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	9428.2	6024.3	6875.5	6841.4	6879.6	7000.4	6955.6	6734.9	7238.4
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	302.8	572.4	592.3	575.6	555.1	528.6	572.3	558.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	5721.5	6303.2	6249.1	6304.0	6445.3	6426.9	6162.6	6679.5
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1521.7	774.5	809.9	807.4	983.9	988.1	795.4	824.5	935.7
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50626.9	32529.2	58199.1	55743.6	56942.0	59312.3	59137.6	59110.5	58774.4
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	25283.9	18737.1	25269.1	25414.9	27749.8	26346.6	25721.7	24240.2	24871.2
9 बैंक ऋण (10.1+11)	110905.5	63418.9	112631.8	113285.8	112267.8	111857.3	111842.7	110711.2	111109.5
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	110901.5	63417.1	112631.2	113285.2	112252.0	111841.4	111826.8	110695.3	111093.5
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	78322.8	79793.4	77827.8	79526.6	79397.4	81562.1	82624.9	82258.8
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	1.8	0.6	0.6	15.7	15.9	15.9	15.9	16.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	नव. '19	अक्टू.'20	नव.'20(अ)	नव.'19	अक्टू.'20	नव.'20(अ)	नव.'19	अक्टू.'20	नव.'20(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	146.3	149.6	147.5	150.9	163.4	164.4	153.6	167.0	166.7	151.9	164.7	165.2
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	141.8	145.4	144.4	144.1	149.7	148.8	142.5	146.8	145.8
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	163.7	188.6	188.5	162.4	195.5	194.0	163.2	191.0	190.4
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	143.8	171.6	173.3	148.4	176.9	177.9	145.6	173.6	175.1
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	147.1	153.8	153.9	145.9	153.9	154.3	146.7	153.8	154.0
1.5 तेल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	126.0	145.4	150.0	121.5	138.0	140.5	124.3	142.7	146.5
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	146.2	146.5	145.9	148.8	150.5	149.9	147.4	148.4	147.8
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	191.4	222.2	225.4	215.7	245.3	241.2	199.6	230.0	230.8
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	136.2	155.9	159.5	134.6	158.7	161.1	135.7	156.8	160.0
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	113.8	114.9	114.3	115.0	117.2	117.0	114.2	115.7	115.2
1.10 मसाले	145.6	145.1	145.5	147.3	162.0	163.5	146.3	161.4	161.2	147.0	161.8	162.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	138.7	150.0	153.2	130.5	141.5	143.1	135.3	146.5	149.0
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	157.7	162.7	163.6	157.2	165.1	165.9	157.5	163.8	164.7
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	166.3	169.0	167.0	167.2	183.4	183.6	169.9	188.8	189.8	167.9	184.8	185.3
3 कपड़ा और जूते	151.3	143.7	148.3	151.5	155.5	156.3	144.2	148.8	149.3	148.6	152.8	153.5
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	152.3	156.3	157.1	146.3	151.1	151.6	149.9	154.3	154.9
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	147.0	151.0	151.6	132.6	136.4	136.6	141.0	144.9	145.4
4 आवास	--	152.2	152.2	--	--	--	153.5	158.0	158.4	153.5	158.0	158.4
5 ईंधन और लाइट	148.6	131.5	142.2	148.4	147.5	148.8	132.2	137.3	138.7	142.3	143.6	145.0
6 विविध	145.6	135.9	140.9	146.1	154.5	155.2	136.3	146.6	146.8	141.3	150.7	151.1
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	150.9	152.8	153.3	139.1	145.1	145.4	145.3	149.2	149.6
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	154.3	160.4	161.6	142.8	152.0	152.6	149.9	157.2	158.2
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	132.1	146.1	146.3	121.7	135.2	135.5	126.6	140.4	140.6
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	149.1	153.6	154.1	136.7	144.4	144.4	142.1	148.4	148.6
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	160.8	161.6	162.7	151.8	156.4	156.7	155.5	158.6	159.2
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	140.6	156.2	156.6	139.8	157.9	157.8	140.3	156.9	157.1
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	147.3	145.1	146.3	149.9	159.8	160.7	147.0	156.7	156.9	148.6	158.4	158.9

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अर्न्तम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2020		
				नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	--	119.5	119.9
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	1000	1052	1060
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	986	1006	1057	1065

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2020	
		नव.	अक्टू.
	1	2	3
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	38122	50698
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	44938	61320

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			नव.	सितं.	अक्टू. (अ)	नव. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	121.8	122.3	122.9	123.8	124.2
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	143.3	147.2	148.8	152.4	151.2
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	155.8	162.6	168.4	170.4	169.0
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	162.5	158.6	158.1	158.8
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.7	199.5	211.1	222.3	213.2
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	146.6	153.8	154.3	154.7
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	148.7	150.7	148.0	149.6
1.1.1.5 मसाले	0.529	143.9	153.0	149.1	153.0	156.5
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	142.2	172.1	167.0	166.9
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	128.7	127.0	124.5	129.7	137.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.2	123.5	110.6	114.2	119.8
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	149.6	155.5	158.0	162.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	104.1	104.6	109.6	113.9
1.1.2.4 फूल	0.204	238.0	238.5	203.4	231.7	308.3
1.1.3 खनिज	0.833	154.5	142.6	145.5	167.6	145.5
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.4	133.0	136.8	162.6	136.8
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	179.0	176.4	176.1	185.1	176.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	85.3	86.0	67.4	72.0	64.0
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	102.2	101.3	91.9	91.1	91.3
1.2.1 कोल	2.138	125.3	126.5	126.4	126.4	126.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	141.9	141.6	141.6	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	131.1	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	92.3	91.1	77.5	76.2	76.5
1.2.3 बिजली	3.064	111.8	110.0	105.3	105.3	105.3
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	118.3	117.8	120.1	120.3	121.3
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	133.9	135.4	140.7	140.7	142.1
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	137.6	138.3	136.9	136.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	137.9	142.1	136.3	136.0
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	114.9	119.7	118.4	122.4
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.3	119.4	137.3	140.5	147.1
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	147.6	145.8	145.7	144.6
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	148.1	143.8	142.9	142.0
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	135.1	105.8	107.5	110.9
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	133.9	138.1	137.9	138.6
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.3	119.5	119.7	118.6	118.6
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.2	126.8	127.5	127.8	129.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	132.6	132.4	131.3	131.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.7	142.8	191.6	183.9	174.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	137.1	145.9	145.8	146.6
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	128.3	131.4	130.7	130.4
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	163.9	143.2	141.9	140.4
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.6	178.2	170.6	170.0	171.0
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	123.6	123.7	123.9	123.8	124.2
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	117.8	118.4	120.0	120.2	120.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	125.1	126.8	124.8	126.0
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	130.5	127.4	128.5	128.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	153.4	153.0	155.3	155.3	156.1
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.4	153.0	155.3	155.3	156.1

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			नव.	सितं.	अक्टू. (अ)	नव. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.7	116.5	113.6	114.7	116.4
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	105.2	101.2	102.3	105.1
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	130.2	128.6	129.9	130.3
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	114.7	114.2	113.8	114.7
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	134.8	131.4	130.8	132.3
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.1	146.0	154.6	155.6	157.2
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	117.9	113.2	115.5	114.7
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.3	138.6	138.3	138.2	139.6
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	139.6	137.7	137.1	138.4
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	135.9	136.1	140.0	141.1	142.7
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	118.6	119.2	118.7	118.0	118.8
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	106.0	102.7	102.8	103.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	136.3	138.4	138.6	138.3
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.3	121.1	121.3	119.9	121.2
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.7	133.1	133.9	133.5	134.9
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	121.0	119.0	120.3	119.9
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.8	135.2	134.7	136.6
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	176.2	176.3	188.2	189.6	189.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	121.6	127.5	125.5	127.5
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.1	119.7	119.1	119.2	119.6
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	122.6	120.9	120.6	121.5
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	115.0	114.0	119.8	120.9	122.8
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	120.8	115.5	115.0	113.2
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	150.6	151.7	154.2	155.2	153.5
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	151.7	154.2	155.2	153.5
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	117.5	116.5	116.1	116.8	117.7
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	119.9	117.0	114.8	115.2	116.6
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	123.4	123.1	123.1	122.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.4	110.8	112.4	115.5	118.5
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	122.6	122.9	125.4	125.8	125.7
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	114.0	114.6	114.3	112.9
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.6	117.8	119.6	120.0	120.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	114.0	112.9	112.9	114.7
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.9	96.6	88.3	89.4	91.6
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	127.3	127.5	130.0	131.0	131.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.3	127.5	130.0	131.0	131.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	108.5	107.7	109.5	109.7	110.8
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	97.8	97.5	97.9	96.7
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.5	94.1	92.2	90.8	93.2
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	114.5	117.9	118.3	120.2
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	116.7	115.7	116.8	116.5	117.1
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.5	121.2	128.3	127.6	126.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	108.5	108.5	109.0	110.3
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.8	103.3	112.7	107.5	113.3
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	112.5	107.9	108.0	108.0
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	119.5	118.5	119.6	119.1	119.5

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			नव.	सितं.	अक्टू. (अ)	नव. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.6	122.1	123.9	125.0	125.6
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	120.2	119.1	120.8	121.3	121.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	84.9	77.6	77.6	81.3
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	106.2	103.4	108.2	108.9	110.8
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.6	96.0	104.9	105.3	107.9
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	107.7	101.8	110.8	111.4	113.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	93.2	97.3	97.3	99.4
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	101.9	106.3	108.0	109.6
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	102.2	111.6	115.4	117.5
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	99.5	102.7	102.6	104.9
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.9	99.4	105.9	105.7	106.0
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.2	123.7	123.2	123.3	128.9
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	106.7	110.9	111.0	113.5
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	112.8	112.6	108.6	108.5	108.9
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	151.4	143.0	143.6	145.4
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.5	115.7	113.3	114.4	115.8
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.9	113.5	110.1	111.9	113.1
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	125.6	123.0	125.4	126.9
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	104.7	106.3	98.6	98.6	98.7
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.5	101.4	96.1	96.3	99.4
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	100.3	102.5	102.6	102.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	123.5	123.9	123.9	125.4
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.4	109.7	109.2	108.9	108.2
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	97.8	97.9	98.8	99.2
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.0	135.2	135.2	134.0
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	118.8	114.3	113.8	114.4
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.8	95.3	97.9	96.5	94.7
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	113.5	106.1	106.1	106.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	139.1	139.7	142.9	142.6	141.7
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.6	103.1	101.6	101.6	102.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	109.4	102.0	102.0	95.7
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.3	112.1	112.6	112.5	113.4
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	111.2	112.2	111.7	112.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.0	117.9	117.9	119.0	118.9
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	104.1	93.3	94.0	98.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	109.7	109.5	114.7	114.0	115.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.7	110.1	110.7	110.8
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	120.3	119.4	119.0	118.9
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	107.3	108.5	109.0	110.3
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	113.1	112.8	113.7	113.9	113.7
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	104.2	105.6	105.9	105.5
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	120.0	119.9	119.9	120.3
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.2	111.0	111.0	111.1	111.2
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	110.1	107.4	110.4	111.2	110.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	80.4	81.9	82.0	81.7
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	111.9	113.8	113.6	112.4

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			नव.	सितं.	अक्टू. (अ)	नव. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	130.4	128.4	129.7	128.2
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	120.9	121.7	121.2	121.6
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	107.9	108.7	107.9	108.1
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	75.4	75.3	75.0	75.3
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.2	123.6	127.7	128.6	128.4
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.7	119.9	122.4	122.4	123.3
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	126.7	128.3	128.8	128.3
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.0	65.6	64.4	64.3	64.4
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	114.5	115.0	118.3	117.3	117.8
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.2	115.2	120.4	119.2	119.9
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	114.8	116.0	115.3	115.5
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	118.0	118.4	126.2	126.7	127.5
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	106.4	106.6	104.7	104.7	104.7
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	114.7	124.9	125.6	126.5
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	128.9	130.5	128.2	128.2	128.7
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	126.9	127.5	127.7	127.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	130.9	129.2	130.5	132.9	132.9
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.9	129.2	130.5	132.9	132.9
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	112.7	113.5	136.9	134.8	136.1
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.9	110.6	135.4	133.2	134.5
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	175.9	163.0	166.4	170.2
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	130.9	131.1	131.0	130.8
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.9	137.0	142.6	142.9	142.8
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	162.5	166.9	168.1	168.1
2 खाद्य सूचकांक	24.378	147.6	152.4	158.0	159.3	158.9

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल-अक्टूबर		अक्टूबर	
				2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	128.0	105.6	124.0	128.5
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	100.4	87.0	99.5	98.0
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	129.3	103.8	126.3	130.7
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	164.9	155.7	145.8	162.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	124.4	108.6	121.7	117.7
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	94.6	62.0	88.5	91.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	135.1	108.6	136.4	137.5
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	135.6	107.4	129.9	140.0
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	124.1	84.7	113.3	133.2
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	143.1	134.6	138.6	149.0

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-नवंबर			
	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
				2020-21	2019-20
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	2020926	812710	983214	40.2	50.1
1.1 कर राजस्व (निवल)	1635909	688430	750614	42.1	45.5
1.2 करेतर राजस्व	385017	124280	232600	32.3	74.3
2 पूंजीगत प्राप्ति	224967	18141	29009	8.1	24.2
2.1 ऋण की वसूली	14967	11962	10910	79.9	73.6
2.2 अन्य प्राप्ति	210000	6179	18099	2.9	17.2
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2245893	830851	1012223	37.0	48.6
4 राजस्व व्यय	2630145	1665200	1606215	63.3	65.6
4.1 ब्याज भुगतान	708203	383425	341812	54.1	51.8
5 पूंजी व्यय	412085	241158	213842	58.5	63.2
6 कुल व्यय (4+5)	3042230	1906358	1820057	62.7	65.3
7 राजस्व घाटा (4-1)	609219	852490	623001	139.9	128.4
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	796337	1075507	807834	135.1	114.8
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	88134	692082	466022	785.3	1076.5

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2020-21

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2019-20		2020					
	2019	नव. 29	अक्टू. 23	अक्टू. 30	नव. 6	नव. 13	नव. 20	नव. 27
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	10165	15658	2885	2540	2262	2360	2357	2001
1.2 प्राथमिक व्यापारी	9190	14558	12884	15647	11331	10912	11215	12584
1.3 राज्य सरकारें	8173	62729	68665	70665	69680	72680	70680	71680
1.4 अन्य	48004	93697	134685	128809	131556	128879	125634	121644
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	66419	72356	152639	152250	153121	149567	140282	126536
2.2 प्राथमिक व्यापारी	43302	27263	57664	61725	55035	49692	39002	38808
2.3 राज्य सरकारें	13386	6078	4033	4033	4103	4103	4233	4233
2.4 अन्य	22465	26531	118301	101876	94930	90606	93761	94013
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	49660	61801	136500	135642	132932	132610	138677	140904
3.2 प्राथमिक व्यापारी	70672	61512	124833	129471	129001	127705	120149	120831
3.3 राज्य सरकारें	11945	17890	15842	15842	15757	15757	15627	16367
3.4 अन्य	70576	53155	122816	119782	123958	126313	132045	131253
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	155112	129972	117945	116438	96693	79718	119046	159713
4.4 अन्य	617	243	392	392	63	714	198	233
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	423957	513228	951749	938281	923666	911184	893661	880853

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
अक्टू. 28	9000	88	38386	8053	39	8997	8053	17050	99.21	3.1972		
नव. 4	9000	99	49324	7052	26	8998	7052	16050	99.22	3.1735		
नव. 11	9000	88	57933	5062	13	8989	5062	14050	99.22	3.1442		
नव. 18	9000	80	43532	5059	7	8992	5059	14050	99.26	2.9789		
नव. 25	9000	70	41371	5052	16	8998	5052	14050	99.28	2.9292		
182-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
अक्टू. 28	3000	59	17305	0	26	3000	0	3000	98.35	3.3594		
नव. 4	3000	64	19311	1	13	2999	1	3000	98.35	3.3598		
नव. 11	3000	61	19019	1	13	2999	1	3000	98.36	3.3497		
नव. 18	3000	77	17144	3	25	2997	3	3000	98.36	3.3356		
नव. 25	3000	103	27304	8	7	2992	8	3000	98.40	3.2599		
364-दिवसीय खज़ाना बिल												
2020-21												
अक्टू. 28	4000	69	13985	0	33	4000	0	4000	96.67	3.4542		
नव. 4	4000	53	13466	0	3	4000	0	4000	96.69	3.4331		
नव. 11	4000	70	17260	1	10	3999	1	4000	96.67	3.4491		
नव. 18	4000	62	17261	0	8	4000	0	4000	96.70	3.4168		
नव. 25	4000	70	18108	741	14	3999	741	4740	96.73	3.3949		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1	2	2
नवंबर	2, 2020	1.80-3.45	3.17
नवंबर	3, 2020	1.80-3.50	3.18
नवंबर	4, 2020	1.80-3.45	3.15
नवंबर	5, 2020	1.80-3.45	3.15
नवंबर	6, 2020	1.75-3.50	3.17
नवंबर	7, 2020	2.45-3.90	3.61
नवंबर	9, 2020	1.80-3.50	3.20
नवंबर	10, 2020	1.80-3.50	3.13
नवंबर	11, 2020	1.80-3.50	3.18
नवंबर	12, 2020	1.80-3.45	3.18
नवंबर	13, 2020	1.80-3.50	3.21
नवंबर	17, 2020	1.80-3.45	3.13
नवंबर	18, 2020	1.80-3.40	3.12
नवंबर	19, 2020	1.80-3.50	3.13
नवंबर	20, 2020	2.10-3.50	3.14
नवंबर	21, 2020	2.50-3.50	2.78
नवंबर	23, 2020	1.90-3.40	3.11
नवंबर	24, 2020	1.90-3.40	3.07
नवंबर	25, 2020	1.90-3.40	3.11
नवंबर	26, 2020	1.90-3.40	3.13
नवंबर	27, 2020	1.90-3.50	3.13
दिसंबर	1, 2020	1.90-3.40	3.08
दिसंबर	2, 2020	1.90-3.40	3.10
दिसंबर	3, 2020	1.90-3.40	3.09
दिसंबर	4, 2020	1.50-3.40	3.02
दिसंबर	5, 2020	2.50-3.45	2.92
दिसंबर	7, 2020	1.90-3.40	3.03
दिसंबर	8, 2020	1.90-3.50	3.09
दिसंबर	9, 2020	1.90-3.50	3.15
दिसंबर	10, 2020	1.90-3.50	3.17
दिसंबर	11, 2020	1.90-3.50	3.13
दिसंबर	14, 2020	1.90-3.50	3.15
दिसंबर	15, 2020	1.90-3.50	3.21

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019	2020			
	नवं. 22	अक्तू 9	अक्तू 23	नवं. 6	नवं. 20
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	162443.00	74825.00	78340.00	76335.00	67680.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	15649.53	876.88	4634.88	1686.58	791.91
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.04-7.24	3.53-5.75	3.65-4.25	3.83-3.84	3.35-4.54

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019	2020			
	नवं 30	अक्तू 15	अक्तू 31	नवं 15	नवं 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	458415.60	395015.55	380112.20	389427.10	373146.10
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	80022.90	81950.20	40838.65	57001.85	64386.20
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.01-13.30	3.25-11.94	3.19-14.19	3.09-11.32	2.79-8.80

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		नवं. 29	अक्तू 23	अक्तू 30	नवं. 6	नवं. 13	नवं. 20	नवं. 27
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	18304	13824	10675	9975	14308	10765	12157
2 नोटिस मुद्रा	3660	3595	804	4481	3082	306	4103	632
3 मीयादी मुद्रा	790	757	816	545	560	301	755	687
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	379116	336437	397522	349122	385681	515057	411117
5 बाजार रिपो	221719	259645	313102	350328	321779	326228	380750	273258
6 कापरेट बांड में रिपो	2468	2953	3099	5545	172	3320	8110	1208
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	70279	46714	56477	49601	53816	57482	57492
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	70233	59684	91127	59096	51551	54335	70609
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	4846	4546	4932	4759	4399	5400	4965
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	2223	5238	5243	4164	1381	758	1555
10.2 182-दिवसीय	2380	1505	2112	4644	5720	5118	8518	7120
10.3 364-दिवसीय	2900	1901	2841	2662	1839	2540	11587	4704
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310	6						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	80714	74420	108608	75578	64989	80598	88953
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	240	3265	429	6988	4614	5196	4325

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-नवं.)		2020-21 (अप्रै.-नवं.)*		नवं. 2019		नवं. 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	52	59771	43	87789	4	440	4	7070
1ए प्रीमियम	70	43259	51	38378	43	84220	4	411	4	6905
1.1 पब्लिक	57	9867	41	8516	28	27174	4	440	3	6999
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	40	8340	28	24377	4	411	3	6837
1.2 राइट्स	15	55059	11	51255	15	60615	—	—	1	71
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	11	30038	15	59843	—	—	1	68
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	24	9227	10	3871	1	461	1	143
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	24	9227	10	3871	1	461	1	143
3.1.1 पब्लिक	34	14984	24	9227	10	3871	1	461	1	143
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3)	106	79910	76	68998	53	91660	5	901	5	7213
4.1 पब्लिक	91	24851	65	17743	38	31045	5	901	4	7141
4.2 राइट्स	15	55059	11	51255	15	60615	—	—	1	71

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2019		2020			
			नव.	जुला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.
			1	2	3	4	5	6
1 निर्यात	करोड ₹	2219854	184142	177954	170329	202583	183535	174559
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313361	25772	23729	22810	27569	24887	23519
1.1 तेल	करोड ₹	292340	27279	13146	14292	26511	12117	11412
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41289	3818	1753	1914	3608	1648	1538
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927514	156863	164808	156037	176072	171417	163148
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272072	21954	21976	20896	23961	23239	21982
2 आयात	करोड ₹	3360954	275255	217931	231601	224168	247051	247840
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	38523	28478	29474	30307	33605	33393
2.1 तेल	करोड ₹	925168	79091	49069	48104	42808	44081	46530
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	11069	6533	6441	5826	5981	6269
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	196165	168862	183497	181361	202970	201310
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	27454	21945	23033	24481	27624	27124
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141100	-91113	-39977	-61272	-21585	-63517	-73280
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161348	-12752	-4748	-6664	-2738	-8718	-9873
3.1 तेल	करोड ₹	-632828	-51812	-35923	-33812	-16297	-31964	-35118
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89262	-7251	-4780	-4526	-2218	-4332	-4732
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508273	-39301	-4055	-27460	-5288	-31553	-38163
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72087	-5500	31	-2137	-520	-4385	-5142

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019		2020				
		दिसं. 27	नव. 20	नव. 27	दिसं. 4	दिसं. 11	दिसं. 18	दिसं. 25
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	3264729	4266200	4257257	4275361	4261092	4274948	4272332
	मिलियन अमरीकी डॉलर	457468	575290	574821	579346	578568	581131	580841
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3032614	3953351	3951006	3965740	3950143	3955679	3953337
	मिलियन अमरीकी डॉलर	424936	533103	533455	537386	536344	537727	537474
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	195484	267075	260651	263659	265223	272327	270026
	मिलियन अमरीकी डॉलर	27392	36015	35192	35728	36012	37020	36711
	मात्रा (मैट्रिक टन)	634.96	670.12	672.92	673.85	674.78	676.65	676.65
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1046	1049	1049	1049	1049	1049	1049
	करोड ₹	10281	11067	11069	11117	11070	11142	11108
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1441	1492	1494	1506	1503	1515	1510
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	26349	34707	34532	34845	34657	35800	37862
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3700	4680	4679	4725	4709	4870	5145

अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2019	2020		2019-20	2020-21
		नव.	अक्टू.	नव.	अप्रै.-नव.	अप्रै.-नव.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130581	132699	137965	139261	6190	7010
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	24326	21958	21924	1156	-2320
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	92325	98992	100070	3651	8272
1.3 एनआरओ	15969	16049	17015	17267	1384	1058

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2019	2020	
		अप्रै.-नव.	अप्रै.-नव.	नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43013	26724	34090	2770	4562	5746
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	56006	35309	41156	3657	5075	6888
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	74390	47671	58368	5609	6838	10153
1.1.1.1.1 इक्विटी	51734	33032	45153	2924	5451	8635
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	2982	265	58	45	48
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	24814	38599	2210	4357	7355
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	4314	4985	536	929	1112
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1757	922	1303	120	120	120
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14175	9206	10206	1197	1197	1197
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8482	5433	3009	1489	191	321
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18384	12363	17212	1952	1763	3265
1.1.1.2.1 इक्विटी	18212	12234	17187	1916	1754	3263
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	128	26	36	9	2
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12993	8585	7065	887	513	1142
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	7572	4865	3799	492	578	614
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3151	2101	2141	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5674	3198	3186	342	493	387
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3403	1578	2061	209	821	122
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	1403	15760	20010	5860	2943	9427
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	552	15805	21594	5962	2998	9763
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-851	45	1584	101	55	336
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	44417	42483	54100	8631	7505	15173

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019	2020		
		नव.	सित.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1482.00	1648.17	938.37	942.44
1.1 जमाराशियां	623.37	39.42	123.46	23.34	23.32
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	7.14	8.26	3.85	3.53
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	73.99	73.61	22.80	25.39
1.4 उपहार	1907.71	153.02	225.36	108.89	110.55
1.5 दान	22.33	0.48	0.61	1.29	0.65
1.6 यात्रा	6955.98	522.28	358.12	272.98	253.26
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	262.96	416.70	162.64	160.81
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	3.04	2.51	3.66	2.92
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	400.98	427.87	333.45	355.77
1.10 अन्य	268.75	18.69	11.68	5.47	6.24

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2018-19	2019-20	2019	2020	
			दिसंबर	नवंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	72.64	73.28	72.78	69.36	69.11
1.2 रीर	114.01	116.75	119.05	117.57	117.14
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	74.18	74.33	73.77	70.69	70.51
2.2 रीर	116.32	119.61	121.91	121.55	121.24
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	63.07	63.59	63.35	58.53	58.33
1.2 रीर	121.70	125.76	128.72	125.27	125.17
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	92.88	93.63	93.28	86.20	85.90
2.2 रीर	94.20	97.32	99.64	96.96	96.89

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2019	2020	
		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	122	76	87
1.2 राशि	38011	2116	1733	2045
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	-	1	-
2.2 राशि	14921	-	300	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	122	77	87
3.2 राशि	52932	2116	2033	2045
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	7.10	3.62	5.48
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	2.03	1.25	1.87
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-15.00	0.00-9.00	0.00-10.30

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	303790	298671	5118	304250	272682	31568
1 चालू खाता (1.1+1.2)	161553	169132	-7579	150955	135448	15507
1.1 पण्य	79952	119602	-39650	75591	90375	-14784
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	81601	49530	32070	75364	45072	30292
1.2.1 सेवाएं	52777	31836	20941	49902	28733	21169
1.2.1.1 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.2.1.2 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.2.1.3 बीमा	602	354	248	590	537	53
1.2.1.4 जीएनआईई	169	298	-128	144	190	-46
1.2.1.5 विविध	39182	19144	20038	41738	20510	21228
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23247	2182	21064	25069	2769	22299
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	635	354	281	661	355	306
1.2.2 अंतरण	21986	2034	19952	20421	2023	18398
1.2.2.1 आधिकारिक	50	286	-236	36	258	-221
1.2.2.2 निजी	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.2.3 आय	6838	15660	-8822	5041	14316	-9275
1.2.3.1 निवेश आय	5434	14997	-9563	3596	13615	-10020
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	142237	128657	13580	152658	137234	15424
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85751	75960	9791	97269	65689	31581
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15650	8336	7314	30475	5892	24583
2.1.1.1 भारत में	14875	4482	10393	29501	2450	27051
2.1.1.1.1 इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3464		3464	4024	0	4024
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1298	37	1262	1488	5	1483
2.1.1.2 विदेश में	775	3854	-3079	974	3442	-2468
2.1.1.2.1 इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	808	-808
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1363	-1363	0	1243	-1243
2.1.2 संविभाग निवेश	70101	67625	2476	66794	59796	6998
2.1.2.1 भारत में	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1 एफआईआई	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
2.1.2.1.1.2 ऋण	20059	14699	5361	11413	10501	912
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1789	1318	471	375	1113	-738
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	21544	18472	3072	20225	24468	-4243
2.2.1 बाह्य सहायता	1802	1366	435	3201	1330	1870
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	29	-27	2	28	-26
2.2.1.2 भारत को	1800	1338	462	3199	1302	1897
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9011	5728	3283	8362	12659	-4297
2.2.2.1 भारत द्वारा	1287	1082	205	769	1005	-235
2.2.2.2 भारत को	7724	4646	3078	7593	11654	-4061
2.2.3 भारत को अल्पावधि	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	10731	10940	-209	8662	9770	-1108
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	437	-437	0	709	-709
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	23881	25699	-1818	18850	30025	-11175
2.3.1 वाणिज्य बैंक	23881	25364	-1483	18837	30025	-11188
2.3.1.1 आस्तियां	9914	10148	-235	7295	16747	-9451
2.3.1.2 देयताएं	13967	15216	-1249	11541	13279	-1737
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13458	11178	2280	10311	8377	1934
2.3.2 अन्य	0	335	-335	13	0	13
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	11061	8523	2538	16314	17050	-737
3 भूल-चूक		882	-882	637	0	637
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	5118	-5118	0	31568	-31568
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		5118	-5118	0	31568	-31568

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2139568	2103519	36049	2263084	2028270	234814
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1137803	1191185	-53382	1122840	1007492	115348
1.1 पण्य	563094	842346	-279252	562264	672233	-109969
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	574709	348839	225870	560576	335259	225317
1.2.1 सेवाएं	371704	224219	147485	371185	213726	157459
1.2.1.1 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.2.1.2 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.2.1.3 बीमा	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.2.1.4 जीएनआईई	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.2.1.5 विविध	275955	134831	141124	310461	152561	157899
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	163725	15370	148355	186466	20598	165868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4475	2494	1981	4914	2638	2275
1.2.2 अंतरण	154844	14327	140517	151896	15051	136845
1.2.2.1 आधिकारिक	349	2014	-1665	269	1916	-1647
1.2.2.2 निजी	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.2.3 आय	48161	110294	-62133	37495	106483	-68988
1.2.3.1 निवेश आय	38270	105623	-67353	26745	101274	-74529
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1001765	906125	95640	1135504	1020778	114725
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	603940	534984	68957	723512	488607	234905
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	110224	58709	51515	226681	43826	182855
2.1.1.1 भारत में	104766	31568	73198	219436	18223	201213
2.1.1.1.1 इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	24395	0	24395	29930		29930
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9145	258	8886	11070	39	11032
2.1.1.2 विदेश में	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
2.1.1.2.1 इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5548	-5548	0	6009	-6009
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	9596	-9596	0	9247	-9247
2.1.2 संविभाग निवेश	493716	476275	17441	496831	444780	52050
2.1.2.1 भारत में	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1 एफआईआई	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
2.1.2.1.1.2 ऋण	141277	103523	37754	84891	78108	6783
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	151732	130099	21633	150435	181998	-31563
2.2.1 बाह्य सहायता	12689	9624	3065	23807	9895	13911
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	12	208	-197
2.2.1.2 भारत को	12675	9423	3252	23795	9687	14108
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	63463	40344	23119	62198	94158	-31960
2.2.2.1 भारत द्वारा	9066	7623	1444	5722	7473	-1751
2.2.2.2 भारत को	54397	32721	21675	56476	86685	-30209
2.2.3 भारत को अल्पावधि	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	75580	77050	-1470	64430	72671	-8241
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	3081	-3081	0	5273	-5273
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	168191	180998	-12807	140212	223336	-83124
2.3.1 वाणिज्य बैंक	168191	178639	-10448	140113	223336	-83222
2.3.1.1 आस्तियां	69820	71474	-1654	54265	124564	-70299
2.3.1.2 देयताएं	98370	107165	-8794	85848	98771	-12923
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	94785	78728	16056	76699	62311	14387
2.3.2 अन्य	0	2359	-2359	99	0	99
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	77902	60029	17873	121345	126824	-5479
3 भूल-चूक	0	6210	-6210	4740		4740
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	36049	-36049	0	234814	-234814
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	36049	-36049		234814	-234814

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सित्त. 2019			जुला.-सित्त. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	161551	169104	-7553	150953	135423	15531
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	132729	151438	-18709	125493	119109	6385
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	79952	119602	-39650	75591	90375	-14784
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	79293	115248	-35955	75243	84287	-9044
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	658	0	658	348	0	348
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		4354	-4354	0	6088	-6088
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	52777	31836	20941	49902	28733	21169
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	33	25	68	11	56
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	44	253	-208	35	204	-169
1.अ.ख.3 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.अ.ख.4 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.अ.ख.5 निर्माण	677	714	-37	589	563	26
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	602	354	248	590	537	53
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	248	1776	-1528	313	1456	-1143
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23947	2654	21293	25793	3290	22503
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	551	923	-372	530	817	-287
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	169	298	-128	144	190	-46
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1539	984	555	1782	683	1099
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	6838	15660	-8822	5041	14316	-9275
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
1.आ.2 निवेश आय	4379	14782	-10403	2808	13314	-10507
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1763	7056	-5293	1327	8038	-6711
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	54	3760	-3706	49	2126	-2076
1.आ.2.3 अन्य निवेश	602	3951	-3349	78	3150	-3072
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1960	15	1945	1354	1	1353
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1055	215	840	788	301	487
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	21984	2006	19978	20419	1998	18421
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	21291	1336	19955	19711	1287	18424
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	645	412	233	674	479	195
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	258	-210	35	232	-198
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	90	190	-100	109	197	-87
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	9	93	-84	8	100	-92
2.2 पूँजी अंतरण	81	97	-16	101	96	5
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	142149	133614	8535	152550	168631	-16081
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	15650	8336	7314	30475	5892	24583
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14875	4482	10393	29501	2450	27051
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13577	4446	9131	28013	2445	25568
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3464		3464	4024	0	4024
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	775	3854	-3079	974	3442	-2468
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	775	2491	-1716	974	2199	-1225
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788	0	808	-808
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1363	-1363	0	1243	-1243
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1363	-1363	0	1243	-1243
3.2 संविभाग निवेश	70101	67625	2476	66794	59796	6998
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	68312	66307	2005	66420	58684	7736
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	20059	14699	5361	11413	10501	912
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1789	1318	471	375	1113	-738
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	7395	7138	257	9664	12339	-2675
3.4 अन्य निवेश	49003	45398	3605	45617	59035	-13418
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13458	11513	1945	10325	8377	1948
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	335	-335	13	0	13
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13458	11178	2280	10311	8377	1934
3.4.2.3 सामान्य सरकार				0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र				0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	21235	21281	-45	20088	35637	-15549
3.4.3अ भारत को ऋण	19946	20170	-224	19317	34605	-15287
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1289	1111	178	771	1033	-262
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	54	71	-17	78	62	16
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	3524	1155	2369	6464	4480	1984
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	5118	-5118	0	31568	-31568
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण				0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.				0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.				0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5118	-5118	0	31568	-31568
4. कुल आस्तियां / देयताएं	142149	133614	8535	152550	168631	-16081
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71843	67071	4772	94110	66340	27770
4.2 ऋण लिखत	66783	60270	6513	51976	66242	-14267
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	3524	6273	-2750	6464	36048	-29584
5. निवल भूल-चूक	0	882	-882	637	0	637

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जुला.-सित्त. 2019			जुला.-सित्त. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1137790	1190988	-53198	1122827	1007305	115522
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	934798	1066564	-131766	933449	885959	47490
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	563094	842346	-279252	562264	672233	-109969
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	558456	811684	-253228	559675	626945	-67270
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4638	0	4638	2588	0	2588
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	30661	-30661	0	45287	-45287
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	371704	224219	147485	371185	213726	157459
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिमूर्ति वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	235	173	505	85	420
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	310	1779	-1468	263	1519	-1256
1.अ.ख.3 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.अ.ख.4 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.अ.ख.5 निर्माण	4770	5031	-261	4383	4186	197
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1749	12511	-10762	2330	10833	-8503
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	168656	18693	149963	191855	24472	167382
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3882	6503	-2621	3944	6078	-2135
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	10839	6933	3906	13255	5078	8178
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	48161	110294	-62133	37495	106483	-68988
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
1.आ.2 निवेश आय	30842	104107	-73266	20884	99036	-78152
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12418	49694	-37276	9869	59790	-49921
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	380	26481	-26100	366	15810	-15445
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4241	27830	-23589	579	23428	-22848
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	13803	103	13700	10070	7	10063
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7428	1515	5913	5861	2238	3623
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	154831	14130	140701	151883	14863	137020
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्ततर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	149953	9410	140544	146616	9573	137043
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4542	2903	1639	5011	3561	1450
1.इ.2 सामान्य सरकार	336	1817	-1481	257	1729	-1472
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	632	1337	-705	813	1463	-649
2.1 अनुत्पादित वित्ततर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	63	656	-593	62	747	-685
2.2 पूँजी अंतरण	569	680	-112	751	716	36
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1001146	941034	60112	1134703	1254317	-119614
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	110224	58709	51515	226681	43826	182855
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	104766	31568	73198	219436	18223	201213
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95621	31310	64312	208366	18184	190182
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	24395	0	24395	29930	0	29930
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5458	17544	-12086	7245	16356	-9111
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5548	-5548	0	6009	-6009
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	9596	-9596	0	9247	-9247
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	9596	-9596	0	9247	-9247
3.2 संविभाग निवेश	493716	476275	17441	496831	444780	52050
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	481114	466993	14122	494044	436504	57540
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	141277	103523	37754	84891	78108	6783
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	52083	50270	1813	71882	91780	-19898
3.4 अन्य निवेश	345123	319731	25392	339309	439117	-99808
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	94785	81087	13697	76798	62311	14486
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	2359	-2359	99	0	99
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशिया लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशिया)	94785	78728	16056	76699	62311	14387
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	149558	149878	-320	149419	265077	-115658
3.4.3.अ भारत को ऋण	140478	142055	-1577	143686	257396	-113711
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	9080	7823	1257	5734	7681	-1947
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	383	501	-117	580	462	117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	24817	8134	16683	48082	33321	14761
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	36049	-36049	0	234814	-234814
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	36049	-36049	0	234814	-234814
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1001146	941034	60112	1134703	1254317	-119614
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	505985	472376	33609	700013	493455	206557
4.2 ऋण लिखत	470345	424475	45870	386609	492727	-106118
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	24817	44183	-19366	48082	268134	-220052
5. निवल भूल-चूक	0	6210	-6210	4740	0	4740

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418243	176244	417145	185898	419426	188366	455989
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	114834	398819	120322	395835	121546	430881
1.2 अन्य पूंजी	64515	22817	61410	18327	65577	23591	66820	25108
2 संविभाग निवेश	3847	246701	4541	260195	4303	241581	5041	253289
2.1 इक्विटी	602	134778	2344	144039	830	138961	1906	149095
2.2 ऋण	3246	111923	2197	116155	3474	102621	3136	104195
3 अन्य निवेश	52422	427272	54980	428886	53694	432321	64921	432817
3.1 व्यापार ऋण	1460	104276	1633	106581	1271	104001	2917	102193
3.2 ऋण	6741	179601	7892	174823	7435	184391	9048	180264
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	27563	133105	27741	132942	34864	137519
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	17892	14378	17247	10987	18092	12841
4 रिज़र्व्स	477807		433707		505702		544687	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092216	669472	1106226	749597	1093328	803016	1142095
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375183		-436754		-343730		-339079

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2019-20	2019	2020		विव 2019-20	2019	2020	
		नव.	अक्टू.	नव.		नव.	अक्टू.	नव.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	-	2.78	2.44	2.45	-	10655649	12416671	10692192
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	-	1.01	1.06	0.79	-	6869045	8849617	6942678
1.1.1 आउटराइट	-	0.63	0.61	0.48	-	862104	900488	727023
1.1.2 रेपो	-	0.19	0.27	0.12	-	2359755	4108317	1762647
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	-	0.19	0.18	0.19	-	3647186	3840812	4453008
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	-	1.74	1.36	1.64	-	3525359	3435633	3625849
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	-	0.04	0.02	0.02	-	261245	131420	123665
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	-	133.87	138.22	137.80	-	8679806	8496046	7987655
1.1 ग्राहक लेनदेन	-	131.61	136.54	136.13	-	7469569	7226105	6802206
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	-	2.27	1.68	1.67	-	1210237	1269941	1185449
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	-	18750.31	28646.23	30269.97	-	2226286	2993114	2986234
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	-	0.64	1.02	0.93	-	33	57	54
2.2 एपीबीएस \$	-	1364.56	961.85	927.29	-	6908	5531	4400
2.3 आईएमपीएस	-	2280.75	3189.72	3391.14	-	202904	274645	276459
2.4 एनएसीएच जमा \$	-	722.06	1015.80	1114.23	-	92562	91386	96069
2.5 एनईएफटी	-	2194.59	2761.65	2734.10	-	1734651	2235389	2218252
2.6 यूपीआई @	-	12187.71	20716.19	22102.28	-	189229	386107	390999
2.6.1 जिसमें से यूपएसएसी@	-	0.74	0.97	0.91	-	13	16	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	-	766.41	920.15	944.24	-	70199	79305	78709
3.1 भीम आधार पे @	-	6.46	10.55	9.39	-	97	192	181
3.2 एनएसीएच नामे \$	-	758.18	848.34	869.63	-	70097	79022	78433
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	-	1.77	61.26	65.22	-	5	91	96
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	-	6062.09	5863.58	5633.00	-	137707	168169	163940
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	-	1762.12	1718.03	1662.58	-	60130	64652	62350
4.1.1 पीओएस आधारित \$	-	1033.52	818.33	874.82	-	31730	26956	30495
4.1.2 अन्य \$	-	728.60	899.70	787.76	-	28401	37696	31855
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	-	4299.96	4145.55	3970.43	-	77577	103517	101591
4.2.1 पीओएस आधारित \$	-	2483.18	1983.98	2112.56	-	37007	37110	42289
4.2.2 अन्य \$	-	1816.79	2161.57	1857.87	-	40570	66408	59302
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	-	4672.07	4591.51	4193.78	-	17844	17802	16704
5.1 वॉलेट	-	3354.08	3639.88	3420.83	-	14652	13718	12717
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	-	1317.99	951.63	772.96	-	3192	4084	3987
5.2.1 पीओएस आधारित \$	-	123.86	37.11	39.38	-	738	1045	1111
5.2.2 अन्य \$	-	1194.13	914.52	733.57	-	2454	3039	2877
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	-	866.12	643.08	596.35	-	644802	524090	494383
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	-	864.86	643.08	596.35	-	643678	524090	494383
6.2 अन्य	-	1.26	0.00	0.00	-	1124	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	31117.01	40664.55	41637.35	-	3096840	3782480	3739970
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	31250.88	40802.76	41775.15	-	11776646	12278526	11727625
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	30384.76	40159.68	41178.79	-	11131843	11754436	11233243

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2019-20	2019	2020		वि. व. 2019-20	2019	2020	
		नंव.	अक्टू.	नंव.		नंव.	अक्टू.	नंव.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	13534.23	22713.54	22521.45	-	471295	796402	778380
1.1 इंटर-बैंक \$	-	1234.84	2103.16	2191.98	-	96802	158866	165155
1.2 इंटर-बैंक \$	-	12299.40	20610.38	20329.47	-	374494	637535	613225
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	2719.42	2977.78	2814.17	-	2539143	3407315	3419474
2.1 इंटर-बैंक @	-	592.01	619.27	585.09	-	1058811	1646090	1653359
2.2 इंटर-बैंक @	-	2127.41	2358.51	2229.09	-	1480333	1761225	1766114
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	6305.28	5688.24	5913.87	-	285376	271622	280522
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	7.99	4.85	4.64	-	381	240	231
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	6269.60	5658.36	5883.59	-	284083	270488	279379
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	27.68	25.04	25.63	-	912	893	912
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	67.02	34.11	37.91	-	134	134	143
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	62.70	29.24	32.33	-	129	129	137
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	4.32	4.87	5.58	-	5	5	6
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	339.83	720.69	684.78	-	9648	18354	18820
5.1 एईपीएस @	-	339.83	720.69	684.78	-	9648	18354	18820

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि. व. 2019-20	2019	2020	
		नंव.	अक्टू.	नंव.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	8851.69	9335.85	9528.15
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	544.11	594.20	601.13
1.2 डेबिट कार्ड	-	8307.59	8741.65	8927.02
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	17253.28	20143.54	20443.15
2.1 वॉलेट @	-	16243.87	18578.62	18857.67
2.2 कार्ड @	-	1009.41	1564.92	1585.48
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	2.32	2.34	2.34
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	2.10	2.10	2.09
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	0.22	0.24	0.25
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	2.35	3.49	3.57
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	48.83	53.94	54.19
6 भारत क्यूआर @	-	15.94	26.05	30.46
7 यूपीआई क्यूआर *	-	-	657.45	697.82

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2019		2020		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6314426	6512659	6486585	6704983	7137069
1. वाणिज्य बैंक	39.66	39.05	40.41	38.98	38.55
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.42	0.39	0.39	0.36	0.34
3. बीमाकृत कंपनियां	24.86	24.90	25.09	26.24	25.33
4. म्यूच्युअल फंड	0.77	1.53	1.43	2.02	2.42
5. सहकारी बैंक	2.01	1.97	1.90	1.86	1.86
6. वित्तीय संस्थाएं	1.15	1.14	0.53	1.19	1.42
7. कॉरपोरेट	0.92	0.84	0.81	0.78	0.94
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.31	3.33	2.44	1.79	2.05
9. भविष्य निधियां	4.87	4.93	4.72	4.96	4.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.99	14.72	15.13	14.70	15.00
11. अन्य	7.05	7.23	7.17	7.11	7.32
11.1 राज्य सरकार	1.99	1.97	2.05	1.99	1.86

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2019		2020		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2905169	3047353	3265990	3393099	3564979
1. वाणिज्य बैंक	32.53	32.46	34.99	33.54	34.60
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.72	0.64	0.76	0.74	0.54
3. बीमाकृत कंपनियां	33.39	32.50	31.63	30.85	30.26
4. म्यूच्युअल फंड	1.12	1.20	1.14	1.74	1.96
5. सहकारी बैंक	4.24	4.16	4.12	4.38	4.19
6. वित्तीय संस्थाएं	0.33	0.31	0.11	1.96	1.92
7. कॉरपोरेट	0.28	0.31	0.30	0.31	0.39
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.05	0.04	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	22.36	23.66	22.22	21.70	21.31
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	4.98	4.73	4.71	4.78	4.80
11.1 राज्य सरकार	0.16	0.17	0.18	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2019		2020		
	सितं.	दिसं.	मार्च	जून	सितं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	538041	514588	538409	881362	982286
1. वाणिज्य बैंक	50.81	45.19	61.06	46.11	53.50
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.92	2.07	2.26	1.48	2.16
3. बीमाकृत कंपनियां	5.55	5.76	7.45	4.64	4.06
4. म्यूच्युअल फंड	14.08	20.42	13.24	23.45	19.90
5. सहकारी बैंक	2.55	2.07	2.55	1.95	1.63
6. वित्तीय संस्थाएं	1.82	2.12	0.58	1.67	1.34
7. कॉरपोरेट	1.57	1.66	1.89	1.43	1.63
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.01	0.02	0.05	0.00
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	11.27	4.80
11. अन्य	21.70	20.70	10.95	7.95	10.99
11.1 राज्य सरकार	17.91	16.36	6.22	4.35	7.76

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	978	27	1439	24	2064	4
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	476	18	-	-	-	-
6	गोवा	122	24	152	17	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	242	6	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1100	29	561	13
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	205	22	487	18	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	4503	16	-	-	-	-
16	मणिपुर	49	29	152	27	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	120	25	87	8	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	464	19	408	12	-	-
23	राजस्थान	1277	29	897	12	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1056	27	1611	26	685	18
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8418	828	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1541	2	--	-
3	असम	4572	55	--	-
4	बिहार	7091	0	--	-
5	छत्तीसगढ़	4501	0	1	4750
6	गोवा	605	304	--	-
7	गुजरात	7756	491	--	-
8	हरियाणा	1411	1229	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	183	0	--	-
12	कर्नाटक	4282	0	--	26500
13	केरल	2181	0	--	-
14	मध्य प्रदेश	0	932	--	-
15	महाराष्ट्र	41789	432	--	25000
16	मणिपुर	384	102	--	-
17	मेघालय	673	36	9	-
18	मिज़ोरम	504	40	--	-
19	नगालैंड	1661	34	--	-
20	उड़ीसा	12717	1479	86	18545
21	पुदुचेरी	298	0	--	806
22	पंजाब	938	0	8	-
23	राजस्थान	0	0	129	2000
24	तमिलनाडु	6737	0	40	14678
25	तेलंगाना	5755	1251	--	-
26	त्रिपुरा	379	9	--	-
27	उत्तराखंड	3216	81	--	-
28	उत्तरप्रदेश	664	0	180	-
29	पश्चिम बंगाल	8946	539	214	-
	कुल	127201	7844	666	92279

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सितंबर		अक्टूबर		नवंबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	7000	6417	6000	5417	2000	1417	39250	34001
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	-	-	-	-	53	53	481	481
3	असम	10595	8089	12906	10996	2300	2300	2000	2000	2500	2500	7800	7800
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	4000	4000	4000	4000	4000	20000	19000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	700	700	2000	1000	2000	2000	6000	5000
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	400	400	200	-	300	300	2000	1700
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	5500	4500	3000	1000	5500	3500	28280	20323
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	4500	4500	2000	1200	2000	2000	22500	19900
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	-	-	1500	1500	1000	1000	3000	2200
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	1405	1405	500	500	1605	1605	6810	5310
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	-	-	2600	2600	-	-	2600	2100
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	10000	10000	8000	6000	8000	5400	45000	40400
13	केरल	19500	13984	18073	12617	2000	2000	-	-	636	-364	16566	15566
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	2000	2000	3000	3000	4000	4000	18000	18000
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	14000	12000	11000	8673	5500	350	65000	52800
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	-	-	-	-	-	-	700	700
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	600	550	250	250	-	-100	1050	900
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	132	132	-	-	232	232	674	574
19	नगालैंड	822	355	1000	423	150	150	250	150	314	314	1064	864
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-	-	-	-	-1000	3000	2000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	225	225	125	125	200	-	550	350
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	4410	3010	2785	535	3321	1871	18216	11816
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	3500	3500	3000	1730	3761	3261	34211	27129
24	सिक्किम	1088	795	809	481	148	148	-	-	312	312	927	927
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	3250	2000	6000	4125	4000	3375	58000	49569
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	4500	4083	3000	2583	3573	3156	29534	25783
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	400	400	300	300	413	413	1113	1013
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	6000	4000	8000	5524	4000	4000	25500	12791
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	1500	1500	1200	1200	-	-	3700	3000
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	4500	3000	3500	2500	4000	3500	29500	20000
	कुल	478323	348643	634521	487454	83120	72920	74210	55912	63219	47094	491026	401996

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहाँ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहाँ अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रेडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जुला. 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाजारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1 और 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई मेल : spsdepr@rbi.org.in
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेपर, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।